

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj)**

Students can retain library books only for two weeks at the most.

| BORROWER'S No | DUE DATE | SIGNATURE |
|------------------|----------|-----------|
| | | |

आजकलका भारत

रमेश थापर

कृत " INDIA IN TRANSITION " का

हरिशंकर और

रवीन्द्रनाथ चतुर्वेदी

द्वारा किया हुआ अनुवाद.



मयूर
किताबें

कीमत ५.७५

प्रथमावृत्ति १९५८

सर्वाधिकार सुरक्षित

मुद्रक
डा. ग. टवले
कॅन्टॉटिक मुद्रणालय
चीराबजार, बम्बई २

प्रकाशक
डा. ग. टवले
मयूर विज्ञान
चीराबजार, बम्बई २

चि० मालविका
और वाल्मिक को
वे अपने
बचपन के
इस कालिका
किसी समय
सिंहावलोकन
करेंगे, इसलिए....

विषय - सूची

| | | | |
|--------------------------|-----|-----|-----|
| विहंगावलोकन | ... | ... | ६ |
| भूत | | | |
| १ - सत्ताहस्तांतरण | ... | ... | ३ |
| २ - एकीकरणका आरम्भ | ... | ... | १३ |
| ३ - एक युगका अंत | ... | ... | २० |
| ४ - दो प्रवृत्तियाँ | ... | ... | ४० |
| ५ - शीतयुद्धका तर्क | ... | ... | ५३ |
| ६ - कॉमिंसकी आर्थिक नीति | ... | ... | ६६ |
| ७ - नई प्रवृत्तियों | ... | ... | ७७ |
| ८ - भाषावाद | ... | ... | ६३ |
| वर्तमान | | | |
| १ - महत्वपूर्ण वर्ष | ... | ... | १०३ |
| २ - प्रचुरताकी योजना | ... | .. | १३१ |
| ३ - सौहार्द्रताका प्रसार | .. | ... | १६७ |
| ४ - पंचशील क्यों ? | ... | ... | १८३ |
| ५ - राजनैतिक शतरंज | ... | ... | १६८ |
| भविष्य | | | |
| १ - सार्वजनीन एकता | ... | ... | २१५ |
| २ - नव क्षितिज | ... | ... | २३७ |
| सूची | ... | ... | २४३ |

वि हं गा व लो क न

एक भारतीय दार्शनिकने कहा है, कि “ मुझसे मेरे देशके विषयमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है । राजनीति और अर्थशास्त्रके सामान्य निष्कर्षों द्वारा भारतकी न तो विवेचना ही हो सकती है और न उसके सम्बन्धमें कुछ ज्ञान ही प्राप्त किया जा सकता है । हम पूर्णरूपेण विचित्र हैं । मोहन जोदड़ो और हड़प्पा युगमें आज तक पिछले पाँच हजार वर्षोंमें हम सभ्य और सुसंस्कृत ही रहे हैं । पराजय तथा निराशा, विजय तथा रत्नपातके बावजूद भी हमारे विचारों और व्यवहारोंकी सुसंस्कृति कायम है । हम सदैव विचित्र बने रहेंगे । भारतीय इतिहास तथा हमारे दृष्टिकोणके निर्माता बुद्ध, अशोक, अकबर और गांधी जैसे महापुरुषों और उनके आंदोलनोंमें यही शिष्टा मिलती है । अब चूंकि हम पुनः स्वतंत्र हो गये हैं, हम विश्वकी प्रगति हेतु नवीन पथोंको प्रकाशित करेंगे ! ... ”

और इस प्रकार यह अनुमान किया जाता है कि भारत शांति स्थापनका प्रयत्न इस कारण करता है, क्योंकि वह सदैव शांतिमय विचारोंका केन्द्र-स्थल रहा है । देशके नेता समाजवादका उपदेश इस कारण देते हैं, क्योंकि समस्त युगोंमें भारतीय व्यवहारका यही अत्यावश्यक तत्त्व रहा है । अहिंसा, शाकाहारिता, नैतिक, आत्मिक, रहस्यात्मक भूषण, पुनर्जन्मकी कल्पना, क्षमा करो और मूल जाओ आदि अनेक गुण हमारी राष्ट्रीय योग्यताके प्रमुख तत्त्व हैं । सबसे बड़ी बात यह बड़ी जानी है कि हम अपने आगामी जीवनके निर्माता हैं और वर्तमान कर्मोंके अनुसार हम उसे अच्छा या बुरा बना सकते हैं ।

हमने वर्तमान युगके अंदर लौह और बौद्ध आवरणके सम्बन्धमें बहुत कुछ सुना है, लेकिन इस मिथ्या धारण की भित्तिके विषयमें हमें अत्यंत अल्प ज्ञान है । इसने भारतीय घटना सम्बन्धी हमारे ज्ञानको अच्छादित कर रक्खा है । भारतीय कार्यवाहियोंकी थोड़ी बहुत अद्वितीय आत्मिक शक्तिमें प्रेरित प्रमाणित करनेके लिये कुछ सशटे-सीधे उदाहरण प्रस्तुत करना मनोरंजनका एक उपयोगी साधन हो गया है ।

एक सामान्य सर्वेक्षण के उपरान्त हमें इस बात पर विश्वास हो जायगा। भारतीय स्वतंत्रता करोड़ों व्यक्तियों के बीरतापूर्ण संघर्ष और अन्यायों सहन नहीं, बल्कि सम्यक् कार्यों द्वारा प्राप्त की गई थी। और आजकल समाजवाद को बिना किसी प्रकार के वर्गसंघर्ष के प्राप्त किया जा रहा है। ऐतिहासिक तर्कों द्वारा भूमि सुधार का प्रयत्न हो रहा है। राजनैतिक विरोधों को भी इसी तरह अनशन तथा आत्मशोधक उपवासों द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। आयकर बचा कर 'स्वेच्छया' अंशदान स्वरूप अदा कर दिया जाता है। 'अहिंसा' आगे बढ़ कर सर्वोदय और दान का रूप धारण कर लेती है और दानों के भी अनेक प्रकार हैं जैसे भूदान, संपत्तिदान, जीवनदान, धर्मदान आदि।

हमें बतलाया जाता है कि सन १९४० 'वादी' का समय व्यतीत हो चुका है। केवल दान ही सदैव के समान अब भी प्रामाणिक और अत्यावश्यक बना हुआ है। यथार्थता वादी इस अनुरागित को चुनौती देते हैं। इस बात पर विश्वास न करनेवाले लोगों को उन देशादोहियों के साथ संघर्ष किया जाता है, जिन्हें विदेशी खेतों में प्रोत्साहन प्राप्त है।

क्या हमने अपने अहिंसक भूतकाल में तथा आजकल भीषण और साहसिक उत्तेजना के दर्शन नहीं किये हैं? क्या हमारे देश के लक्ष्मणी किसी भी स्थिति में समाजवादी प्रक्रिया का विरोध नहीं करेंगे, जिसके कारण समाज के अंदर उनकी स्थिति उपेक्षित हो गई है? क्या भारतीय जमींदारों ने अपने आसामियों को अपने समकक्ष रखने जाने के प्रत्येक प्रयत्न का सदैव विरोध नहीं किया है? यदि लोग अपने कर्मों को पूरा-पूरा अदा कर दिया करें तो अंशदान की क्या आवश्यकता है? इस तरह के प्रश्न निश्चित रूप से सार्थक हैं। किन्तु हमारे मौलिक विचारों को यह बातें अप्रचलित प्रतीत होती हैं।

सम्भव है कुछ लोग इसका कारण जानने का लोभ सवराण न कर सकें। इसका उत्तर भी तैयार रखना है। हमें वर्तमान भारतीय जगद्विस्तार की प्रगति समझाई जायगी। तत्परचात हमें ऐसे सुवृत्त इतिहास की ओर उन्मुख किया जायगा जिसमें किसी एकान्ती घटना निर्माण अनेकानेक पाठकों और प्रतिपादकों की उपेक्षा की गई हो।

वि हं गा घ लो क न

परिणामस्वरूप हमें निम्नलिखित सत्यों और अर्थसत्त्वों का एक अजीब सम्मिश्रण देखनेको मिलेगा जिसमें कदा कदा थोड़ा-बहुत अंतर पड़ सकता है।

तथ्य १ — जहाँ एक ओर सन १८५७ में राजाओं तथा सामन्तोंने स्वतंत्रता संग्रामके अवसरपर भारत-वासियों का नेतृत्व किया, वहाँ दूसरी ओर इसके आगे और पीछे राजा राममोहन राय जैसे सुधारक और स्वातिपात्र विचारक जल्द-बाजीसे मुक्ति प्राप्त करने का विरोध करनेके लिये शेष रह गये। लुटेरों, दुसाह-सिक्कों और धार्मिक रहस्यवादियों आदि सभीको सार्वजनिक निष्ठा प्राप्त हो गई। साथही साथ साहसी अन्वेषक मस्तिष्क जो समयके साथ चल रहे थे, पृष्ठभूमिमें पहुँच गये।

तथ्य २ — बीसवीं शताब्दी आते आते आतंकवादी किसी गुप्त सत्त्वाके स्थानपर ए. सी. ह्यूम नामक एक अमेरिकी राजनैतिक आकाङ्क्षी और ध्यान अकृष्ट किया और एक ऐसी सत्त्वाकी नींव रखी जो आगे चल कर 'भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस' कहलाई। उन्होंने यह कदम एक सुरक्षा कपाट पानेके लिये उठाया था। परन्तु फिर भी उन्हें भारतीय स्वदेशाभिमानी लोगोंका समर्थन मिला।

तथ्य ३ — जब इसके मजदूर जारशाहीकी जड़ खोदनेमें व्यस्त थे और जब साम्यवादी विचार समारके अनेक भागोंमें व्यक्त हो रहे थे, उस समय भारतीय राजनीतिक पथ-प्रदर्शक, ब्रिटिश मिशनरोंके प्रति स्वामिभक्ति प्रदर्शन सम्बन्धी बातचीतमें लगे हुए थे।

तथ्य ४ — भारतने लेनिनके स्थानपर गांधीमें क्रांतिकारी भावनाके दर्शन किये थे। गांधीने स्वतंत्रता स्वर्परो सविधानवादी दलदलसे निकाल कर सार्वजनिक कार्यवाईके मुहल धरातलपर ला रक्खा। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो भारतीय रंगमंचपर सक्रियता आ गई है। इसके पश्चात सत्य और नैतिक शुचिताको प्रधानता देनेवाला आर्हिमक शांतिपूर्ण सत्याग्रह आया। इसके अजीब रूपका ससार उपहास करता था। किन्तु लंगेटीधारीकी धोड़े ही दिनोंके अंदर अभूतपूर्व सख्यामें अपने अनुयायी प्राप्त हो गये। उनके नेतृत्वमें यह सपूर्ण उपमहाद्वीप सक्रिय हो उठा।

तथ्य ५ — चीनकी क्रांतिने उद्देहित कर रक्खा था। भारतमें शांतिपूर्ण सत्याग्रहका प्रभाव था। चीनमें रक्षकी नदियों बहती थीं। भारतमें रक्षकी एक

बूंदके गिरते ही सन्ध्याग्रह रोक दिया जाता था। चीनके अंदर साम्राज्यवाद और सामंतवाद विरोधी झुंझार अभियान तीव्रतर होता गया। भारतमें भी तीव्रता तदनुरूप ही थी, किन्तु अंतर्वस्तु पूर्णतया भिन्न थी। साम्राज्यवादका सर्वनाश नहीं करना था, बरन् उसे उखाड़ फेंकना था।

तथ्य ६—फासीजम सामने आया। समारमें महायुद्धकी दुंदुभी बज उठी। एशियाके सुविस्तृत प्रदेशोंको जापानने परेलेले रींद बाला। जनता विरोध करनेके लिये संगठित हुई। भारतमें क्या हुआ? भारतवासियोंने युद्धकायोंमें असहयोग किया, क्योंकि उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं हुई थी। उन्होंने विरोध नहीं किया। उन्होंने सहायता भी नहीं दी।

तथ्य ७—जब आतंकवाद फासीजम भूलुठित हो गया, जापानके विरोधमें लड़नेवाले एशियावासियोंने अपनी बेदुर्बलियोंमें से पुराने परिचयी आकांक्षाओंकी ओर फेर दिये। औपवीची तरह एशियाभरमें औपनिवेशिक युद्ध आरम्भ हो गये। लेकिन भारतमें यह बात नहीं हुई। ब्रिटिश शासन समाप्त करनेके लिये शांतिपूर्ण मार्गों पर आरम्भ हुई और अंतमें सफल भी हुई, चाहे देशका विभाजन भले ही बरजा पड़ा हो। आकांक्षा और आकाश दोनोंने सैन्यता स्वरूप हाथ मिला लिया।

तथ्य ८—अब साम्राज्यिक दंगोंका दृष्टिकोण रूप दिखलाई पड़ा। क्या यह इस बातका प्रमाण था कि भारत भी रक्तप्रेमी है? निश्चित रूपसे नहीं। अन्यथा क्या बापूकी भयरहित वाणीकी शक्त करनेवाली हथियारों की गोलियोंके अक्षर पर आधुनिक आधुनिक दर्शन हो सकते? इस दुःखद घटना की समझालीन साम्राज्यिक शांतिवादी नालुक संतुलन मुड़ होना गया। अनेक उत्तेजना फैलाने वालोंके पदचिह्नों और छेड़छाड़के बावजूद भी जो यदाकदा यत्र तत्र कथम मचानेमें सफल हो जाते थे, शांतिवादी साम्राज्य कायम रहा तथा साम्राज्यिक भेलजोल बना रहा। क्या इतिहासमें अन्य कोई ऐसा उदाहरण खोजनेपर मिल सकता है, जहाँ केवल एक व्यक्तिके बलिदान द्वारा इतना भारी परिवर्तन सम्भव हुआ हो?

वि हं गा व लो क न

यदि अब भी आपको भारतके अद्वितीय रूपमें कुछ सदेह रह गया हो तो आपकी ऐसी धारणाको मिटानेके लिये अन्य अनेक “ निर्णयात्मक तथ्य ” दिखलाये जा सकते हैं ।

तथ्य ६ - जिन लोगोंने अंग्रेजोंके साथ सत्ता हस्तांतरण विषयक शान्तिवार्ता की, वे संदनके आश्रित बने रहनेके लिये तैयार न थे । उन्होंने क्रमिक रूपसे अपनी निराश्रयता अधिकाधिक प्रदर्शित की । भारत राष्ट्रमेड़लसे सम्बंधित रहनेके उपरांत भी अपनी परराष्ट्रीय नीतिके अंतर्गत राष्ट्रोंकी पारस्परिक शान्तिका समर्थन करता है, यह स्थिति साम्राज्यवादो हितोंके पूर्णतया विपरीत है ।

तथ्य १० - गृह नीतिके अंदर सरकारने सौमित्र मताधिकार और गतकालीन सुविधान लागू करके अपने आपको सन्तुष्ट नहीं किया । एक अधिक नवीन एवं लोकतांत्रिक स्वरूपकी रचना की गई है । एक बगकी अपेक्षा दूसरे वर्गके पास अधिक धन और सुविधा उपलब्ध होनेकी अवस्थामें जितने निष्पक्ष और स्वतंत्र सामान्य चुनाव सम्भव हैं वैसे ही भारतमें भी हुए । और इनके परचात पूँजीजीवियोंने मजदूरोंकी पुकार पर ध्यान देकर दस वर्षके अंदर समाजवाद प्राप्त करनेका वचन दिया । जनताको उन्होंने यही विश्वास दिखाया था ।

अभी तक हमने अंतिम तथ्यके विषयमें तो कुछ सुना ही नहीं है जो समय बीतनेके साथ साथ अधिक शक्तिशाली होना जायगा और इनमें कोई सदेह नहीं कि लोगोंके अंदर यही दृष्टिकोण अपनावनेकी प्रवृत्ति प्रमुख रूपमें विद्यमान है । वे घटनाओंमें से ऐसे ही तथ्य खोज निकालते हैं, और उनमें से भी केवल उन्हीं पर ध्यान देते हैं जिनमें उन्हें सतोष होता है तथा अन्योकी अपेक्षा कर देते हैं । वे सरकार और जनताकी प्रगतिको एक निश्चित रूपमें प्रस्तुत करते हैं तथा उन अनेक परस्पर विरोधी तत्वोंकी अपेक्षा कर देते हैं, जिनसे मिला कर उस निश्चित रूपकी रचना हुई है । वे यह अनुमान कर लेते हैं कि घटनायें एकात्मिक रूपमें लीह मुहक सीमाओंके अंदर बन सकती हैं और दुराग्रहपूर्वक इस बातको अस्वीकार कर देते हैं कि दिल्लीके विचारों पर सुदूरवर्ती प्रदेशोंकी प्रगतिका भी कुछ असर पड़ा होगा ।

भारतीय घटनाओं की विशिष्टता

इस बातसे तो कोई व्यक्ति अस्वीकार नहीं कर सकता कि भारतवासियोंकी और भारतीय घटनाओंकी अपनी एक खास विशिष्टता रही है और रहेगी।

इस विशिष्टताका उद्भव केवल भारतीय रूचि नामक भावात्मक तत्त्वसे ही नहीं बल्कि उस बेगरील सकलमाने भी होता है जिसे आज समस्त समार देख रहा है। वस्तुतः हम नवीन आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक स्तरोंके प्रति अधिकाधिक जागरूक होते जा रहे हैं, जिसका हमें पहले न तो अनुभव ही होता था और न हमारी धारणा ही थी। पर्याप्त विलम्बके पश्चात् औद्योगिक क्रांति हमारे और अग्रसर हो रही है। भारतीय रूचि हमने प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती।

फिर भी समस्त बाहरी प्रभावोंका भारतके अंदर प्रविष्ट होते समय थोड़ा-बहुत परिवर्तित हो जाना आवश्यक है। इसके अंदर कोई अद्वितीयता नहीं है। सभी लोगोका यह सामान्य अनुभव रहा है।

जीवनके सभी स्पर्शोंमें सुधार और समन्वयका प्रभाव देखनेको मिलता है। भारतवासी निरक्ष और विरक्त थे। वे यह भी जानते थे कि उन्हें ऐसे विदेशी शासकोंका सामना करना पड़ रहा है, जो अपने देशके उदार दबावके प्रति सचेत थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलनके नेतृत्व द्वारा संघर्षके पृथक मार्ग खोजनेके लिये यह तथ्य ही पर्याप्त औचित्य प्रस्तुत करते हैं। इस संघर्षका स्वरूप पृथक हो सकता था लेकिन जिन सचेतोंने भारतवासियोंको ऐसा करनेके लिये प्रेरित किया, वे लगभग हमेशा ही थे जैसे वर्तमान युगकी सभी क्रांतिकारी कार्यवाहियोंके प्रेरक हैं।

गांधीजीकी अहिंसक पीढ़ी पासीस्ट जर्मनीके सैनिकोंके सामने किस काममें आती। जिन विमोने उनके विरुद्ध हलकी-सी भी आवाज उठाई थी, उसे उन्होंने नेस्तनाबूद कर डाला था। यूएनके काराशिविरो (कमेन्टेशन कैप्स) में लाखों व्यक्तियोंको मौतके घाट उतारना पड़ा। यह सोचना कि वे सत्य और ज्ञानकी अपील के सामने मुक जाएंगे, सिर्फ उपहासास्पद कल्पना है।

स्वतंत्रता संघर्ष तथा उसके पश्चात् प्रभावोंके अनेकानेक स्वरूपोंमें ऐसे अनेक उदाहरण खोजे जा सकते हैं। संघर्षोन्मुख स्वदेशाभिमानी दृष्टिकोणके लिये यह आवश्यक संशोधन है जो आजकल इस देश तथा इस देशवासियोंके लिये सुझाई जानेवाली अनेक विषय और कभी कभी उपहासास्पद सिद्धान्तोंकी नींव प्रस्तुत करते हैं।

विहंगावलोकन

अन्य राष्ट्रोंके समान ही भारतको भी आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा। वेद, रामायण, महाभारत, बुद्ध, अशोक, अक्षर और गांधी, संघर्षनामादी सन्ध्यामी और रहस्यवादियोंकी भूमि भी आणविक युगकी कठिन वास्तविकताके सामने इतनी ही अधोमुख हैं, जितना शताब्दियोंकी गुलामीके उपरान्त नव जागरण प्राप्त करनेवाला चीन है।

जो लोग हमें 'दान' प्राचीन घर्मे पुस्तकों एवं भोजनों पर आलेखित ग्रंथोंकी ओर प्रत्यावर्तित करना चाहते हैं, उन्हें पुनः विचार करना पड़ेगा। ईर, बुद्ध, जोरास्टर, ईसा, मुहम्मद, कन्फ्यूशियस, त्याओ-सी आदि अपने समयमें एशियाके शक्तिशाली महापुरुष थे। किन्तु वर्तमान युग भूतकालीन सर्वरोगाग्र औरविधेके सहारे जीवित नहीं रह सकता। उसे उन समस्याओंका उत्तर खोजना पड़ेगा जिनका सामना उनके पूर्वजोंने कभी न किया हो।

इसी प्रकार हमें उन वातका भी उत्तर खोजना पड़ेगा जिसे भारतका "एक बड़ा प्रगल्भावक चिन्ह" बताया जाता है। उन नवविकसित भारतका जो मानव जीवनकी कहानीका रूप निर्धारित करनेवाली प्रमुख शक्तियोंमें से एक है। जब तक यह 'प्रगल्भावक चिन्ह' रहता है तब तक निर्णयात्मक बीसवीं शताब्दीके उत्तरार्द्ध का रूप निर्धारित करनेवाली उसकी कार्यक्षमताके मोटे तौर पर अनुमान लगाना भी कठिन है।

बहुतुन भारतकी स्थिति अधिकधिक विनम्र होनी जानी है, क्योंकि जहाँ योजनायें और कुछ रूपोंमें उनके परिणाम भी प्रभावोत्पादक हैं, वहाँ लोगोंकी परिस्थिति योही ही परिवर्तित हुई है। भूमिपर जोतनेवालोंका अधिकार नहीं है। एक छोटेमे व्यापारी वर्ग द्वारा भारी लाभ उठाये जाते हैं। विदेशी विनियोजन भी बढेष्ट है और अर्थव्यवस्थामें प्रविष्ट होते जा रहे हैं। मामूली विरोध प्रदर्शनको कुचलनेके लिये अभी तक गोलियों बरसाई जाती हैं। भयवार और सिंघारशका बाजार गर्म है। परंतु जनता सामान्यतया कांग्रेसपाटी सरकारका समर्थन करती है। इसी कारण कांग्रेसको पूर्ण आत्मविश्वास है कि वह १९५७ में होनेवाले आम चुनावमें विजयी होगी।

वर्तमान निर्णायक संधिकालमें इस परिस्थितिको समझना, उसमें सक्रियता उत्पन्न करनेवाली और उसका निर्देशन करनेवाली मुख्य प्रवृत्तियोंको देखना, देशके राजनैतिक जीवनके लिये अत्यंत महत्वपूर्ण है ।

किमी विशेष व्यक्तिवशः उन्मूलक स्थिति पर किन्हीं नीतियोंको आधारित बतलाना, समस्त उपलब्धियोंको अस्वीकार करके रुढ़िगत रूपमें वितर्क करना, भारतकी नवोदित परिस्थितियोंमें दूसरे देशोंके अनुभवको ध्वस्त लागू करना आदि बालोंमा परिणाम राष्ट्रीय प्रगतिके आंदोलनको निष्प्रभाव करना है और फलस्वरूप वह इस सकटपूर्ण समयमें प्रतिरक्षा करनेमें असमर्थ और नेतृत्वहीन हो जायगा ।

भारतके वर्तमान स्वरूपको देखते हुए ऐसा सकट बिना किमी चेतावनीके अकस्मात् प्रकट हो सकता है और उसमें देशकी शांतिप्रिय विचित्र जनताके श्रेष्ठों पर प्रक्षेपित होनेवाली अनेक आशयें भी हूव सकती हैं ।

अगस्त १९४६

भूत काल

सत्ता हस्तान्तरण

गिरि, समुद्र, धरती, नाचै, लोक नाचै हँस रोह ।

—कवीर

ज्योतिषियोंसे भविष्य पूछनेकी आदत हम भारतवासियोंकी पूर्वजोंकी देन है । भविष्यमें क्या होगा, यह जाननेकी जिज्ञासा राजनैतिक क्षेत्रमें भी दिखाई पड़ती है ।

हमारे आधुनिक इतिहासमें सी-भी वर्षोंमें कालांतर हुआ है, विद्वत्पूर्वक आज भी ऐसा कहनेवाले कम नहीं हैं । १७५७ में प्लासीकी लड़ाई, इसके बाद १८५७ में विदेशी सत्ताके विरुद्ध पहली क्रांति हुई और सी वर्षों बाद भारत स्वतन्त्र होगा — अर्थात् १९५७ में !

परन्तु इन भविष्य वक्ताओंकी गणनामें कहीं कुछ गलती जरूर हो गई । हमें दस साल पहले ही १९४७ में स्वतंत्रता मिल गई । अतः ये १० वर्ष हमारे इतिहासमें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं । इस अवधिकी घटनाओंका दूरगामी प्रभाव हुआ ।

सन् १९४७ के पहलेका काल बहुत ही उथल-पुथलका था । सत्ताके अन्त्यतः प्रबल माघाज्यवादको हमने आन्दोलन दिया था । परन्तु हमारा आन्दोलन अहिंसात्मक था, नैतिक मामल्य और सत्याग्रहका था । हमारे आरस बिये हुए सत्याग्रहका जोर धीरे-धीरे बढ़ता गया, उसमें किसानोंकी जागृति थी, मजदूरोंका आन्दोलन था । उपवास — 'भूख हड़ताल' — जेल जाना — जेलमें हूटना आदि जारी था । उस अभिनव 'शस्त्र' का परिणाम व्यापक और चिरकालीन होनेवाला था । उस समय हमारी निर्भय भावना प्रकट हुई । शौर्यको विश्वास मिला । उसी कालमें समझौतावादको हमने स्वीकार किया, पीछे हटे और गड़बड़ मचानेके करणीभूत हुए । इस गड़बड़ीमें दो बातें बिलकुल स्पष्ट हो गईं ।

पहली : अधिजोके अत्याचारसे जनताका निरचय रह हुआ ; विदेशी सत्ताका मुकाबला करनेके लिए — स्वराज्य प्राप्त करनेके लिए, लाखों लोग आन्दोलनमें शामिल हुए ।

“इन्कलाब जिन्दा बाद!”

दूसरी : स्वाधीनता की घोषणा अधिक स्पष्ट, अधिक तीव्र हुई। केवल अंग्रेजों को हटा देने ने ही काम चलने वाला नहीं, यह बात भी लोगों की समझ में आ गई। उन्होंने अधिक-भारताविक स्वतंत्रता की माँग की। इसके बिना राजनैतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं। राष्ट्रीय समाने सबका मिलान हुआ था—स्वास्थ्य प्राप्त करने वाले—उमर के लिए सुझावला करने वाले—मर्मा वीर एक छत्रछाया में इकट्ठे हुए—राष्ट्रीय मन्त्रालयों के नीचे आये—और ‘इन्कलाब जिन्दाबाद’ में वातावरण गूँज उठा।

स्वाधीनता आन्दोलन के समय ये दोनों ही बातें विलकुल स्वाभाविक थीं। परन्तु साम्राज्यवाद को समझने में पहले लग रहे थे। भारत में तो उसे बहुत बड़ा धक्का लगा। इस समय साम्राज्यवादियों के मुख-स्वप्न—नये सुनामी नवीनता; आकर्षक लग रही थी। विदेशी साम्राज्यवाद के बदले स्थानीय पूँजीवाद की स्थापना करके चलने वाला न था। आकाश में गिरकर खड़पर टँगने के सनान एक के चंगुल में निश्चित रूप दूसरे के बंदी होने में पड़ने की ताकत न थी। हाँ, यह अवसर था कि यह चेतना हममें सनान न थी। कुछ लोगों में तो स्पष्ट थी, पर कुछ में आधूनी थी। किन्तु हम चेतना से एक लाभ अवश्य हुआ, कि हमारा आन्दोलन सुन्वसित न हुआ। स्थानीय पूँजीपतियों के हाथ की कटकुली बनने में बालसे हम बच गये।

दूसरे महायुद्ध के समय हमारे इस आन्दोलन की हिमायत अच्छी तरह व्यक्त हुई। जर्मन-जापानी फौजें अनेक माहूम पड़ीं। यूरोप खंड लगभग तिन टुकड़ों में चीन और दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों पर जापानी सैनिकों ने अपनी जगहों पर हुक्मन बजाई। ब्रिटिश, फ्रेंच और डच साम्राज्यवादियों को अच्छा लगा नहीं। अमेरिकी ने युद्ध की तैयारी अधिक न हुई थी। फासिस्ट मन्त्रालयों ने दोहा पारा नाला की ओर बढ़ रही थी—बीटले तामेवाली रशियन सेना को बगल हटती हुई—और अफ़्रीकी सीमा पर जंगलों में छिपने।

ऐसे समय अवसरकारी नेताओं की अगुआई बन आई। हमारे देश में भी वही हाल होगा, ऐसा भय लग रहा था। परन्तु लोग अनुभव हो चुके थे, उन्होंने साम्राज्यवाद से किसी भी अवस्थाने समर्पण न करने का निश्चय लिया था।

सत्ता हस्तांतरण

राष्ट्रीय सभाका कहना था कि हमारी स्वराज्यकी माँग स्वीकार करें। ऐसा होनेपर ही हम फासिस्ट आक्रमणके विरुद्ध लड़ेंगे, राष्ट्रीय सभाका यह आग्रह था। पर अप्रेमजोंकी ओरसे कोई उत्तर आना सम्भव न था। फासिस्ट विजयी हुए तो समारकी हिन्दुस्तानकी-क्या परिस्थिति होगी, इनकी कल्पना दमरोंकी अपेक्षा पं. नेहरू-को अधिक थी, इसीलिए देशी और विदेशी प्रयत्न उन्होंने मिये। उनका यह प्रयत्न इसी उद्देश्यसे था कि कोई उपाय निश्चयना है क्या, देखना चाहिए।

परन्तु ब्रिटिश सरकारकी शक्ति ज्यों की त्यों रही। सर स्टैंफर्ड क्रिप्स जैसे प्रतिनिधियों से कहकर देखा, पर व्यर्थ। फासिस्ट विरोधी, साम्राज्यवादका विरोध करनेमें ऐसी विचित्र अवस्था शायद ही हुई हो। आन्दोलन रोमना असम्भव-भा था और उस आन्दोलनके कारण जापानी पीजको मराना दिखाकर बुलाने जैसा हुआ होता। बंगालकी सीमा पर वे जमकर बैठे ही थे।

‘भारत छोड़ो’ ऐसी घोषणा अवश्य हुई, परन्तु संगठित आन्दोलन आरम्भ नहीं हुआ। वैसा हुआ होता तो ब्रिटिश सेनाका यहाँ कहीं भी पता न लगता होता। वे अपनेमें ही उलझकर रह जाने और चालीस करोड़ जनताकी यह कानि सफल हुई होती। क्योंकि सहृदयपर चढ़ाई करनेके लिए सारी पीजें तैयार थी।

जापानी सेना बंगालमें प्रवेश करे यह कल्पना ही नेताजी सुभाषचन्द्र बोसकी आई. एन. ए. के कितने ही लोगोंकी अन्तर्गत लगी थी। आई. एन. ए. के पहले स्थापक मोहनमिह्र तो जेलमें थे, क्यों कि जापानियोंका आधिपत्य मानने में उन्होंने इन्कार कर दिया था। स्वयं नेताजीके मंत्रिमंडलमें भी यह उलझन उपस्थित हुई थी कि जापानियोंको भारतमें प्रवेश करने दिया जाय या नहीं।

यह एक कठिन निर्णय था। इंडियन नेशनल आर्मीने जापानियोंके साथ भारत-की स्वतंत्रता प्राप्तिके सपनेमें सहयोग प्राप्त करनेकी आशासे मेल किया था, लेकिन जापानियोंके भी अपने कुछ इरादे थे। लेन देनकी प्रक्रियाके अनुसार कुछ व्यवस्था की गई थी। इसका मूल्य तो इतिहास ही निर्धारित करेगा, पर जिन बातपर हमारा ध्यान जाना है, वह यह है कि इंडियन नेशनल आर्मीके सिपाहियोंमें फासिस्टविरोधी भावनाये बराबर मौजूद थीं—ऐसी भावनाएँ जिसकी प्रतिध्वनि ब्रिटिश शासन भारतमें गूँज रही थीं।

साध्यायवादी प्रचार चाहे कितना ही क्यों न हो, पर वह किसी अव्ययनशील विचारोंको यह मोचनेपर मजबूर नहीं कर सकता कि भारतवासी और उनके नेता जापानियोंका पक्ष लेना चाहते थे। भारत तो पूर्ण रूपसे फासिस्ट विरोधी था। क्या गांधीजीने जो ऊपरसे नीचे तक शांतिकारी थे, किसी अनेकितन पत्रकारसे भेंट करते समय नहीं कहा था कि “भारतकी अहिंसा अधिकमें अधिक शांतिक रूप प्रदर्श कर सकती है—अंग्रेजी फौजोंके मार्गमें किसी प्रकारकी स्वावट न डालना और जापानियोंकी सहायता तो किसी प्रकार भी नहीं;” इन कथनका स्पष्टीकरण करते हुए उन्होंने बतलाया था कि “याद रखो, अंग्रेजोंने अधिक में जापानियोंको देशके बाहर रखनेका इच्छुक हूँ। क्योंकि भारतमें अंग्रेजोंके हारनेका अर्थ केवल यही होगा कि भारत उनके हाथसे निकल जायगा, पर यदि जापान जीत गया, तो भारत सब कुछ खो देगा।” गांधीजी द्वारा सुनाया गया हुआ ‘स्वावट न डाल-नेकी नीति’ पर यह आधारित था।

इन विश्वासोंके उपरान्त भी यह बात अस्वीकार नहीं की जा सकती कि फासिस्ट विरोधी युद्ध अभियानोंने अंग्रेजोंने अनहयोग किया और कुछ अवसरोंपर स्वावट डालनेका प्रयत्न भी किया। ऐसे देश द्वारा इनके अनिरक्त और किसी प्रकारकी नीति अपनाया अनुचित होता, जो अपने आपको एक विचित्र परिस्थितिमें फँसा हुआ पा रहा था, क्यों कि वह स्वयं फासिस्ट विरोधी था, किन्तु फिर भी गुलामीके कारण युद्धके प्रयत्नोंमें भाग लेनेकी तैयार न था।

विस्मय चर्चित तथा उनके समान अन्य लोगोंको जो भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलनकी तत्कालीन नीतिके विषयमें हीन इरादे जोड़नेके इतने शीघ्र हैं, यह स्मरण रखना चाहिए कि उन्होंने स्पष्ट रूपमें फासिस्ट विरोधी नीति जवने अपनाई उसके पहलेमे ही भारतीय नेता इस व्यवस्थाके विरोधी सर्वांगमें सक्रिय महायत्ना दे रहे थे। आज भी स्पेनके प्रजातन्त्र राज्य और जापानी साम्राज्यवादमें सज्जन चीनके पक्षमें उनके प्रयत्नोंकी सूक्तियाँ बहुत स्पष्ट हैं।

भारतके फासिस्ट विरोधी स्वके बारेमें दो मत नहीं हो सकते। शायद इससे यह बात मनममें आ जाय कि इन सक्तयानमें अनहयोगका विरोध करनेवाली एक मात्र राजनैतिक शक्ति, भारतीय साम्यवादी पार्टी, सहृद और धृष्टाने व्याप्त इस

सत्ता हस्तांतरण

घातावरणमें मजदूरों, किसानों और विद्यार्थियोंका इतनी शीघ्रतासे एक दल कैसे बना सगी, खासकर उस समय जब कि पार्टीके नेता जल्ताकी युद्धविषयक नीतिको समझने और उसे व्यवहारिक रूप देनेमें इतनी भयंकर भूल कर रहे थे, कि उनका हर दशामें बदनाम होना निश्चित था।

साम्यवादी पार्टीको 'जनयुद्ध' विषयक नीतिके कारण उस समय अत्यन्त प्रभाव करनेमें भले ही सहायता मिली हो, पर यह बात भी इतनी ही सही है कि मार्क्सवादी इस नीतिकी सच्चाईके बारेमें चाहे जितनी दलीलें दें, पर इसके कारण यह पार्टी सामान्य राष्ट्रीय आन्दोलनोंमें वास्तवमें दूर पड़ गई। देशके अधिकतर लोगों द्वारा उनकी नीति देशविरुद्धी समझी गई, क्योंकि इसका अर्थ इतना तो अवश्य था कि सोवियट संघकी प्रतिक्रियाकी तुलनामें देशकी स्वतंत्रता कम महत्वपूर्ण थी।

आज तक भी इस 'जनयुद्ध' सन्धी नीतिका प्रभाव दिखाई पड़ता है। लेकिन भारत आम्नानीसे जूझ करने और भूलनेके लिए तैयार रहता है। वह समय सबसे अधिक कठिन था, जिसका सामना किसी भी राजनीतिक दलके नेताओंको करना पड़ा था। द्वितीय विरयुद्ध कालमें कृषिमियों, समाजवादियों, साम्यवादियों और महासभाइयोंने जो जो नीति अपनायी, उसके बारेमें किसी प्रकारका अंतिम निर्णय कर पाना बहुत सदेहासद है। उस समय बिकारपूर्ण विचारोंकी इतनी विचट्टी हो गई थी कि उसके बारेमें इस प्रकारका कोई निर्णय करना कठिन है।

फिर भी भारतवासियोंका ब्रिटिश साम्राज्यवादके विरुद्ध क्रोध शांत नहीं हुआ था। जैसे जैसे फासिज्म हार स्वीकार करनी गई, वह क्रोध भड़कना गया। जब आई. एन. ए. के अफमर्गोंवर अयेजेजों द्वारा अहंकारवश मुकदमा चलाया गया, तब एकाएक ही ये वीर बन गये। अभूतपूर्व सगठनके साथ विरोध प्रदर्शन होने लगे। ऊपर और पीछामें जर्जरित वृद्ध बकरील और राजनीतिज्ञ भी भूलाभाई देसाईको लोगों ने जब अग्ररिचिन लोगोंकी पैरवी करते देखा, तो प्रत्यक्ष विचारधाराके भारतीयोंमें जोश आ गया। इस मामूहिक विरोधको कुचलनेकी शक्ति दमन चक्रमें भी न थी।

इसके परचातु भारतीय नौसेनाका विद्रोह हुआ। 'चावल भत्ती' बहे जाने वाले सिपाहियोंपर अब विश्वास नहीं किया जा सकता था। क्योंकि निर्मित साम्राज्य-

राजनैतिक दाव-पेच

वादी दमनका पीलादी टाँचा सब चटख उठ्य था। सुदूर इंग्लैंडमें बैठे साम्राज्य निर्माताओंमें इस खतराकी रोशनीको देख लिया था।

१८ फरवरी १९४६ को नौ सैनिकोंके विद्रोहका श्री गणेश हुआ और १९ फरवरीको गृहमंत्रीने ब्रिटिश लोकसभामें भारतमें सत्ता हस्तान्तरण विषयक परामर्श देनेके लिए एक केबिनेट मिशन भेजनेका निर्णय सुनाया। यह निर्णय तथा इसके उपरान्त जो कुछ हुआ, उसे स्वेच्छा से हस्तान्तरणकी आश्चर्यजनक ऐतिहासिक घटना कहा जाता है। पर सचार्थपर इस तरह पढ़ी नहीं जाना जा सकता।

नैमित्तिक विद्रोहके समय कहा जा सकता है कि भारतीय सैन्यशाक्ति, विभाजन और फूटपर विजयी हो गई थी, ऐसी विजय जिसका प्रभाव किसी हद तक इस विद्रोहके दर्शकोंपर पड़ा था। समुद्री बेड़ेके जहाजोंपर सुनियन जेजके स्थान पर जो गड्डे लहरा उठे थे, वह थे काँधेसी, मुस्लिमलोगों और साम्यवादी। सबके जिम नारेमें गूंज उठी थीं, वह केवल एक ही था कि 'एक हो।' इस विद्रोहकी सभी जगह बढने हुए असतोष (काश्मीर-बंगाल तथा दक्षिणके) से बल मिला।

यह सत्य है कि नैमित्तिक विद्रोहके चरम क्षणोंमें भी बड़े-बड़े दलोंके राजनैतिक नेताओंमें विरोधी भावनाएँ बा, पर लोगोंके कानिपूर्ण उन्माहके सहारे विभाजन और फूटकी भावनाओंपर विजय प्राप्त करनेकी संभावना मौजूद थी। नेहरूजीने उसे देखा था। उनकी दम्बदमी दौड़ते यह अंदाज लगाता था कि वे इस प्रकारके विद्रोहका नेतृत्व ग्रहण कर लेंगे। पर गांधीजी और कलभभाई पटेलकी सावधानीका प्रभाव पड़ा। हिंसात्मक उथल-पुथल रुची पिशाचके सामने निहित स्वार्थ पीछे हटने लगे थे। विद्रोहका चरमहिन्दु बीन गया। अब भाग्यवासी गैरांग महाप्रभुओंने सत्ता प्राप्त करनेके प्रसिद्ध राजनैतिक दाव-पेच और अक्सर वादितामें पुनः उलझ पड़े। यह ऐसा वातावरण था, जहाँ श्री जिन्ना और उनकी मुस्लिमलीग एक लाभदायक सौदा पटवनेकी आशा कर सकते थे।

मरणायें होने लगीं। इसी समय केबिनेट मिशन आ पहुँचा। भारतके राजनैतिक दल जो विद्रोही जनताके दबावके कारण संगठित होनेपर बाध्य किए जा सकते थे, अब पुनः आपसमें लड़नेके पुराने दाव-पेचोंमें उलझ पड़े। केबिनेट मिशनके

सत्ता हस्तांतरण

आगमनके फलस्वरूप चरमोत्कर्ष प्राप्त इन तथ्यावहित वातावरणोंका उद्देश्य एक ऐसी अव्यवस्था उत्पन्न करना था, जो भारतके विभाजनके लिये अत्यन्त आवश्यक थी।

दो राज्य प्रगट हुए। उनमें से एक की उत्पत्ति कारण मुसलमानों द्वारा हिन्दू शासनका ढर था। यह साम्राज्यवादकी एक अनात्मविह्न प्रवचना थी, जिसका उद्देश्य नई चालोंके द्वारा अश्वनी शक्ति और प्रभावको यहाँ कायम रखना था। विभाजित देशकी सीमाओंसे उसके बाद होनेवाले साम्प्रदायिक टंगोमि हुए रक्तपात से पवित्र किया गया। नवनिर्मित सीमाओंके दोनों ओर लाखों व्यक्ति अपने पूर्वजोंकी भूमिमें उलाह पड़े गये।

इन विषयमें उनको कोई भी सहायता न कर सकता था, क्योंकि सत्ताहस्तांतरण कालमें कानून और शांति कायम रखनेके लिए लार्ड माउन्टेडन द्वारा जो सीमातयोजना बनाई गई थी, उनमें केवल पञ्जाबी सैनिक रये गये थे—भारतीय फौजोंके वही दस्ते जिनके इस साम्प्रदायिक रक्तपातसे प्रभावित होनेकी सभ्य अधिक सम्भावना थी।

सीमातयोजनाके इस परिणामका दोष लार्ड माउन्टेडनके मित्र मदन स्वामि अधिक ही है, किंतु इस कटुसत्यमें तो इन्कार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस, मुस्लिमलीग या साम्प्रदायी पार्टीमें से किसीने भी फौजोंके इस पञ्जाबी रूपका कोई विरोध नहीं किया था। यह बताना कठिन है कि यह कैसे हो गया। किसी दृढ़ तक इसका कारण मुख्य राजनैतिक दलोंका अग्रजोंपर विश्वास था।

द्वान्तवर्षमें इस प्रकारकी साम्राज्यवादी चालपर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि किसीको विभाजनके परिणामस्वरूप इतनी अधिक जनसङ्ख्याके स्थानान्तरणकी या सामूहिक निष्क्रमणकी कल्पना नहीं थी। यदि इस सम्भावना पर विचार किया गया होता, तो इसमें संदेह नहीं कि इस रक्तपातको रोकनेके लिए पर्याप्त कदम उठये जाते।

इस भोषण दृश्यके बारेमें अब कहा जाता है—“शान्तिपूर्ण हस्तांतरण” “ऐच्छिक पलायन” “राजनैतिक नेतृत्वका एक महान कार्य।” आज भारतवासी

भविष्य की ओर प्रथम चरण

उनके दूसरे ही रूपने परिचित हैं। पर इस प्रकारके कोष और अभिचरि लभ्यो, हिमा और धृष्टाके बीचमे होकर स्वतंत्र भारतने भविष्यकी ओर अपने प्रथम चरण बहाये।

स्वतन्त्रताके समर्पितके परिणाम बलराश जाना है कि सत्ताहस्तांतरणके द्वारा एटली, माउंटबेटन, चर्चिल और ईडनकी विचारधाराओंवाले व्यक्तियोंने इस सामूहिक जागरणको शान करनेके साथ ही साथ ब्रिटिश स्वायत्तके हितमें अपनी नष्टबध्नी स्थिति कायम रखनेकी आशा की थी, परन्तु कॉमिन्स पार्टीके नेताओंने राजनीतिक शनरजक खेल यथेष्ट बुद्धिमानांमे खेलना शुरू कर दिया।

सीमान्तके उदभवोंके उपरान भी समस्त भारतमें विश्वासपूर्ण स्वतन्त्रता-भावना दीप्त पड़ती थी। लोग विभाजनसे असंतुष्ट थे, पर उन्हें दृढ़ विश्वास था कि अब वे अपनी इच्छानुसार कार्य करनेके लिए स्वतंत्र हैं। उनमें अब उस निर्णयकी मूर्खताओंको तोड़नेकी शक्ति थी, जिसके द्वारा देशका शासन भारतवासियोंको सौंपा गया था—वे अन्त्य मूर्खतायें जो ब्रिटिश पूँजीके रूपमें देशके आर्थिक व्यवस्था पर नियंत्रण किए हुए थीं।

दशमल भारत और सत्ताकी परिस्थितियोंने एक प्रकारका परिवर्तन हो चुका था। चालीस करोड़ व्यक्तियोंने साम्राज्यवादके उन अवशेषों तथा विश्वके पूँजीवादी बाजारोंने पीछा छुड़ानेके लिए पहली बार कदम बहाये थे, जो अब तक एशिया तथा आफ्रिकावासियोंके धन और प्रयत्नोंका लाभ उठानेके लिए मगझते रहे।

भागत की कन्वुनिस्टपार्टी जो इस साम्प्रदायिक हत्याकांडके निरुद्ध नगरोंके दंगोंमे मुक्त करनेके लिए धमिक्का संगठन कर रही थी, इन परिवर्तनोंका सही मूल्यांकन करनेमें असमर्थ रही। तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी श्री पी सी जोशी जिन्होंने इस परिवर्तनको देखा था और जो अपनी पार्टीके कार्यकर्ताओंको इस विचारधारामे अवगत करानेके लिए निरंतर सतर्क कर रहे थे, इस बातपर उनका विश्वास टपक न कर सके।

श्री बी टी रणदिवेके नेतृत्वमे एक नये अद्विष्ट निरुद्धने सत्ताहस्तांतरणमे साम्राज्यवादको प्राप्त होनेवाले लाभोंको बचा-बचाकर तथा सत्ताकी परिवर्तनशील परिस्थितिमे आपनिवेशिक पूँजीपति वर्गद्वारा लाभ उठानेकी शक्तिको घटाकर समझा, कांग्रेसी नेताओंके एक बड़े भाग और जनताकी साम्राज्यविरोधी भावनाओंका

स चा ह स्ता न्त र ए

नैतन्यपूर्ण गलन अर्थ लगाया। उन्होंने स्वयं साम्राज्यवादी शक्तियोंमें विद्यमान समस्याओंके परिणामोंकी ओरमें ओंखें फेर लीं और अन्तमें यह अमन्य सिद्धान्त बनानेकी भूल की कि किमी प्रकारका कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस फिरकेने इस प्रकारकी दलीलोके सहारे उपरोक्त विचारधारामें विरोध करना शुरू कर दिया, जिसे 'जोशी रिफार्मिज्म' कहते हैं। मार्कसीवादी विचारधारा इस प्रकारकी योजनाओंके विस्तारगामे बौद्धता उठी, जो आगे चलकर निस्वभरमें प्रगतिशील आन्दोलनका एक तत्व बन गया।

इस समय बहुत कम लोगोंने इस बातको समझा कि इस प्रकारके विचार और व्यवहारका अर्थ प्रजातांत्रिक विचारोंको अनेकों वर्षों तक जजीरोंमें जकड़ना है - और यह प्रभाव इस कारण हुआ कि युद्धोत्तर कालमें इस प्रकारकी सजीर्ण और सर्वहीन विचारधाराका राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक सुधारकों द्वारा कभी टटकर मुक़ाबला नहीं किया गया।

दूसरे राज्योंने महान आशापूर्ण परिस्थिति भागी सफ़टोंमें निरी हुई थी। साम्यवादी-पार्टी जो इस अवस्थाको दूर करके लोगोंके सामने वास्तविक परिस्थिति रखनेमें समर्थ थी, तड़कता रही थी और इस स्वाधीनता आन्दोलनके नाभोंको संयुक्त करनेमें अग्रगण्य थी और यह बात उस समय थी, जब कि साम्राज्यवाद अपने मौजूदा हर प्रकारके राजनैतिक तथा आर्थिक साधनों द्वारा भारत एवं पाकिस्तानके नये राज्योंकी सहानुभूति पानेके लिए सतत खुशामद कर रहा था।

भारतकी साम्यवादीपार्टी जिनने गलतियोंके बावजूद भी लोगोंकी विचारधारा बदलने, सामुदायिक संस्थाएँ बनाने, संघर्षका नेतृत्व करने तथा जनता द्वारा शक्ति प्राप्त करनेके लिए कार्यक्रम बनानेमें इतना अधिक कार्य किया था, इस परिस्थितिपर कबू पानेके समर्थ भी नहीं आ सरी थी। उनकी पुकार सुनी - अन्तमुनी कर दी गई और कभी-कभी स्वयं पार्टीके कार्यकर्ता भी उसे न समझ सके।

ऐसी शून्य अवस्थामें कम्युनिस्ट पार्टीने प्रशासनका भार संभाला। मायदायिक दलोंने समस्त देशको हिला डाला था। सीमाना पार करनेके लिए लाखों व्यक्ति चल रहे थे। कानून और शांतिके संपूर्ण मानकोंके पूर्णरूपमें नष्ट होनेका भय उपस्थित हो गया था। यह ऐसी विप्लव परिस्थिति थी, जिनके कारण बहादुरमें बहादुर व्यक्ति भी हार

चि क ट प रि स्थि ति

मान जाता ! यह वास्तवमें वही परिस्थिति थी, जिसे सत्ताहस्तान्तरणके नामपर साम्राज्यवादियोंने बनानेका विचार किया था और एक ऐसा पदार्थ था, जिसके पोछे बैठकर ब्रिटेन अपने घनी व्यापारिक सस्थानों तथा अपने भारतीय हिंदू राजनीतिज्ञोंकी सहायतासे आर्थिक एवं राजनैतिक निर्णयान्तरक प्रभाव जारी रख सकता था ।

इसमें बढ़ो और कोई गलती नहीं हो सकती थी । ब्रिटेनने राष्ट्रीय शक्तियोंका नेतृत्व करनेवाले भारतीय पूँजीपतियोंके नये दृष्टिकोणका कोई अनुमान नहीं लगाया था, जिसका प्रतिनिधित्व कांग्रेसपाटी कर रही थी ।

एकीकरण का आरंभ

क्या योद्धाओंका रक्त और माताओंके आसू पृथ्वीपर गिरकर भूमिमें मिल जायेंगे ? क्या उनसे स्वर्ग विजित नहीं हो सकेगा ?

—रवीन्द्रनाथ ठाकूर

लगभग दो सौ वर्षोंतक एक विदेशी सत्ताने भारतके करोड़ों व्यक्तियोंपर एक दलके विरुद्ध दूसरेको खड़ा करके शासन किया था। इस नीतिको थोड़े शब्दोंमें इस तरह कह सकते हैं कि “लड़ानो और राज्य करो।” अखिल भारतीय स्तरपर हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्यका लाभ उठाया गया। जब इस खिचावमें किसी प्रसारकी ढील पड़ती दीखती तो गुजरातियोंके विरुद्ध मराठों, तमिलोंके विरुद्ध तेलगुओं और बंगालियोंके विरुद्ध बिहारियों आदिको खड़ा करके यह बात हमेशाके लिए संभव बनाई गई। देशके भाषिक-मातृवर्तिक क्षेत्र इस प्रकार परस्पर जोड़ दिये गये थे, जिससे इस प्रकारकी राजनैतिक चालें चलाना हमेशा संभव बना रहे।

यह सच है कि देशकी प्रशासनिक व्यवस्थामें इस प्रकारकी एकता निर्मित की गई थी, जिसमें जनतापर रोक रह सके तथा देशकी संपत्तिकी सतत लूटमें सुविधा बनी रहे। पर इस एकताकी रक्षा केवल ब्रिटिश हितोंके प्रसारके लिए होती थी। इस कारण जिन समय इस एकतामें खतरा दीखता, उसी समय ‘अल्प सङ्ख्यकोंके हित’ ‘हिन्दू राज्य’ ‘विभाजन’ और ‘बीरफाड़’ से संबंधित बात होने लगती। देशका विभाजन हो चुका था, लेकिन अब उससे बच एक अन्य भयंकर संकट सामने आया

स्वतन्त्रताके पूर्व भारतमें ५६० रियासतें थीं, जिनमें अधिकतर (लगभग ५५४) विभाजनके उपरान्त नवनिर्मित भारतमें अवस्थित थीं। क्षेत्र और साधनोंमें उनमें भारी अन्तर था।

हैदराबाद और काश्मीर जैसी कुछ रियासतें इटली और फ्रांसके बराबर (क्षेत्र-फलवाली) थी और कुछ विलासपुर जैसी—छोटी छोटी भी थीं, जिसका क्षेत्रफल

जीने-मरने का सवाल

५०० वर्गमीलसे कम तथा जनसंख्या एक लाखसे कुछ अधिक थी। यह सामनों द्वारा शासित भारत था, जिसके बारेमें अंग्रेजोंने एक बार स्वतंत्र भारतीय सीमाओं-के बाहर एक पृथक् फेडरेशन बनानेका विचार किया था।

पर अब वह भारतके अंग थे। उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया गया था। लेकिन ब्रिटिश राज्यके पलायनके पश्चात् सार्वभौमिकताकी समाप्तिके साथ-साथ इस क्षेत्रमें एक सफ्टपूर्ण दरार बन गई थी। ये रियासतें देशके लगभग छह भागोंमें फैली हुई थीं, जिसका क्षेत्रफल करीबन १,००,००० वर्ग मील और जन-संख्या आठ करोड़ मनुष्य लाख थी। (इन संख्यामें जम्मू और कश्मीर शामिल नहीं है।)

यहाँके राजा भारतके अंग थे, पर व्यावहारिक रूपमें वे निरक्षर थे। उनके लिए तथा विशेष रूपसे बड़ा रियासतोंके लिए अंग्रेजोंने इंग्लिश के पास सत्ता पहुँचानेके कारण भारी चुकट उपस्थित हो गया। उनके अस्तित्वका विरोध भारतके राष्ट्रीय आन्दोलनों द्वारा हमेशा किया गया था। उन्हें 'काल-व्यतिक्रम' बनाना गया था। यह एक कठिन परिस्थिति थी।

भारतके मूल शासक किस प्रकार यन्त्रियोंके सामने इस प्रकार आत्मानीने मुक सकते थे, जिन्होंने चालाकीसे भारतीयोंका नेतृत्व ग्रहणकर लिया था? क्या उन्होंने १८५७ के महान् विद्रोहका नेतृत्व नहीं किया था? जब कि अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे, तब क्या जन्म और पूर्व पद्धतिके अनुसार भारतपर शासन करनेके लिए वे आदर्श शासक नहीं थे? उनके लिए वही एक अतिम अवसर था, जब कि वह इस अवस्थामें अपनी पुरानी सामन्ती सत्ता दधिया सकते थे।

यह उनके जीने और मरनेका सवाल था। और उन्हें यदि किसी प्रकारकी प्रेरणाकी जरूरत होनी तो पाकिस्तानका उदाहरण उनके सामने था। वहाँ सामनों द्वारा शासित मुस्लिमलोगने एक राज्यको पूँजीपति हिन्दुओंके निर्वरणमें डूब निया था। यह सही है कि पाकिस्ताना मुसलमानोंके सामने तबोंने पूँजीपतियोंके एक छोटे वर्गके साथ इस अधिकारकी बाँट रखा था, फिर भी नये राज्यकी प्रमुख शक्ति तो वही थे। भारतीय सामन्त इसी प्रकारका आचरण क्यों न करें?

एकीकरण का आरंभ

१९४७ में भारतीय एकताके ध्वावशेषोंपर शक्ति संपन्न राजाओंके नेतृत्वमें निरारा सामंती तत्व दृष्ट पड़े। हमेशा ब्रिटिश साम्राज्यवादके यही सगसे विरवाभपात्र सहायक थे। अमलमें वह इसी प्रकारके सरक्षणपर आभित थे। अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके भविष्यके लिए सकृद उपस्थित करनेवाली इस उथल-पुथलमें वे पारस्परिक एकता प्राप्त करना चाहते थे। उनके पास धन था, व्यक्तिगत सेनायें थीं और उन्हें आशा थी कि जनताकी दृष्टिमें अब भी उनके लिए स्थान है।

राजाओं तथा बड़े-बड़े जमीन्दारोंने निःसर्कोच हिन्दू महामभा, राष्ट्रीय स्वयमेवक सघ, जनसघ जमी सस्थाओंके साम्प्रदायिक आन्दोलनोंमें सहानुभूति प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। इन दलोंको सगमें अधिक आश्रय विशेषरूपमें पञ्जाबमें छोटे व्यापारियों और कारीगरोंने मिला, जिन्होंने नई नीमाओंमें सक्रमग करनेकी प्रक्रियामें अपना सघ बुद्ध खो दिया था।

राजाओं और जमीन्दारोंको भीघ्र ही यह विरवाभ हो गया, कि वे इस कटुताका लाभ उद्य सकते हैं और इस कारण विभाजित भागोंके इस मध्यम वर्गीय भागपर आभित साम्प्रदायिक सस्थाओंकी सक्रिय सहायता देना शुरू कर दिया, इन कार्य-वाहियोंके लिये कारण आमान थे।

क्या अभी मुसलमान पचम दलीय (फिफथ कालमिस्ट) नहीं थे? क्या उन सघने पाकिस्तान निर्माणके पक्षमें मत नहीं दिया था? इस बातको आमनीमें भुना दिया गया था कि मुस्लिमलीगने पाकिस्तान निर्माणके पक्षमें मत उन थोड़े-से मुसलमान मनशलाओंमें प्राप्त किये थे, जिनकी १९३० के लगभग अध्रेंजोंने मनाधिकार दिया था।

राजनैतिक कारणोंमें भी राजाओं और जमीन्दारोंने हिन्दू साम्प्रदायिक सस्थाओंको सहानता देनेके लिए अनेक कारण खोज निकाले। वे लोग अधिकतर सपत्तिके वर्तमान अधिकारोंको बनाये रखनेके पक्षमें थे। वे 'ईश्वर रहित भौतिकवाद' के कट्टर विरोधी थे। उनकी कार्यवाहियोंमें शक्तिशाली काथेम पार्टी कमजोर पड़ जायगी और ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जायगी, जिनमें सामंतवर्ग अपनी जड़ जमा सकेगा। सभी कारणोंसे इस प्रकारका समझौता तत्कममल और व्यभदायक दोख रहा था।

सांप्रदायिकता के विरुद्ध अभियान

अगस्त १९४७ के परवान आनेवाले महीनोंकी बात सोचिये। पाकिस्तानके सामने (नवाब, जमीन्दार और इसी प्रकारके अन्य लोगोंने) हिन्दू जनताके कलेश्याममें सहायता और सहयोग दिया। यह बात विशेष रूपसे पंजाबमें हुई, जहाँ इस प्रकारके तत्व बहुत शक्तिशाली थे। एक भी परिवार न बच सका। बंगालमें भी जहाँ इनका रूप कुछ भिन्न था, यह सक्षमक रोग शीघ्र फैल गया, यद्यपि यहाँ वह इतना सक्षिप्त और बरार नहीं मालूम पड़ता था। देशकी मौमके दोनों ओर इस प्रकारके आक्रमण संचालित किये गये, जिनमें एक हत्याके परवान दूसरी हत्याएँ होनी रहीं, अब तक कि इस दृश्यने कलेश्यामका रूप न धारण कर लिया।

भारतीय क्षेत्र बहुत विस्तृत था। तीन या चार करोड़ मुसलमान रह गये थे। वे पाकिस्तान न जा सके, यद्यपि उनका यह विचार हो सकता था। पाकिस्तान कभी इतना विस्तृत नहीं हो सकता था कि उनमें वे समा सके। वे उसनेवाले कबूतरोंकी तरह थे।

इसी परिस्थितिके विरुद्ध विभाजित भारतके अधिष्ठार पैंनीपति एकता और धर्म निरपेक्षताकी रक्षामें लड़ने लगे। यह केवल एक सहानुभूति ही नहीं बरन् एक जहरत भी थी, क्योंकि नवविजित शक्तिको संचालित करनेके लिए इसके अनिरीक्त अन्य कोई मार्ग न था।

मुसलमान आगसम्बन्धोंकी सुरक्षा, बदलेकी भावनाकी प्रक्रियाकी रोकना, भारतमें बसनेवाले अनेक संप्रदायोंने विरवात और आशाका संचार — यही प्रमुख आवश्यकताएँ थीं। गांधीजीने अपना संपूर्ण साहस बढोरकर साम्प्रदायिकताके उग भयंकर दैत्यके विरुद्ध अभियान शुरू कर दिया, जो भारतीय स्वतन्त्रताके जन्मने ही उगे समस्तकर डालनेके लिए कृतसंकल्प था। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रोंका दौरा किया, जहाँ उन्होंने प्रेम और भ्रातृत्व भावनाका पाठ पढ़ाया। उन्होंने आत्मशुद्धिके लिए अनशनके द्वारा अपने निर्मल शरीरको कष्ट दिया। वे स्थिर बुद्धिने केन्द्र बन गये। यही उनका सर्वोत्तम कार्य था। साम्यवादी भी जो उनके राजनैतिक सिद्धान्तोंका इतना विरोध करते थे, यह मान गये कि धर्म निरपेक्षताकी रक्षाके लिए उनके इस प्रकारके साहसिक सघर्षके अभावमें स्वतन्त्रताकी रक्षाकी आशा कम थी।

ए की क र ए का आरंभ

परिस्थिति बदली, देशके अधिकारा भागोंमें शांति बनी रही। प्रभावित क्षेत्रोंमें साम्यवादियोंके साहसी दलोंने नागरिक समितियाँ बनाईं। जो क्षेत्र अधिक प्रभावित थे, वहाँ हिन्दुओंने मुसलमानोंकी रक्षा करना आरम्भ कर दिया। हत्यारे इस तरह अलग पड़ते गये और उनके सामनी तथा सामान्य पूँजीपति संरक्षक, अपना साहम खोने लगे। घृणा और सदेहकी भावनायें बनी हुई थीं, पर अब वे बाबूमें थीं।

इस प्रकार निराशा होकर साम्प्रदायिक लोग उस अकेले व्यक्तिना विरोध करनेके लिए उठ खड़े हुए, जिसने ऐसे समयमें भारतवासियोंकी माननीय आत्माका प्रतिनिधित्व किया था और जिसके बारेमें उनका विश्वास था कि वह उनके तथा उनकी सकलताके बीचमें बाधा है। इसलिए प्रार्थनाके लिए जाते समय उनकी हत्या गोली मारकर की गई। उनका बलिदान अतिशय प्रायश्चित था। शत्रु और मित्र सभी रो उठे। शांति जिसका उदय हो चुका था, अब निधित हो गई। पर भारतकी आत्माकी साम्प्रदायिकताके इस दैत्यने मुक्ति शिलाया अभी बाकी था।

इसके उपरान्त भी छिटपुट साम्प्रदायिक विद्रोह विरोध रूपसे पूर्वा बंगालके अनेक भागोंमें जारी रहे। पर यह अधिकतर पाकिस्तानी शासकों द्वारा दिये जाने-वाले जोशके फलस्वरूप होते थे, जिसका आसानीसे स्थानीयकरण हो जाता था। भारतमें रक्तपिपासा शांत हो चुकी थी। मुसलमानोंके बारेमें अनेक व्यक्तियोंको अब भी सन्देह था, पर वे अब उनकी मौजूदगी सह सकते थे। गांधीजी चले गये, पर उनकी आत्मा बनी रही, जिसने विद्यमान घृणा और कटुताको समाप्त करना जारी रखा।

प्रथम लक्ष्मरका सामना कर लिया गया, पर उसका भयानक रूप काश्मीर और जूनागढ़की रियासतोंके भविष्यमें सञ्चिन्त सङ्कटके समय युद्धकालीन महत्त्वकी थी साम्प्रदायिक दलोंके रूपमें, साथ ही साथ प्रगट हुआ। इन दोनों रियासतोंकी सीमाएँ और उनकी अपनी पृथक विशेषता थी।

जूनागढ़ जो प्रमुखरूपसे हिन्दू क्षेत्र था, एक मुसलमान नवाब शासकके अधीन था। काश्मीर जो प्रमुखरूपसे मुसलमान क्षेत्र था, एक हिन्दू महाराजाके अधीन था। धार्मिकरूपके अतिरिक्त सामनी साम्राज्यवादी बंधनोंने वहाँके शासकोंको पाकिस्तानका मुखापेक्षी बना दिया। जूनागढ़की समस्याका शीघ्र ही फैसला हो गया।

क या इ लियों के ह म ले

नवाबने पाकिस्तानके पक्षमें मत दिया। पर वहाँकी जनताने दूसरा ही निर्णय किया। उन्होंने देशभर अधिकार कर लिया और नवाब भागकर बरौची जा पहुँचा। पर काश्मीरकी समस्या अधिक उलझी हुई थी। वहाँ साम्राज्यवादी दलध स्वार्थ निहित था।

महाराजाने डालमशेल की और यह मालूम पड़ा कि यह विलम्ब जानबूझकर हो रहा है। यह कहा जाता था कि इस समय रियामन्तके प्रधानमंत्री श्री आर. मी. काक देशद्रोहीता पार्टी अदा कर रहे हैं। मुननेमें आया कि इस व्यक्तिने भोपालके नवाब और तत्कालीन राजनैतिक सचिव कनराव कोरफील्डसे मिलकर काश्मीरमें भारतमें सम्मिलित न करनेके लिए एक षडयंत्र बना लिया था। उस समय यह भी समाचार फैल रहे थे कि कुछ प्रभावशाली राजा सामन्ती भारतकी 'स्वतंत्रता' धोखिन करनेके लिए प्रयत्नशील हैं। मत्त बात तो एक दिन आ ही जायगी, पर घटनाओंके सामान्य सर्वेक्षणमें यह स्पष्ट हो ही जाता है कि इस प्रकारके कुछ प्रयत्न जागे थे, जिनमें अंग्रेजों द्वारा सहायता की जा रही थी। काश्मीर-संकटने इस षडयंत्रा भेद खोलनेमें सहायता की।

काश्मीरके महाराजाके लिए इस प्रकारके अनिश्चयता कोई खास कारण न था। सामान्यतया उनमें भारतमें सम्मिलित होनेकी आशाकी जल्ती थी - विशेष रूपसे इस कारण कि रियामन्तकी जनताके आन्दोलन, जिनमें सभी दल शामिल थे और जिसका नेतृत्व एक मुसलमान कर रहा था, इस बातके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि राज्यकी सीमाएँ भोग्नकी हो भाग बनें। फिर भी यह मालूम पड़ा कि काश्मीर पाकिस्तानको दिया जा रहा है।

महाराजाका अनिश्चय स्वयंसेवक बड़े जानेवाले पाकिस्तानी सेनाके दलों तथा सीमाप्रान्तके क्वाड्रिलियोंके आर्क्षस्मक हमलेमें सनाम हो गया। पाकिस्तानी सेनाके अंग्रेज सेनापतिशे इस आक्रमणके समयके बारेमें सूचना थी। बादमें पता चला कि उसने भारतीय सेनाके अंग्रेज सेनापतिशे भी इस बातकी पहलेमें खबर दे दी थी। तथापि भारत असावधान था, क्योंकि इस समय उसकी समस्त शक्ति साम्प्रदायिक दंगोंके शांत करनेमें लगी हुई थी।

एकीकरण का आरंभ

काश्मीर की सहायता के लिए भारतीय फौज पहुँची। आक्रमणकारी पीछे हटा दिये गये। एक दीर्घमालीन युद्ध होता रहा, जिसका अंत युद्धक्षेत्र में हुआ और जिसका स्वरूप बहुत भारी पड़ा। लेकिन अब यह पता चला है कि यदि भारतीय फौजों की प्रथम टुकड़ियों २४ घंटे भी देर से पहुँचनी तो भारत के उत्तर में पाकिस्तान को एक मूचवान पारितोषिक तथा साम्राज्यवाद को एक आदर्श क्षेत्र मिल जाता।

महत्वपूर्ण बात यह है कि उन समय में अब तक काश्मीर प्रश्न ब्रिटेन तथा अमेरिका की दुम्मी चाल और दोनो की चाल चोखी बहानी है। आगे चलकर हम देखेंगे कि मनमोहन को इस प्रकार व्यवस्थित करने से सन्न प्रपन्न हुए थे, जिससे यह बुद्धावस्था क्षेत्र पाकिस्तान के हाथ में चला जाय, जिसका सीधे-साधे शब्दों में अर्थ उन्हीं के हाथ में जाना है।

दोनों और साम्राज्यवादी चालों की इस पुष्टभूमे में भारतीय पूर्वापत्तियों के शासक वर्ग को मालूम पड़ गया कि उनकी शक्त को मुख्य स्तर पर सामन्तों की धोखे में है, जो साम्राज्यवाद के पक्ष में साम्प्रदायिक प्रतिक्रियावादियों की सहायता में काम कर रहे हैं। अनुभवने पर प्रमाणित कर दिया कि यह माधवराव स्वरूप न था।

वास्तविकता यह है कि जब काश्मीर-समस्या उपस्थित हुआ तब कांग्रेस का एक अनुदार भाग इस दुविधा में था कि क्या भारतीय फौजों को दगे दगने में लगी हुई है, धीनगर की रक्षा के लिए भेजी जायें। नई विचारधारा वाले दलने जिसका नेतृत्व नेहरूजी कर रहे थे, यह फैसला कच्चा डाला। उन्होंने यह अच्छी तरह देख लिया कि मुस्लिम बहुमत वाले इन क्षेत्रों के भारत में शामिल हो जाने पर धर्म-निरपेक्षता की भावना फैलाने में भारी मज्हायता मिलेगी और साथ ही साथ भारतीय सीमा पर स्थित एक अन्य सुविधापूर्ण स्थान को भी साम्राज्यवाद विदा भोग लेगा।

यह एक ऐतिहासिक निर्णय था, जिसका भविष्य की घटनाओं पर बड़ा भारी असर पड़ा। वास्तव में इसके द्वारा भारत में साम्राज्यवाद के शक्तिशाली सामन्ती मोर्चे पर आक्रमण करने का रास्ता साफ हो गया।

एक युग का अंत

जिनके शरीरमें जोश नहीं वे कठरा सुख-दुख क्या जान सकेंगे ?
'आज' जिस राष्ट्र मान नहीं, उस राष्ट्री दृष्टिसे 'कल' के
आनंद और कष्ट की क्या कीमत ?

— मुहम्मद इस्माल

यह 'सना' जिनका अंग्रेज प्रभुओंने हस्तान्तरण किया था, मौजूद थी, पर उसे
मजबूतीमें पकड़कर हट करना शेष था, अन्यथा वह राजनैतिक दलानोंके हाथमें
पहुँच जागी, जो साम्राज्यवादी क्षेत्रमें अधिकतम मूल्य देनेवाले व्यक्तिके पास उसे
बँधकर रख देते । १९४८ और ४९ में भारतीय परिस्थिति की वास्तविकता यही थी ।

भारतीय पूँजीजीवियोंने कुछ जाने और कुछ अनजाने इस परिस्थितिको समझ
लिया था । उन्हें इस शक्तिको स्वाधिन्य प्रदान करने तथा राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त
करनेके लिए दो कदम उठाने पड़े । पहली बात, स्वतंत्र भारतके संविधान निर्माणका
कार्य आगे बढ़ा । दूसरी बात, हमेशाके लिए यह स्पष्ट करनेको कदम उठाये गये
कि भारतके सामग्री शक्तियोंके लिए नई व्यवस्थामें कोई स्थान नहीं है ।

परिस्थितिवश इस समय कैंग्रेसमें थोड़ी एकता थी । हृदयके अंतःफलमें यह
भावना मौजूद थी कि जहाँ तक हो सके एक से अधिक शक्तियोंका मामला न करनेका
प्रयत्न करना चाहिए । यह भावना सभी युगोंमें स्वतंत्रता संघर्षोंके समय हुआ
करती है । किसी हद तक यही भावना उसी वैदेशिक नीतिक कारण तथा इस
विचित्र सांघोदरणकी वजह है कि तत्स्थानका यह अर्थ है कि भारत एक देशके विरुद्ध
दूसरेको सहायता नहीं देगा । स्वयं परिचय की ओर मुक्त्यर्थ अधिक स्पष्ट था ।

इसी कारण आर्थिक नीतिमें किसी प्रकारके महत्वपूर्ण परिवर्तनके लिए किमत्तक
दिखाई पड़ती है, क्योंकि उन्हें डर था कि नाजुक मौजेपर इस कारण पूँजी-
जीवियोंकी एकता कहीं नष्ट न हो जाय । उस समय भी दृष्टिकोणोंके अन्तर थे,
पर उसका देशकी नीतिपर कोई खास प्रभाव नहीं दिसलाई पड़ा ।

एक युग का अंत

भारतीय समाजवादियों ने यद्यपि इस सत्ताहस्तांतरण का पूर्ण महत्व समझ लिया था, पर उन्हें यह पता नहीं था कि क्या नीति अपनाई जाय। उन्होंने कांग्रेस पर मौलिक आर्थिक नीति अपनाने के लिए द्वापर अन्तःपर हमेशा की तरह उनकी व्यावहारिक रूप देने में वे उलझ गये, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पर व्याप्त निहित स्वार्थों का साथ छोड़ने की अपेक्षा साम्यवादियों के शक्ति-मंच के विपर्यय वे अधिक चिन्तित थे।

सत्ता हस्तांतरण के समय ही नहीं, बल्कि आन्तरिक भी उनकी नीतिका निर्धारण इसी मानसिक अन्तर्द्वन्द्व के आधार पर होता रहा है। अन्य वामपक्षियों के साथ मिलकर उन्होंने सुयुक्तमोर्चा बनाने का विरोध किया, पर अपनी एक नई सत्ता बनाकर इस विशाल सत्ता को विभक्त करने का प्रयत्न किया।

उनके अन्तर नेताओं ने विरोध रूप में श्री जयप्रकाश नागदण और अन्योन्य पटवर्धन ने मार्क्सवादी और गांधीवादी मान्यताओं को मिलाने का प्रयत्न किया। फलस्वरूप वे स्वयं भी उसमें उलझ गये और अपने पीछे चलनेवालों को भी उलझा दिया। समाजवादियों के कार्यक्रमों का बड़ी रूप अपनाया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश अधिकारियों के निष्क्रमणकाल की उनकी असंदिग्ध शक्ति और प्रभाव नष्ट हो गई।

साम्यवादी पार्टी तथा अन्य वामपक्षी दलों ने ऊपर से ही इस परिस्थिति का अध्ययन करके बिना अधिक सोचे यह निर्णय निकाला कि वे पूँजीजीवी हमेशा की तरह स्वतंत्रता के साथ विश्वासघात करने की तैयारी कर रहे हैं तथा वे शक्तिके सत्ता के स्थान पर उसकी परछाई में अपना 'अधोलक्षणी दुकानों' से ही मनोरंजन कर लेंगे।

साम्यवादियों की पुगनी नीति जिसके द्वारा हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध विद्रोह विरोध उपस्थित किया गया था, की टी रणदिवे के नये नेतृत्व में चुपके में छोड़ दी गई। तेलंगाना के किसानों का संघर्ष अपना मार्ग स्वयं बनाने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। भूमिके दूसरे आन्दोलन भी बन्द कर दिए गये। नई नीतिके अनुसार अगस्त १९४७ में प्राप्त हुई नकली स्वतंत्रता के विरुद्ध शहरो में हिंसक कार्यवाही सुभाई गई और इसका अर्थ था, साम्राज्यवादियों, मार्क्सवादियों और पूँजीजीवियों को एक दूसरे के सहायक समझकर उनके विरुद्ध संघर्ष।

संविधान की रचना

यह गलत नोति थी, जिसके कारण दानपण्डियोंके नेना जलाने दूर पड़ गये। अपने दलके सुधारवादियोंको खलप करनेके नाज़र साम्यवादियोंने अपने आरक्षी ही नष्ट करना शुरु कर दिया। ज़रानूनी घोषित हो जाने पर दलके कई कर्जाओं सचके तथा जैलोंने साथ-साथ बाग़ानापूर्वक मुकदमा किया। पर यह बीगता अर्थहीन था जिसका इन्हें भाग मूल्य चुकाना पड़ा। इस प्रसंगपर आगे विचार किया जाना, यहाँ कैमरेमहा धनवादियोंपर विचार करना उपयुक्त होगा।

मल्लभारी वर्गेन भारतको प्रजातांत्रिक राज्यका रूप प्रदान किया, पर जिन्हें इस पूँजीजीवी प्रजातंत्रके दुस्वस्वयी मणोंका पता था, उन्हें इसके बारेमें कोई उम्माद नहीं था। भारत पर पहलेने ही मुरझावन्दी गन्तुने द्वाग़ शासन हो रहा था, जिसके अनुसार अभिमुक्तोंपर किसी प्रकारके मुकदमा बनानेकी ज़रूरत न थी। वर्गीयतके रूपमें पुर्वासवी फ़ारसिंग और दमन का इस प्रजातंत्र द्वाग़ जगने स्वे गये, जिसपर अब उन व्यक्तियोंका अधिकार था, जो अभी थोड़े दिन पहले देशकी जेलोंकी शोभा बहा रहे थे।

यहाँ दीख रहा था कि आक्षेप राज्योंमें रचे हुए संविधानके अंदर शायद अब भूले, गने और निगुह रहनेकी स्वतंत्रता तथा ऐसी ही अन्य अनेक प्रजातंत्री स्वतंत्रताय शामिल करनी पड़ेगी। इस पारिस्थितिकी अधिक विचारनेके लिए इस संविधानकी रचना उन्हीं लोगोंके द्वारा हो रही थी, जिन्हें भारतकी विज्ञान जनमतकी उपेक्षा करके सीमित मताधिकारके आधारपर अंग्रेज़ोंने निर्गन्धित किया था।

लेकिन ज्यों-ज्यों उसका स्वरूप तैयार होता गया, यह स्पष्ट होने लगा कि जो संविधान बनकर तैयार होगा, उसमें सामान्य निरर्थक बाग़जानके स्थानपर राष्ट्रीय आंदोलनकी भौतिक धारणायें अंग्रेज़ोंमें व्यक्त होगी।

जैसा मसमल जाना है, बीमबी राजाजीके मध्यकालमें संविधानकी रचना कोई कठिन कार्य नहीं है। इस अनेक दिशानाले नियमों अपनी साहित्य उपलब्ध है तथा भिन्न-भिन्न सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक स्वरूपवाने राष्ट्रोंके अनेक व्यावहारिक उदाहरण भी मौजूद हैं। भारतको भी स्वाभाविक रूपमें इसी उदाहरणोंका सहारा लेना पड़ा। संविधानके नामपर अंग्रेज़ोंने अपनी इच्छानुसार जो अनेक कानून बनाये थे, उनके आधारे देशको किसी संविधानका अनुभव न था।

एक युग का अंत

प्राचीन कालके महान नीतिज्ञोंका देश उदाहरण प्रस्तुत कर रक्ता था, पर उनके निद्वान्त अत्र लागू नहीं होने थे ।

भारतके पूँजीजीवियोंने इन सभी साधनोंका सहारा लेनेका निश्चय किया । पूँजीवादी देशोंने मौलिक स्वतंत्रताओं तथा समाजवादी देशोंने मौलिक अधिकार ग्रहण किये थे । यह सच है कि 'स्वतंत्रता' और 'अधिकार' शब्दोंका भारी दुरुपयोग हुआ है, पर ग्राम्य संविधानमें उन्हें सविवरण अनुमूचित करना एक अग्रिम कदम था । यही बात कुछ निर्देशक निद्वान्तोंके बारेमें कही जा सकती है, जिनके द्वारा अनेक जालियोंमें विभक्त हिन्दू समाजके बहुत दिनोंमें रके हुए सुधारोंका राम्ना खुल गया । यह सब आधुनिक विचारोंका परिणाम नहीं, बरन सत्यार्थ रूपमें मफल्ता थी, लेकिन उसकी जड़े राष्ट्रीय आन्दोलनकी आत्मा एवं परम्परामें गहरी उमी हुई थीं ।

इस प्रारम्भमें कुछ ऐसी भी बातें थीं, जिनमें श्रान्ति रखनेका दर था । जिन लोगोंकी भूमि, उद्योग और व्यक्तिगत संपत्ति राज्य द्वारा हस्तगत करनी पड़ जाय, उनका मुआवजा देनेके लिए विश्वास दिलाया गया था । ऐसे वायदे कागजपर अच्छे लगते हैं, पर भारत जैसे पिछड़े हुए गरीब देशमें इसके कारण ऐसी व्यवस्था जारी रखनेके लिए पोल्ट रह जाती है, जिसमें देशकी सर्वतोमुखी नीत्र श्रान्ति रख जाय । जिसके पाम पैमें न हों, ऐसी सरकारके लिए मुआवजा दे पाना केवल स्वप्न-सा है ।

लेकिन पूँजीजीवियोंने यह आशा करना कि वे अपनी शक्तिकी आधारभूत आर्थिक व्यवस्थाको पूर्णरूपेण नष्ट कर देंगे, बहुत असम्भव था । इसके अनिरीक्त इस समय कांग्रेस पार्टीके विभिन्न दलोंके मतभेदोंने कान्फवमें अपना निरिक्त रूप धारण करना शुरू नहीं किया था, यद्यपि इन मतभेदोंके बीटारु संविधानके प्रारम्भमें उसके प्रगतिवादी और श्रान्तिवादी तत्वोंमें शिखलार्द पडते थे । जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके इतिहासका अच्छी तरह अध्ययन किया है और ब्रिटिश साम्राज्यवादके विरुद्ध संघर्ष के दरम्यान उसके वायदोंका ध्यान रक्ता है, उनके लिए संविधानके स्वरूपमें ऐसी अनेक भारी खामियों भी थीं । वयस्क मताधिकार स्वीकृत हो गया था, पर उस पवित्र वायदेका कहीं उल्लेख नहीं था, जिसके अनुसार कृषि योग्य भूमि

जोतने वालोंको बाधना देनी थी। इस बाधकी पूर्ति होनेपर देशकी दशा बदल जावे तथा अर्थव्यवस्थापर अमीन्दारीकी पकड़ दूर हो जावे।

उननिषद् के नये क्षेत्र देना लिए गये थे, पर भारतमें लागे हुई विदेशी पूँजीके भविष्यके बारेमें कोई जिक्र नहीं था, (अर्थव्यवस्थामें प्रमुखताके कारण यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न था।)

स्वतंत्र गणतन्त्र घोषित होनेके उपरान्त भी ब्रिटिश कामनवेल्थसे गठबन्धन बनाये रखनेका निर्णय भी कुछ कम प्रणालीसद न था।

१९४८ और १९४९ में साम्यवादी पार्टी द्वारा इन कामियोंके विरुद्ध जनमतका निर्माण एक महत्वपूर्ण कार्य होना चाहिए था। दुर्भाग्यवश इस हेतु वामपक्षियोंमें समुचित दृष्टिकोण बनानेके लिए कोई सही प्रयत्न नहीं किया गया। यदि यह होता तो प्रजातन्त्रमें संशय दूर हो जाता। इसके विरुद्ध पूरे संविधानका विरोध किया गया, जो प्रथम तो एक गलत मार्ग था और सत्यतया गैरकानूनी और असंगति आश्लेषकोंके लिए बहुत बड़ा कार्य था।

यदि प्रत्येक मद्द्की सफेद या स्याह मानकर बननेका दृष्टिकोण न होता, तो उन विवादास्पद दिनोंमें भी कांग्रेस पार्टीके नेताओंपर उनकी त्यागी हुई कुछ प्रतिज्ञाओंकी पूरी करनेके लिए जनमतका पर्याप्त दबाव डालना सम्भव हो जाता, यह तो होना ही नहीं था। हुआ यह कि जसा कांग्रेस पार्टीके हाई कमान्डने चाहा उसीके अनुसार प्रारूपपर विवाद आगे बढ़ा।

विधान निर्माण परिषद्के बाहर भी कांग्रेस पार्टी मो नहीं रही थी। यदि राजाओं तथा सामंती साम्राज्यिक सहयोगियोंकी अपनी शक्ति बचाने दो जाती, तो वह संविधान जिये वे बना रहे थे, लागू न हो पाता। इसके क्षेत्र बनानेके लिए यह फैसला हुआ कि नई परिस्थितिमें उन्हें अशक्त बना दिया जाय।

आक्रमण करनेके लिए नरेरा इसमें अधिक अरक्षित बच हो सकते थे। उनके सहयोगी (हिन्दू महासभा, जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) गांधीजीके बलिदानके उपरान्त अपना तिर उठानेकी स्थितिमें न थे। साम्राज्यिक दलोंके पीछी खंड गैरकानूनी घोषित कर दिये गये थे। राजाओंमें भी अगला रुढ़म उठानेके

एक युग का अंत

बारेंमें मतभेद था। कुछ नरेश स्वतंत्र भारतमें सम्मिलित भिये जानेके विरुद्ध अतः तक लड़नेमें तैयार थे। दूसरोंने समझौता करना ठीक समझा और नया नगरके जामनाहवकी सलाह सुनना पसंद किया। अन्तमें उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्यवादके प्रति श्रद्धा प्रकट करनेका निर्णय किया और आशाके विपरीत यह सोचा कि दिल्लीके बाबोंपर लड़न रोक लगा लेगा। पर भारतीय पूँजीजीवी भी पिनबके खतरोमें पारिचित थे। व्यापारके समान राजनीतिमें भी लड़नके समान धनी और चालाक सहायक रखनेवाले प्रतिद्वन्द्वीको वे नहीं चाहते थे।

कॉंग्रेस पार्टीके सर्वाधिक योग्य और सोच-भजनभर कदम उठानेवाले नेता सरदार वल्लभभाई पटेल पर स्वतंत्र रियासतोंको विलीन करके प्रमुख भारतके सीमावर्ती क्षेत्रोंमें मिला दाननेकी जिम्मेदारी डाली गई। कुछ छोटी कुछ बड़ी कुछ नकशेपर एक बिन्दुके समान शैक्नों रियासतें उनकी जोंचके लिए सामने आईं।

उन्होंने इस कामके लिए कोई लान्या-बीड़ा कमीशन नियुक्त नहीं किया, जो आगे पीछे सोवसर एकीकरणके लिए एक मोटी हथौड़ा सुझाता। उन्होंने वह काम उसी तरह शुरू कर दिया जैसा कि अंग्रेज करते और उसे बड़ी गुन्दरताने थोड़े समयमें एव बालबलमें बड़े प्राजनायिक ढंगमें संपन्न कर दिया।

प्रथम तो राजाओंमें पूट डालना और उनके एक प्रभावशाली दलका इस बातपर विश्वास पैदा करना जरूरी था कि यह बात माननेके हितही होगी कि वे परिवर्तित परिस्थितियोंमें अपने लिए एक सुरक्षित स्थान प्राप्त कर लें। इसके साथ ही साथ उन्हें यह भी बतलाया गया कि ऐसा न करनेकी दशामें उनकी निरक्षर स्थिति, जनताका क्रोध और तीव्र आलोचनाका लक्ष्य होती जायगी। यह सीधी-सीधी बात थी और यों कहना चाहिए कि अनेक मुख्य राजाओंने इसीके अनुसार आचरण करना स्वीकार कर लिया। समस्त भारतके लिए कोई आज्ञा प्रगारित नहीं की गई। यह बतलाया गया कि प्रत्येक समस्यापर उसके महत्वकी दृष्टिमें पृथक विचार किया जायगा।

नरेशोंके प्रति चिंता व्यक्त करते हुए भारत सरकारने यह भी घोषणा कर दी थी कि सामन्ती दुनियाके कुछ प्रमुख राजाओंको देशके प्रशासनमें महत्वपूर्ण स्थान दिये

सामंती दुर्ग टूटने लगे

जायेंगे। अन्तमें भूतकालके इन अवशेषोंको भारी पैसान और हरजनेका लोभ दिया गया। पैसा तो उनकी हमेशाकी चाहो थी। वे आलमियोंकी तरह शान-शौकतकी जिदगी बितानेके अतिरिक्त और किसी कामके योग्य न थे।

एकीकण योजना कार्रहामें परिणत हुई। सामंती दुर्ग टूटने लगे। उनका आम्रमर्मरण बारी-दारीमें होने लगा और जिनपर आमाजीने विजय पाई जा सकती थी, उन्हें पहले सत्तन सिना गया। यह निलोनीकरण का प्रथमका हुआ। प्रथम तो २१६ रियासतें जिनका कुल क्षेत्रफल ८४७७४ वर्ग मील तथा जनसंख्या १ करोड़ २० लाखमें कम थी, सीमादली प्रान्तोंमें अर्थात् उड़ीसा, मध्यप्रदेश, बरार, बिहार, मद्रास, पूर्वी पंजाब तथा बम्बईमें विलीन कर दी गई। दूसरे कुल १६०६१ वर्ग मील क्षेत्रफलकी २२ रियासतें मिलाकर हिमाचल प्रदेश नामकी एक नई इकाई बनाई गई। तीसरे २६४ रियासतोंकी सीमायें मिलाकर सौराष्ट्र, मध्यभारत और पेम्बू नामक बड़ी इकाईयां बनाई गईं, जिनका क्षेत्रफल १५०,४०० वर्ग मील और जनसंख्या लगभग २ करोड़ ४० लाख थी। अन्तमें हैदराबाद, मैसूर, दूबन-कोर-कोचान और दुर्गा पृथक् इकाईयां बनीं जो इस रियासती दुनियामें प्रमुख थीं।

जिन समय विलीनीकरणकी यह प्रक्रिया जारी थी, तब शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्यवाद इस घटनाकी बाम्बेविप्लवके प्रति सचेत हुआ। पहले उन्होंने सोचा कि सामंती शक्तिवें विरुद्ध साम्यवादियोंके बढ़ते हुए सङ्घर्षोंके दशनेके लिए रियासतोंका रूप बदल रहा है। एक अर्थमें इसके कारणोंमें यह भी एक कारण था, क्योंकि कि सामंती शक्तिके प्रमुख दुर्ग हैदराबादमें साम्यवादी पार्टीने निजाम तथा उनके आगीर-दागोंके विरुद्ध सङ्घर्षका सफल नेतृत्व किया था, जिसके कारण उन्हें दक्षिणके पयारपर एक थोर स्थान सेलगाता प्रदर्श छोड़नेपर विवश होना पड़ा था। यद्यपि मुसलमान और अमबिरामी विमानोंने न केवल धानी हुई भूमिका अर्थमें बँटवाग कर लिया था, बल्कि हबिवागोंके द्वारा अपने लाभकी रक्षा भी की थी। निजामके रजाकार गुंडे तथा अन्य सज्जन निपारी इस भारी भूभागमें प्रवेश भी नहीं कर पाते थे। ४० लाखमें अधिक आबादीवाले २ हजार गांवोंमें निजामका शासन समान हो गया था। १३००० वर्ग मीलके इस क्षेत्रमें जहाँ पहले ५०० से १२०,००० एकड़

एक युग का अंत

भूमेवाले जागीरदार कानूनी और गैरकानूनी लगानोंसे किसानोंको लुटा करते थे, वहाँ धन जनताका राज्य था ।

यदि तैलंगानामे परिस्थितिवश जो अवस्था हुई, वह न हुई होती, तो संभव है कांग्रेस पार्टी राजाओंके विरुद्ध कुरमतामे कार्यवाही करती, क्योंकि काश्मीरयुद्धकी जवाबदारियोंके किसी हद तक उनके हाथ बँध दिए थे । साम्प्रदायियोंके दबावके कारण कांग्रेसकी रफ्तार तेज हुई और कांग्रेसोंने सोचा कि अब 'हान्ड' बड़नेका समय आ गया है ।

हैदराबाद, कराची और लंदनके बीच आवागमन जारी था । कानूनी सलाहकारके रूपमे बाल्टर मोकटन इधर-उधर दौड़ रहे थे । पाकिस्तान और थाईलैण्डसे ब्रिटिश और अमेरिकन युद्धमाममी वायुमार्गमे हैदराबाद पहुँचाई जा रही थी । भारतके नगरेष्वर बम-बर्षाकी बात-चीत हो रही थी । निजाम अधिक डेढ़े हो रहे थे और दिल्लीकी आशाओंका उलटपन करते हुए मन तक मुचाबला करनेकी धमकी दे रहे थे । परिस्थिति गंभीर थी ।

जुलाई १९४८ में विस्मय चर्चित द्वारा भारत सरकारकी नीतिकी आलोचनाके कारण सद्दार पटेल भी इस गोपनीयताके पर्देको हटाने पर सहस्रोद्घाटनके लिए विवश हुए । विधान निर्मात्री परिषदमे बोलते हुए उन्होंने बतलाया कि " हम अन्धही हैनियतके अंग्रेजों द्वारा अपने प्रशासन, नेताओं और निवासियोंकी अप्रत्याशित, द्वेषपूर्ण और सुरक्षित आलोचनाओंको बहुत दिनों तक शांतिके साथ सुनते रहे " आगे उन्होंने पहली बार यह स्वीकार किया कि " हमें भारत और युनाइटेड किंगडम दोनोंमें स्थित निहित स्वार्थों द्वारा भारतकी अधिक कठिन परिस्थितिकी उत्ताधिकारके रूपमे सौंपनेमे सन्नमित चालोंका अच्छी तरह पता था । भारतकी चलतान राष्ट्रोंकी तरह विभाजित करनेका सन्धि प्रयत्न किया गया था । बड़े पैमानेपर शांति भंगकी स्थिति पैदा की गई । "

और अन्तमे कांग्रेस पार्टीने लीह पुरुषने मंचेन किया कि " वर्तमान भारतीय इतिहासका कोई भी गंभीर विचार्य यह धारणा बनानेमें नहीं चूक सकता कि देशके विभाजन तथा उसके साथ आनेवाली मुसीबतें उस दलकी फूट टालनेवाली

सांभंतवादका अंत

कारगुजारियोंका परिणाम थी, जिसके प्रेरक और उद्बोधक मि चर्चिल हैं। इस कारण मि चर्चिल और उनके सिद्धांतोंमें इतिहासके व्यापारतथमें इन दुस्माल घटनाओंके सम्यन्धमें जबाब देना पड़ेगा। ”

यह कार्ययोजना बड़ी सरल और एक अन्दीमेदमकी तरह थी। पीछे लौटना नहीं हो सका था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद तथा उसका सर्वोधिक विश्वासपात्र मित्र विजाम बहुत पीछे रह गये। अब तब लगभग माल रियासती भारत घुटने टेक चुका था। साथ ही दिने सरकार काश्मीरके युद्धमें एक धाँप उत्पन्न करनेके लिए यथेष्ट सतर्क थी। राष्ट्रसपनी छत्र-च्छायामें बानी चालू हो चुकी थी तथा साम्राज्यवादियों द्वारा ध्यान बँटानेके लिए कोई नई परिस्थिति पैदा करनेकी आशा बहुत कम थी।

थोड़े दिनों बाद १३ सितम्बर १९४८ की पर्याप्त राजनैतिक और सैनिक तैयारीके उपरान्त भारतके सशस्त्र सैनिकोंने पुनितम कार्यवाही की। हैदराबादका प्रतिरोध बालूकी दीवारकी तरह ममत्त हो गया। भारतमें मार्क्सवादके श्वनरी दरिद्यों वज उठी। अब पूँजीजीवी परिस्थितिकें स्थायी थे।

इनाहावाद विश्वविशालयके दोषान्त समारोहके अवसर पर नवम्बरमें सरदार पटेल यह कहनेकी स्थितिमें आ गये कि “हमें कठिनाईमें प्राप्त इस एक्ताको रद्द करना चाहिए। हमें उन बानोंपर ध्यान देना चाहिए, जिनमें एकता स्थापित होती है, न कि उन बानोंपर जिनमें भेद बढता है। ”

एक्ता प्राप्त करनेके इस नाहुक समयके दरम्यान भारत सरकारकी ब्रिटेन तथा अमेरिकीकी अनेकों बार यह विश्वास दिलाना पया कि उनके लिए कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं की जायगी। यह विश्वास उत्पन्न कराना आवश्यक था। लार्ड कजनके शब्द अब भी सत्य थे। अपनी पुस्तक ‘मुद्गर पूर्वकी समस्या’ में उन्होंने लिखा था कि “दुनियाँके गोलेके तीसरे अत्यन्त महत्वपूर्ण भागके युद्धोपयोगी केन्द्रमें भारतीय साम्राज्य स्थित है। ...लेकिन उसकी केन्द्रीय और नियंत्रक स्थितिके प्रभाव उसके पास तथा दूरके पक्षोन्मुखोंके भाग्यपर पड़ने वाले प्रभाव एवं भारतीय धुरी पर घूमनेके कारण उनके भाग्य-परिवर्तनसे अच्युती तरह और कहीं दिखलाई नहीं पड़ता। ” इस दुनियाँके गोलेके इस तीसरे अत्यन्त महत्वपूर्ण भागमें भारी

एक युग का अंत

जिम्मेदारियोंके उपरान भी भारतीय धुरीपर नियंत्रण न रहनेके कारण साम्राज्यवादको भारी चिन्ता होनी ही चाहिए थी ।

अप्रैल १९४७ में मिलेने होनेवाली ' एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस ' में श्री नेहरूने इन राष्ट्रोंकी भावनाओंको बतलाते हुए कहा था कि " हम एशियावर्गी बहुत दिनों तक पश्चिमी न्यायवादी और मजानियोंमें दरतास्ते देते रहे, अब यह कहानी पुगनी पड़ जायगी । इन अपने परोपर खड़ा होने तथा उन लोगोंने सहयोग करनेको तैयार रहेंगे, जो हमने सहयोग करना चाहते हैं । हम दूसरोंके हाथोंके खिलेने नहीं रहना चाहते । "

फिर भी राष्ट्रमन्त्रे भारतीय प्रवक्ता बोड़े-बहुत पीछे चलते रहे । जिन मामलोंमें उनके विचार साम्राज्यवादियोंसे मेल नहीं पाने थे, उनमें होशियारीने वे अपना हाथ खींच लेते थे । फिर भी हमने आशा बंधनी थी ।

राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्थामें विदेशी पूँजीको परेल्हू खेजमें अपनी स्थिति कायम रखनेका विश्वास दिलाया गया । भारत और उसके पड़ोसी देशोंमें अंग्रेजोंकी भारी पूँजी लगी होनेके कारण यह एक महत्वपूर्ण तत्व था । साम्यवादी पार्टीपर रोक लगा दी गई । हड़तालें फसद नहीं की जाती थी । पुगने प्रशासनका पैलादी ढाँच बना रहा । यहाँ तक कि देशकी सेनाओंमें भी कमसे कम दो सौ से तीन सौ तक अंग्रेज आफसर महत्वपूर्ण पदोंपर बने रहे ।

यह सब बातें यह बतलानेके लिए नहीं लिखी गई हैं कि इस प्रशस्की आचारिक और बाह्य नीति भारतके नये शासकोंको नापसन्द थी । भारतीय पूँजीजीवियोंने पश्चिममें भाई-बारा बनाये रखनेके लिए इस प्रशस्की नीति अनाकर यह आशा बोंगी कि मधुमाग बना रहेगा । यह बात लाभप्रद और बुद्धिमानी की थी ।

लेकिन १९४६ के आरम्भमें साम्राज्यवाद धिन्ति हो उठ्य । इसका एक प्रमुख कारण भारतीय पूँजीजीवियोंका शीघ्रतापूर्वक संगठन था । यह महत्वपूर्ण बात थी और नये संविधान द्वारा भारत अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय मामलोंमें स्वावलम्बनी और अभ्यन्तर होता दिखाई पड़ रहा था । यह साफ दीखने लगा कि इस स्थितिके कारण यह

साम्राज्यवादी हिंसे के अधिराधिन सपने में आयेगा । मधुसूदन शर्मा के मध्य व्यतीत करने की आशा कम थी ।

राजनैतिक गठनबन्धन में नया भारत बरामद की दृष्टि चाहता था । वह ऐसी 'सहायता' लेने में हिम्मत कर रहा था, जिसके कारण उसे अपनी स्वतन्त्रता के समझौते करना पड़े । इसके अतिरिक्त एशिया के दूसरे देशों को भी औपनिवेशिक बंधनों में मुक्त करना चाहता था । इस मामले पर १६ राष्ट्रों के हिन्दोशिया के बारे में दिल्ली में होनेवाले अधिवेशन में गरमागरम बहस हुई । नेहरूजी ने थोड़े शब्दों में दुबारा यह दृष्टिकोण व्यक्त करते हुए कहा कि "दूसरे देशों पर आश्रित, आक्रामक उनके हाथ का बहुत पुराना रिर्लाना एशिया अब अपनी स्वतन्त्रता के बारे में उनका कोई हस्तक्षेप सहन नहीं कर सकता ।" लार्ड कर्जन की 'भारतीय धुरी' अब स्थान-भ्रष्ट होती मानम पड़ी ।

भारत सरकार के साम्यवाद विरोधी लेखों का प्रदर्शन या और कोई अन्य आचरण साम्राज्यवादियों को भक्ष्य न कर सके । इस सम्बन्ध में 'न्यू स्टेट्समैन' और 'नेशन' के संपादक किंगले मार्टिन ने एक महत्वपूर्ण तत्व बतलाया । उन्होंने लिखा था कि "मुझे एक महत्वपूर्ण सूत्र द्वारा यह बतलाया गया है कि भारत में कम से कम एक लाख कम्युनिस्ट तथा अन्य लोग कैद हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रीय सरकार द्वारा इनके आदमों के बिना मुकदमा चलाये कैद किये गये हैं, जिनके अभियोगों शायद ही किसी समय किये हों ।"

साम्राज्यवाद ने सोचा कि यह हो सकता है, पर भारत में विश्वशांति और भाव-भाव की बात-चीत जोरों पर है । क्या राजगोपालाचारी ने मुद्रा को गैरकानूनी घोषित करने के लिए नहीं कहा था ? ऐसी भावनाओं में साम्यवाद को समुद्र करने की गंध आती थी । भारत भले ही ब्रिटिश सामन्तव्य में रहना स्वीकार कर ले, पर उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता । उसे एक-दो पाठ पढ़ाने ही चाहिए । दिल्ली की कूटनीतिक सूत्रों द्वारा इस बात-चीत की चेतावनी मिल गई कि क्या होनेवाला है ।

लेकिन ज्योतिषी के शब्दों में 'प्र ह अ च्छे थे ।' वह चीन की शक्तिशाली भूमि पर होनेवाली उथल-पुथल से प्रेरित हो उठे । एशिया के राष्ट्र समुदाय में

एक युग का अंत

नाटकीय परिवर्तन हो गया। भारी संभावनाओंमें पूर्ण कम्युनिस्ट चीनके उदयसे पड़ाने साम्राज्यवादी शक्तियोंको सीएमएर दिना और बुरी तरह दबाये हुए औपनिवेशिक लोगोंने—विशेष रूपसे भारत, वगैरह और हिन्देशिया वालियोंमें जिन्होंने स्वतंत्रताकी शक्ति पहली बार अनुभव किया था, नई शक्ति का संचार हुआ।

राजनीतिमें अशिष्ट कुछ लोग जिन प्रकार हमें विश्वास दिलाना चाहेंगे, उस प्रकार दिल्ली द्वारा कम्युनिस्ट चीनकी वसूली तथा राष्ट्रपति उनके प्रवेशके लिए मार्ग बनाना किसी खास व्यक्तिकी कल्पनाकी आकांक्षिक उपज न थी। यह नीति भारत तथा उन अनेक गैरकम्युनिस्ट देशोंके राष्ट्रीय हितोंने समर्थ थी, जिनपर साम्राज्यवादी दबाव अब भी मौजूद था और जो उनके सामने अपने आपको अशिष्ट पाने थे। वे एम. ए.बी.करके शब्दोंमें 'माउन्टेन-गुंगके नेतृत्वसे रक्षा-वालोंका अंतर्राष्ट्रीय महत्व बढ़ गया है।' वे यह भी कह सकते थे कि साम्यवादी चीनके अस्तित्वको एक नया बल मिला है।

कम्युनिस्ट चीनके प्रति एशियाके इस दृष्टिकोणसे निर्माणमें भारतने नेतृत्व किया, क्योंकि यहाँ का सत्ताधारी वर्ग एशियाकी इसमें होनेवाले लाभोंसे समझ मका। नेहरूजी ऐसे अवसर छोड़नेके अभ्यस्त न थे। इसके बहुत पहले ४ दिसंबर १९४७ को ही उन्होंने स्पष्ट रूपमें कहा था कि "आप कोई भी नीति निर्धारित करें, पर देशके विदेशी मानकोंको सहायित करनेकी कला इसी बातमें मजबूत है कि आप यह जान सकें कि सबसे अधिक फायदेकी बात क्या होगी। हम अंतर्राष्ट्रीय सौहार्दनाकी बात कर सकते हैं और जो कहते हैं, उनके अनुसार काम कर सकते हैं, पर ध्यानमें रखने पर मालूम पड़ेगा कि किसी भी देशकी सरकार अपने देशके लाभके लिए कार्य करती है और कोई सरकार ऐसा काम करनेकी हिम्मत नहीं कर सकती, जिसमें देशकी हानि हो। इस कारण चाहे देश साम्राज्यवादी, समाजवादी या साम्यवादी हो, उसका विदेशमंत्री अपने देशकी भलाईकी ही बात प्रमुखरूपसे सोचता है।"

इसी भावदंडके अनुसार भारतने आचरण करना शुरू कर दिया तथा इसी भावपूर्ण आगे बढ़ी हुई एक अन्य स्वोपरोक्तिकी हमेशा याद रखा, जिसमें उन्होंने कहा था

कि “अनमें विदेशी नीति आर्थिक नीति पर परिणाम होती है और जब तक भारत अपनी आर्थिक नीति टोक प्रकरसे निर्धारित नहीं करता, उसकी विदेश-नीति भी अस्पष्ट अवांछित और लक्ष्यभ्रष्ट बनी रहेगी।”

१९४६ के उत्तरार्धमें स्पष्ट होनेवाली अन्तर्राष्ट्रीय स्थितिपर यहाँ दृष्टि डालन अनुपयुक्त न होगा। शक्तियोंके पारस्परिक सम्बन्धोंने एक बहुत बड़ा निर्णायक परिवर्तन हो गया था। कम्यारोंके प्रथम राज्य, रूसकी स्थापनाके समय तक साम्राज्यवादी शक्तियोंमें कुचलनेके लिए मारा बिसर मौजूद था। अफ्रीका और एशियाके साधनों तथा परिधर्मोंका लाभ फूरतापूर्वक जितना वे कमूल कर पाते थे कमूल करके वे मोटे हुआ करते थे। उन्होंने अपनी ‘प्रजातांत्रिक’ तथा ‘उदार’ संस्थाओंकी स्थापना दूर-दूर तक फैले इन उपनिवेशोंमें मेहनत और आँसू पैदा करनेवाले दमनके आधारपर की थी।

इसलिए इनमें कोई आश्चर्य नहीं, यदि उन्होंने बोलशेविक क्रांतिमें ‘एक दैत्य’ के रूपमें देखा हो और अपनी सेनायें मुसगठित करके इन नवजात कम्यारोंके राज्य पर इन विस्वाँसके साथ आक्रमण किया हो कि वे इनके सामने अधिक टिक न सकेंगे, पर वे टिक गये और आशाके विपरीत हड़नाके साथ सामना किया। दखल देनेवाली सेनायें हार कर पीछे हट गईं।

पर साम्राज्यवाद शांत होनेवाला न था। ब्रिटेन और अमेरिकाकी मददसे जर्मन सैनिकवादमें पुनर्जीवन किया गया। बोलशेविक खतरेका उत्तर फ़ासिस्टवाद था। यह हथियार भी द्वितीय विश्वयुद्धके सख्तपूर्ण वर्षोंमें निकम्मा होकर नष्ट हो गया।

सोवियत संघमें हिटलरकी फौजोंका मुख्य आक्रमण सहना पड़ा। लाखों आदमी मारे गये। एक दशाब्दीके लाभ तलवार और आगिकी में डूब गये। पर साम्राज्यवादकी समाजवादकी सीमाओंका विस्तार होते हुए देखकर भय हुआ। युद्धकी राखने पूर्व यूरोपमें अनेक जनप्रजातांत्रिक राज्योंने जन्म लिया।

और जब चीन्ने भी साम्राज्यवादका जुआ उतार फेंका, तो सभी देशोंके दरसकोंको यह स्पष्ट दीखने लगा कि समाजवाद अब टिक जायेगा और सपूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रियाएँ विश्वके सभी लोगोंको इसी रास्तेपर ले जाएँगी। इन विचार

एक युग का अंत

पाराश्रोका तत्कालीन प्रभाव एशियाकी भूमिपर दोखने लगा, जहाँ उपनिवेशवादके ताडवका प्रदर्शन भुल्लमरी और नम्रताके रूपमें हो रहा था ।

अब तक स्वतंत्र विचारधारावाले एशियावासियोंको राजनैतिक और आर्थिक रूपसे बदनाम किया जाता था । एक एक करके उन्हें आत्ममर्णण करना पड़ा था । अणुबम धारी ; जिनकी शक्तिका नृशंभ प्रदर्शन होरोरिमा और नागरासीमें उस समय हुआ था, जापान-संघि प्रस्ताव कर चुम्नेके बाद अब यह सोचने लगा कि निरवको अपने अधिगममें लेनेके उनके रान्नेमें अब कोई रुकावट नहीं आ सकती ।

पर नवजात चीनके उदाहरणका प्रभाव पड़ा । संयुक्तराज्य अमेरिकाके पिछू चांग कर्दे श्रेष्ठके कृमिनटागरो सहानी देशमगियोंका नेतृत्व करनेवाली साम्यवादी पार्टीने हरा दिया । अपने उत्पीडकोंके हृदयारोपर कच्चा करके चीनवासियोंने पेरिंगपर अपनी सार्वभौमिकता और शक्ति स्थापित कर ली । साम्राज्यवादको विश्वास हो गया कि एशियाके दूसरे देशोंको अब परास्त करना आसान न होगा । ऐसे व्यवहारका यह प्रभाव पड़ेगा कि यह देश भी अपनी समस्याओंका हल उसी रूपसे ढूँढनेका प्रयत्न करेंगे, जिनमें चीनको बड़ी अच्छी सफलता मिली है ।

१९४६ में उपस्थित इस चैलेंजका सामना साम्राज्यवादने ऐसे दुधारी आक्रमणमें किया, जिसके बारेमें वे सोचते थे कि उसका सामना करना संभव नहीं होगा ।

प्रथम आक्रमण शैद्धांतिक था । साम्यवादको बड़े बीभत्सहृषमें चित्रित किया गया । एशियाके शान्तचर्चोंको यह बतलाया गया कि यदि वह ' सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ' कैमलिनके प्रभावमें आ जायेंगे, तो उनका क्या होना । समाचार-पत्रोंमें इस प्रकारके झूठे प्रचारकी वाद-नीं आ गई । इस प्रचारका मुख्य उद्देश्य, यह प्रमाणित करना था कि चीन अब सोवियट सपना श्रद्धा बन गया है ।

इस आक्रमणका बहुत थोड़ा लोभ हुआ । एशियाकी साम्राज्यवादी स्मृति इतनी स्पष्ट थी कि उसे इस प्रकारके मिथ्या प्रचारसे नहीं भ्रमया जा सकता था । अमेरिकाकी उत्तेजनाओंके विरुद्ध कम्युनिस्ट चीनके दृढ़ कदमके कारण उन लाखों व्यक्तियोंकी प्रशंसा प्राप्त हुई, जिनकी सदियों पुरानी निराशा यह थी कि वे अपने

आक्रमण का दूसरा दौर

रबेन उत्पीड़ितोंके मुँहमे निकलनेवाली गालियों और दुःस्ववहारों पर रोष नहीं लग पाते थे। ऐसी बजर भूमिपर इस प्रकारका निरर्थक बालोचित मिथ्या प्रचार जब नहीं जमा सकता था।

आक्रमण का दूसरा दौर 'सहायता' के नाम पर हुआ। विचार यह था कि यदि बादविचारने आप किसी मनलेको हल नहीं कर सकते, तो पैमेमे वह कम हो जायेगा। यह मकसद हो जाता, पर यही भी साम्राज्यवादी भूत उस 'सहायता' के नामपर कुछ शर्तें लगानेके पीछे पड़ी थी। बघनोमे मुक्त होनेवाले एशिया-वामियोंने केवल अभी हालमें जीने हुई सार्वभौमिकताका कुछ भाग छोड़नेके लिए ही नहीं बल्कि समाजवादी दुनियाके विरुद्ध शान्त्युद्धमें भी सम्मिलित होनेके लिये करा गया। और इसका अर्थ 'प्रतिरक्षा संधियाँ' नामवाली समझौतेमें सम्मिलित होना ही न था, बल्कि उमध्य अर्थ अर्थिक और राजनैतिक बायकाट भी था, जिनका सीधा-सादा मतलब अविभक्त देशोंको साम्राज्यवादी बाजारमें दबा पर अर्पित करना था।

पहले आक्रमणमे यह आक्रमण अधिक मजबूत रहा, क्यों कि कुछ एशियायी देशोंके शासकोंने 'सहायता' स्वीकार करनेक अंदर विद्यमान सुष्ठुको अच्छी तरह देख नहीं पाया तथा मनोवैज्ञानिक रूपमें वे 'प्रचारक, शोषक, नाम्यवादियोंके बारेमें बान करनेके लिए तैयार थे।

ऐसी सहायताने द्वारा अनेक सरकारोंको नष्ट करना था, पर भारतने उसके विरोधमें नेतृत्व लिया। उसे 'महापला' की भारी जरूरत थी, पर ऐसी सहायताकी नहीं, जिसके साथ कुछ बघन हो। भारतके पूँजीजीवी शासन जानते थे कि जनता सार्वभौमिकताके किसी प्रकारके अन्तर्गतकरणके बारेमें कोई कमील नहीं सुनेगी। यहाँ तक कि राष्ट्रमंडलके नाममानके बंधनकी भी भारी आलोचना हुई थी और साम्रज्याध्यके समर्थकोंकी इसकी सार्वजन्य मिद्ध करनेके लिए भारी कटिंगें उठायी पड़ी थी।

इसके अतिरिक्त एक अन्य तत्व भी था, जिसे भारतीय पूँजीजीवियोंने शीघ्रता पूर्वक देखकर उसका लाभ उठाया। वह शाक्तियोंके नये सन्तुलनमें भारतीय सुक्षोप-योगी स्थिति थी। चीनके समाजवादी दुनियाके एक अंग बननेके उपरान्त साम्राज्यवाद

एक युग का अंत

केवल अपने खजनेके साथ ही भारतका विरोध कर सकता था, जो एशियाकी दूसरी एकमात्र महाशक्ति था। भारतके शासकोंने इस भयका कायदा उठानेकी सोचकर तटस्थताका पूरा लाभ उठाया।

यह तलवारकी धार पर चलना था। यदि यह नीति बहुत आगे तक कार्यन्वित की जाती, तो इस बातका दर था कि साम्राज्यवाद भारतमें भी उगी प्रसारके प्रयत्न करेगा, जो अबादानके तेलक्षेत्रके महत्वपूर्ण प्रश्नको लेकर वह ईरानमें कर रहा था। यदि यह नीति समाजवादी दुनियाके प्रति अधिक बेगरी हो जाती, तो साम्राज्यवादके तीन विरोधी भागवान्नी इसे राष्ट्रीय और एशियाके हिस्सोंके प्रति विधागघात समझते। तलवारकी धारकी यह यात्रा बड़ी कुरातनापूर्वक सम्पन्न हुई।

१९४६ में समाजवादी देशोंने व्यापार चालू करनेकी बातचीत शुरू हुई। १९५० के आरम्भमें साम्यवादका दमन भी धीरे धीरे कम हो चला, यद्यपि उसके ऊपरने रोक और उमरी गैरमानूनियत बहुत दिनों तक नहीं हटाई गई। कम्युनिस्ट चीनके प्रति भारतकी मित्रता और प्रेमपूर्ण सम्बन्धोंका भारी प्रदर्शन किया गया। यह मोचनेवाले लोगोंके लिए कि इस दिशामें भारत बहुत आगे बढ़ रहा है, निज्यतके स्वशासनका प्रश्न जीवित रहा गया, जिसमें मालूम पड़े कि निष्पत्तना अपना काम कर रही है।

प्रमुख मुकाब तो भावनाहीन पश्चिमकी ओर बना हुआ था। मार्च १९४६ में गण्टूरपति दमनने भारतके प्रधानमंत्रीको अमेरिका भ्रमणके लिए आमन्त्रित किया, यह आमन्त्रण स्वीकार कर लिया गया। इस महीनेके अन्त तक श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित वाशिंगटनमें राजदूत नियुक्त की जा चुकी थी। इस बालर भूमिमें नेहरूके आगमनकी पूरी तैयारी हो गई थी।

अक्टूबरमें दमनने इसका अभिवादन किया। इस अभिवादनके राज्य बड़ी कुशलतापूर्वक चुने गये थे। उन्होंने कहा था कि 'भाग्यकी वही इच्छा थी कि आपके देशको पहुँचनेके एक नये मार्गको ढूँढनेके प्रयत्नमें यह देश खोज लिया गया। मैं आशा करता हूँ कि आपकी यह यात्रा भी एक रूपमें अमेरिकाकी खोज होगी।' नेहरूजीने पूर्वी और पश्चिमी दुनियाके दो बड़े गणतन्त्रों द्वारा एक दूसरेके दृष्टिकोणको परस्पर समझनेकी बात कही।

इस यात्रा ने बहुत आशा की गई थी। अमेरिकी ने केवल नेहरू को ही अपने पक्ष में करने की नहीं सोची थी, बरन धीरे-धीरे इस महत्वपूर्ण प्रदेश में ब्रिटिश प्रभाव को हटाने की भी आशा की थी। पर नेहरू ने भारत की शांति की खोज तथा किसी ऐसे मानने में न पैसे का इरादा बराबर व्यक्त किया, जिससे अर्थ किसी प्रकार के शान्त युद्ध में सम्मिलित होना था। उन्होंने कहा था कि " भारत स्वतंत्र राष्ट्रों के परिवार में किसी के प्रति द्वेष या शत्रुता के बिना सम्मिलित हुआ है और वह प्रत्येक अभिवादन करने और अभिवादन कराने के लिए तैयार रहेगा। वास्तव में उसे अपनी विदेश नीति स्व-हित तथा विशाल दृष्टिकोण पर आधारित करने पड़ेगी; पर इसके साथ ही साथ वह अपनी आदर्शवादता को उमने पुर देना। "

इस प्रकार दृष्टिकोण अमेरिकन प्रभुत्वों को प्रभाव नहीं कर सका था, जो कुछ के लिए पूर्ण रूप से नैयाब थे। यह वही दृष्टिकोण था, जिसके कारण अनेक प्रतिष्ठित उदार अमेरिकियों ने मेकार्थिशन दमन का सिकार बनना पड़ा था। यह वही दृष्टिकोण था, जिसके कारण अनादन लिंकन के देश में अनेक स्त्री-पुरुषों को जीविक के साधनों से हाथ धोना पड़ा था।

जैसे जैसे यह निम्नापूर्ण अन्तर्गत आने लगा, अमेरिकी के शासकों के व्यवहार में शीतलता बढ़ने लगी। लेकिन अमेरिकी वास्तव में यह जान नहीं थी। उनके उदार विचार जो उस क्षण कुचल दिए गये थे, भारत के इन व्यक्ति के प्रभाव में प्रतिबलित हो उठे। यदि अमेरिकी की यात्रा कुछ परिणाम निकला तो यह कि अपने नेहरूजी के शान्त युद्ध में तत्कालीन सरकारों के प्रति अधिक जागरूक कर दिया। भारत वापस लौटने पर उनकी यह धारणा स्पष्ट हो गई कि तत्कालीन अधिक प्रभावशाली होना चाहिए।

१८ नवम्बर १९४६ को इस यात्रा के बारे में बोले हुए नेहरूजी ने कहा कि अमेरिकी के कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों ने भारत की किसी दल में सम्मिलित न होने की वर्तमान नीति की तारीफ की तथा कुछ ने उसको पसंद किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि उनकी नीति उसी प्रकार की है, किसी नीति जार्ज वाशिंगटन तथा उस के राष्ट्र के अन्य संस्थापकों ने शुरू में अपनाई थी। उन्होंने जानबूझकर और निश्चित

एक युग का अंत

रूपने उन दिनों ससारकी समस्याओंने अपनेको अलग रखा था।” यह शब्द-योजना बड़ी होशियारीपूर्ण पर निश्चित थी। इनका अर्थ समझनेमें कोई भूल नहीं कर सकता था।

फिर भी अमेरिकाके रियासती विभागके भुलक्कड़ राजनीतिज्ञोंने सही करना शुरू किया। अमेरिकन कांग्रेसके सामने नेहरूजीकी इस वक्तूताका ज़िम्मे उन्होंने कहा था कि “जहाँ स्वतंत्रता अथवा न्यायके ऊपर विपत्ति आई हुई है अथवा जहाँ दमन हो रहा है, वहाँ न हम तटस्थ रह सकते हैं और न रहेंगे।” का जानबूझकर यह गलत अर्थ लगाया गया कि भारत वास्तवमें आगल अमेरिकन दलके साथ है। किसी हद तक यह धारणा आन्तर्नीसे इस बातकी समझ देती है, कि भारतके प्रधानमन्त्रीकी अधिक सुशाम्द क्यों नहीं की गई और उनकी तटस्थता पर गंभीरता-पूर्वक विचार क्यों नहीं किया गया, विशेषतः उम समय जब कि अक्टूबर १९४६ में अमेरिकानी यह यात्रा चीनके कम्युनिस्ट गणतन्त्री स्थापनाके साथ ही साथ सम्पन्न हुई थी।

तलवारकी धारकी यात्राका अब प्रथम परिणाम मिलना शुरू हो गया। इस शीतयुद्धकी उलझनोंमें दूर लगेले जीवनकी अधिक सुगन्ध और निर्मल बननेकी पुरानी समस्याका तटस्थतामें एक मनाया मिल गया था और भारतको बाहर भी हमका समर्थन प्राप्त होने लगा।

अमेरिकन सरकार गलत चालमें पकड़ ली गई थी और उनकी समझमें नहीं आ रहा था कि इस विकट परिस्थितिमें आगे कैसे चला जाय। उसने आमान रास्ता पकड़ा। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि वह कम्युनिस्ट चीन नामक दीमकको नष्ट करना चाहते हैं — एक ऐसी नीति जिसमें पक्षमें त्रिटेन नहीं था, क्योंकि वह कोई ऐसा साहसिक प्रयत्न नहीं करना चाहता था, जिसका परिणाम सदिग्ध हो। प्रश्न भी इसी दृष्टिकोणका समर्थक था।

अमेरिकाके साधियोंका सोदा-मादा तर्क था। उपनिवेशोंमें ब्रिटिश और फ्रान्सको उनके कारण बहुत कठिनाई उठानी पड़ी थी, जिसका समझा उन्हें आबुलकारी बालरकी महायन्त्रमें बानेरी आशा थी। इस नये साहसिक कार्यमें सम्मिलित होनेका

अर्थ होता अधिक महायुद्ध और परिणामस्वरूप अधिक आकुलता ! क्योंकि महा-युद्ध का अर्थ था अमेरिकन विस्तार की मदद के लिए अधिक श्रमोत्पन्न खड़े करना ।

एक वाक्यमें हम कह सकते हैं कि साम्राज्यवादी शक्तियों की मित्रता में ठिपे हुए अन्तर बरफी तैलीयें बहने लगे थे । इसका परिणाम था एशिया और अब अफ्रीका को भी अपने स्वतंत्र आचरण के लिए अधिकतम अवसर प्रदान करना ।

इस पृष्ठभूमि में भारत के शासकों ने देशों रियामनोस विनाश पूरा कर डाला तथा नये गणराज्य के सुविधान को अपना लिया । ये दोनों परिवर्तन आपस में अच्छी तरह जुड़े हुए थे और केवल अनुकूल विरव-परिस्थिति में ही संभव हो सके ।

यह ठीक है कि हस्तान्तरित मत्ता मुन्द हो चुकी थी, पर अंग्रेजों के उत्तराधिकार ने प्राप्त आर्थिक परिस्थिति अब सफ़ाया हो रही थी । अन्ततः आदर्शवादी पौंडरावना बुरी तरह खर्च हो रहा था । देश का खजाना युद्धकालीन मुद्रास्फीति के दुष्परिणामों से अब भी अनुभव कर रहा था । अन्त में विदेशी व्यापारिक धारा बह रही थी । २६ जनवरी १९५० को स्वतंत्र सार्वभौमिक गणतंत्र की स्थापना के उपरान्त इस परिस्थिति में भीषणता नई समस्याओं उत्पन्न करनेवाली थी ।

भारत में होनेवाले परिवर्तनों को न दख पाने के कारण देश की कम्युनिस्ट तथा कुछ अन्य विरोधी पार्टियों की नीति में उलझल पैदा हो गई थी । वे अब भी नेहरू को भारतीय चांग काई शेक के रूप में देखते थे । उनके लिए कांग्रेस पार्टी आपल-अमेरिकी के इशारों पर चलनेवाले हथियार के रूप में थी । क्या उनके नेताओं ने विदेशी पूँजी के सम्बद्ध विशेष रक्षण प्रदान नहीं किये थे ? क्या उन्होंने एक के उपरान्त दूसरी शरणों को भेग नहीं किया था ? क्या उन्होंने समाजवादी दुनिशाने मित्रता स्थापित करने की सभावना को खत्म नहीं कर दिया था ? क्या भारत-कमिश्नों की अवस्था कुल मिलाकर बिगड़ी नहीं थी ? इस प्रकार के ऊपरी विवेचन तथा पश्चात्तों को एक दूसरे में सुवन्धित न करने की जिद ने कम्युनिस्ट पार्टी को अंधा कर दिया और राष्ट्रीय परिस्थिति में प्रकट होनेवाली नई शक्तियों को समझने से उन्हें रोक ।

एक युग का अंत

पर पूँजीजीवी परिवर्तित परिस्थितियोंके अनुसार पहलेमे ही आचरण करने लगे थे ; देशकी राजनैतिक और आर्थिक समस्याओंपर पूरा नियंत्रण रखनेवाली कांग्रेस पार्टीके अंदर विद्यमान इन तत्त्वोंका सुवर्ण फूटके द्वारा प्रतिबिम्बित हो उठा । मोटे रूपमें प्रगतिशील दलने अलग होकर अपना नया दल बना लिया था । असंतुष्ट लोगोंने प्रतिक्रियावादी सस्थाओंमें भाग लेना शुरू कर दिया । विचार और नीतिक सुवर्ण, उन्मूलक नेहरू और परिवर्तन विरोधी पटेलके दृष्टिकोणोंमें अंतर अधिक स्पष्ट था ।

पूँजीजीवियोंके अन्दर शक्ति प्राप्त करनेके सपनाका यह आरम्भ ही था, ऐसे सपनोंका जो स्वतंत्रताके उपरान्त वाले वर्षोंमें देशकी बाईं ओर मुका देण, समाजवादी दलोंमें मित्रता और सहयोग स्थापित करेगा तथा भारतके लाखों व्यक्तियोंके लिए नये क्षेत्र खोल देगा ।

दो प्रवृत्तियाँ

जब कभी आपसे दुविधा हो. उस सपने गरीब और सपने कमजोर अमीर चेहरा याद करो, जिसे आपने देखा हो और अपने मनमें पूछो कि जो कदम आप उठाना चाहते हैं, वह किसी प्रकार उसके लिए उपयोगी होगा और क्या वह उससे कुछ लाभ उठ सकेगा ।

— मो. क. गांधे

२६ जनवरी १९५०। १९३० से अनेकों बार वर्षके प्रथम मासकी इस तारीखको भारतके देशभक्त विदेशी शान्तसे स्वतंत्रता प्राप्त करनेके सपनेमें अपने आपको नये निरमे लानेकी राह देखनेके लिए इकट्ठे होते रहे हैं । वही पूर्व यही दिन था, जब अंग्रेजोंके प्रति आशा त्यागकर बंजिमने औपनिवेशिक स्वशासनके स्थानपर पूर्ण स्वराज्य अर्जना उद्देश्य घोषित किया था । इसी कारण जब भारत गणराज्य घोषित हुआ, तो उस घोषणाने निम्ने २६ जनवरीका दिन चुना गया ।

पर इस घटनाके मद्द्नकी बहुत कम लोगोंने समझा । अनेकों व्यक्तियोंके निम्ने इस गणनेत्र दिनका उत्सव केवल १५ अगस्त १९४७ को घटनेवाली घटनाकी औपचारिक स्वीकृति थी । सन्धमे परे इसमे वहाँ और कोई बाल नहीं हो सकती थी । २६ जनवरी १९५० से भारतने अपनी यात्रा स्वतंत्र सार्वभौम राज्यके रूपमें आरम्भ कर दी । सनाइतानरके उपराजवत्ते अन्तरिक्षके बर्षे समान हो चुके थे । एक नये युगका प्रारम्भ हुआ था ।

पर सन्ध सगारने ही इस नये गणराज्यका जन्म देखा । २७ जनवरीको श्रुत राज्यने प्रमुख पश्चिमी शक्तियोंके साथ उत्तरी अटलांटिक सैनिकी हविदारोंने तम करनेके समझौतेपर हस्ताक्षर किये और १ फरवरीको एक वर्षके भीतर उद्भूत वन बनानेके अरने विचारको व्यक्त किया । जिसके एक वममें अनेक अणु बमोंके बराबर विध्वंसक शक्ति होगी । १९५० के प्रथम चतुर्थांशने शीतयुद्धके 'सन्ध' और हुनियाके दलोंमें अधिक विभक्त होनेकी प्रवृत्तियोंके विस्फारको देखा । ४-

दो प्रवृत्तियों

शीतयुद्ध की नीति नई नहीं थी। यूनान और तुर्की की पौड़ी सहायता देनेवाला टूमेनका सिद्धान्त तथा आगे चलकर इसी सिद्धान्तके मार्शल-नीतिके रूपमें विरागने (वह भी द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्तिके कुछ ही वर्षोंके अंदर) अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितिकी भीषणताको रेखांकित कर रहा था। अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप दोनों स्थानों पर जनमत इस नीतिके आचरणसे न रोक सता और इसीसे अव्यवस्था तथा आध्यात्मिक शक्तिहीनता का अच्छा परिचय मिल जाता है।

यह सच है कि वामपंथी और शान्तिवादी, असंगठित स्वतंत्र तत्त्वोंके साथ मिलकर दूसरे युद्ध की दिशामें विश्वके बहावको रोकने का प्रयत्न कर रहे थे। पर उनके प्रयत्न इन दमनकारी तैयारियोंको निष्फल करनेके लिए बहुत सीमित तथा कम थे। फिर भी यह मानना पड़ेगा कि शीतयुद्ध की रणनीतिमें ही यह अग्रसर था कि वह स्वस्य दृष्टिकोणको दूषित कर सके।

उदाहरणके लिये स्पष्ट उत्तेजनाके परिणामस्वरूप समाजवादी दुनियाके देशोंने भी अपनी सीमाएँ सुरक्षित करनेके लिये सन्नद्धतासे कदम उठाने शुरू कर दिये। निर्धारित साम्यवादी मार्ग छोड़ना एक कमजोरी तथा दगावाजी का चिन्ह माना गया। सोवियत संघ द्वारा टीटो प्रश्नपर विचार तथा पूर्वी यूरोपमें प्रस्तुत होनेवाले अनेक राजनैतिक मुद्दोंमें यह इंगित कर रहे थे, कि शीतयुद्धसे मुक्त समझे जानेवाले देशोंमें भी क्या हो रहा है। यह सही है कि इन साम्यवादी अंतर्द्वंद्वोंमें और भी अनेक समस्याएँ उलझ रही थीं, ऐसी समस्याएँ जिन्हें अच्छी तरह समझना अभी बांकी था। पर इसका मुख्य कारण बढता हुआ भय था।

और जिस प्रकार शीतयुद्धके कारण राष्ट्रोंके समूह एक दूसरेके विरुद्ध खड़े हो गये थे। उन्ही प्रकार राष्ट्रोंके अंदर भी तीव्र मतभेद बढ़ गये थे। फासिस्ट शत्रुमें संयुक्त मोर्चा लेनेवाली एकजाने भावना मर चुकी थी। और उसका स्थान अनेक समस्याओंसे लेकर होनेवाले अनेक दोषारोपणोंने ले लिया था, जिसके कारण इस प्रमुख महत्वपूर्ण प्रश्न की ओरसे ध्यान हट गया कि बीगदीं शताब्दियोंमें बिना शान्तिके प्रगति संभव नहीं है और उसे पानेके लिए सह-अस्तित्वके सम्य उपाय ढूँढने चाहिये।

आज हम परस्पर इतने अधिक सन्निहित और एक दूसरेपर आश्रित हैं कि हम यह नहीं कह सकते कि एक जगह घटनेवाली घटनाएँ दूसरी जगह असर पड़ना जरूरी नहीं है। शीतयुद्धको अंतमें एशियामें प्रविष्ट होना ही था। चीनकी घटनाएँ और एक विस्तृत क्षेत्रमें साम्यवादका प्रसार एशियामें शीतयुद्ध—नीतिके प्रारम्भ-बिंदु नहीं थे, जैसा कि कुछ लोगोंका विश्वास है। क्या कम्युनिस्ट गणराज्यकी स्थापनामें पहले जापानके राष्ट्रीयकरणका निर्णय नहीं हो चुका था। क्या संयुक्त राज्य अमेरिका प्रशांत महासागरमें स्थित सैकड़ों द्वीपोंको 'नये टुकड़े विमान-बाइकोमें' परिवर्तित करनेके लिये अपने अधिकारमें नहीं ले चुका था? क्या अंग्रेज और फ्रान्सीसी पूर्वी और पश्चिमी एशियामें स्थित अपने उपनिवेशों और अश्रित राज्योंमें अपना अधिकार कायम रखनेके लिए बुरी तरह नहीं लड़ रहे थे? और क्या विदेशी सामंजस्यभार उत्तर ध्रुवमें बँटनेवाली भाग्य, पाकिस्तान, ब्रह्मा और हिंदीशिया जैसी एशियायी सरकारोंको सहायता नानकारी साधनके द्वारा नष्ट करनेका यत्न नहीं किया गया था? सफल होनेके लिये शीतयुद्धकी रणनीतिका समस्त विश्वकी दृष्टिमें निर्धारण आवश्यक था। और संयुक्त राज्य अमेरिकामें इस चीनकी अन्धवी तरह देख लिया था।

हस्तक्षेप करनेवाली विदेशी फौजोंने नवीन स्थापित मोवियन राज्यपर आक्रमण किया था। उन्ही प्रसार २७ वर्षके अन्तर्वर्द्धके पश्चात् स्थापित कम्युनिस्ट चीन भी दगाव और बदमानोंका शिकार बनाया गया। उनके समुद्री तटकी उन राष्ट्रोंकी नौसेनाओं द्वारा घेराबंदी कर दी गई, जिनके साथ उसकी कोई लड़ाई न थी। चांग काई शेक पीछे हटकर अपने द्वीपमें बैठे हुए संयुक्तराज्य अमेरिकाद्वारा निर्धारित विस्फोटक रोल खेलने लगे। अब होनेवाली सन्धि हस्तक्षेप करनेकी प्रारम्भिक तैयारी थी। इसी बीच साम्राज्यवादने चीनके दक्षिण चीनसागरमें एक आक्रमण स्थान बनानेके लिये पट्टयंत्र रखा। जापान भी साम्राज्यवादका कार्य सम्पन्न करनेके लिये उत्साहित किया गया।

अमेरिकन युद्धनीतिज्ञोंने अभी यह तथ्य नहीं किया था कि इन शीतयुद्धकी दूरीमें गरम युद्धके रूपमें परिवर्तित किया जाय या एशियामें। निर्णय तो एक सीधी पूर गणना-पर आश्रित था। अर्थान् युद्ध बहों जागी करना चाहिये, जहाँ वह धन, जन और आयुधों,

दो प्रवृत्तियाँ

विशेष रूपसे जनमें सजने कम कीमतमें सम्पन्न किया जा सके । और इस कारण १४ फरवरी १९५० को जब कि एक ओर सोवियत संघ कम्युनिस्ट चीनके साथ ३० वर्षीय मित्रता और सहयोगकी सन्धि हस्ताक्षर कर रहा था, वहीं वैश्वक्रमें १७ अमेरिकन कूटनीतिज्ञ तथा एशियायी दलोंके प्रभु दक्षिणपूर्वी एशियाकी आर्थिक सहायताके प्रश्नपर बातचीत करनेके लिये एकत्रित हुए । इस निर्दोष सन्द-
जालमें उनको एक परिचित जाल दिखाई पड़ रहा था, उन्होंने ऐसी सहायताका प्रभाव योरोपमें देखा था ।

१५ मई तक मिट्रिश राष्ट्रमंडलके ७ देशोंके प्रतिनिधि मिडनीमें दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशियायी देशोंमें साम्यवादके विरुद्ध उभाड़नेकी सफल योजनाकी प्रारम्भिक कार्यवाही निश्चित करनेके लिए एकत्रित होने लगे थे । शीतयुद्ध बदलेकी भावनाके साथ अपने परिचित रूपमें एशियामें प्रवेश पा गया था ।

भारतीय गणराज्यकी सरकार शीतयुद्धकी इन बालोंके प्रति पूर्णरूपेण अलगरूक थी, पर इस समय वह अधिक हैरान नहीं थी । प्रमुखरूपमें वह मिट्रिश राष्ट्रमंडलकी सदस्यताके कारण विरक्त थी । उसे आशा थी कि इन व्यवस्थाके द्वारा वह इस भयंकर परिस्थितिमें साक निकल सकेगी । आखिरकार ब्रिटेनने क्या कोई शौकके साधियोंमें संयन्ध बिच्छेद करके क्या चीनके गणराज्यमें नियमित स्वीकृति प्रदान नहीं की थी, एक ऐसा कदम जिसके बारेमें दिल्ली वालोंने सोचा कि यह उनके हठका परिणाम था । इसके अतिरिक्त ब्रिटेन भारतका समर्थन इस आशाने कर रहा था कि वह साम्यवादी दुनियामें युद्धमें फैलनेकी अमेरिकानी जल्दवाजीकी नीतियोंमें एक अवरोध उपस्थित कर सके । ब्रिटेनकी मजदूर पार्टी भी थोड़े बहुमतमें चुनाव जीत चुकी थी ।

भारत सरकार सोच रही थी कि एशियामें उनकी स्वतंत्र स्थितिका उपयोग साम्राज्यवादसे लाभदायक शाने स्वीकार करना लेनेमें हो सकेगा । अप्रैल १९५० में नेहरूजीकी घोषणाका यही अर्थ था, जब उन्होंने कहा कि “ क्या मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित कर सकता हूँ कि जिस प्रकारकी नीति हम अपना रहे हैं, वह सटस्थ प्रतिरक्षात्मक या नकारात्मक नीति नहीं है । ” यह साम्राज्यवादियोंके

लिए इशारा था कि उन्होंने यदि अपनी नीतिमें परिवर्तन नहीं दिया, तो प्रतिक्रियाके लिए अन्य मार्ग मौजूद हैं।

इन प्रकरणा दृष्टिकोण धीरे-धीरे बनने लगा था। कंप्रिमेके नेना अपने अपने कहने लगे थे कि भयप्रस्त होनेकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि तत्स्थानाके लचीले संयोजरण द्वारा सामाज्यवादकी भी घरेलू आर्थिक उन्नतिमें सहायता देनेके लिए बाधित किया जा सकता था। यह एक प्रकारकी मीठी-मीठी बात थी और भाग्यही इसके सबन्धमें किसी प्रकारकी हिचकिचाहट क्यों होनी चाहिए।

मस्तिष्कमें इस प्रकारके विचारोंके साथ १६ जनवरीको कंप्रिमे कार्यकारिणी समितिने भारतके लिए एक विशाल आर्थिक योजना प्रस्तुत करनेकी एक 'योजना आयोग' नियुक्त करनेकी सिफारिश की।

वास्तवमें मत्ता-हस्तान्तरण करनेमें आर्थिक समस्यापर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त देशके विभाजनके परिणामस्वरूप पाकिस्तानमें आनेवाले लाखों निष्कनगार्थियोंके कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बहुत कुछ अस्त-व्यस्त हो गई थी। कश्मीर युद्ध, विशेषरूपमें उसके व्यय (लगभग चार लाख रुपये प्रतिदिन) ने समस्या और भी विगड़ गई थी।

सरकारी अनुमानपर आधारित विभाजनके तुलनाओंके कुछ आकड़े शरणार्थियोंने आर्थिक समस्या हमें दिखाता सकते हैं। केवल पश्चिम पाकिस्तानमें शरणार्थियों द्वारा भूमिके अतिरिक्त छोड़ी गई अन्य अवल संपत्ति लगभग १०० करोड़ रुपयोंकी थी अर्थात् मुसलमान शरणार्थियों द्वारा भारतमें इस प्रकार छोड़ी गई संपत्तिमें पंचगुनी। मुसलमान विमानों और जर्नीदारों द्वारा भारतमें १० लाख एकड़ घटिया जमीनके बदले १० लाख या एक करोड़ एकड़ मिर्बाईवाली जमीन पाकिस्तानके हाथमें पहुँच गई थी। अन्य दावोंकी बराबर जीव नहीं हुई है, पर पूरा हिमाचल लगानेके उपरान्त चल और अचल संपत्ति का अगर भारत द्वारा ग्रहण करनेके लिए बहुत अधिक निरुत्तेज। इन आकड़ोंमें यह बात समझमें आ जाती है कि उस समय पहली बार सामने आनेवाली शरणार्थियोंका समस्या धितानी अधिक उलझी हुई थी। उसको मुसलमानोंकी सन्तान भी सीमित थी।

दो प्रवृत्तियाँ

पाकिस्तानके अधिनायके पञ्जाबका बडिया गेहूँ और कपास पैदा करनेवाला भाग तथा बंगालका जूट-क्षेत्र था। इन दो बटु मन्वोंने भारतमें जहाँ एक ओर जनसंकट उपस्थित कर दिया, वहाँ दूसरी ओर रई और जूट उद्योगोंके लिए भी दूसरा संकट उत्पन्न कर दिया। क्योंकि कच्चे मालके मुख्य स्रोतोंने उनका मन्वन्ध विच्छेद हो गया था। अचानक अधिक ख़मीन पर जूटरी खेती करनेका अर्थ अन्नकी कमीको बढ़ाना था। “एक समयका भोजन छोड़ो” के नारे और जनसंख्यापर नियंत्रण, के अलावा इस समस्याका कुछ विश्वमनीय इलाज न था।

यातायात भी गंभीर रूपमें अस्तव्यस्त हो गया था। पहले कर्कोची और बम्बई दोनों बन्दरगाह उत्तरी भारतका यातायात संभालते थे। अब केवल बम्बई रह गया था और बन्दरगाहका अवरोध आगानीमें दूर नहीं किया जा सकता था, उन दिनोंमें भी नहीं, जब किसी प्रकारका आर्थिक और व्यापारिक विस्तार नहीं हुआ था। आशा यही थी कि ज्यों-ज्यों विमानकी गति बढ़ेगी, यातायातके अधिक अवरोध उत्पन्न होंगे। इनमेंसे कुछ तो विभाजनके आर्थिक परिणाम थे और सरकारने यह समझ लिया कि इनका शीघ्रतापूर्वक कोई हल संभव नहीं है। इसमें समय लगेगा और भारतकी प्रगतिके मार्गमें इन स्तब्धताओंको हटानेके लिए योजना बनानी पड़ेगी।

परन्तु शरणार्थी समस्या और कारभीरके मामलेपर शीघ्र ध्यान देना आवश्यक था। यह समस्याएँ विस्फोटक थीं और साम्प्रदायिक संस्थाओं तथा सामंतवादी अवशेषों द्वारा आगानीमें इनका लाभ उठाया जा सकता था। यह प्रश्न एक दूगरेतो जुड़े हुए थे। क्योंकि उनकी उत्पत्ति भारत और पाकिस्तानके तनावके कारण हुई थी।

इन बातोंकी घेतायनीके बावजूद भी कि साम्राज्यवादी शक्तियाँ इस मध्यस्थताका लाभ स्वयं उठाना पसंद करेंगी, कारभीर राष्ट्रपक्षके हाथों सौंपा जा चुका था। जनरल ए. जी. एम्. बेन्टन द्वारा मध्यस्थताके प्रथम प्रयत्न विफल होनेकी सूचना ७ फरवरी १९५० को दी जा चुकी थी। अब यह दिखाई पड़ता था कि शायद यह प्रक्रिया जारी रहेगी, क्योंकि ऐसी विदेशी शक्तियाँ जिनका इसमें स्वार्थ था, इस उलझनको बनाये रखना चाहेंगी, जिससे भारत और पाकिस्तान परस्पर विभाजित बने रहें।

सामान्य स्थिति

कॉंग्रेस पार्टीको भी यही डर था और इसी कारण वह पाकिस्तानके साथ अपने सम्बन्धोंको परस्पर मिलकर मुबारनेकी इच्छुक थी। उनसे यह भी अनुभव कर लिया था कि परिचयी पाकिस्तानने सभी हिन्दू निकाल देने गये हैं और ऐसी ही कुछ परिस्थिति पूर्वी पाकिस्तानमें तैयार की जा रही है। पाकिस्तानके प्रधानमंत्री लियाकत अली खानको दोनों देशोंमें सम्मान्यत मामलोंपर बातचीत करनेके लिये २ अप्रैलकी दिल्लीमें आमंत्रित किया गया। बहुत कम लोगोंसे किसी प्रकारकी आशा थी, क्योंकि कश्मीरके प्रश्नका उपयोग पाकिस्तानमें राजनैतिक रूपसे डावाडोल सरकारका पक्ष हट करनेके लिये किया जा रहा था, जिस सरकारका जनताकी स्थिति मुबारनेका बेहद इरादा नहीं था।

फिर भी भारत और पाकिस्तानके बीच एक समझौतेपर हस्ताक्षर हो गये। इससे पूर्वी पाकिस्तानसे आनेवाले निष्क्रमणार्थियोंका दबाव कम हो गया और आपसके सर्वधर्मों एक हद तक सामान्य स्थिति आई। अप्रैलने अन्तमें नेहरूजी एक जवाबी यात्रा करौचीके लिये हुई। बातचीतके इन दो स्थितिनीलोंने बीचके समयमें राष्ट्रमण्डले काश्मीरके लिये ओवन डिक्शन नामक एक अन्य मध्यस्थ नियुक्त किया था।

अब कॉंग्रेसके नेताओंने अपना ध्यान भारत वानियोंकी अन्त-चष्ट और मकानकी समस्याओंकी ओर आकृष्ट किया और हमेशाकी तरह प्राथिक मामलोंमें अपना ध्यान लगाने ही उमकी हत करनेके मार्गमें मतभेद दिखलाई देने लग। उन्मूक्त तथा परिवर्तन विरोधी वही सैद्धान्तिक मतभेद, जिसमें कॉंग्रेस पार्टी इस शताब्दीके प्रारम्भमें तथा उमकी दूसरी, तीसरी और चौथी दशकियोंमें जकड़ी रही थी।

यह अन्तर पहले महात्मा गांधी द्वारा दूर कर दिये जाते थे, जिनकी भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसमें अनेक दलोंका नाजुफ शक्ति सन्तुलन रखनेके लिये बड़ी विनियम, पर आवश्यक स्थिति थी। लेकिन वे भी इन विचारधाराओंके व्यक्तीकरणको नहीं रोक पाते थे।

सभी राजनैतिक विचारधाराओंका प्रतिनिधित्व करनेवाली भारतीय राष्ट्रीय कॉंग्रेसके विकासका अध्ययन करने पर यह दिखलाई पड़ेगा कि दो स्पष्ट दृष्टिकोण

दो प्रवृत्तियाँ

पनप रहे थे। एक ओर परिवर्तन विरोधी, दक्षिण पक्षियोंका कहना था कि साम्राज्यवादमे सघर्ष लेते समय एकता कायम रखनेके लिये आर्थिक समस्याओंको पृष्ठभूमिमें छोड़ना चाहिये। दूसरी ओर उन्मूलक कामगारी अग्निक जोरदार वचा थे, जिनका कहना था कि इस सघर्षका आधार आर्थिक होना चाहिये। ज्यों ज्यों आंदोलन तीव्रतर होता गया, उन्ही अनुष्ठानमें यह दृष्टिकोण शक्तिशाली होता गया। और यद्यपि इन दोनोंमें एक प्रकारकी एकता रखी गई थी, पर १९४२ में दूसरी वार्तोंके साथ युद्ध-विषयक दृष्टिकोणके कारण साम्यवादी विचारधाराका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसमें अलग होना दरअसल विभिन्न पक्षोंके इस सघर्षको ही बतलाना था। इस सघर्षको मार्क्स-विचारक अच्छी तरह न समझ सके और न उसका विवेचन ही कर सके।

जो लोग हमेशा यही चिन्तानेके आरो हैं कि वर्तमान कांग्रेस पार्टीने इसकी समझबादी धीरेधीरे बतलाउं है, उन्हें चाहिये कि पने पलटकर कांग्रेसके उन दिनोंके पुराने घोषणापत्र पढ़ें, जो शक्ति प्राप्त करनेके लिये आंदोलन जारी था। यह सच है कि यह केवल उन आदर्शियोंकी घोषणा थी, जिन्होंने अब तक शासनकी बागडोर नहीं सभाती थी, पर वह एक संपूर्ण आंदोलनकी जागरूकताका स्वर बतलाते हैं। गांधीजी और पटेल जैसे परिवर्तन-विरोधी नेताओंको भी कामगारियोंके अनेक निर्यात आंदोलनकी जड़ने आनकाल भारी दमकके कारण मानने पड़े।

स्वतंत्रता कांग्रेसके अंदर उस समानवादी विचारधाराके प्रतिपादक जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाषचंद्र बोस थे। और जो कुछ वे कह रहे थे, उमे उस समानवादी और साम्यवादी विचारधाराका एक अश समझना चाहिये, जो समान देशमें फैल रही थी।

१९०७ में कांग्रेसके मूल अधिवेशनमें ही कांग्रेसके नरम और गरम दलोंमें मतभेद हो गया था। उन दिनों गरम दलका नेतृत्व तिलक, लाजपत राय और आरविंद घोष जैसे दिग्गज कर रहे थे। नरम दल द्वारा, जिनका जोर था, अपने अधिक बोलनेवाले साधियोंके उपर छड़ी उछालनेके लिये हर प्रकारका ढंग

उन्मूलनवादी विचारधारा

काममें लाया गया। पंडालमें पूरे अधिवेशनके दौरानमें व्यवस्था बनी रही। बादविवादके स्थानपर मराठी चप्पलों तकको कानमें लाया गया।

यह खींचतानी चलती रही। कभी कभी तो यह दवाव मालूम भी नहीं पड़ता था। उसके उपरांत गांधी-दरबिन समझौतेमें स्वीकृत शर्तोंके घोड़े ही दिन बाद मार्च १९३१ में कांग्रेसके कोंचो अधिवेशनमें रटिशोणका अंतर स्पष्ट रूपमें दोखने लगा। जवाहरलाल नेहरू और सुभाषचंद्र बोसके नेतृत्वमें उन्मूलनवादी वामपंथी इन विचारधाराको माननेके लिये तैयार नहीं थे कि इस समझौतेकी वस्तुतः सत्याग्रह आन्दोलनकी निफलताके कारण पड़ी थी। इसके अनिश्चित गम्भीरता सैनिकों तथा भगतसिंहकी बात भुला दी गई थी। नेहरूजी शारीरिक कष्ट तथा मानसिक चंचल सहन कर रहे थे। बोस वामपंथी घोषणापत्र पढ़ने लगे। क० मा० सुरी तक ने लिख डाला कि, “करोँचीकला गांधीजीका अग्रण यदि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दिया जाना तो उसेजना उत्पन्न कर देना।”

यह उत्तेजना इतनी अधिक थी कि गांधीजीने उन्मूलनवादी विचारधाराने समझौता करना ही अधिक उचित समझा। प्रमुख रूपसे नेहरूकी प्रेरणाने मौलिक अधिकारों तथा राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थाके बारेमें एक प्रस्ताव पास किया गया। समस्त कांग्रेसको आर्थिक उन्मूलनवादी बनानेकी ओर यह एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि जो मिदयन्त स्वीकार किये गये, उसके अन्दर प्रमुख उद्योगों और यन्त्रालयों का राष्ट्रीयकरण, धन-अधिकार तथा कृषिविषयक मौलिक सुधार सम्मिलित थे। उसके बारेमें क० मा० सुरीने कहा है कि “इसमें पूँजीजीवी घबरा उठे, पर कष्ट मार्क्सवादियोंको चुनपु नहीं किया जा सका।” लेकिन वे भी यह स्वीकार करते हैं कि यह प्रस्ताव इस कारण स्वीकृत हुआ, क्योंकि “वह उदंड पंडित जवाहरलाल नेहरूका लादला बैरा था।”

पाँच साल बाद लखनऊ अधिवेशनमें यह रटिशोण अधिक जोर देकर प्रतिपादित किया गया। १९३६ से १९४० तक राष्ट्रीय योजना समितिके कार्यका, यह मिदयन्त आधार बना, जिसका सभापतित्व नेहरूने किया था और उनके वर्तमान निर्णयोंमें निश्चित रूपसे इस पूर्वकालके बीजाणु हैं। अच्छी तरह कांग्रेसी

दो प्रवृत्तियाँ

विचारधाराके इन कामगामी उन्मूलक तत्वोंको समझना इस कारण जरूरी है क्योंकि आत्मीयताके बर्णनोंमें साम्यवादी और समाजवादी दलोंके अलग होनेके उपरान्त भी इनका बना रहना अधिक महत्वपूर्ण है, विशेष रूपसे उस समय जब कि हम वैधिस पार्थिक वर्तमान रूपको समझना चाहते हैं।

१९५० तक जवाहरलाल नेहरू तथा बल्लभभाई पटेल ने दो प्रभावशाली व्यक्ति वैधिस पर छुआये हुए थे। एक पार्थिक दो अन्यतम अभिवक्तियों द्वारा प्रणिहित परस्पर विरोधी विचारधाराओंकी अंतर दूर करनेके लिये गांधीजी अत मौजूद नहीं थे, जिनके प्रति नमस्त पूजाजीवियोंका एकनिष्ठ विश्वास था और जो उसकी अत्यंत शक्तिशाली ईद्रियके समान काम करती थी।

यह दोनों व्यक्ति विचार, विश्वास तथा माधनोंकी दृष्टिमें पूर्णरूपेण अलग-थलग थे। वे दोनों व्यक्ति राष्ट्रीय आंदोलनके सचकोंके दरम्यान ही राजनैतिक जीवनमें ऊँचे उठे थे, जो गांधीवाद तथा वर्तमान राजनैतिक विचार तथा व्यवहारमें मिलकर बनी एक आश्चर्यजनक उपज थे। और निरुद्ध पूर्वमें स्वतंत्र होनेवाले भारतमें एक दूसरेका अनादर नहीं कर सकते थे, कि वह पूजाजीवियोंमें वर्तमान शक्तिका अनुदान प्रतिबिम्बित कर रहे थे, जिस वर्गके पास आसन्न राजशक्ति थी।

सुंदर सक्रिय नेहरू जनताकी प्रतिद्ध वदनीय मूर्ति बने हुए थे। गम्भीर सोच समझकर बद्ध रखनेवाले पटेलका प्रेमने अधिक भय माना जाता था। नेहरू विदेशमें शिक्षित, उदार और उन्मूलनवादी थे। पटेल पक्के कृषक, निरदुरा और शान्ति कुशल थे। एक मानव और पटनाओंके इतिहासका विद्यार्थी हमेशा अपने अभिनयके प्रति और उस अभिनयकी भविष्यमें जन्म लेनेवाले ऐतिहासिकों द्वारा मूल्य निर्धारणके प्रति हमेशा जागरूक था। दूसरोंके मन और सिद्धान्तसे घृणा थी और प्रमुख रूपमें शक्ति और उसके व्यवहारिक सगुणने मतलब था। नेहरू अपना प्रभाव लोगोंमें समझनेसे प्राप्त करते थे। पटेल अपनी पकड़ राजनैतिक रूपमें बनाये रखना चाहते थे। राजकीय व्यक्तिका मार्क्सवादमें दखन था और लेनिन उसका आदर्श था। कृषक ऐसे विचारोंका कहर शत्रु था। दोनों भारतको शक्तिशाली तथा सुख बनानेमें कृत मरुत थे। यह उन दो व्यक्तियोंका मत वैधिस

था, जो एक दूसरेके प्रतिकूल आर्थिक सिद्धान्त प्रतिपादित कर रहे थे, जिसने बरेलू मोर्चेपर कांग्रेसकी कार्यवाहियोंको हास्यास्पद बना दिया ।

बल्लभभाई पटेल हमेशा साधन संपन्न वर्गके प्रमुख भागके हितोंके समर्थक थे । उनकी यह धारणा थी कि केवल यही वर्ग भारतपर शासन कर सकता है । उनके लिये प्रगति और आर्थिक समानताके नारे केवल निर्वाचनके हेतु ही काममें लाई जानेवाली चालें थीं । कृषक और कामगार केवल धन पैदा करनेके लिये बनाये गये थे और यह कार्य कुशलतासे वह तभी संपादित कर सकते थे, जब उनकी देख-भाल राज्यके उदार धनी ट्रस्टियों द्वारा की जाय । उनका गमराज्य यही था ।

पटेलकी यह धारणा थी कि यदि कोई वर्ग इन बड़े पूँजीजीवियोंके अस्तित्व पर हमला करनेकी हिम्मत करता है, तो शीघ्रता तथा कठोरतासे उसका दमन करना चाहिये और यही सिद्धान्त उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रमें स्थानांतरित किया, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह विश्वास था कि कोई साम्राज्यवादी या बड़ी शक्ति भारतकी उपनिवेश सहायता देनेमें मना नहीं करेगी । वह शक्तिका आदर करते थे और उनके लिये संयुक्त राज्य अमेरिका शक्तिशाली था ।

ऐसे देशमें जो नग्न और भूखा दोनों था तथा जो केवल विहीके नवीन और प्रेरणात्मक संदेशकी राह देख रहा था (ऐसी संदेशकी जिसमें असीमित शक्ति हो, जिससे भारतीय पूँजीवादी एकाधिकारधर वर्ग खबनेवालोंकी योजनायें विफल हो सकें), नेहरू बिना प्रभाव डाल सकते हैं, इस ओरने पटेल अंधे नहीं थे । चूंकि वह नेहरूपर नियंत्रण नहीं रख सकते थे, इस कारण उन्होंने अपना ध्यान अपने पामवाले एक मात्र अस्त्र-काँग्रेस पाटाकी मशीन-की ओर दिया ।

उन्होंने काँग्रेसमें ऐसे नेताओंको भरना शुरू कर दिया, जो उन्हींकी तरह सोचते थे तथा सफ्टकॉलीन परिस्थितिमें जो उन्मूलनवादी नेहरूने एक जाओ कह सकें । इस कालमें उनकी सहायता स्वयं नेहरूने ही की । नेहरूने काँग्रेस सत्तापर अपना नियंत्रण दृढ़ करनेके लिये कोई कदम केवल इस कारण नहीं उठाये कि उन्हें दर था कि वही वह सत्ता स्वयं उनका ही किसी दिन नियंत्रण न करने लगे । वे अपने एकात्मिक संघर्ष और एकात्मिक सफलताको पसंद करते थे । यह अपने

दो प्रवृत्तियाँ

आदर्शोंके प्रति दृढ़ विश्वास रखनेवाले व्यक्तिकी रोमांटिक पहुँच थी, लेकिन ऐसी पहुँच जिसके अन्तर राष्ट्रके लिये भारी भुक्त विद्यमान था।

आरम्भमें कौमेसमें विद्यमान इन दोनों प्रवृत्तियोंके प्रतिवादकोंका सामंजस्य नष्ट करनेके लिये बहुत कम करण थे। दोनों इस बातमें सहमत थे कि हस्तान्तरित सत्ताकी दृष्टि किया जाय। उनकी योजनाओंमें सामतवादको कोई स्थान नहीं था। ब्रिटेनसे सम्बंध सौहार्दपूर्ण होनेके अनिश्चित और अन्य किसी प्रकारके नहीं हो सकते थे। भारतको सोचने और साँस लेनेके लिये अवकाश चाहिये था और एक टीली तटस्थता उसका सही इलाज था, पर भारतकी आर्थिक प्रगतिके बारेमें इस प्रकारका अस्पष्ट दृष्टिकोण नहीं चल सकता था।

पूँजीजीवियोंके प्रधान दलने जिनका प्रतिनिधित्व पटेल कर रहे थे, यह स्वीकार कर लिया कि प्राकृतिक साधनोंका तत्कालीन विकास जरूरी है, जहाँ स्थानीय व्यापारियोंकी दिव्य मालूम पड़ती हो, उन क्षेत्रोंमें विदेशी पूँजीका प्रभाव खत्म करना चाहिये, जमींदारी निःसंदेह पुरानी पड़ गई है तथा किसानों और मजदूरोंके जीवनकी अवस्थाओंमें कुछ सुधार करना ही चाहिये। पर भारतके बड़े व्यापारियोंके हितोंमें ऊपर राज्यकी समझनेके हर प्रकारके प्रयत्नना दृढ़तासे विरोध करना चाहिये।

नेहरूको यह दृष्टिकोण मानना पड़ा। ऐसा करना उनके लिये कुछ कठिन भी नहीं था, क्योंकि १९१० के मध्य तक जो परिस्थिति बनी हुई थी, वह चाहती थी कि इस मामलेकी धीरे-धीरे सुलझाया जाय। इस कारण नेहरूने जो योजनाएँ और सिद्धान्त तैयार किये थे, उनका शीघ्र ही मजाक इस आधारपर उड़ाया जाने लगा कि प्रश्नको निदालोंके दायरेमें ही मुन्यमानेका प्रयत्न नहीं करना चाहिये। अधिकतर नेहरू ही ऐसी आलोचनाका नेतृत्व करते थे।

विलंबित आर्थिक मॉर्गेके समर्थनमें किसी प्रकारके आंदोलन या असबद्ध प्रयत्नोंकी कूरतापूर्वक कुचलनेके साथ-साथ कौमेस नीतिके इस पहलूका कम्प्यूनिस्ट तथा अन्य वामपंथियोंने यह अर्थ निकाला कि यह स्वतंत्रता आंदोलनके सिद्धान्तोंके साथ स्पष्ट विश्वासपात है। जिस समय यह बातें सामने आईं, इनका कुछ अन्य अर्थ निकलना सम्भव न था। जर्मनीके भूखे किसानोंकी भूमि का दृक्ता प्राप्त करनेकी

भविष्य का निर्माण

मोंगको छुट्टा दिया जाता था। इसके अनिश्चित जमींदार पैंजीपति तथा श्रृषक अपनी भूमि परमे जोतनेवालोंको बेदखल कर सकते थे। मजदूरोंके संपर्कके अधिकतर पुलिसके अन्यायोंमें कुचल दिया जाता था। सफेद पोश कर्मचारियोंकी भी अवस्था कुछ अच्छी नहीं थी। विदलीय समझौतों, लाभ बंटनेकी योजनाओं तथा औद्योगिक मतभेदोंके शान्तिपूर्ण समाधानोंके द्वारा कामगारोंको उनके नैरारापूर्ण भाग्यकी ओरसे विमुख नहीं किया जा सकता था।

यह भी ध्यान रखना चाहिये, यह समान विस्फोट उन समय हो रहे थे, जब अन्नकी स्थिति बिगड़ गई थी, जब वस्तुओंके भाव बढ़ रहे थे तथा जब कांग्रेस इस बिगड़ती हुई परिस्थितिमें सुभालनेके लिये बहुत कम प्रयत्न कर रही थी। जनताके इस दिशाके संपर्क नैतृत्व करना कामगारियोंका प्रमुख कर्तव्य था, पर यह तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रकी गतिमान परिस्थितियोंको अच्छी तरह समझे बिना, ऐसा करना बहुत नाजुक था। ऐसे गतिशील तन्त्र ही भविष्यका निर्माण करनेवाले थे।

कॉंग्रेस की आर्थिक नीति

सम्भावना है जैसी ब्रिटेन और अमेरिका के पूँजीजीवियों ने की थी। इस विषय पर साम्राज्यवादी क्षेत्रों में मतभेद नहीं था। मत्तारा हस्तांतरण देश के विभाजन के बाद ही सम्भव हुआ, यही तब उन भारी सुझावों और इशारा कर रहे थे, जिनके कारण भारतीय पूँजीपतियों के दिवा स्थान नष्ट हो जायेगा।

स्पष्ट ही भारतीय व्यापारियों और औद्योगिकों ने प्रथम कदम यह लेना चाहिये था कि विदेशी पूँजी को अब पुनः मुक्ति नहीं प्राप्त हो सके। यह भाग इस कारण जरूरी थी कि कॉंग्रेस पार्टी द्वारा यह विश्वास दिलाया जा रहा था कि विदेशी पूँजी न तो ली जायगी और न उसे देश के बाहर ही खदेड़ा जायेगा।

फरवरी १९४८ को अरानी बचुता में श्री नेहरू तबने यह कहा था कि “आर्थिक दृष्टि से कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होगा। जहाँ तक सम्भव होगा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायेगा।” आगे १६ अप्रैल १९४८ को औद्योगिक नीति-विषयक सरकारी प्रस्तावने इस विषयों अधिक स्पष्ट कर दिया। इस प्रस्तावने बनलाया गया था कि राष्ट्रीयकरण पीछी सामान, अणु-शक्ति तथा रेलवे (जिनका राष्ट्रीयकरण हो चुका था) तक ही सीमित रहेगा और कोयला, लोहा, इस्पात तथा अन्य महत्वपूर्ण उद्योगों के विषय में “सरकारने यह निर्णय लिया है कि अगले १० वर्ष तक मौजूदा उद्योगों में पनपने दिया जाय”। और “शेष औद्योगिक क्षेत्रों को सामान्य रूप से व्यक्तिगत प्रयोजन के लिये उन्मुक्त रखा जाय”।—कमने कम कम समय तक जब तक कि इस परिस्थितिका पुनरावलोकन न हो।

इन सबका अर्थ यह था कि भारत में चलनेवाले बड़े-बड़े साम्राज्यवादी एकाधिकारों को देशी ममकारों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के समक्ष अवसर प्रदान करने का विश्वास दिलाया गया था। फिर भी अनेक पर्यवेक्षक इस प्रस्ताव के राष्ट्रीय कृत औद्योगिक विद्वानों के अंश के उपबधोरी निंदा करते रहे। कोयला, लोहा और इस्पात, जहाज निर्माण, वायुयान-निर्माण, तार, टेलीफोन और बैतार के तार के उपकरणों के विषय में हल्का-भा इशारा करने का स्पष्ट अर्थ यह बतलाना था कि तत्कालीन सरकार किन दिशा में मोच रही है। यह सब है कि सरकारी प्रवक्त्यों ने इस ओर ध्यान आकर्षित नहीं किया, पर जैसा हम आगे चल कर देखेंगे, कि यह प्रस्ताव आगे आश्चर्यजनक आर्थिक प्रगति की कुंजी बन गया।

विदेशी पूँजी को विस्थाप

प्रस्तावने सुझावना साक्षात्कारों में भी न हो जायें, इन इनके कारण उन्हें पुनः विभाग दिखाने का प्रस्ताव किया गया। एक व्यावसायिक टिप्पणी में यह घोषणा की गई, कि “सरकार द्वारा वैयक्तिक क्षेत्र में हमारी सीमाओं और नियंत्रित करने की सम्भावना पर यत्न बहुत विविध है, लेकिन जिस नीति को घोषणा हुई है उसमें हमारे और कोई इरादा नहीं है।”

उसके उपरान्त रहे-मड़े व्यवस्थाओं को समाप्त करने के लिए टिप्पणी में पुनः विभाग दिखाना गया था, कि “यह प्रस्ताव विदेशी पूँजी को और भारतीय उद्योगों में उनके प्रयत्नों को पूर्ण स्वतंत्र देना है और साथ ही विभाग दिखाना है कि राष्ट्रीय हितों में इसे नियंत्रित किया जाना चाहिये।” प्रस्तावना यह अर्थ भारत सरकार को प्रबंधन, तांत्रिक शिक्षा और निवेशों के लिए विदेशी पूँजी की आवश्यकताओं को स्वीकार करता है तथा भारतीय प्रयत्नों की अतुल्यता विदेशी पूँजी और बुद्धिमान अभिचारन करने की बुद्धिमानी दिखलाना है। यथार्थ में सीमाओं को विचारों में यह बात बहुत आगे थी।

कुछ लोगों ने यह सोचा होगा कि इन विचारों के उपरान्त तथा यह जानते हुए कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य के सम्बंधित रहेवाला है, तब और ब्रिटिश के धनी राजाशाह धन की पर्याप्तता में बहुततर भारत के नये शासकों की अन्तर्गत में कुछ करने के लिए आवश्यक समझी प्रस्तुत कर देंगे। साक्षात्कार हमने अधिक और विन विचारों की अपेक्षा कर सकते थे। दरअसल यह स्थिति इनके समझौते में थी कि साम्राज्य की एक अन्य सामग्री विचारों ने इन नीतियों को बड़े बड़े राज्यों में भीतर करवा आत्म कर दिया।

फिर भी सहायता योरी ही प्राप्त हुई। इसके विपरीत ब्रिटिश और अमेरिकन पूँजी क्षेत्रों में भारत की प्रतिक्रिया के बारे में आलोचना होने लगी। पश्चिम के व्यापारियों की चेतावनी दी गई कि वे होशियारी के कम बगैरे और भारतीय व्यापारियों के साथ करने में तब तक उत्साही न करें, जब तक कि अधिक ‘एल’ विभाग न प्राप्त हों।

परिचर्चा विरोधी, दक्षिण-पश्चिमी सरकार पटेल के नेतृत्व तथा बड़े पूँजीजीवी हितों की प्रतिक्रिया के प्रतिम पार्टी इसी विचारों को पोषणी रही कि महाकाय प्राप्त हो जायेंगे।

कॉंग्रेस की आर्थिक नीति

यह सच है कि शीतयुद्ध की परिस्थितिके एवं विदेशोंमें स्थित धनिक मित्रोंकी इस निरंतर मोंगके कारण कि भारतको 'साम्यवादी संकट' से अधिक स्पष्टरूपमें पृथक् कर लेना चाहिये, यह तत्व अज्ञान हो उठे थे। नेहरूजीकी तटस्थता एक आवश्यक सुझाव थी, पर फिर आखिर वह हमेशा यह तो कह ही सकते थे कि स्वतंत्रतामें साम्यवादी पार्टी अवैध घोषित कर दी गई है।

इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्थाके इन मिश्रित विचारोंके साथ नेहरूने १९४८ में संयुक्त-राज्य अमेरिकाकी यात्रा की। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, वे भारतमें इस स्पष्ट धारणाके साथ वापस आये कि हजबेन्टके पश्चात्त-वाला अमेरिका अधिक दिशावृत्ती बन गया है और घरेलू समस्याओंको हल करनेके लिये आत्म-निर्भरताकी आवश्यकता पर अधिक बल देने लगे।

साथ ही सरदार पटेल और उनके साथी यह अच्छी तरह समझते थे कि साम्राज्यवाद विरोधी विदेश-नीति तथा साम्राज्यवाद की सहायता पर आधारित गुट-नीतिके अन्तर मिटाने पड़ेंगे। गणतन्त्र की स्थापनाके वर्ष अर्थात् १९४० में गुट और विदेशके लिये ऐसी नीति निर्धारित करनेका सुर्घर बना रहा, जिसमें उनका अन्तर्विरोध नष्ट हो जाय।

यह अनिर्णीत सुर्घर था। नेहरू तटस्थताके सिद्धान्तको छोड़नेके लिये तैयार न थे। यद्यपि वे इस बातसे सहमत थे कि साम्राज्यवादका विरोध इतना करना आवश्यक है, जिससे वह अपनी बैलियोंका मुँह खोलनेके लिये उत्साहित हिये जा सकें। लेकिन साथ ही वे बार-बार इस बातकी चेतावनी देते थे कि संयुक्त-राज्य अमेरिकाके दबावके सामने आत्मसमर्पण करनेसे भारतीय भावनाको टेम लगेगी और बेमिन्न जनतासे दूर पड़ जायगी। यह एक महत्वपूर्ण तत्व था, क्योंकि पार्टीकी निरुद्ध भविष्यमें साधारण चुनाव लड़ने थे। स्वदेशके पाम एशिया और मध्य-पूर्वमें अमेरिकियोंके दुःसाहसिक प्रयत्नोंने देगके शक्तिशाली व्यापारियोंको भी इस प्रकारके तर्क करनेके लिये विवश कर दिया, क्योंकि वे अब पुनः गुलामीकी स्थिति मग्न करनेके लिये तैयार नहीं थे।

इन उलझे दिनोंमें यह बतलानेके लिये किसी ज्योतिषीकी जरूरत नहीं थी, कि देशकी आर्थिक नडिनाइयोंको दूर करनेके लिये किसी प्रभावशाली औपधिनी

जरूरत है। आत्म-निर्भरता की नीति का अर्थ तोममें कपोंके कार्पक्रमों का स्वरूपमें परिणत करना था। हममें कालि होनी आवश्यक थी, भूमि की धुआ की पूर्ति होनी चाहिये। विदेशी लागत को प्राप्त करना आवश्यक है। लोगों को काम करने की प्रेरणा देनी चाहिये, उनमें यह विश्वास उत्पन्न करना चाहिये कि उनके प्रयत्नों का परिणाम केवल धनी व्यक्तियों को अधिक धनी बनाना न होगा। विदेशी विनिमय की रक्षा के लिये एक योजना बनानी चाहिये, जिनमें औद्योगिक उपकरण सरीखे ज मकें क्योंकि इसके बिना कोई स्थायी और वास्तविक प्रगति सम्भव नहीं थी।

लेकिन कांग्रेस का परिवर्तन-विरोधी दल ऐसे किन्हीं आर्थिक कदमों के लिये तैयार नहीं था, जिसमें विदेशी व्यापारी डर जायें। उन्होंने लोगवें कपों की प्रतिस्पर्धा का प्रदर्शन विरोध किया। वह एक योजना की आवश्यकता मानने के लिये तैयार थे लेकिन ऐसी योजना जिसे ब्रिटेन और अमेरिका का आर्थिक दायित्व प्राप्त हो सके।

नेहरू, जो आर्थिक मसलों को समझने के अभी उत्तुंग नहीं रहे, इस अस्पष्ट स्थिति को स्वीकार करने के लिए उस समय तब तैयार थे, जब तक कि उनकी विदेश-नीति सामान्यवादियों के आशीर्वाद पर आधारित या उसकी पूरक नहीं बनती हो। जब कभी ऐसी सम्भावना दायनी थी, वे स्वातंत्र्य की बननी देने के लिये तैयार रहते थे। यह ऐसी सम्भावना थी, जिसे मादर पेटेल की केंद्रित पद्धति नहीं करती थी लेकिन नेहरू को किसी मजबूत आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार दायी आर्थिक योजना का काम शरम हो गया, लेकिन विदेश-नीति और गृह-नीति में विरोध बना रहा।

१९४० के अन्तमें जब कि योजना के रचयिता उनके प्राप्त की अनिष्ट रूप प्रदान कर रहे थे, कांग्रेस के परिवर्तन-विरोधी और पूँजीपति तत्वों के सवने प्रभावशाली प्रवक्ता सरदार पटेल की मृत्यु ने छीन निश। आशा तुलुप, पाटी-मशीन उनके विदुषों के हाथमें बनी रही। लेकिन वह अब उन्मूलनवादी नेहरू की विशेष प्रतिद्वंद्विता नहीं कर सकते थे।

सत्यानं नेहरू की स्थिति उतनी ही निर्बल बनी रही। उन्हें अपने विरोधों का ध्यान रखना पड़ता था, लेकिन वे अब उन्हें उस स्थिति में पटक सकते थे

कॉंग्रेस की आर्थिक नीति

जिमके लिये वे पहले तैयार नहीं थे। शक्तियोंकी इस नई व्यवस्थाकी पृष्ठभूमिमें प्रथम पंचवर्षीय योजनाकी घोषणा की गई, जो अपने रूपमें उन्मूलनवादी लेकिन तत्त्वमें परिवर्तन विरोधी थी। तत्कालीन कांग्रेस पार्टीकी स्थितिमें यह पूर्ण प्रतिद्वन्द्वता थी।

पहले उसके रूप पर विचार करना ठीक होगा। योजना आयोगने योजनाके आरम्भके आरम्भिक शब्दोंमें ही उसके कार्यक्षेत्रकी और निम्नलिखित शब्दों द्वारा ध्यान दिलाया था “— राज्य इन प्रकारका सामाजिक रूप प्राप्त करने और उसकी रक्षाका अधिराधिक प्रयत्न करेगा जिससे जनताका अधिक कल्याण हो तथा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, एक राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवनकी सभी सुस्थाओंमें विद्यमान हो। साथ ही अन्य वस्तुओंके साथ निम्नलिखित वस्तुएँ प्राप्त करनेकी और अपनी नीति उन्मुख करेगा। (क) यह कि सभी धनी या पुरुष नागरिकोंकी अपनी-अपनी जीविमाना पर्याप्त साधन प्राप्त करनेका अधिकार हो। (ख) समाजके भौतिक स्रोतोंका सामूहिक और नियंत्रण इस प्रकार वितरित हो, जिसमें सर्वसाधारणकी भलाईमें अधिक सहभाग्य मिले। (ग) यह कि आर्थिक व्यवस्थाका परिणाम उत्पादनके साधन और धनका जनसाधारणके नुस्खानेके लिये केन्द्रीकरण न हो सके।

जो व्यक्ति इन शब्दोंको इस वास्तविकताकी दृष्टिमें पढ़नेका प्रयत्न करेगा कि बिड़ला और टाटाके समान तत्व नहीं, बल्कि सरदार ही उनकी लिये पंचवर्षीय योजना लागू करनेवाली है, उसे इस कार्यक्रमके उन्मूलनवादी होनेकी आशा हो जायेगी। आन्तरिक भारत एक पिछड़ा हुआ देश था, जिसे शताब्दियोंके पिछड़ेपनसे दूर करनेके लिये दृढ़ और तत्कालीन विनाशकारी आवश्यकता थी। यह स्वाभाविक ही है कि ऐसी दशामें यह अधिक प्रगतिवादी रास्तेकी तरह स्वतन्त्र व्यक्तिगत प्रयत्नोंकी विलासिता सहन नहीं कर सकता था।

इस कारण यह तर्जमन्मन था कि योजनामें समाजवादी कार्यक्रमके अनुसार प्रगति हो, जिसमें साम्राज्यवादी निर्भरताका अन्त हो सके और लोगोंमें भारी कार्य करनेकी प्रेरणा यह विश्वास दिलाकर प्राप्त की जा सके कि स्थानीय शोषकोंकी पकड़ ढीली कर दी जायगी। देश एक एक कदम करके धीरे धीरे नवीन औद्योगिक

योजना आयोग के निर्देश

राष्ट्र की ओर बढ़ सके और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा जिसमें हम दिशाने अपनी स्वतंत्रता और सार्वभौमिकता स्थापित करनेका उत्साह हो।

सोवियत देशों में हम यों कह सकते हैं कि भारत के लगभगियों की भारी शक्ति का उपयोग इस प्रकारसे किया जाय, जिसमें देश की प्रगति की रोकनेवाली आर्थिक व्यवस्था की बुगड़ियों की जड़ों को बुगड़-पुगड़ हो सके। किसानों की समस्या को प्राथमिकता देनी चाहिये, जिसका देश की जनसंख्या में बहुमत है। किसानों को उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न करने के लिये उत्साहित किया जा सकता है।

भूमिका इस प्रकार वितरणा होनेसे नष्ट उत्पाद प्राप्त होगा और दृष्टि में उनी होगी। खेतों में नवीन उपकरण और साधन प्रस्तुत करने के लिये ऐसे उद्योगों को प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ वह बन सकें, क्योंकि इनके बिना निर्मल भूमि को उत्पादन शक्ति नहीं बढ़ाई जा सकती। हमारे देश में, एक एकड़ भूमि में पूर्वकालीन १० एकड़ भूमि के बराबर उपज होनी चाहिये, अन्यथा भूमि-सुधार निरर्थक है।

हमारा अर्थ यह है कि भौतिक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिये, जिन औद्योगिक प्रतिष्ठानों की आवश्यकता है, वह इस्पात, विद्युत-शक्ति और उन अनेक साधनों के बिना नहीं बढ़ सकते, जिन्हें या तो खोजना पड़ना या जिनका निर्माण करना पड़ता। उत्पादन में अधिक उत्पादन की प्रेरणा मिलनी है और समानान्तर विकास संकल्पना में मूलभूत है। एक बार इन क्रियाओं का प्रारम्भ हो जाने पर यह अधिक उपयोगी बननी जाती है और फलस्वरूप जीवन की अनेकानेक उन्नतिका कारण बन जाती है।

समाजवादी राष्ट्रों का यही दृष्टिकोण होता है। समाज के अधिक धनवान व्यक्तियों से सबीरों की हितों को योजना में बाधा उपस्थित करने से रोक जाना है और पृथी इस कारण सम्भव हो पाती है, क्योंकि उसे उत्पन्न करके उस पर कठोर नियंत्रण रखा जाता है। मूल्यों को बढ़ाने से रोक जाना है और साम उद्योगवालों को अवरुद्धी समझा जाता है। प्रत्येक देश की कुछ विशेष समस्याएँ होती हैं, लेकिन भौतिक समस्याएँ बहुत कुछ एक समान ही रहती हैं। योजना आयोग के निर्देशों में यही आचार्य व्यवस्था की गई थी।

कॉंग्रेस की आर्थिक नीति

अब हम पंचवर्षीय योजनामें वर्तमान तत्वोंपर विचार करेंगे। यह कुछ और ही थे। दिसम्बर १९५२ में बनकर तैयार होनेवाली इस योजनामें १९५१ से १९५६ तकके पांच वर्षोंमें रु २०६६ करोड़ लगानेका विचार था। इसमें एक अनुपूर्वक योजना अक्टूबर १९५३ में घोषित की गई, जिसमें इसके अतिरिक्त रु १५० करोड़ लगा दिए गये थे। और इस प्रकार कुल योग रु २२४६ करोड़ था। अन्तिम राशि रु २३६५ करोड़ थी।

इसमें सबसे बड़ी मद परिवहन और यातायात की थी, जो युद्धकालमें बहुत पिस चुका था। कुल नियोजनका लगभग एक चौथाई भाग इस काममें आ गया। विद्युत् और मिचाई की बहु-उद्देशी आयोजनाके लिये अनुमानित धन परिवहन अर्थात् रेलवेके लिये अनुमानित धनका आधा था। योजनाोंने कृषिपर अधिक ध्यान देनेकी बात कही थी, लेकिन उस पर सीधी नियोजित राशि कुल व्ययकी १७.५ प्रतिशत थी, जब कि परिवहनके लिये २४ प्रतिशत लगाये गये थे। वास्तविकता यह है कि कृषि, मिचाई और विद्युतका सम्मिलित व्यय परिवहनके व्ययसे कुछ ही अधिक था।

आवृत्तकी स्थिति चाहे जो कुछ रही हो लेकिन यह स्पष्ट था कि योजनाओंको भारतके अन्दरी कमोके बारेमें बहुत चिंता थी। इसमें देशकी विदेशी मुद्रा प्रणिवर्ष बहुत व्यय हो जाती थी। वे इस स्थितिसे समाप्त करनेके लिये हस्तक्षेप थे और भारतको अपनी कृषिपर आश्रित देखना चाहते थे। यह विषय हमेशा विवादस्पद रहेगा कि क्या प्रथम पंचवर्षीय योजना कालमें भारत सरकार कृषिमें ओरने ध्यान दृष्टा सकती थी, बचपि उसका अर्थ होता पुगनी और परिचित नीतिको को जारी रखना? अन्तमें आत्मनिर्भरता एक लाभकारी उद्देश्य था और आगे चलकर हम देखेंगे कि बहुत पिल्लविन औद्योगिक कार्यक्रमोंको पूरा करनेके लिये उसने भारतकी कैसे सहायता की।

प्रथम योजनाके अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्रमें उद्योगोंपर बहुत कम नियोजन हुआ था, अर्थात् कुल ७-६ प्रतिशत। योजनाोंका घोषित उद्देश्य था, “जनसंख्यामें होनेवाली अन्तर्जातीय वृद्धिसे देखते हुए उपभोक्ता सामानमें लगभग युद्ध पूर्वकी स्थिति प्राप्त कर लेना।” एक वाक्यमें योजनाका उद्देश्य यह था — कि सत्ता हस्ता-

नरणाके ६० वर्ष पश्चात् भारत आर्थिक दृष्टिसे उस स्थितिसे प्राप्त करण चाहता था, जिन स्थितिमें १९० वर्षके ब्रिटिश शासनके उपरान्त वह पहुँचा था।

योजना की प्रतिक्रिया कभी अनुत्साहपूर्ण थी। किसीमें जोश नहीं था। कांग्रेस क्षेत्र तक इस विषयपर बातचीत करनेके लिये विशेष उत्सुक नहीं थे। परिवहन पर बल उन पुराने दिनोंका स्मरण दिलाता था, जब भारत साम्राज्यवादी उद्योगों की पूर्णके लिये कच्ची सामान देनेवाला एक बड़ा भंडार था। योजना की गणनामें औद्योगिक उन्नति तो शासक आई ही नहीं थी। और लोगोंको रोजी-रोज्गार देनेकी आवश्यकता पर विचार नहीं किया गया।

वास्तवमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसने अपनी पूर्ववालीन महत्वपूर्ण प्रतिज्ञाओंके साथ योजना बनाने समय विश्वासघात किया था। क्या नेहरूने ४ अक्टूबर १९३६ को कांग्रेस पार्टीकी राष्ट्रीय योजना समिति, जिसके वे स्वयं अध्यक्ष थे, को भेजी जानेवाली अपनी एक टिप्पणीमें यह नहीं लिखा था, कि जिन प्रस्ताव द्वारा योजना समितिकी नियुक्त हुई है, उसमें हमने यह अपेक्षा की गई है कि इस महत्वपूर्ण उद्योगों, मध्यम स्तरीय उद्योगों और कुटीर-उद्योगोंके विकासकी प्रवृत्ति करें। उसमें यह कहा गया है कि बिना औद्योगीकरणके देशकी आर्थिक उन्नति सम्भव नहीं है। हमें औद्योगीकरणमें नीजता लाती है और यह बतलाना है कि महत्वपूर्ण और मौलिक उद्योग वहाँ और तेरे आरम्भ किये जावें।” योजनाके इस निश्चय और नये दृष्टिकोणमें कितना अंतर है !

यह सब है कि भारतीय रूढ़ीवादियोंके हितोंकी प्रशंसा और उनकी निंदा तथा अमेरिकाके रोप-शमनकी इच्छाकी प्रतिज्ञावा योजनामें थी। इस तर्क द्वारा सभी बातें समझमें नहीं आ सकतीं, क्योंकि १९४४-४५ में यदा विरला आदि द्वारा जो योजना बनी थी उसका भी यही उद्देश्य था, लेकिन फिर भी उन्हें इस निष्कर्षपर पहुँचनेके लिए विवश होना पड़ा कि, “आर्थिक अवस्थानमें प्धान प्रमुख रूपसे विजली और पूँजीका निर्माण करनेवाले उद्योगोंके गठनकी ओर वंक्षित करना चाहिए।” उन्होंने आगे कहा था, कि “अपनी आर्थिक योजना की सफलताके लिए हम यह आवश्यक समझते हैं कि निम्न आधुनिक उद्योगों

कॉंग्रेस की आर्थिक नीति

परदेरास संपूर्ण आर्थिक विकास आधारित है, उनको जिनकी शीघ्रतामें बसाया जा सकता हो, बसाया जाय । ”

टाटा-विप्लवा योजनामें भारतीय कृषि उत्पादनको दूनेमें अभिक करनेकी व्यवस्था थी । खोद्योगिक उत्पादनको पंचगुना बढाना था । १०,००० करोड़को १५ वारिके अंदर उपभूय्य करनेवाली इस टाटा विप्लवा योजनामें लगभग आधी राशि उद्योगिकी लिये तथा ६ कृषि और पिचाईके हेतु व्यय करनेका सुझाव था । इसके विपरीत रु २२४६ करोड़ पाँच वर्षोंमें व्यय करनेकी सरकारी योजनामें रु १७६ करोड़ अर्थात् ७६ प्रतिशत राशि उद्योगिकी लिये थी, जब कि रु ६४० करोड़ कृषि तथा पिचाई और विजलीमें सम्बन्धित बहु उद्देशीय आयोजनाओंके लिए रखे गये थे । इन आम्बोंमें परिवर्तन हुआ, लेकिन विभिन्न क्षेत्रोंमें अनुमानित राशिका अनुपात लगभग वही बना रहा ।

स्पष्टतया दिल्लीमें बनी इस निराशापूर्ण योजनाको समझनेके लिये उन अन्य तत्वोंपर भी विचार आवश्यक है, जो देशकी आंतरिक नीतिपर भारी प्रभाव डाल रहे थे । यह तत्व क्या थे ? उन्हें केवल एक सर्वग्राही शीर्षक—शीत युद्ध—में रखा जा सकता है ।

विश्वका दो परस्पर विरोधी दलोंमें विभाजन और १९५१ में उनके बीच एक प्रकारका शिक्का ही था, जिसने अपनी आंतरिक प्रवृत्तियोंके स्पर्ध द्वारा विभक्त और भुनावेमें पड़ी हुई कॅप्रेम पार्टीके लिये अपने दृष्टिकोणके अनुरूप और भारतीय स्वतंत्रता संग्रामके आदर्शोंकी प्रतिपादक नीतिका पालन अमभव बना दिया ।

परस्पर विरोधी दलोंकी शक्तिका अनुमान लगा कर कॅप्रेम पार्टी यह निश्चय नहीं कर पा रही थी कि किस ओर झुकना चाहिए । समान समारकी सामान्य समाजवादी प्रवृत्तिमें परिचित स्वयं नेहरूने भी ‘टहरो और देखो’ दृष्टिकोण अपनाया ही अधिक उचित समझा । वे इसमें अधिक और कुछ नहीं कर सकते थे । क्योंकि सरदार पटेल और उनके साथियोंका कॅप्रेम पार्टी—यंत्रण नियंत्रण बहुत सुख था । इसी कारण किसी ऐसी नीतिका अपनाना उनके लिये अमभव हो रहा था, जिसका अर्थ भारत और आंग्ल-अमेरिकन दुनियोंके माँगोंका अलगाव हो ।

आगे हम देखेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किन प्रकार आगे बढ़ी, उससे क्या प्रत्यक्ष लाभ हुए और किन प्रकार उसकी आलोचनाओं ही ब्रिटिश पार्टीने द्वितीय योजनामें विशेष रूपसे जवाहर नेहरूके प्रभावके कारण स्वीकार कर लिया । इस समय तो हमें उन प्रवृत्तियोंपर विचार करना है, जो प्रथम योजनाके पाँच वर्षोंमें प्रगट हुई तथा जो एक या दूसरे रूपमें भारतके अनेक निर्णायक परिवर्तनोंका रूप निर्धारित करनेवाली थीं ।

नई प्रवृत्तियाँ

राज्यसे जनमनकी शक्ति उन्नी प्रकार अधिक है, जिस प्रकार अनेक संतुष्टोंसे निर्मित रस्मी मिड तक़्को प्रसीटनेके लिये शक्तिपूर्ण होती है ।

(नीति सार)

१९४७ से १९४९ तक कॉम्रेन पार्टी द्वारा निर्धारित एह—नीतिमें स्पष्टकारी कमी ने इस आंदोलनके अनेक अग्रगण्य तत्वोंको निराश कर दिया । ज्यों ही प्रथम योजनाकी स्वररेखारा पता चला यह सच्य खुले रूपमें होने लगा ।

केरल कॉम्रेस केबिनेटमें फूट पड़ गई थी । योदे ही दिनों परवान पार्टीके आग्र दलकी दो शक्तिशाली विभूतियों— टी प्रकाशम् और एन० जी० रंगा ने, प्रजापार्टी बनानेके लिये कॉम्रेस छोड़ दी । इसके उपरांत एक अन्य हस्ती, ले० बी० कृपलानीरा त्यागपत्र सानने आया । और योजनाके प्रशिक्षित होनेके साथ ही गाय राजनीतिक रूपमें नेहरूके निकटतम साथी, एनी बहमद सिद्दीकी सचिव मंत्री पदने अपने त्यागपत्रकी स्वीकृतिके लिये जोर डालनेका निरवय कर लिया । कॉम्रेसके इस सङ्कटा प्रभाव दूसरे क्षेत्रोंमें भी पडा, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेशके ममान कॉम्रेसी गढ़में भी इसी प्रकारसे सम्बंध निच्छेद हुए ।

यह ठीक है कि कॉम्रेसमें होनेवाले इस विभाजनकी सभी शक्तियों एक ही प्रकारकी नहीं थी । उनमें कुछ स्वार्थी और बहुत अनुचित हितोंपर आधारित थीं । कुछ कॉम्रेस नीतिके साधारण वाम पक्षीय भुजावने प्रेरित थीं । लेकिन इस विद्रोहकी मुख्य शक्ति सिद्दीकी त्यागपत्रके निर्णयने प्राप्त हुई, जो वामत्वमें साधारण उन्मूलनवादीसे भी दो कदम आगे थे । कॉम्रेस टैंचमें सुधार करनेके सचमें बड़े समर्थक बही थे ।

व्यक्तित्वोंके इस सचर्चको 'परिवारके भीतरी झगड़े' के रूपमें कह कर टालना परंपरागत था । और इसमें कोई संदेह नहीं कि तत्प्राप्तियत कृषक होने-वालोंके तर्कोंके अनुसार यह परिवारके झगड़ेकी तरह ही दीखते थे, जो साधारण

बुनावोंके कारण सामने प्रगट हुए थे। लेकिन इस वास्तविकताको भुला दिया गया था कि वृषकरण उस पार्टीमें नहीं होता है, जो सनस्यारोंको आनविभागके साथ कुलमानी और अपना पक्ष रट करती हो। व्यक्तिवाद और दलबंदी केवल सभ्यके समय ही अपना काम कर पाते हैं।

लेकिन इस अत्यंत महत्वपूर्ण तत्वका भी इस समय ध्यान नहीं दिया गया कि इस विद्रोही या अलग होनेवाले व्यक्तियोंके राष्ट्रीय नीतिके प्रश्नोंको नहीं बरन प्रमुख रूपसे स्थानीय विषयोंको ही अपने विरोधका आधार बनाया था। वह उन्मूलनवादियोंको बोलीमें बोलने थे और कोंग्रस-सरकारका हीन विरोध करनेके लिये बहिष्कारों तकने मिल गये। उन्होंने कोंग्रस-व्यवस्था निंदन करनेवालोंके साथ अपने भारी मतभेदोंको भी छिपानेका प्रयत्न नहीं किया, किन्तु प्रतिप्रतिक्रियाशील पुन्योत्पन्नता दंडनको सत्ताका समर्थन बनानेमें मदद दी थी।

यह विद्रोह कमिसेसके अनुसूची उन्मूलनवादियोंकी ओरसे हुआ था, यद्यपि जिन लोगोंने उनका साथ दिया उनमें अनेक अल्पवादी थे, जो देशमें व्याप्त असंतोषका लाभ उठाना चाहते थे। साधारण शब्दोंमें ये विद्रोही, देशके अनेक भाषा-भाषी दलोंपर आधारित मध्यम-वर्गीय पूँजीजीवियोंके समर्थन प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जो इस बारेमें बहुत उत्तेजित थे कि उनके हितोंका वलिदान सारे भारतमें अपनी कोठिमें रखनेवाले बड़े व्यवसायियोंके एकाधिकारके सामने किया जा रहा है। लेकिन इसके बारेमें आगे विचार करेंगे। यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि कमिसेस पार्टीकी राय आगमने नहीं हो रही थी। देशमें असंतोष व्याप्त था। और वह निरंतर उसमें छुटकारा पानेका मार्ग खोज रहा था।

दक्षिण और बामपंथी विचारक निरंतर हठ पूर्वक इन परिवर्तनोंको सही और छुट्ट भगंड ही समझने लगे। यह अलोकित विवेचन था, क्योंकि देशका मुख्य समाजवादी पार्टीके सदस्योंको भी प्रभावित कर रहा था। ६ अप्रैल १९२१ को बहुमतमें बम्बई-नाम्य-समाजवादी पार्टीकी कार्यकारिणी समितिने अपने २६ प्रमुख और सक्रिय सदस्योंको पार्टीके हितोंके विरुद्ध कार्य करने तथा “जानबूझकर उद्वेगपूर्वक उसके कार्यमें बाधा डालनेके कारण” बम्बई और महाराष्ट्रमें निष्काशित करनेका निर्णय लिया।

नई प्रवृत्तियाँ

यह निष्पत्ति समाजवादी भीमानी अरुणा ग्राम-अलीके साथ बादमें साम्य-वादी पार्टीने सम्मिलित हो गये। वे लोग जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा प्रतिपादित अस्पष्ट और निरर्थक नीतियोंका पालन नहीं कर सके थे। कांग्रेसरी तरह यहाँ भी यह विद्रोह प्रातीय स्वरूपमें महाराष्ट्रमें विकसित हुआ, जहाँ कांग्रेस पार्टीने भी पहले इसी प्रकारकी भारी फूटका सामना किया था और परिणामस्वरूप यूरोपियन कम्युनिस्ट पार्टीसे सम्बन्धित "कमिन फार्मिङ्ग प्रति स्वामिभक्ति" प्रदर्शित करनेवाली निराला मजदूर पार्टीकी रचना हुई थी।

अनेक प्रतिक्रियावादी राजनीतिक विचारनेने यह दिखलानेका प्रयत्न किया है कि कांग्रेसियोंमें ही इस प्रकारके एक विरोधी दलका निर्माण होना देशके लिये अच्छा था। उनका मुख्य तर्क यह था कि यह दल 'सेफ्टी बाल्ड' की तरह कार्य करेगा और अशांत विद्रोही तत्वोंसे साम्यवादी दलमें प्रवेश करनेमें रोकेंगे। घनश्याम दास विश्वाके पत्र 'ईस्टर्न इकोनोमिस्ट' के लेखमें यह विचारधारा बहुत पनपी। बड़े-बड़े व्यापारियोंके लिये कांग्रेस दलमें इस प्रकारकी सफाईमें अच्छी और क्या बात हो सकती थी अर्थात् उन्मूलनवादियोंका निवारण जिसमें 'सेफ्टी बाल्ड' के निर्माणमें महत्त्वना मिलनी लेकिन यह स्वप्न शीघ्र ही भग होनेवाले थे।

पुन साहसी नेहरूने इस परिस्थितिसे रक्षाके लिये अपना एकात्मिक प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया। उन्होंने तत्काल ही यह अनुभव कर लिया कि उन्हें अपने देशवासियोंसे यह बताना आवश्यक है कि पंचवार्षिक योजनाके बावजूद भी वे ब्रिटेन और संयुक्त-राज्य अमेरिकाके विदेशी विभागके दृष्टादेपर नाचनेवाली कोई कठपुतली नहीं हैं।

उन्होंने केवल उनी विषयों पर जिन पर समस्त भारत एकमत था अर्थात् साम्राज्यवादी देशोंके भीमानी और भयकर युद्ध अभियानोंसे अपने देशको पृथक् रखना। यह ऐसी कार्यशैली थी जिसका टाटा-विश्वालके हार्मियोंके साथ-साथ पार्टीके परिवर्तन विरोधी तत्वोंसे भी समर्थन करना पड़ना है। इसके अतिरिक्त इस कदमसे पार्टीके विद्रोहियोंमें भी किसी सीमा तक यह विश्वास उत्पन्न होना निश्चित था कि मामला इतना बुरा नहीं है जितना वे समझते थे।

देशने एक ऐसी आदर्शजनक विजेपताय दर्शन दिया, जिसे जीताने कभी दिक प्रचार समझा ही न जा सका। जहाँ एक ओर विरोधी दल परेलू आर्थिक समस्याओंके प्रति जनताका समर्थन प्राप्त करनेका प्रयत्न कर रहे थे, नेहरूने देशके दौरा करके बंबल युद्धके भयभर सभ्य और शान्तिही रत्नाके लिये भारतके प्रयत्नोंका सदेम प्रचारित किया। जहाँ कहीं वे गये, उन्होंने बहुत भारी भीड़को आकर्षित किया। जनमाने बैठकर निवेशी सनस्था, शान्तिके अर्थ और पराजित बन्के जीव-जगतपर प्रभाव आदि विषयों पर उनके भाषण सुने। विदेशी नीतिमें आशाद मस्तक दूबे प्रधान मंत्रीके लिये निगेधियोंने एक मजाक ही प्रस्तुत किया, क्यों कि वास्तविकता यह थी कि देश गवर्के साथ उनके रोत्तमी सराहना कर रहा था।

सयुक्त-राज्यीय युद्धनीतिही भूलों और सनारमें व्याप्त शांति भावनाओंके अन्तर्गतिय आगड़ेने नेहरूके प्रयत्नोंका नाटकीय प्रभाव वाला। कोरिया युद्धके विषयमें भारतकी समस्त चेतावनीकी ओर युद्ध-प्रिय जनरल मक आर्थर द्वारा ३८ वीं अक्षांशके आगे दम्न तथा उनके साम्यवादी चीनकी भुमर देनेके पोथिन उद्देशके कारण विशेष ध्यान आकर्षित हुआ। सयुक्त राज्य अमेरिकाके आश्रित सहयोगियोंके लिये यह खोपग बहुत अधिप प्रमाणित हुई। शोभनापूर्वक टुमेनने मेक आर्थरको मुद्दर पूर्वी स्माइले ११ अप्रैलको परसुक्त कर दिय था। उसके उपरान घटना-चक्र तेजीमे घूमा, जिनका अन् कोरियाकी युद्ध-वरीमें हुआ।

लेकिन एंग्लोमें अपनी इज्जत बचानेके लिये विजित अमेरिकाके तथासथित औद्यिक शान्तिवादी प्रारम्भ कर दी। उनका उद्देश एक इज्जतदार शान्ति कायम करना नहीं था, बल्कि वे आगतको जन-धीनमे युद्ध करनेके लिये उसी प्रकारका एक शत्रुनागर बनाना चाहते थे, जैसा यूरोपमे सोवियट सघसे युद्ध करनेके लिये पश्चिमी जर्मनीको बनाया जा रहा था।

भारतने इन प्रकारकी शान्ति-चरित्र भागीदार बनना अस्वीकार कर दिया, जिनने अमेरिकाको अरना औद्योगिक निधनण हटानेके उपरान भी जगानमें तथा उनके आस-पास अन्, स्वन और बाधुमेन रखनेका अधिकार बना रहना था। साम्यवादी

नई प्रवृत्तियाँ

नीति के विरुद्ध यह एक भारी प्रचारान्मक चोट थी, क्योंकि भारत, सोवियत संघ जन चीन और अन्य समाजवादी देशों के साथ मिलकर समारकी जनसंख्या के भारी बहुमत का निर्माण करना था। अनेक स्वतंत्र और ईमानदार व्यक्तियों ने यह मींग प्रस्तुत करना आग्रह कर दिया था कि "हमें समारकी समस्याओं को निवटाने के लिये प्रयत्न चाहिये।"

कटकपूर्ण काश्मीर समस्या पर भी दिल्ली ने अधिक स्वतंत्रता व्यक्त करनी आग्रह कर दी। मई में राष्ट्रमधीय मुद्रा परिषद के प्रस्ताव को अम्लीकृत किया जा चुका था, पर संयुक्त राज्य ने प्रभावित इस सस्था द्वारा इस मनमार्क निराकरण का प्रयत्न जारी रखा। जुलाई में प्रेक ग्राहम पुन 'मध्यस्थता' के लिये आये। लेकिन अम्लूर के अर्ध तक काश्मीर विधान निर्मात्री-परिषद् की रचना में समस्या के समाधान के लिये साम्राज्यवाद का आग्रह ताकने के नीति में एक नेणीयमक विक्षेप उपस्थित हुआ, वही नीति जिसके अनुसार पाकिस्तान का साम्राज्यवादियों द्वारा पक्षग्रहण करने के लिये उनमें समझौता करने के दृष्टिकोण को उन्नाह प्राप्त होता था।

उसी समय ६ अक्टूबर १९५१ को वह सूचना प्राप्त हुई, जो वर्तमान शक्ति मतुलन को कमपूर्वक बदलनेवाली थी। स्टालिन ने धोपणा की थी कि सोवियत संघ ने अणुबम का स्फोट किया है और वह अन्य अणु परीक्षण करेगा। सुदूर अमेरिका में स्थित निममोप्रापों ने इस विस्फोट का अवन किया था, निमम अर्थ यह अक्ति करना था कि अणुबम पर अब साम्राज्यवादियों का एकाधिकार नहीं रहा।

पश्चिम के अनुकूलित जनमत पर इसका प्रभाव बहुत दुग पड़ा। अब ब्रिटिश और अमेरिकन नगर भी अणुशक्ति द्वारा नेस्तनाबूद होने के भय में मुक्त न थे। संयुक्तराज्य की समस्त रणनीति और सकटकालीन योजनाओं का आधारशिला अणु-अर्धों का एकाधिकार ही तो थी।

युद्धपट्टियों के सामने एक भारी दुविधा उपस्थित हो गई। पूँजीवादी दुनिया की प्रत्येक राजधानी में एकाधिपति और उनके राजनीतिक दल आश्चर्यचकित थे कि अब समाजवादी सत्ता के पास इस प्रकार के बन होने का क्या परिणाम होने वाला है। भारत में कांग्रेस के परिवर्तन विरोधी सदस्य जो सदैव सर्वाधिक शक्तिशाली

और अजेय सुपुत्रराज्य अमेरिकाके साथ मित्रता करनेकी बात सोचा करते थे, अब कुछ अन्य बातें भी सोचने लगे ।

नेहरूने कांग्रेस यंत्रणा निर्धारण करनेवाले पुख्तामशम टंडन और उनके अन्य साथियोंके पेश कस ही दिये थे । अगस्तमें उन्होंने और अनुसूचितप्रान्त आजादने पार्टीकी कार्यकारणी समितिमें त्यागपत्र दे दिया, जिसमें दक्षिणपंथी परिवर्तन विरोधी दलवाले टीने पड़ गये, क्योंकि वे जानते थे कि अगर लोगोंको यह अनुभव हो गया कि नेहरू मरीचे जनप्रिय नेता पार्टीकी कार्यप्रणालीसे अमृतुष्ट हैं, तो चुनावोंमें बेमिम नहीं जीत सकेंगे ।

यह भी अफवाह फैली हुई थी कि प्रधानमंत्री अपने पदमें भी त्यागपत्र देनेकी वृत्तपर विचार कर रहे हैं । एक अन्य पार्टीके लो जनेकी भारी सम्भवना थी । ऐसे बातावरणमें प्रतिक्रियावादियोंने पीछे हटनेका निर्णय लिया । टंडनने त्यागपत्र दे दिया । नेहरूने कांग्रेस पार्टीकी बागडोर संभाल ली । अक्टूबरके आरम्भ तक निदवई भी केन्द्राय मंत्रिमंडलमें आ गये ।

भारतीय जीवनके महत्वपूर्ण समयमें उसीके रूपमें हमेशाकी तरह असंगठित नेहरू दल आणादिक शक्तिसंतुलनके इस परिवर्तनके कारण अधिक शक्तिशाली हो गया । सारे देशमें प्रथम सामान्य निर्वाचनकी तैयारी होने लगी ।

इतिहासमें प्रथम बार सन १९५२ में संपूर्ण जनसंख्याके लगभग आधे अर्थात् १८ करोड़ वयस्क, केन्द्रीय और राज्याय विधान परिषदोंके ४००० से अधिक प्रतिनिधियोंको निर्वाचित करनेके लिये मत देनेवाले थे । ७५ पार्टियों और दलोंसे सम्बंधित लगभग १७००० सदस्य निर्वाचित होनेके लिये मतदानाओंका समर्थन प्राप्त करनेमें शकनशील थे, जिनकी संख्या उन समय समारमें सबसे अधिक थी ।

उस विभातकी कम्पना कीजिये । लगभग ७२,४००० निर्वाचनस्थलोंके निरीक्षणके लिये ५,६०,००० कर्मचारियोंको लगाया गया था । जहाँ तक मत पेटिक्लेशोंका सम्बंध है, उनकी संख्या २५,८४,००० थी । भारतमें इस प्रबंधका अनुमानित व्यय १० करोड़ रुपये था ।

नई प्रवृत्तियाँ

विदेशोंके प्रतिक्रियावादी लेखकोंको, जो इस ध्रममें ही पनपे थे कि केवल आत्म सौमन ही अपने मणधिकारका प्रयोग करना जानते हैं, इस अभूतपूर्व घटना-की ओर ध्यान देनेके लिए विवश होना पड़ा। कुछ लोगोंने तो अपना यह कपोल-कल्पित दृष्टिकोण बना लिया था कि भारतके अशिक्षित देशवासियों किन्हीं प्रकार केंद्रिमके पक्षमें ही यह सोचकर अपना मत देने कि वह गांधीजीका समर्थन कर रहे हैं, यद्यपि वह मर चुके थे। ऐसी कल्पनाएँ परिवर्तनीय मतिधारा की विशेषता हैं, क्योंकि अपने पूर्वराष्ट्रीय उपनिवेश-वास्तविकोंके विचारों और कार्यक्रमों होनेवाले परिवर्तनमें वे अब तक अपना समझौता नहीं कर सके थे।

निर्वाचनमें निरासताही प्रतीतके लिये अपने तैयारी की गई थी। यह सही है कि गैर केंद्रिमियोंको अनेक दसकपटे उठानी पड़ी थीं। वे अस्मान्त ऐसा समझन नहीं बना सकते थे जो उनके अधिकारकी रक्षा क्रयैह निर्धारित केन्द्र पर कर सके। उनके पास न धन था, न सत्तावाक्य-यत्र थे और न मत्तधारी पार्टीका विश्विय महारा ही था। प्रचारकार्यके लिये वे मजदूरी मुविधाका भी उपयोग नहीं कर सकते थे।

अपने भूमिगत कार्यरत्नाओंकी दुर्भाग्यपूर्ण अवधि समाप्त करके साम्यवादी पार्टी प्रगट हो रही थी। बी. टी. रणदिवेकी दुम्माहमिक और सकुचित नीतियोंने भारतीय साम्यवादी पार्टीके संगठनका प्रभाव विमान मजदूरोंके मुहद क्षेत्रोंमें भी कम कर दिया था। जब भी सी. जोशी जनरल मेट्रेटनी थे, तब मध्यि सदस्योंकी संख्या १,००,००० थी, जो अब घटकर २०,००० से भी कम रह गई थी। पार्टीने एक नये कार्यक्रमकी घोषणा की थी, जो हालांकि बदलनेवाली परिस्थितियोंके विपरीत था, फिर भी अपने निराश कार्यकर्त्तार्योंको किन्नी सीमा तक सश्रित करनेमें सफल हुआ। लेकिन राजनैतिक चित्रमें केंद्रिमकी निश्चित विजयका दृश्य दोगने लगा था।

आन्तरहीन वेडंगी आहूतिवाली केंद्रिम पार्टीके अंदर आपसी चुनावोंमें उम्मीद-वारोंके रूपमें मनोनीत होनेके लिये अभूतपूर्व होड़ लगे हुई थी। परिवर्तन किन्हीं दक्षिण पक्षियोंका उद्देश्य अपने समर्थकोंके लिए प्रभावशाली सभामें स्थित

प्राप्त करना था। इन विषयों में वे यथेष्ट सकल हुए, क्योंकि पार्टी-यंत्रण अब भी उनका नियंत्रण था और कोई चुनाव संगठन शक्तिके अभावमें नहीं लग जा सकता।

उन्मूलकवादियों ने देखा कि चुनाव टिकटके लिये उनके स्वयंसेव नेहरूजी समर्थन इस आधारपर नहीं कर रहे हैं कि इस युक्तिमें केवल फूट ही अधिक बड़ेगा जब कि पार्टीको इस समय एकताकी भारी आवश्यकता थी। कई कारणोंसे जिन अनेक व्यक्तियोंको सदस्यता प्राप्त नहीं हुई, उन्होंने अपने आपको स्वतंत्ररूपमें सज किया। उन्हें यह आशा थी कि स्पष्ट आर्थिक नीतिके अभावके फलस्वरूप देशमें फैले हुए असन्तोषका बहु लाभ उठा सकते हैं।

निर्वाचनमें यह 'स्वतंत्र' एक बड़े प्रेरणादायक चिन्ह थे। असतुष्ट कॉंग्रेसी, छिपे हुए संप्रदायवादी और अव्यवस्थित उन्मूलकवादी स्वतंत्र सदस्योंके रूपमें लड़े होकर विरोधी दलोंकी व्यवस्थित पार्टियोंके साथ स्वतंत्र समझौता स्थापित करनेमें सफल थे। यह स्पष्ट दौलत रहा था कि वे कॉंग्रेस पार्टीके समर्थकोंको विभाजित कर देंगे। लेकिन हमने भी अधिक भयंकर एक अन्य द्वापके तथ्यावधि स्वतंत्रोंकी अर्थात् राजाओंके समूहकी चालें थीं, जिन्होंने जमींदारी समानिती बढ़ाने हुई मौंगके विरोधमें माननीय टिप्पणी रचाके लिये अपनी पार्टियों बना ली थीं। इनेशाकी तरह संगठित हिन्दू संप्रदायवादकी महात्म्या, जनसभ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक स्मिर्तोंकी शक्तिके साथ उन्हें बहुत समानता दिखाई दी।

इन तथ्यावधि कुलोन सबनोंने कुछ ने चुनावके समय लुटरीय संगठन यह धर्म उत्पन्न करनेके लिये किया कि नरेशोंके पुराने राज्योंमें नष्ट होनेके कारण उनके राज्योंमें अगलबगल फैली हुई ईश्वर वंशोंके लोग पुराने बशकमानुष राजसर्वोंके स्वागतके लिये आतुर हैं। गाँववालोंके विरुद्ध दावजनीने उन्होंने सहयोग दिया, सहायता दी और यदाकदा हमने भाग भी लिया। और फिर आदर्शोंन व्यक्तिके रूपमें प्रगट होकर इस अव्यवस्थाकी रोह न कर पानेके लिये कॉंग्रेसी प्रशासनकी भर्त्ता करते थे। भारतमें भूतनके विरुद्ध अभियानने जिसके फलस्वरूप अनेक छोटे-मोटे राजाओंको बंदी बनाया गया था, सामंतवादियोंके

नई प्रवृत्तियाँ

स्वतन्त्रको भंगकर दिया, लेकिन यह उस समय तक न हो सका, जब तक चुनावोंमें इन चालोंमें अनेक सदस्य निर्वाचित करवानेमें वे सफल न हो गये ।

कौंग्रेसकी कृष्टमे परिचित वामपंथियोंने सयुक्त मोर्चा बनानेका प्रयत्न किया, जिसमें उनकी विपरीत हुई शक्ति सगठित हो जाय । यह प्रयत्न विशेषरूपमें हैदराबाद और टाउनशोर-बोचीनमें सफल हुए, लेकिन अन्य भागोंमें वह इतने अव्यवस्थित और अमैद्धानिक थे कि कोई वास्तविक निर्णायक भूमिका न खेल सके, इसके अनिश्चित सगठनकी दृष्टिमें वामपंथी इतने शक्तिशाली नहीं थे, कि वे अखिल भारतीय स्तरपर कौंग्रेसका मुकाबला कर सकें । कम्युनिस्ट पार्टीने अपना आक्रमण उन्हीं क्षेत्रोंमें केंद्रित रखा जहाँपर महत्वपूर्ण संपर्क हुए थे और जहाँ अधिक नैयारी और हलचलके बिना ही जनताका समर्थन प्राप्त करनेकी आशा थी । केवल कौंग्रेस ही इस मैदानमें ऐसी पार्टी थी, जिसने ४००० विभिन्न निर्वाचित क्षेत्रोंमें प्रत्येक स्थानके लिए चुनाव लड़ा ।

जनताके मत प्राप्त करनेकी इन समूची प्रतिक्रियामें एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि प्रमुख राजनीतिक पार्टियोंमें जयप्रेमोंमें बहुत कुछ समानता थी । वह सब एक कल्याणकारी राज्यकी आवश्यकताको स्वीकार करते थे, जिसका अर्थ पूँजी-परिचयपर नियंत्रण था । यह सब है कि वामपंथियोंने समाजवादकी बात की थी और हिन्दू महासभाने यह घोषणा की थी कि वह वर्गहीन समाजकी सम्भावनापर विश्वास नहीं करती है, लेकिन जनताके उन्मूलक दृष्टिकोणोंमें बहुत मान्यता दी जाती थी । भूमिके निर्णायक प्रश्नपर जमींदारोंका विरोध किया जाता था और महाराजा केवल यही कह पाती थी कि यदि इन अधिकारोंको प्राप्त करना 'नितात आवश्यक' हो जाता है तो पर्याप्त क्षति-पूर्ति करनी चाहिये । सभी दल प्रमुख और मौलिक उद्योगोंके राष्ट्रीयकरणके सम्बंधमें सहमत थे, यद्यपि प्रमुख और मौलिक उद्योगोंकी व्याख्यामें यथेष्ट अंतर हो सकता था और भाषिक प्रांतिक निर्माणका विरोध करनेमें कोई भी दल साहज्य न कर सकता था ।

राजनीतिमें अंतरोंको बढ़ाचढ़ाकर बतलाना परंपरागत है, लेकिन भारतमें कोई निष्पक्ष दर्शक विभिन्न प्रवृत्तियोंमें समानताके स्तर न इन्हेंकी भूल नहीं कर सकता

निरक्षर व्यक्तियों की प्रौढ़ता

है। कुछ लोग कहेंगे कि भाग्य के शब्दाब्धियों के इतिहासकी यह विशेषता है। इस पारणास्य कारण चाहे जो कुछ हो, लेकिन वीर भी व्यक्ति इस तत्वकी उपेक्षा नहीं कर सकता कि विशेषतया आधुनिक कालमें अनेकों हितोंके प्रतिपादक और विचार गारा वाले राजनैतिक दल आवश्यकतासे अधिक, संयुक्त समाजके लिये न्यूनतम कार्यक्रमोंकी आवश्यकता पर जोर देते हैं। माध्याम्य चुनावोंमें संपूर्ण विषय भी इस वास्तविकताकी नहीं दिया मकल था।

चुनाव आरम्भ हुए। इसके लिये इतने विस्तृत संगठनकी आवश्यकता थी कि मतदानमें अनेकों मतदाताओंमें फैलाना पड़ा। अतिरिक्त व्यक्तियोंके शाप और अनु-शासित दलपर मतदानमें देखकर समार आश्चर्यचकित रह गया। लगभग १० करोड़ ४० लाख अर्थात् ६० प्रतिशत निर्वाचकोंने अपने इस महान अधिकारकी प्रयोग किया।

यह आश्चर्य उम समय और भी बढ़ गया, जब यह पता चला कि यद्यपि २२ मेंसे १८ राज्योंमें वंशिय भारी बहुमतमें जीती है लेकिन उन्हें लगभग ४२ प्रतिशत से कुछ कम मत ही प्राप्त हो सके हैं। अस्तव्यस्त साम्यवादी पार्टीने अपनी भूमिगत कार्यवाहियोंके उपरान्त एक भीमिन क्षेत्रमें सुदृढ़ करनेके बावजूद भी विरोधी दलका नेतृत्व प्राप्त कर लिया है। हिन्दू सम्प्रदायवाद उन स्थानोंमें भी बुरी तरह हार गया जो दूरे और लूटने केन्द्रस्थान रहे थे और गंगा-जमुनी समाजवादो, जिन्होंने यद्यपि १ करोड़ १० लाखमें अधिक मत प्राप्त किये थे, वास्तवमें पराजित हुए, क्योंकि समस्त नया विधान सभाओंमें उनका विरोध कम और प्रभावहीन था।

यह परिणाम निरक्षर व्यक्तियोंकी प्रौढ़ताके खोजक थे, जिन्होंने मतदानमें, अधिक निर्झर्षित, नईव अपने सुनिश्चित भागोंपर ही चलेनेवाले यूरोपियनोंमें भी, अधिक सन्नमतायी दिसलाई थी। हमने भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि बरकरार मतधिकारका एक बार स्वाद चखनेके उपरान्त चाहे शासकवर्गके कुछ तत्व यह सोच लें कि प्रजापंथ यहाँ सुनिश्चित नहीं है, पर भारतीयोंकी इस अधिकारसे वंचित होनेके लिये तैयार होनेकी संभवता नहीं थी।

नई प्रवृत्तियाँ

नेहरूको यह समझने का न लगी कि कॉंग्रेस पार्टीने क्या अपेक्षा कर जाती है। अब कॉंग्रेस अपनी पुरानी सेवाओं और परंपराओं का भरोसा नहीं कर सकता था। उसे अपनी प्रतिदिन की नीति-पत्रों के द्वारा ही समर्थन प्राप्त करना पड़ेगा। यह बात कैसे पूरी की जाय, यह एक बड़ी समस्या थी। लेकिन उन कॉंग्रेसी सदस्यों को जिन्होंने चुनाव में भाग लिया था, एक परिपत्र भेजते हुए नेहरूने आदेश दिया कि मुनिरिचल आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत एक मुक्त राजनैतिक पार्टी के रूप में काम करने की आवश्यकता है।

जुलाई तक उन्ना प्रदर्शन जमावारी मनात हो चुकी थी। अक्टूबर तक गामु-दायिक परियोजना प्रशमन प्रानीय भारतको उनके मध्यकालकी ओर उन्मुख करनेके लिये जारी कर दी गयी थी। औद्योगिक कामगारों की एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा परियोजना अर्थात् निर्वाह निधि के लिये उनमें पैसा कटना आरम्भ हो गया। दिसम्बर तक रु० २०६६ करोड़ की प्रथम पंचवर्षीय योजना नई मण्डल के मामले में स्वीकृत प्राप्त करनेके लिये प्रस्तुत हो चुकी थी।

सचमुच एक कठिन समस्या के मुलामने के लिये यह प्रयत्न बहुत कम थे, लेकिन कॉंग्रेस के आर्थिक दृष्टिकोण में नई अविवेकितता आ गयी थी, जो समय बीतने के साथ-साथ बड़कर परिणामस्वरूप मनाच्य पार्टी के अंदर दलों की कूट बहनेवाली थी।

अनकी उपलब्धि कम थी। रोजगार मुश्किल में मिलने थे। फिर भी लोगों ने मांग देकर पार्टी को पुनः सत्ता में कर दिया था, चाहे उनकी वास्तविक शक्ति भले ही कम हो गई हो। यदि महत्वपूर्ण समस्याओं की ओर अब भी ध्यान न दिया गया तो अगला निर्वाचन कॉंग्रेस की हार दख सकता था। प्रथम, वास्तविक स्वतंत्र, अमिल भारतीय सरकार की नीति में इन्हीं विचारों की प्रधानता थी।

अंतर्राष्ट्रीय स्तर में भी भारत ने एक अधिक दृढ़ विदेशी नीति अपनाई। दुनिया के कुछ अब पहले की तरह इनने अधिक उग्रस्थित नहीं होने थे। सामान्य निर्वाचन होने तक बार-बार इस बात पर बल दिया जाता था कि भारत तटस्थ ही नहीं बन सकता तटस्थ है। कठिन चुनाव घोषणा-पत्र में इन सक्रिय तटस्थता का स्पष्टीकरण 'स्वतंत्र' किया गया। विदेशनीतिक यह रूप उस समय मामले आया जब कि

सागर-वासियों के सामने संयुक्त राज्य अमेरिका की युद्ध-नैयामियों अधिकाधिक स्पष्ट होती जा रही थीं ।

अफ्रीकानों भी विस्फोटक स्थिति बढ रही थी । मिश्र, ईरान, मध्यपूर्व और भूमध्य सागर के तटवर्ती देश उत्तेजित हो रहे थे । २७ मई १९५२ के दिन यूरोप ने नाटो के ६ विदेश मंत्रियों ने एक यूरोपीय मैनार्की स्थापना करने के लिये एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिये ।

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा जापान को पुनः सशस्त्र करने और उसे युद्धसामग्री, युद्धपोत और वायुयान निर्माण की शक्ति देने के कारण एशियामें भी तनाव था । कोरिया प्रश्न की पृष्ठभूमिमें पहुँचाने के उपरान्त अमेरिकन विधायनीति ने युद्ध की शान्त सुनिश्चाने के लिये हिन्द-चीन को चुन लिया था ।

साम्राज्यवाद की इन चालों की स्पष्ट विवेचन नेहरूने १२ जून की की थी जब उन्होंने उत्तरी, अन्तर्जातीय सचिव सङ्गठन और संयुक्त राष्ट्र की एशिया और अफ्रीकामें वर्तमान उपनिवेशवाद की रक्षा के लिये पञ्चसत मन्त्रियों के रूपमें परिवर्तित होने की प्रवृत्ति के प्रति भारत सरकार की चिन्ता व्यक्त की । उन्होंने कहा कि अपने निरिच्छित पक्ष को छोड़कर धीरे धीरे अग्रगण्य रूपमें उपनिवेशवाद के रद्द करने की ओर संयुक्त राष्ट्रसंस्था मुख्यावश्यक है । साथ ही साथ शान्ति की एक महान सन्ध्या समझने के स्थानपर, उसके कुछ सदस्य उसे युद्ध आरम्भ करनेवाले सङ्गठन के रूपमें अधिकाधिक देखने लगे हैं । ”

समझमें व्यक्त करने के लिए यह दृष्टिकोण बहुत शक्तिपूर्ण था, क्योंकि इसमें भारत की तथाकथित साम्यवादविरोधी अभियान के विरुद्ध करके अफ्रीकामें होनेवाले मुक्ति-आन्दोलनों का जिन बना दिया ।

मिश्र के मुल्तान फाटने लगी छोड़ दी थी और नगीब नमीर के नेतृत्वमें सैनिकों द्वारा नियंत्रण था । इसमें अधिकृत ट्यूनीशियामें आगमन घेराबंदी की स्थिति हो गई था और अल्जीरियामें भी सुडमेडो के समाचार मिले थे । ब्रिटिश अधिकृत कनियामें स्वतंत्रता रिमागुण सूर्य बहोने क्षेत्र प्रवासियों में होने लगा था । दक्षिण अफ्रीका की रणभेद-नीति ने जो अब बहुत जोरों पर थी उस "अरब महादीप" के सभी स्थानों पर सर्वधर्मों में तनाव पैदा कर दिया था ।

नई प्रवृत्तियाँ

ऐसी स्थितिमें भारत निरपेक्ष दार्शिकों के समान बैठकर यह सब नहीं देख सकता था क्योंकि इस अफ्रीकन अणुनोपक्ष केवल अनेक भारतीय जातिवर्गों ही सम्बन्धित नहीं थीं, वरन् विश्व समस्याओंमें भारतीय शक्ति भी इस बात पर आश्रित थी कि यह इमराजल और तेल नीलाने सुनम अफ्रीका और अरब समारका कितना समर्थन प्राप्त कर सकते हैं ।

अफ्रीका और मध्यपूर्वकी समस्याओंका विरोध करनेका अर्थ भारतको साम्राज्यवाद और विशेष रूपसे ब्रिटेनके साथ सीधे तथ्यमें लाना था । दिल्लीका शासकीयक्षेत्र इस बातको अच्छी तरह समझता था, लेकिन घटनाक्रमने भारतको इसमें पेंगनेके लिये विवश कर दिया ।

तथापि ध्यान देनेकी बात यह है कि इस कार्यकी आलोचना करते समय इस क्षेत्रमें ब्रिटेनके दखल देनेवाली बातकी ओरसे आस्थावी रूपमें आशंका फैल चुकी थी । विशेष रूपसे फ्रांसीसी उपनिवेशवादके विरुद्ध आन्दोलन किया गया था । एशियायी दृष्टिकोणमें यह बात इस कारण प्रभाव डाल मनी क्योंकि हिंदीचीनकी घटनाओंमें भी प्रलय सम्बन्धित था ।

विदेशी मामलोंमें भारतीय स्वतंत्र दृष्टिकोण काश्मीर प्रश्न पर यथेष्ट प्रभाव डालना रहा । सुयुक्त राष्ट्रके प्रतिनिधि प्रोफ़ेसर आइडमने मितवरमें यह घोषणा की थी कि वह भारत और पाकिस्तानके बीच कोई समझौता स्थापित न कर सके । नवम्बर तक काश्मीरकी विधान-निर्मात्री-परिषद उत्तराधिकारी शासन व्यवस्थाके स्थानपर भारतके साथ राज्यके बिलीनीकरणको स्थायी रूप प्रदान करनेके लिये कार्यरत हो गई थी । यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं थी कि सालगी समाप्ति तक काश्मीरमें सप्रदायवादी हिन्दू-प्रजा-परिषदका आंदोलन आरम्भ हो गया था जो ऐसा मालूम पड़ता था कि साम्राज्यवादियोंकी मीनानुकूलता पर किया गया है ।

यही आंदोलन था जिमने शेख अब्दुल्लाको 'स्वतंत्र काश्मीर' का विचार प्रोत्साहित करनेका मौका दे दिया, जिस बारेमें वह महीनों पहलेसे मनसूबे बंध रहे थे । ध्यान देने योग्य बात यह है कि अमेरिकन ममाचार-पत्रोंमें लगभग उनी समय उनकी चापलूसी करनेवाले लेख प्रकाशित हुए । 'वाशिंगटन पोस्ट'

नजर पत्रम एक लेखकने यहाँ तक लिख दिया की काश्मीरका बचा बचा अन्दुलाके पीछे चलेगा ।

दिल्लीके यथार्थ वादियोंके लिये 'स्वतंत्रता' के ऐसे सिद्धान्तोंका केवल यही अर्थ हो सकता था कि काश्मीर विश्रामदान करके अमेरिकामें मिला जाय, क्योंकि केवल यही बहुमूल्य नैतिक मोर्चेके बदलेमें हम प्रकारकी बनावटी स्वतंत्रता प्राप्तमें सहारा द सकता था । आश्चर्यकी बात यह है कि भारतमें कुछ प्रगतिवादी भी हम प्रकारको विचारधाराका तब तक समर्थन करते रहे, जब तक कि उन्होंने अपने विचारोंके सम्भावित परिणामोंको नहीं समझ लिया ।

अन्दुला-काश्मीर अमेरिकी हाथ होनेसे, जिसकी पुष्टि अन्तर्गत सरकारने अनेक बार की है, भारत और अमेरिकी बीच बढनेवाले मतभेदोंकी ओर ध्यान रेखित हो जाता है, वहाँकी घटनायें, खुले विरोधका केवल एक ही पहलू थीं ।

पहले यह दोषारोपण किया गया था कि अमेरिकन कूटनीतिज्ञ, नेपालके अराण क्षेत्रमें सामनवादी शरणार्थियोंको भारतीय सत्ता और सहायतासे अस्वीकृत करनेकी पूरी पटा रहे हैं । उनकी पूर्वी सीमाने नानाक्षेत्रमें वहाँ निवास करनेवाली जातियोंमें भी अमेरिकन धर्मप्रचारक कार्य कर रहे थे । धर्म परिवर्तन करनेवाले नये व्यक्तियोंमें यह सिखलाया जाता था कि उन्हें भारतके समान विधनी राज्यमें अना होना चाहिये । हिमालयकी उत्तरी सीमाके गहारे चीनी जन गणराज्य और तिब्बतके विरुद्ध अमेरिकन गुप्तचरोकी कार्यवाइयोंकी भी सूचना मिली थी ।

जब काश्मीर संकटका विवरण प्राप्त हुआ, जैसा कि होना चाहिये था वास्तविकता सामने आ गई । यह पता चला कि स्वतंत्रता और व्यक्तिगत शक्ति प्राप्त करनेके विचारोंमें डूबे हुए शेर अन्दुलाको अमेरिकन कूटनीतिज्ञोंने उन्माद प्राप्त हुआ था । उनका निधयको दृढ़ बानेके लिये अर्थ और प्रचार दोनों तरहकी सहायता देनेकी भी प्रतिज्ञा की गई थी । इनकी ओरसे पाकिस्तानमें भी संपर्क स्थापित किया गया था । राष्ट्र सदीय प्रेसकोंमें भी सम्भावित शायकीय परिवर्तनका इशारा कर दिया गया और वे हम काममें अपनी सेवा प्रस्तुत करनेके लिये तैयार थे ।

नई प्रवृत्तियाँ

इस कार्यवाहीको जितनेके लिए प्रकाश परिषदका आदेशोत्तर केवल एक परदा था । इस संपूर्ण कार्यवाहीमें समस्त मध्य पूर्वमें छिप कर आक्रमण करनेके अमेरिकन ठेगानी गथ आ रही थी ।

अगस्त १९५३ में कुश्तानापूर्वक रत्न हुए इस पक्षपक्षका प्रमाण सरकारके हाथ आ गया । अनुत्ता और उनके सहयोगियोंमें बंदी बना लिया गया और इस प्रकार एक सफटपूर्ण परिस्थितिमें रचा हो गई ।

अनुत्ताके विरुद्ध की गई कठोर कार्यवाहीने भी अमेरिकाका राज्य विभाग अनुत्ताहित नहीं हुआ । उन्होंने अपना जाल पश्चिमामने फैलाया, जहाँ प्रान मजोपदका कार्यभार नाजिमुद्दीनने उनके निदू मुहम्मद अलीन ले लिया था । यह गरम अफवाहें थीं कि कगबो-वाशिष्टनके बाय एक भुगीका निर्माण हो रहा है । लेकिन इसके बारेमें आंग बनानाबने ।

महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत और अमेरिकाके सम्बंधोंमें यह गम्भीर प्रकाशमय परिवर्तन उस समय हो रहा था जब ५ मार्च १९५३ को स्टालिनका मृत्युके उपरान्त सोवियट सभने अन्तर्राष्ट्रीय तनावको कम करनेके उद्देश्यमें पूर्व कालीन औपनिवेशिक तथा समारके अविश्वसित क्षेत्रोंके साथ निकट आर्थिक और राजनैतिक सम्बंध स्थापित करनेके लिये एक नाटकीय नीति अपनाई था । इसके अतिरिक्त अगस्त १९५३ में मेलोवोदने यह प्रकट किया था कि हमने उद् जन बम बना लिया है जो सयुक्त राज्य अमेरिकाकी युद्ध नैवारियोंके लिये एक अतिरिक्त प्रतिकार था ।

हर जगह सम्राज्यवादी पाठे हट रहे थे और वह वर्गोंमें पूर्वस्थिति एक विश्वमनोयताकी ओर ध्यान न डकर तेजोंने निज खोजनेमें लगे हुए थे । अफ्रीकामें मुक्ति-आदेशोत्तर प्रभावित-क्षेत्रका विस्तार हो रहा था । यद्यपि ईरानमें परिवर्तन हो चुका था, जहाँ साहनी प्रानमया मुमद्दीनको अमेरिकापर अश्रित सैनिक क्रांतिके द्वारा पद-अष्ट कर दिया गया था, फिर भी प्रामीमी सम्राज्यकी दीवाल गिर रही थी । विनाश आक्रम उल्लंघन कर रहा था । मोगकी विद्रोहमें सम्मिलित हो गया था ।

अमेरिकन नीति

अमेरिकन नीतिमें लश्कू पन प्रमुखतया संयुक्त राज्यके सामान्य चुनावोंमें रिपब्लिकन पार्टीके सत्तापक्ष राजनैतिक पार्टीके रूपमें प्रतिष्ठित होनेके कारण क्षया था। जनरल आर्सेन द्वारा की अभ्युत्थानमें नई सरकार परिस्थितियों सुभलक्षितों व्यस्त हो गई, लेकिन भारतका स्पष्ट विरोध निम्न-शक्तियोंका समुदाय बदलने ही वाला था।

भा पा वा द

चाहे हम चलते हों, बैठे हों, खड़े हों अथवा दावों या धारों पैर उठाते हों, हमें अपनी जन्मभूमिको चोट नहीं पहुँचानी चाहिये ।

(अथर्ववेद)

भारत जैसे देशमें विदेशी परिवर्तनोंका आतंरिक नीति पर ख़ूब प्रभाव पड़ता है । ज्यों ही १९५२ में यह स्पष्ट दिखलाई पड़ा कि वर्तमान आर्थिक समस्याओंके मुलभूतमें पूँजीजीवियोंकी सहायता करनेके लिये साम्राज्यवादी नहीं आ रहे हैं और भारतको अपने प्रयत्नोंका ही भरोसा करना पड़ेगा, राजनैतिक विचारधारेमें भी परिवर्तन होने लगा ।

यह विश्वास फल गया कि आर्थिक क्षेत्रमें सरकारी हस्तक्षेपक बिना कोई प्रगति सम्भव नहीं है और सरकारका सहारा लेनेकी आवश्यकताका प्रभाव यह हुआ कि पूँजीजीवियों और उनके राजनैतिक मध्यन वर्गमें भारी मनभेद हो गया ।

कठोर प्रयत्नों द्वारा भी बड़े व्ययनाशी निजी प्रयत्नके भारी उद्योगोंके विकासके लिये निजी पूँजी कभी प्राप्त नहीं कर सकते थे । इस कारण उन्होंने यह निर्णय लिया कि चाहे सहायताका अथ वित्तीय मदद भले ही हो, लेकिन फिर भी पूँजीजीवियोंके द्वारा देशकी आर्थिक उन्नतिमें सहायता करना सरकारका कर्तव्य है । इसका अर्थ यह था कि सरकारको जनतापर कर लगाकर उस पैसोंको भारतीय व्यापारियों और औद्योगिकोंको देना चाहिये । वास्तवमें यही ऐसा नारा था जिसे सभी पूँजीजीवियोंका समर्थन प्राप्त होता ।

लेकिन पूँजीजीवियोंके मध्यम वर्गीय लोग इस सम्भावनाके बारेमें बिलकुल प्रसन्न नहीं थे । उनके बड़े भाइयोंका लाभके समस्त स्रोतों पर एकाधिकार बहुत दिन रह चुका था । उन्होंने अपने कम शक्तिशाली माधियोंको विकास और प्रसारकी सुविधाओंमें काफी समय धरित रखा था । अब चूँकि बड़े स्तर पर लाभ हो सकते थे, मध्यम पूँजीजीवियोंने यह अवरय सोचा कि इस सम्भावना का आत्मसमर्पण बड़े पूँजीजीवियोंके सामने न किया जाय, क्यों कि यदि वैयक्तिक

पूँजीजीवियों की विशेषता

उद्योगोंमें सरकार द्वारा सहायता देनेका नारा सुनद किया जाता है, तो उसका असली तन्त्र नौ बड़ी हडप कर जायेंगे।

सभी पूँजीवादी समाजोंमें सामान्यतया विशाल सह बड़े और मध्यम पूँजीजीवियोंका सघर्ष भागमें एक विशेष प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनकी अपनी कुछ निजी और एकात्मिक विशेषताएँ हैं। हमके विशेष अध्ययनकी आवश्यकता है, क्योंकि इसी बात पर बोधिम पाट्टिकि आर्थिक दृष्टिकोणमें होनेवाले कामधंधी सुव्यवस्था समझना आश्रित है।

यह मानी हुई बात है कि प्रत्येक पूँजीवादी देशके पूँजीजीवियोंमें अनेक सामान्य विशेषताएँ होती हैं, जिसके कारण हमें आर्थिक और राजनीतिक इतिहासमें उनके विशेष रोलको समझनेमें सहायता मिलती है। लेकिन इसी विशेषतापर इतना अधिक बल दिया जाता है कि इसके कारण प्रत्येक देशके पूँजीजीवियोंकी रचनाकी अन्य विशेषतायें धुँसली पड़ जाती हैं जो उनमें भिन्न हैं और जिनकी जड़े उसी देशकी जनताके इतिहास और विकासमें उमी हुई होती हैं। भारतीय पूँजीजीवियोंमें इस प्रकारकी विशेषताओंका भाग सामान्यमें अधिक है।

आश्चर्य, इस मरीजकी हम सचेष्टमें परीक्षा कर डालें। इतिहासज्ञ भारत सम्बन्धी पूरी बातों पर विश्वास नहीं करने, लेकिन उसके ५००० वर्षोंमें अधिकके कुछ अस्पष्ट और कुछ स्पष्ट इतिहासमें यह बात पूर्ण रूपसे प्रकट हो जाती है, कि भारत कभी संयुक्त इच्छा नहीं रहा। पूर्वघातमें अपनी सार्वभौमिकताकी घोषणा करनेवाले बड़े-बड़े साम्राज्य अवरय स्थापित हुए थे। वह एक विशाल क्षेत्रमें फैले हुए थे और अपने आदेशोंका पालन करवानेके लिये उन्होंने एक बड़ा विशाल नौकरशाही यंत्र स्थापित कर रखा था। लेकिन मौर्य, गुप्त, कुशान और सप्तवाहन सामनवाल्में भी एक साम्राज्यमें भारतके समस्त भूभागका नियंत्रण नहीं किया। देश अधिकतर अनेक राजवंशोंके प्रभावमें रहा, जिनमें कुछ ने अपने विरोधियोंके ऊपर सर्वशक्तिमत्ता स्थापित कर रखी थी, लेकिन जो सफ्टकालमें अपनी साम्राज्यवादितान्त्रिक दावा बहुत कम ही प्रमाणित कर पाते थे।

भा पा चा द

हम यह भी जानते हैं कि भारतमें अलग-अलग भाषा, लिपि और रीति-रिवाजों वाली अनेक स्पष्ट सभ्यताएँ पल्लवित हुई हैं। यद्यपि बहुत कुछ समान बातोंसे ही यह निरली थी, लेकिन उन्हें अपनी स्वतंत्र विशेषताएँ थीं। यदि सुदृढ़ता निर्माण वालीन भूतकालमें कोई शक्तिशाली एकता स्थापित करनेवाली मत्ता होती, तो निश्चिंद भारतीय एकतामें व्याप्त विभिन्नता और अनेकरूपता, सम्भव नहीं हो सकती थी।

सामन्य प्रदान करनेवाले वर्तनीयोंके आगमनके साथ ऐसी शक्ति प्रकट हुई जिसने लूट और अधिपतित्वेशिक प्रशासन स्थापित करनेके लिये भारतके विभूत क्षेत्रों और करोड़ों निवासियोंको एक केन्द्रीय व्यवस्थासे आधीन कर दिया। लेकिन वह बहुत विनम्रमे आये थे। भारत विभिन्नतामें पड़लेमे ही धनी था और अब सभ्यते लिये सुयुक्त हो गया। निर्दय साम्राज्यवादके सम्पूर्ण अन्याचार भी उस चाजको नष्ट न कर सके, जिने कुछ लोग भारतकी अनेक राष्ट्रीय विशेषता कहते हैं।

विदेशी ब्रिटिश शासकोंपर इन विशेषताने इतना स्पष्ट प्रभाव डाला कि कुछ समय उपरान्त अपनी मत्ता कायम रखनेके लिये उन्होंने इसी विभिन्नताका उपयोग करनेका प्रयत्न किया। राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दुओंको मुसलमानोंमे लडाया गया और उन क्षेत्रोंमें जहाँ इन प्रकारका भाषाईय विभाजन नहीं था, दूसरोंकी सारथानीमे तैयार किया गया। स्वेच्छापूर्वक भारतकी प्रांतोंमें विभाजित किया गया, जिसके लिये सर्वधानिक शब्द था, “सुविधाजनक प्रशासनिक इकाईयें”। लेकिन अधिकतर प्रांतोंमें दो या दो से अधिक भाषिक-सांस्कृतिक समूहोंको इकाई रखा गया, जिसमें वह ‘बादो और राज्य करो’ नीतिके सहज शिकार बन सके।

विलीनीकरण बहुत कम ही हो मत्ता। लुटेरे विदेशियोंकी उपस्थितिमें भी सम्प्रदायोंके बीचकी खाई न पादी जा सकी। धीरे धीरे प्रांतोंके निर्बल साधियोंके ऊपर दूसरा समूह प्रधानता स्थापित करना गया।

तनाव बढ़े। उनके अंतर अधिक स्पष्ट रूपमें व्यक्त होने लगे। लामिसोंने सेलहू और मलयालमों पर प्रधानता प्राप्त कर ली, मराठोंपर गुजराती छू गये, बंगाली, बिहारियोंमे पृष्ठा करते थे आदि। साम्राज्यवादी प्रशासनके लिये यह अक्षी स्थिति

थी, पर भारती ऐतिहासिक प्रगति पर इसका पूरा प्रभाव अच्छी तरह समझना अभी शेष है।

अनेक लेखक और राजनीतिक-मिलेयक हिन्दू-मुसलमानके प्रश्न तक अपनेको सीमित रखते हैं और वह मही रूपसे इसे घृणाका एक अस्थायी परिणाम समझते हैं, एक ऐसा रोम जो धर्मनिरपेक्ष दार्शनिकोंके निरंतर प्रचार द्वारा दूर हो जायगा। कुछ लोग इस फूटका प्रमुख कारण उत्तरी भारतवासियोंकी राजनैतिक क्षेत्रमें प्रगति और दक्षिण भारतवासियों इस स्थितिके प्रति असह्य बनताते हैं।

इस मनभेदकी विद्यमानताको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। यह अंतर उतना ही पुराना है जितना रामायण। विषयवर्तन-स्थला सामाज्य तौरपर इसकी भागेलिक विभाजन रेखा है। यह समझा अनेक नियमोंमें व्यक्त होनी है, लेकिन इस सनन भाव ही इस तनावका मुख्य कारण थी। दक्षिणवासी इसे 'हिन्दी-माप्राज्यवाद' कहना पसंद करते हैं।

इस मनभेदकी भाविष्यमें काफी होशियारीमें समालना पड़ेगी, लेकिन आज भारतके विकास पर इसका प्रभाव इनना निर्णायक नहीं है, जितना देशके अन्दर विद्यमान अनेक स्पष्ट मान्यनिक और भाविक दलोंका है। अधिकतर यह तत्व समझने नहीं आता। मार्क्सवादो लखत तक उसे बहुत ही पानि और सीमित लगने समझते हैं। भारतीय पूँजीजीवियोंका अध्ययन केवल इसी सांस्कृतिक और भाविक तनावकी पृष्ठभूमिमें किया जा सकता है। इस क्या देखते हैं?

ब्रिटिश सामन और उसके बादके बयोंमें भागने बड़े पूँजीजीवियोंका शीघ्रता-पूर्वक पतनित होना देखा है, जिन्हें साधारणतया बड़े व्यापारी-तत्व कहा जाता है। दोनों विधियुक्त तथा पैसा पैदा करनेके प्रत्येक अवसरके कुशलतापूर्वक दोहनके कारण बाहे उसका अर्थ माप्राज्यवादी पूँजीमें मनमौता करना हो, साथ ही साथ पैसे द्वारा स्वयंका आदोलनोकी मशयल देनेके कारण ये तत्व आर्थिक और राजनैतिक जीवनमें आगे आये।

एक विद्वत्को अंग्रेजोंकी ओरसे खिताब मिलते थे। दूसरा विद्वत् कांग्रेस नेताओंके विरवागवाजके रूपमें काम करता था। अपनी स्थितिके चलपर वह इस

भा पा बा द

प्रकारका दोन्ना पार्ट सरलतामे भेल पाते थे और जब राजनैतिक आधार पर हिन्दू महासभाका मितरा उगता हुआ दिखलाई पड़ा, निश्चय वहाँ भी अपनी उँगली रखनेमें पीछे नहीं हटे ।

साम्राज्यवादियोंने जेना विरोध केवल इसी सीमा तक था कि वे उनके एकाधिकारी फैलावके विषयमें बाधा उपस्थित करते थे और बिदलाओंकी विचारधारा डाटा, टालमिया, गोइनरा, सिंधानियों आदि बड़े व्यापारी ' परिवारों ' से कुछ विशेष भिन्न नहीं थी ।

भारतीय बड़े पूँजीजीवियोंने अपना जाल सारे देशपर फैला दिया और ताम्रलोठों से लेकर रेल इन्जन तक, खाना परजनेके स्निग्ध पदार्थों से लेकर बढिया इस्पात तकका उत्पादन आरम्भ कर दिया । अपनी एकाधिकारी पद्धति अधिक दृढ़ करनेके लिये उन्होंने अपना सम्बंध विदेशी कम्पनियोंने भी स्थापित कर लिया, बाहे इसका अर्थ नष्ट, चोर्लोका ही बचना हुआ । लाभके किसी क्षेत्रको उन्होंने धाँकी नहीं छोड़ा ।

इस विषयमें टाटा और निदला एशिया और अजीमाके पिछड़े हुए क्षेत्रोंमें काम करनेवाले व्यापारियों और संचालकोंके बहुत कुछ समान हैं तथापि एक तत्व ऐसा भी है जिसका उदाहरण अन्यत्र नहीं मिल सकता । थोड़ेमे अववादोंको छोड़कर भारतके बड़े पूँजीजीवी अधिकतर मारवाडी व्यापारी हैं । वे विवाह और अन्य दगरी दस्य और अशस्य प्रभावोंसे परस्पर जुड़े हुए हैं । उनमें टाटा सरीछे जो थोड़ेसे गैर-मारवाडी हैं, उन्हें भी उनके राजनैतिक नेतृत्वके पीछे चलना पड़ता है । उनके अखिल भारतीय कार्य-कलाप उन्हें मध्यमवर्गीय पूँजीजीवियोंके हितोंके सधर्ममे ला देते है, क्योंकि विदेशी अपने साधियोंके शिष्ट इनका आधार क्षेत्रीय है और ये आवश्यक रूपसे अपने ही भाषिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमें व्यापार करते हैं । धनवानोंका यह कम शक्तिशाली भाग निदला और टाटाको अपना बड़ा भाई नहीं समझता जिनका वे सहारा ले सकें, वरन् वह उन्हें एक नये ढंगका आर्थिक साम्राज्यवादी समझते हैं जो भारतीय रचना करनेवाले विभिन्न स्पष्ट भाषिक क्षत्रोंकी उन्नतिके बाधक है ।

बड़े पूँजीजीवियों और विदेशी पूँजीके विरुद्ध होनेवाला यह संघर्ष बहुत बामनविरुद्ध है। जब किरलोस्कर डिजिटल इंजनोंका उत्पादन आरम्भ करते हैं तो बिष्टला या टाटा उसका अधिक ऊँचे स्तर पर उत्पादन आरम्भ करके किरलोस्करकी तरफ़ी रोक देते हैं, जब स्थानीय सोडा वाटरकी फेक्टरियोंकी शक्ति होती है; कोय कोल उनका व्यापार सन्नात कर देता है। निश्चय अपनी माडकी मोटरों बेचना चाहते हैं और इस बातका प्रयत्न करते हैं कि मोटरोंके विषयमें देशकी आयात नीतिमें आवश्यक परिवर्तन कर दिया जाय। दियासलाई बनानेका दक्षिणने कुटीर उद्योग करने वालोंकी 'विमको'से कड़ा मुद्रावला करना पड़ता है। गोदरेज और अन्य छोटे मोटे साधुन निर्माताओंकी लोवर वर्करी सरीखी सगुच्छ कंपनियोंका सामना करना पड़ जाता है। यदि कोई मशीन बन्ना बनानेकी मशीनके निर्माताकी बात करता है तो निश्चय उनमें आगे बढ़ जाते हैं और अपने उन्हें स्वयं अहमदाबादमें मिल शक्तिसे बालूना पड़ता है, जो अपने सामान्यके लिये उन पर आश्रित नहीं रहना चाहते। और मरावाकी इस बातका इनीमान करनेके लिये मुद्रावलायोर भी एकविध स्थापित कर डालते हैं कि स्थानीय पत्रोंका न तो पूर्ण निरक्षण हो, न उन्हें विज्ञापन मिले और अपने में ये चल भी न सकें। इस बातके असाध्य उदाहरण गिनाये जा सकते हैं। इन सब बातोंमें यही दोषता है कि भारतीय और विदेशी एकत्रिपति एक दूसरेके पूरक बन कर इस प्रयत्न करने करते हैं, जिनमें भारतीय सामृतिर क्षेत्रोंमें उनके छोटे पूँजीजीवी भाइयोंकी कार्य करनेका अवसर ही न मिल।

इन लोगोंका भय उचित ही था, क्योंकि जिन क्षेत्रोंमें वे कुछ शक्ति कर सके उसमें भी सहजताके लिये उन्हें अधिकतर इन अमिल भारतीय व्यापारी क्षेत्रोंका सहान होना पड़ता था और सहजताके साथ उनके अपनेक उपग्रह जुड़े रहते थे। यदि मध्यमवर्गीय पूँजीजीवीके अधिकांशोंके पूँजी डोपेकी परीक्षा की जाय, तो यह पता चलेगा कि वे बालकमें अपने स्वाना नहीं हैं।

भारतीय पूँजीजीवियोंकी रचनाय यह रूप पहली बार देखने पर अच्यवस्थित भले ही मालूम पड़े, लेकिन जितना ही उन्हें ऐतिहासिक रूप और वर्तमान परिस्थितिकी दृष्टिसे पता जाता है, उतनी ही परिस्थिति साफ़ हो जाती है। बड़े पूँजीजीवी

भा या चा द

जिनका संचालन क्षेत्र समस्त भारत है और जो अधिकतर मारवाड़ी है, आर्थिक विदोहनके लिये अपने ही भाषिक क्षेत्रमें निर्वाध अधिकार चाहनेवाले नव्यम पूंजी जीवियोंकी उन्नति और प्रसार रोकने हैं ।

यह सच है, जो प्रमुखतया आर्थिक है, उस समय राजनैतिक स्तर तक पहुँच गया, जब राज्यको देशके साधनोंको विकसित करनेके लिये प्रयत्नशील होनेके लिये विवश होना पड़ा, क्योंकि साम्राज्यवाद उन शर्तों पर सहायता देनेके लिये तैयार नहीं था, जिनकी उपयुक्तता उनके बड़े पूंजीजीवी मित्र स्वतंत्रता और सार्वभौमिकताके प्रति जागरूक जनताके सामने निरुद्ध कर सकते । आर्थिक नीतिमें राज्यके नेतृत्वका प्रश्न बड़े और मध्यम पूंजीजीवियोंके बीचके इस सघर्षमें राजनैतिक कर्पावलि पर पहुँचा देता है ।

प्रारम्भिक रूपमें यह सघर्ष देशका सांस्कृतिक-भाषिक आधार पर पुन विभाजित करनेकी मंजूरि देनेके लिये होनेवाले राष्ट्रीय आंदोलनमें दिखलाई पड़ता है । मध्यम पूंजीजीवी अपने कार्यक्षेत्रमें हड़ता प्राप्त करनेके लिये यह कदम उठाना आवश्यक समझता है । निम्न प्रकार बड़े पूंजीजीवियोंने राजनैतिक शक्ति प्राप्त करनेकी आशासे अखिल भारतीय कोंग्रेसकी सहायता की थी, उसी प्रकार मध्यम पूंजीजीवियोंने नये राज्योद्देश निर्माणमें सक्रिय सहायता दी, ताकि वे उनके प्रभावमें रहें और सघर्ष नीति पर अधिक प्रभावशाली दवाव डाल सकें । मध्यम पूंजीजीवी अपने राज्योद्देशके निर्माणके लिये हड़ता चाहते थे ।

लेकिन उनके प्रयत्नोंकी स्पर्शा हमेशा इतनी स्पष्ट नहीं दीप्त पड़ती । मद्रासके तमिल और बम्बईके गुजराती आदिके समान प्रधान भाषिक-सांस्कृतिक वर्गके पूंजीजीवी यथेष्ट विरमिति हैं, जिन्हें 'बग' पड़ा जा सकता है । राज्य पुनर्रचनाकी भीम इनकी ओरसे इतनी जोरदार नहीं है, क्योंकि यह विरमिति बड़े राज्यके अपने निर्वल साथी पूंजीजीवियोंके प्रयत्नोंको दबा सकते हैं । लेकिन वह किम्वदन्त अधिकतर उस समय समाप्त हो जाती है, जब अखिल-भारतीय बड़े पूंजीजीवी प्रमुख शत्रुकी स्पर्शा उन्हें दीखने लगती है ।

राज्य पुनर्गठन आयोग

एक सुदृढ़ केन्द्रीय प्रशासनिक प्रतिपादक ढांचा विकसित आदि, प्रांतों की पुनर्गठनाधीनता को नहीं देना सके, क्योंकि अपनी प्रकृतिक कारण राज्यों में वे अपने कोई समर्थक न पा सके, वे बंगालियों, पंजाबियों, विहारियों, तेलगुओं, मद्रासीयों और मलयालियों में कोई बड़ा पूँजीजीवी न हों सके। शायद दम्बई शहर में रहनेवाले गुजराती व्यापारी, जो भारतीय एकाधिकारी पूँजी से जुड़े हुए हैं, उनके एकमात्र माथी थे। मद्रास अधिक विकसित, और भारत के मध्यमवर्गीय पूँजीजीवियों ने राजनैतिक रूप से सबसे अधिक सुगठित, अहमदाबाद के गुजराती भी अखिल भारतीय प्रभाव रखनेवाले इन वर्गों की शक्ति समाप्त करने के इच्छुक थे।

यह शक्ति समाप्त हो जा सकती है। नये ढंग से रचे हुए प्रांतों का अर्थ था, मध्यम पूँजीजीवियों द्वारा आसानी से नियंत्रित किये जा सकनेवाले व्यवस्थापिका सदस्यों का चुनाव। व्यवस्थापक प्रत्येक क्षेत्र में अनुचित विरासत करने पर बहुत कुछ जोर डाल सकते थे, जिस विरासत के लिए विशेष सहायता प्राप्त होती और जिसका अर्थ था अपने क्षेत्रों में प्रभुत्व, और बड़े पूँजीजीवियों द्वारा नियंत्रित, केन्द्रीय सरकार द्वारा शासित और विभाजित न होनेवाले मध्यम पूँजीजीवियों को लाभ के नये क्षेत्र प्राप्त करना।

और इसी कारण १९५२ के अखिर चरण में जब यह स्पष्ट हो गया कि सरकार अधिक विकास-कार्योक्त नेतृत्व करनेवाली है, भारत के सबसे अधिक पिछड़े हुए सांस्कृतिक मणिक क्षेत्र, आग्र में प्रथम भाषिकराज्य की घोषणा करनेवाला एक आरोलन पथक उभर। वहाँ के कमिश्नरों ने कमिशन के आदेशों की अवहेलना की।

पोद्दी श्रीरामलू ने पण्यराज आमतण अंतरान प्रारम्भ कर दिया। ५८ वें दिन उनकी मृत्यु हो गई। वे आग्र की एकमात्र प्रतीक थे और उनकी मृत्यु के परिणाम स्वरूप जोरा इतना बढ़ा कि दिल्ली को उनके सामने मुकना पड़ा। १९ दिसम्बर १९५२ को नेहरूने घोषणा की कि सरकारने यह मोग मान ली है।

एक वर्ष के अंदर ही अंदर, २२ दिसम्बर १९५३ को सीमाओं को पुनर्गठित करने के प्रस्तावों सभी दृष्टियों से परीक्षा करने के लिए राज्यपुनर्गठन आयोग की नियुक्ति कर दी गई।

भाषावाद

जब भविष्यके इतिहास रचयिता इन घटनाओंको लिखेंगे, उन्हें इन घटनाओंमें भारतीय प्रगतिमें एक नवीन निर्णायक रूप दिखलाई पड़ेगा। इस समयमें अपनी पृथक विशेषतायें रखनेवाले भारतीय मध्यम पूँजीजीवी देशकी नीतिपर अपना प्रभाव दालना आरम्भ कर देते हैं। भविष्यमें दो नये शब्द बहुत जनप्रिय बन जाते हैं “सार्वजनिक क्षेत्र”। ये दो शब्द बड़े पूँजीजीवियोंमें सन्तर्पण करनेके बड़े भारी दृश्य हैं।

यह ठीक है, कि आरम्भमें सार्वजनिक क्षेत्रकी नीति मध्यम पूँजीजीवियोंकी भी समझमें नहीं आई और यह मालूम पड़ा कि इसका अर्थ यही है कि आर्थिक कुशलताके हितार्थ पूँजीवादी सरकार कुछ कार्य अपने हाथमें ले लेगी। लेकिन यह दृष्टिकोण भी उस समय समाप्त हो गया, जब राज्यने सक्रिय रूपसे उन क्षेत्रोंमें भी प्रवेश किया, जिन्हें बड़े पूँजीजीवियोंने अपना आरक्षित स्थान समझ रखा था, जैसे इस्पात।

भारतका इस प्रकारके हस्तक्षेपका विचार ब्रिटेन और अमेरिकाके इसी प्रकारके कार्यसे बनेष्ट पृथक था। उनकी अर्थव्यवस्था विकसित है और वहाँ यदि राज्य किसी आर्थिक कार्यक्रमको स्वयं सँभालनेके लिये आगे बढ़ता है, तो उन्हीं क्षेत्रोंमें जिन्हें वैयक्तिक प्रयत्न विभिन्न कारणोंमें सफलतापूर्वक नहीं सँभाल सकते। भारतके सम्बंधमें यह बात नहीं है। नवीन अर्थव्यवस्थाकी तुलनामें यह देश अविकसित ही है और इस कारण राज्यके हस्तक्षेपका अर्थ केवल एक ही निम्नता है कि सरकार विकासद्योगों में नैतृत्व करके कमरा प्रभुत्व स्थिति प्राप्त करनेवाली है।

१९५२-५३ में शक्तियोंके इस विचित्र संगठनका कोई राजनैतिक विवेचन नहीं किया गया। फल स्वरूप भारत वामपंथियोंमें मित्यता करनेकी ओर बढ़ा। विदेशी समस्याओंमें नेहरूकी साम्राज्यवाद विरोधी स्थितिमें “दो शिबिरोंके बीच बगियेका तनाव” कहकर छल दिया गया और आश्चर्यकी बात यह है कि यही दृष्टिकोण दक्षिण और वामपंथी दोनोंने अपनाया था।

इस सम्बंधमें अनेक अंग्ल-अमेरिकन तेल-कंपनियों द्वारा भारतमें तेल शोधक अखाने स्थापित करनेके बारेमें होनेवाली सन्धियोंकी ओर ध्यान गया। इन सन्धियों-

के पल स्वल्प विदेशी पूँजीको आवश्यकतासे अधिक अच्छा व्यवहार प्राप्त हुआ, क्योंकि उन्हें अपने लाभ निभाल करनेकी आशा थी। केवल यही आत्ममर्षण दिखलाई पड़ता था। इसके अनिष्टिक और कुछ नहीं।

इस प्रकारकी परस्पर विरोधी नीति समाजिकजालमें अधिकतर दिखलाई पड़ती है। तथापि राजनैतिक विस्लेषणका कार्य इसकी मुख्य प्रवृत्तियोंको हूँदना, वर्ग संगठनके रूपमें इन्हें समझना और सम्भावित प्रगतिको पहचाने देखना है। यह नहीं किया गया, यद्यपि १९५३ के अन्तमें न केवल नेहरू, एनोमिंघेटेड चेंबर ऑफ कामर्सके सामने यह कह रहे थे कि औद्योगीकरणका मुख्य भाग सरकारके ऊपर है, बल्कि आईमनहावर और उनके मित्र पाकिस्तानमें नैतिक महायन्त्रावी सचिके बारेमें बातचीत करते हुए भी सुने गये थे। सम्भवतः हमारी बात और भारतकी भविष्य-नीतिपर इसका प्रभाव किसी सीमा तक समझ लिया गया था। भारतके अंदर होनेवाले परिवर्तनोंमें इन्हें सम्बंधित न करनेके कारण उनके वास्तविक अर्थकी पूर्ण विवेचना न हो सकी।

१९५३ के अन्तमें न तो कंप्रेसियोंने और न समाजवादियोंने यह अनुभव किया कि अगले दो वर्षोंमें क्या होनेवाला है। कुछ लोग तो इससे भी आगे बढ़कर विश्वासपूर्वक यह घोषणा करने लगे कि अवाहालगत नेहरू और उनकी सरकारको स्वयं उस मार्गकी कुछ भी कल्पना नहीं थी, जिसपर वे चलनेवाले थे, एक ऐसा मार्ग जिसमें भारतके असमर्थ व्यक्तियोंके लिये आश्चर्यजनक समावनाये प्राप्त होनेकी आशा थी।

महत्वपूर्ण वर्ष

अपनी मानुभूमिका कीन दोस्त है और कीन दुश्मन !
आप स्वयं विचार पूर्वक देखकर पता लगाइये ।

— मज्दूर ।

वर्तमानके बीच भूतकालमें थे । भूतकालका परिणाम वर्तमानकालमें दीखता है । यही सतत कम है । और स्वतंत्र भारतके इतिहासमें १९५४ और १९५५ के वर्षोंमें परिवर्तन-बिंदुके रूपमें स्मरण किया जायगा । यह एक महत्वपूर्ण निर्माण-काल था, जिसने वर्तमानका रूप निर्धारित किया ।

घटनाओंने षड्यंत्र रचकर भारतको तथा भारतके विचारोंमें गम्भीर परिणामोंसे पूर्ण विषय बना डाला था, कुछ समय तक तो सत्कारी रूपमें मास्को, वाशिग्टन, पेरिस और लंदनकी यही धारणा बनी रही । इसका उत्तर स्पष्ट था । शीत युद्धसे व्युद्भूत-रचनाके सूत्रोंके लोगोंमें लश्करोंके बिनासेपर लश्कर खड़ाकर दिया था । भारत इस प्रश्नके किसी प्रकारमें निर्णय करनेमें सहायता कर सकता था ।

यद्यपि कोरियामें बंदूकें शांत हो गई थीं, लेकिन संपूर्ण चीनी समुद्रतटपर सशस्त्र और हथियारोंकी गुंज बनी हुई थी । हिंद चीनमें शीघ्रताके साथ एक नये अंतर्राष्ट्रीय संपर्ककी सुपरिचित स्थिति पल्लवित हो रही थी । यूरोपीय बाह्यका मंडार भी बहुत सूखा हुआ था । वाशिग्टनने हस्तक्षेपके लिये यही अवसर उपयुक्त समझा । इस संपर्कके इतने निकट होनेपर भी लोग अंतिम स्थितिमें अवरोध उपस्थित करनेके लिये पूर्ण प्रयत्नशील थे । दूसरे शब्दोंमें, इस शीत युद्धके अंदर ही छुटकाया पानेके कारण भी दीख रहे थे ।

चिन्होंने युद्धपर दाब लगा रखा था, भिक्षुमनेवालों पर दुरी तरह दबाव डाल रहे थे । लेकिन इन भिक्षुमनेवालोंके, विशेष रूपसे मास और बर्गानिवांके हित इतने अधिक परिब्याप्त थे और वे सम्राट्वादी दुनियाँने तब तक सवर्ण करनेके लिये तैयार न थे, जब तब कि मुद्र, निकट आर मध्यपूर्वमें उनके हितोंकी रक्षाका प्रबन्ध न हो जाता । इन चीजोंकी कुन्नी भारतके पान थी ।

भारत अपने सक्रिय तटस्थताकी स्थितिसे निश्चिन्नात्र भी हटनेका इरादा नहीं करता था। यही वह स्थिति थी जो युद्धके दशवर्ष अग्रसर कर रही थी तथा यूरोप और एशियामें विघटन सृष्टे हुए बाह्यके ढेरसे गीला रखनेवाले युद्ध-विरोधी विचारोंको शक्ति प्रदान कर रही थी।

समुक्त राष्ट्र अमेरिकाके कुशल राष्ट्रनिर्देशने यह निष्पत्ति किया कि अब मखमली दस्ताने चढ़ाकर उससे आइमें काय करनेका समय आ गया है। भारतको खील देनी थी। उसे शीघ्र युद्धकी कालविक्रान्ति परचित्त कराना था।

कहा जाता है कि १९४३ के अंतिम चरणमें समुक्त राज्यके परराष्ट्र विभागका पाकिस्तानको सैनिक सहायता देनेके बारेमें समझौता हो चुका था और वह इस बातकी घोषणा करनेके लिये एक अनुकूल अवसर ढूँढ रहे थे, जिनमें 'सह्यायिता जवाहरलाल नेहरू' को एक मन्त्रक दिया जा सके। इनका अनुकूल अवसर खोजा जा रहा था, जिनमें वह अपने आपसे निःसहाय युद्धके समान समझकर सामान्य विरोधके परवान आत्मसमर्पण कर दें।

निश्चित रूपसे विचार यही था कि एशियामें सर्वप्रथम युद्ध-सकटकी स्थिति उत्पन्न करके, पाकिस्तानको भारी सैनिक-सहायता देनेकी घोषणा कर दी जाय, ताकि उसका उपयोग कारगरमें हो सके और तब नेहरूमें यह पूछा जाय कि वे किस पक्षको 'स्वतन्त्रताने चुनना' पसन्द करेंगे। उन्हें यह भी स्पष्ट बताना था कि 'गलत चुनाव' करने पर वे भारी मुसीबतमें पड़ जायेंगे। जहाँ तक सामान्य कार्यक्रमका सम्बन्ध था, वह दीख रहा था कि बीननाममें विघटन होनेवाली गम्भीर स्थिति शायद निष्पत्ति करण बन जाय।

पाकिस्तानी नेता, विरोध करने इरादर मित्रोंके सिद्ध और सेनाके प्रधान सेनापति, जनरल अयूब खानको यह विश्वास दिला दिया गया था कि अनुकूल अवसर आने तक वह दुराभिप्राय प्रकाशित नहीं की जायगी, बल्कि सैनिक सहायता शीघ्रतापूर्वक पहुँचाने जाने लगेगी। इस प्रकार गुप्तत्वमें पाकिस्तान उद्बोधका कार्य करनेके लिये तैयार किया जा रहा था, जब कि इस नीतिके शिक्कर भारतको इस बातका तनिक भी भान नहीं था कि उसके विरुद्ध क्या तैयारियाँ हो रही हैं।

महत्वपूर्ण वर्ष

लेफ्टिन इम योजनाकी सुरसुराइट मालूम पड़ने लगे थी। कहा जाता है कि पाकिस्तानसे जबरदस्ती बाहर निकाले जानेके कारण वर्तानियों सरकार अग्रगत थी और उन्होंने मामूली तौरसे यह इशारा कर दिया था कि इस प्रकारकी कुछ कार्यवाही हो रही है। इसका पुष्टिकरण नहीं हुआ था और वाशिंग्टन स्थिति भारतीय रूतावास द्वारा दिल्लीको यह विरवाम दिलाया गया था कि यह सब गप है। सीभागसे उस समय वी. के. कृष्णमेनन अमेरिकामें ही थे। उन्होंने दिल्लीसे पुष्टिधरणकी सूचना दी। पुरानी वहावतके अनुसार विल्ली बाहर आ गई थी, तथापि चूटोंको भी मतर्क रहनेकी सूचना मिल चुकी थी।

नेहरू इमे मुनकर हके बके नहीं बरन कोथित हुए। केवल थोड़े से “वॉशिंग्टन भर्त्तो”को छोड़कर जो कहते थे कि “भारतने यही मोंगा था,” समस्त भारतवासियोंके यही विचार थे। राष्ट्रकी दृष्टि अरक्षित परिचमोतरीय सीमाकी ओर घूम गई। मानसिक उलमयें बुर हो गईं। राजनैतिक विचारधारामें एक भारी मटभ लग।

सबसे पहले पाकिस्तानको एक मित्रतापूर्ण चेतावनी दी गई कि संयुक्त राज्यसे सैनिक-सहायता स्वीकार करनेसे काश्मीर तथा अन्य समस्याओंकी संपूर्ण पृष्ठभूमि और सदर्म बदल जायगा, जिनके आधार पर अब तक इस विषयमें विचार-विनिमय हो रहा था। यह घटना २३ दिसम्बर १९५३ की है।

एक महीनेके उपरान्त, २३ जनवरी १९५४ को भारतीय दृष्टिकोण कांग्रेस पार्टीके ५६ वें अधिवेशनके अवसरपर नेहरू द्वारा सभापतिके पदसे दिये जानेवाले भाषणमें अधिक स्पष्टतामें दिखलाई पड़ा। उन्होंने “देशकी ओर लक्षित चैलेंज” का मुसबला करनेके लिए “राष्ट्रीय एकता” स्थापित करनेकी मोंग की। उन्होंने पाकिस्तानके सामने “युद्ध न करनेकी सधि रखी”। संयुक्त राज्य अमेरिकामें उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि “भारत युद्धमें कोई भाग नहीं लेगा।”

फलान्तरूप संयुक्त राज्यस्य परराष्ट्र विभाग अशांत हो उठा। उन्होंने अत्यंत योग्यतापूर्वक जिस भयादोहक रणनीतिकी रचना की थी, वह लक्ष्यभ्रष्ट हो चुकी थी। समारके सामने अब उनकी नासमझी प्रगट हो गयी थी, लेकिन उसका प्रत्यावर्तन

हो सकता था। पाकिस्तानमें सहायताके लिए दबनरुद्ध होकर वे बहुत आगे बढ़ चुके थे।

एक महीने बाद २४ फरवरी १९५४ को राष्ट्रपति आरसन होकरने नेहरूको इस दुर्भाग्यपूर्ण निर्णयकी सूचना दी, तथापि उन्हें यह विश्वास दिलाया कि इस सैनिक-महान्यासका उद्देश भारतके विरुद्ध नहीं है। इस असंगत आश्वासनका उत्तर भारतीय प्रधानमंत्रीने १ मार्चको समरुके मामले दिश। उन्होंने घोषणा की कि जो कदम उग्रता जानेवान्ता है, उसने पाकिस्तानको भारतके विरुद्ध आक्रमण करनेका उल्थाई और महायत्न मिलेगी। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिकाके बीच एक गहरी खाई बनती जा रही थी। क्या वह कभी पाटी जा सकती थी ?

भारतीय नेतृत्वके सामने इस समय जो समस्या थी, वह कुछ इसी प्रकारकी थी। संयुक्त राज्यकी नीति द्वारा शीतयुद्ध इस उप-महाद्वीप तक आ चुका था। यदि उसे रोका न जाता तो वह एशियाके अरर सपरिदेहनका विस्तार करके एव सैनिक आवश्यकताओंपर अग्रनमे ज्यादा बल देकर भारतीय आर्थिक विकासको नष्ट-भ्रष्ट कर सकता था।

अमेरिका द्वारा भारतकी मददके लिये किनी भी स्केनमें ध्यानेकी अब बहुत कम आशा थी। तटस्थता तथा सक्रिय तटस्थताको अब अधिक स्वाधरात्मक और निर्माणत्मक बनाना जरूरी था। पहलेकी तरह केवल सीदेवाजीके स्थानपर भारतको अब अपनी नीतिके मूल सिद्धान्त समाजवादी दुनियाके लाभकारी सपरि स्थापित करना जरूरी था।

स्वभावतः पाकिस्तानपर सबसे पहले ध्यान न दिया जा सका। इसी समय यह सूचना प्राप्त हुई कि पाकिस्तानी कीर्जोंको बराबर उनकी सख्या १ करोड़ सुमजित सैनिक की जानेवाली है। ६ करोड़की जनसख्यावाले देशके लिये यह सख्या असाधारण रूपसे बड़ी थी। और स्थल सेना बढानेका अर्थ एक ही होता था अर्थात् भारतके विरुद्ध अभिशन। क्योंकि उसकी सीमावे भारतकी छोरकर और निती देशके निष्ट भेद्य नहीं थीं। दूसरे राज्योंमें काश्मीर, पंजाब और राजस्थानको खतरा था। उस समय बंगाल सुरक्षित था, क्योंकि कर्कोकी गणनामें एनी पाकिस्तानकी सुरक्षा सम्भव न थी।

महत्त्वपूर्ण वर्ष

दोनों देशोंके क्षेत्रफलको देखते हुए यदि भारत भी किसी समानान्तर सेनाध्य निर्माण करता, तो उस सेनाका पाकिस्तानी कौजोंने कमसे कम निगुना होना जरूरी था। उस राष्ट्रके लिये, जो अपनी शक्ति शक्तिपूर्ण आर्थिक प्रगतिके लिये सरंचित करना चाहता हो, यह विचार कल्पनासे परे थे। नेहरूने बुद्धिमत्तापूर्वक राजनैतिक विचारधाराके ऊपर आयुधोंकी दीर्घी कल्पना न करनेके लिये जोर डाला, क्योंकि इसमें आर्थिक कठिनाई उपस्थित होती और अंतमें केवल साम्राज्यवादी बुद्धनीतिके हितोंकी ही पूर्ति होती।

इसके अनिश्चित समस्या इतनी निराशापूर्ण न थी जैसी कि मालूम पड़ रही थी। समग्रमें पूर्व ही सैनिक गठबंधनका भेद खुल जानेका, पाकिस्तानमें विद्यमान संपर्षी दोनों पक्षोंपर भारी प्रभाव पड़ना निश्चित था। पहली पूर्ण थी राष्ट्रमंडलका भाग समझे जानेवाले क्षेत्रमें समुकराज्यीय प्रवेशको रोक्नेके लिये ब्रिटिश अवरोध। यह अवरोध अनेक कुटिल मार्गोंका आधार लेनेवाला था, लेकिन इसका निश्चित था कि सदन अमेरिकन कृपेपेयिन पाकिस्तान द्वारा भारतकी शक्तिभंग होना कभी पसंद नहीं करता, क्योंकि भारतका एक ब्रिटेनके प्रति मित्रतापूर्ण था और साथ ही साथ राष्ट्रमंडलीय भविष्यके लिये उसकी स्थिति बहुत महत्त्वपूर्ण थी।

पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान या अन्य राज्योंमें कहना चाहिये पंजाब और बंगालमें बढ़ता संपर्ष इसकी दूसरी पूर्ण थी और दिल्लीने इस ओर ध्यान दिया। पाकिस्तानमें बंगालियोंका बहुमत था, लेकिन साम्प्रतमें पंजाबियोंका प्रभुत्व था और वे ही अधिक शक्तिशाली थे। वहाँ भी समुक्त राज्य अमेरिकनकी सहायतासे विग्रह बढ़नेकी सम्भावना थी। व्यवहारिक राज्योंमें सहायताका अर्थ था, पंजाबी प्रधान पाकिस्तानी सेनाको अधिक शक्तिशाली बनाना, जिसे निरोध होकर सहन करनेके लिये पूर्वके बंगाली तैयार नहीं थे।

यद्यपि ठम समय यह विचारधारा इसकी स्पष्ट नहीं थी, जसी कि ऊपर बतलाई गई है, परन्तु भारत सरकारने इसका मौलिक सिद्धांत समझ लिया था। इसके विरुद्ध प्रतियुद्धाक्रमण नियोजित किया गया। ब्रिटिश सरकारको यह बात स्पष्ट बनना

दी गई कि भारतको यह आशा है कि वह पाकिस्तानमें, होकर बिये जानेवाले संयुक्त-राज्यीय प्रयत्नों पर रोक रखेगा। इस कार्यमें अमरुत होनेका परिणाम भी ब्रिटेनमें समझा दिया गया। इसी बीच काश्मीरमें स्थितिको अधिक सुन्द किया गया। ६ फरवरीको जम्मू और काश्मीरकी विधानसभामें भारतमें स्थायी विलीनीकरण की घोषणा कर दी।

राष्ट्रसंघकी मध्यस्थताका निर्णय इस प्रकार उलटने पर पाकिस्तान बुझे तरह बिगड़ा और बीसलाया, लेकिन इसका परिणाम समीको अच्छी तरह दिखलाई दे रहा था। भारत इस भयाहोहनके सामने मुकनेके लिये तैयार नहीं था और आवश्यकता पड़नेपर संयुक्त राज्यके परराष्ट्र विभाग द्वारा प्रभावित राष्ट्रसंघसे सहयोग करना अस्वीकार कर सकता था। आश्चर्यजनक बात यह थी कि पाकिस्तानमें दिये जानेवाले इस मददेसे ब्रिटिश दम्नरशमी भी पूर्ण सन्तुष्ट थी।

और उसके उपरान्त अनेक नई प्रतियोगी सामने आई, जिनका उदय संयुक्तराज्य एवं पाकिस्तानके मध्य हुए सैनिक समझौतेमें ही हुआ, यद्यपि वे असमर्थित प्रतीत होती थीं। पुर्नगली और मद्रसीली बस्तिमोक्ष प्रश्न पुनः प्रकाशमें आ गया।

भारत सरकारने अच्छी तरह समझ लिया कि छोटे स्थान भी संयुक्तराज्य अमेरिका द्वारा भयाहोहन और अवरोध उपस्थित करनेके लिये प्रयोगमें लाये जा सकते हैं। पुर्नगली तो बार्सिलेटन पर लगभग आश्रित ही था। जहाँ तक मद्रसीली प्रश्न था, वह भी बीननाम युद्धमें संयुक्त राज्यीय सहायताके प्रतिदान स्वरूप इस गंदे खेलमें खेलनेके लिये बाधित किया जा सकता था।

बहुत काल तक निर्धारित रखी जानेवाली मद्रसीली बस्तिमोक्ष नियमितियोंको आगे बढानेका सन्देश मिल गया। २१ अक्टूबर १९५४ तक पाटीपेरी, बारोछल, चदनगर, माहे, यनाममें प्राचीनी मंडा भुज्य दिया गया। दिल्ली और पेरिसमें होनेवाले समझौतेके पत्रस्वरूप इनका सदागिद शासन भारतके सुपुर्द कर दिया गया, यद्यपि चदनगर तो बहुत पहले ही भारतमें विलीन हो चुका था।

महत्वपूर्ण चर्चा

तथापि गोआ, रामन, इंदू और दादरा नामक पुर्नगाली बस्तियोंमें परिस्थिति अधिक उलझी हुई थी। पुर्नगाली इन छोटे स्थानोंको छोड़नेके लिये तैयार नहीं थे और स्वाभाविक रूपसे भारत सरकार ऐसे समय पुर्नगाली करनेमें हिचक रही थी, जब कि सरकारी नीति शान्तिपूर्ण समझौतोंके पक्षमें हो।

इसी बीच अन्य घटनाओंने भारतके नये दृष्टिकोणको सुप्रगणित कर दिया। १९५४ में प्रारम्भिक भागमें बीतनाममें प्राचीनी स्थिति तीव्रतासे बिगड़ने लगी। मुक्ति सूत्रों द्वारा दिल्ली पहुँचनेवाले समाचारोंने यह प्रगट हुआ कि संयुक्तराज्य अमेरिका मुक्ति आंदोलनका पाया पलटनेके लिये अणुशस्त्रोंको प्रस्तुत करके मासको इस बातपर विवश कर रहा है कि वह इन क्षेत्रोंमें अपना प्रभुत्व स्थापित करनेका सपना जारी रखे।

नेहरूने सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकारसे यह स्पष्ट कर दिया कि इस दंगली दुःसाहसिक नीतियोंके निरुद्ध एशिया सगठित हो जायेगा और भारत तथा चीनको इन प्रयत्नोंके निराकरण हेतु आवश्यक कदम उठानेसे मसखरी कोई भी शक्ति नहीं रोक सकेगी। ब्रिटिश और फ्रान्सीसीयोंमें प्रतिक्रिया हुई। उन्हें एशियाका अच्छा अनुभव था और इस कारण वे अच्छी तरह समझ गये कि इस प्रकारके समझौतेका क्या परिणाम हो सकता है और एक एक कदम करके २६ अप्रैल १९५४ को सुदूर पूर्वी समस्यापर विचार विमर्श करनेके लिये इतिहास प्रसिद्ध जिनेवा सम्मेलनका आयोजन हुआ।

यह प्रथम राष्ट्रसंघके बाहर हुआ था और इस प्रकारकी अंतर्राष्ट्रीय बैठकमें जन-चीनने पहली बार भाग लिया। संयुक्त राज्य अमेरिकाने इस प्रस्तावका विरोध किया, लेकिन वे इस बैठककी आयोजनाको नष्ट न कर सके, क्योंकि यह समार व्याप्त शांतिकी आवश्यकताके अनुकूल प्रयत्न था।

इस सम्मेलनका आयोजन भारतीय कूटनीतिकी महान विजय थी, इसी महान कि संयुक्त राज्य अमेरिकानी चालाकियों द्वारा उसे सम्मेलनमें होनेवाले वादविवादमें भाग लेनेसे वंचित किया गया। पूर्वशक्ति तरफ़ इस अपमानको नहीं पचाया

कोलंबो सम्मेलन

कोलंबो। अतः भारत, हिंदीशिया, ब्रह्मा, पाकिस्तान और श्री लंकाके सम्मेलनको नामक स्थानपर एक बैठक करनेका आधार प्राप्त हुआ।

जिनेवा सम्मेलन आरम्भ होनेके २ दिन परचल होनेवाली इस बैठकके अनेक प्रयोजन थे, जो अनेक रूपोंमें परस्पर गुंथे हुए थे। भारत, ब्रह्मा और हिंदीशियाके छिटोछोटे समान या और वे भाषाज्यवादी द्वाद और अतिजनगुप्त सामग्य करनेके लिये एशियाको एकत्र स्थापित करनेमें सहारता करनेके इच्छुक थे। वहाँ तक श्री लंकाका धरन है, वह अपने अस्तित्वका ही ज्ञान बाले की इच्छा रखता था।

लेकिन पाकिस्तान द्वारा बैठकमें भाग लेनेका निर्णय मजबूत था। निमंदह पाकिस्तानके नये प्रधान मंत्री मुहम्मदयलीस विचार था कि वे अपने नये मित्र अर्थात् समुक्त राज्यके पक्षरू विभागको उत्तेजित करनेका कार्य करेंगे। तथापि इस प्रकारकी स्वयं मजलीमें सम्मिलित होनेका वास्तविक कारण पूर्वी पाकिस्तानके सामान्य निर्वाचनोंका निराशार्थ परिणाम ब्याजूम पड़ना है। जनरल पार्टी अर्थात् मुस्लिमलोकका अस्तित्व इस देशमें लगभग मिटा जाना गया था। उसके स्थान पर एक नया अवरोधित यूनाइटेड फ्रंट पार्टी प्रतिष्ठित हो गई थी, जो पाकिस्तानके एरनीति और विदेशी नीतिमें प्रयत्न नहीं थी। प्रधानमंत्री मुहम्मदयलीस देवी अस्तित्वार्थी परिस्थितिमें अपने सभी दाव मनाम नहीं कर देना चाहते थे।

नीतियोंमें भिन्न भिन्न छिटोछोटावाले पाँच गुंथे मिश्रण एशियाके असंगठित लोगोंके लिये तटस्थता और स्वयंमताधी नीति निर्धारित कर आनी।

बादविवादके दरम्यान ठनका लाभान उनका ही प्रकाशन हुआ, जिसका जिनेवा सम्मेलनका ही रस था। यद्यपि पाकिस्तान और श्री लंकाके प्रतिनिधियोंके मुंह स्वतंत्रताको बात कुछ अजीबानी मालूम पड़ती थी, जब कि उन्होंने स्वयं अपनेसे कुछ अर्थों तक बंधनमुक्त बना जाना था, लेकिन अंतर्गत कानमें एशिया ऐसी अनेक विशेषतायें उपस्थित करता चाहता था।

उन्हे कैसे कोलंबो शक्तिशाली विचार सामने आने लगे, अपने भाग्य, ब्रह्मा और हिंदीशियाके छिटोछोटाका प्रभाव स्पष्ट होना दिखलाई पड़ा। लेकिन उन दिनों इस घटनाका महत्व और उसकी सार्थकताका पूरी तरह मूल्यांकन न हो सका।

महत्वपूर्ण वर्ष

जिनेवा सम्मेलनको विशेष रूपसे चीनजगत्के प्रश्नपर अनेक उद्यान पतनोंका सामना करना पडा, लेकिन प्राणि सन्त और नियमित रही। जब प्रश्नके प्रधानमंत्री लेनिनसन्त, संयुक्तराज्य अमेरिकाकी सहायता द्वारा शांतिपूर्ण सम्झौतेमें अग्रज टालनेके उद्देश्यसे सम्मेलनके वद्विधारना विचार किया, तब मासने पियरे मेंट्रेस प्रश्न नामक नये प्रधानमंत्रियोंको चुनकर जिनेवा भेज दिया। उन्होंने चीनके प्रधानमंत्री चू-एन-लीके बातचीत की और इस प्रकार समझौतेका मार्ग खुल गया। ११ अगस्त तक एशियाके एक अन्य सत्रस भूभागपर लगभग आठ वर्षके युद्धके उपरान्त वद्वक स्थायी रूपसे र्मान कर दी गई।

लेकिन सगारकी अग्रज विचारधारा संयुक्त राज्यीय नीतिनी नपुनसुतापर अभी अग्रज ध्यान केन्द्रित भी न कर पाई थी कि एक नये नाटमीय परिवर्तनकी सूचना फैल गई। जिनेवामें सगलता प्राण करनेके उपरान्त अपने देशकी लीडते समय चू-एन-ली, जवाहरलाल नेहरूसे विचारविनिमय करनेके लिये वायुमार्गसे दिने पधारे।

मानान्वयता इहे एक महज घटना समझा जाता। क्या भारतने जन चीनके प्रश्नका राष्ट्रगघने समर्थन न किया था? और क्या भारतने जिनेवा सम्मेलनमें न्यास मतभेदके कारणोंसे दूर करनेमें सहायता न दी थी? क्या भारतने शान्तिके पक्षका जोरदार समर्थन न किया था? और इसके अनिरिक सम्य विचारविनिमयके पक्षाल भारत और चीन द्वारा हस्ताक्षरित निज्जनविपरक सवि भी दोनों प्रधानमंत्रियोंकी भेटका कारण हो सकती थी।

लेकिन एशियाने इन तर्कों के बारेमें नहीं सोचा। वह इस विचारसे ही आनक्तिन हो उठा कि एशियानी दो हस्तिरों आपसने मिल रही थी। अब इस बातकी पूरी आशा थी कि इस पास्पर भित्तनके परिणाम स्वल्प साम्राज्यवाद अकेला पद जायगा और औपनिवेशिक बंधनोंने मुक्ति पानेवाले आंदोलन जोर पकड़ने लगे। सगारकी १०० करोड़ जनसंख्याके प्रतिनिधियों द्वारा मिलकर मित्रताके बंधन अधिक दृढ करनेका प्रयत्न कोई साधारण बात न थी।

पंचशील की घोषणा

एशियाको निराश होनेका कोई कारण न था। चू-एन-त्सी २५ जूनको दिल्ली आये और उनका एतना भारी आतिथ्य-सत्कार हुआ, जितना किसी विदेशी राजनीतिज्ञका अब तक न हुआ था। और थोड़े समयके ही अन्दर पंचशीलके महान सिद्धांतोंकी घोषणा हुई। चीन और भारतने मिलकर सत्कारके सामने सह-आस्तित्वके पाँच मौलिक सिद्धांतोंकी घोषणा की, जिसके आधार पर राष्ट्रोंमें सहयोग और शांति स्थापित की जा सकती थी।

प्रत्येक ईमानदार तथा समझदार निष्कारणकारके सम्मिलित स्वर बन्नेवाले ये पाँच सिद्धांत क्या थे।

(१) पारस्पर एक दूसरेकी संप्रतीय अखंडता और सार्वभौमताका आदर
(२) अनन्यात्मकता (३) एक दूसरेकी आन्तरिक समस्याओंमें हस्तक्षेप न करना (४) समानता और परस्पर सहायता (५) शांतिपूर्ण सह अस्तित्व।

हाला कि यह निरर्थक सिद्धांत अशक्त प्रतीत होते थे, लेकिन वर्तमान विस्फोटक परिस्थितिमें यही निरर्थक सिद्धांत सक्रियताके पञ्चानक पथ प्रदर्शक बन गये। इस कारण हमने कुछ आश्चर्य नहीं होना चाहिये कि साम्राज्यवादी शक्तियोंने इस घोषणाका उपहास किया। इसके अतिरिक्त वह कर ही क्या सकते थे! जो भूमे उनको नहीं रही थी, उनका प्रवेश करनेकी वैधता अब वे किस प्रकार प्रमाणित कर सकते थे।

शांति जनताके लिये "पंचशीलका सिद्धांत" औपनिवेशिक कथनोंसे मुक्ति पानेका सिद्धांत था। जिन्हें मुद्दा कर था, उनके लिये यह शांति सपनिन करनेका एक साधन था और साथ ही सामान्यतम नागरिकोंको शांतिपूर्ण प्रातिके लाभ दिलानेका आश्वासन देता था।

अब तक सह अस्तित्वको सम्राज्यवादी समारने अपनी नीतिका मौलिक तत्त्व घोषित कर रक्ता था। कुछ लोग साम्यवादी सम्रा दिखलानेके लिये इस सिद्धांतको कथनके रूपमें प्रस्तुत करते थे, लेकिन अब यह सिद्धांत अग्र-वाक्योंसे मुक्त होकर विश्वकी बहु संख्या जनताका मिलन-बिंदु हो गया।

महत्त्वपूर्ण वर्ष

भारत और चीनने इन पाँच सिद्धांतोंके आधारपर अपने सम्बंध कायम करके सहस्रस्तित्वको स्थान प्रदान किया। जैसा कि सर्व विदित है, इन सिद्धांतोंका प्रथम बार प्रयोग तिब्बत विषयक संधिमें हुआ। अब इन दोनों देशोंके बीच सभी प्रकारके सम्बंधोंका आधार बन जानेपर उन्होंने मास्कुनिक व्यापारिक संपर्क तथा एक दूसरेके दृष्टिकोणको समझानेका पथ प्रशस्त कर लिया।

भारत और चीनने हम बातका प्रण किया कि वे एक दूसरेमें शिक्षा ग्रहण करेंगे और सुनारके सामने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, जिसका अनुकरण वे आसानीसे कर सकें। अझाने भी इसी प्रकारकी घोषणापर हस्ताक्षर कर दिये और तत्काल ही एशिया तथा अफ्रीकाई देशोंका एक सम्मेलन बुलाने पर गंभीरताके साथ विचार होने लगा। पंचशील ही उनमें एक स्थान पर खींचकर लानेवाला चुंबक हो सकता था और इसीके द्वारा जाति, रंग, धर्म, विचार, राजनैतिक व्यवस्थामें अंतर होनेके बावजूद भी शांति हेतु मित्रता सुझा दी जा सकती थी। नवोदित राष्ट्रोंको अपनी उन्नति और स्वतंत्रताको सुदृढ़ करनेके लिये वास्तविक शान्तिकी आवश्यकता थी।

पंचशीलका अर्थ स्पष्ट करनेके लिये १५ अक्टूबरको नेहरू दक्षिण—पूर्वी एशिया तथा चीन-भ्रमणके लिये निकल पड़े। उनकी इस यात्राका परिणाम विम्वृत और गंभीर होता निश्चित था। भारत और चीनके बीच बन्दे हुए मित्रतापूर्ण सम्बंध ही वह केन्द्र बिन्दु थे, जिसको आधार बनाकर एशियायी एकता और सौजन्यताका सपीयकरण हो सकता था। नेहरूनी चीन यात्रा और वहाँकी मित्रता और प्रेम प्रदर्शनने एशियायी इतिहासमें एक नया अध्याय जोड़ दिया।

वर्षान कोलंबो शक्तिधर्मि हिन्देशियाके भोगर नामक स्थानपर मिलीं। उन्होंने एकमत होकर यह निश्चय किया कि एशिया अफ्रीकाई देशोंका एक सम्मेलन बुलाया जाय, जिसमें जन चीन भी उपस्थित हो। राजनैतिक घटनाओंका सामान्य दृष्टा इस घोषणाका केवल एक ही अर्थ निकाल सकता था अर्थात् उपनिवेशवादका अन्त, साम्राज्यवादकी रहित शक्ति का अन्त, उम युग का अन्त जिसमें स्वतन्त्र राष्ट्र एशिया और अफ्रीका वासियोंको गुनाम बनाकर परिपुष्ट हुए थे।

अन्तर्गतों हमने सम्मिलित करना स्वाभाविक था। उस समस्त महाद्वीप पर अपना नियन्त्रण बनाये रखनेके लिये साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा नृशान्तम साधन अन्ताने जा रहे थे। एशिया उनके हाथोंमें निरुत्तना जा रहा था और इस कारण अन्तर्गतों अपना आधिपत्य कायम रखनेके लिये उन्होंने कोई साधन न छोड़ा।

फ्रांसिसियोंने उत्तरी अफ्रीका वानियोंका क्लेशग्राम किया। ब्रिटेनवासियोंने केनियाके मूल निवासियोंको जीवन-भुक्ति देनी शुरू कर दी। अमेरिकनोंने, जिन्होंने इन्हीं तरीकोंमें अपना राज्य स्थापित किया था, पश्चिमी एशियाके तैलक्षेत्रमें राजद्रोह और हत्याके क्रान्ति प्रविष्ट होनेका प्रयत्न किया।

वास्तविकता यह थी कि अन्तर्गतों जहाँ कहीं स्वेतागोसा प्रभाव था, ईश्वरके प्रतिनिधिके रूपमें उन्होंने वहाँ चलकर इस प्रकारके जीवन दानपत्रा उपदेश दिया जिसमें एगोन समीपवर्ती अपने मौलिक अधिकारोंसे भी वंचित रह जाये। एशिया और अन्तर्गतोंके अन्तिम निज होनेकी बात समझनेके लिये किसी गहन अध्ययनकी आवश्यकता नहीं है।

१९५४ में समस्त भारतमें ब्रिटिश विरोधी विचार पनप रहे थे और वही विचार समस्त औपनिवेशिक समारमें अनेक रूपोंसे नवीन स्वतंत्र भावनाओंको सन्तुष्टि करनेका नेतृत्व कर रहे थे। ये भावनायें, हमारे विचारों और कार्यों पर अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रह सकती थीं। दूसरे शब्दोंमें, पाकिस्तान तथा अन्यत्र होनेवाले साम्राज्यवादी पद्धतियोंने उत्पन्न निराशाके परिणाम स्वरूप देश-भक्तिमें परिपूर्ण राष्ट्रीय भावनाओंकी लहर दौड़ने लगी और उसने उन नीतियोंको जन श्रिय बना दिया, जिनसे भारत अपने पैरोंपर खड़े होकर भविष्यमें भयादोहन और दगावके गने प्रयत्नोंसे अपनी रक्षा कर सकता था।

प्रथम बार भारत सरकार समाजवादी दुनियासे व्यापार करनेकी सम्भावना पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने लगी, जिस व्यापारका अर्थ अपनी अर्थव्यवस्थामें सुधार करना था। ऐसे संबंधोंके लिये इसने अच्छा कौन-सा समय हो सकता था।

महत्त्वपूर्ण घर्ष

सोवियत सचमे मलेनमोवरी नीतिरी आलोचना होने ही लगी थी। उन्होंने भारी औद्योगिक उत्पादनके स्थानपर उपभोक्ता वस्तुओंके उत्पादन पर जोर डाला था। यह ऐसी नीति थी जो लागू होनेके उपरान्त सोवियत सच द्वारा अविकसित देशों और विशेष रूपसे जन चीनको सहायता देनेकी समता कम कर देनी। सोवियत आदेशाली तर्क कर रहे थे कि विदेशोंके औद्योगिक उपकरणों की आवश्यकताओंकी पूर्तिके लिये और सोवियत वास्तियोंके जीवनस्तरको अधिक ऊँचा उठानेके लिये आवश्यकता है कि औद्योगिक विस्तार किया जाय न कि उसे कम किया जाय।

कुत्तानिन और सुरुषेवके चीन यात्राने लीटनेके परिणाम स्वरूप वादविवाद उत्कर्ष शिखरपर पहुँच गये। वहाँकी औद्योगिक उपकरणोंकी तत्कालीन आवश्यकता तथा 'परिस्थित ज्ञान' ने उनके ऊपर भारी प्रभाव डाला था। यह स्पष्ट था कि चीनकी आवश्यकताओंको पूरा करना पड़ता। सोवियत सचके दृष्टिकोणमें आनेवाले परिवर्तनके सभी चिन्ह १९५४ के अन्तिम दिनोंमें स्पष्ट दिखलाई पड़ने लगे थे।

फरवरी १९५४ तक मलेनमोवने कुत्तानिनके लिये जगह कर दी। अर्थ-शास्त्रियोंने इन परिवर्तनोंका ठीक ही विवेचन दिया था कि यह सोवियत सचका अविकसित देशोंको परस्पर लाभकी शर्तोंपर सहायता देनेके महान प्रयत्नोंका प्रारम्भ है। यह वह नीति थी, जिसने अमेरिका अनिश्चयमें पड़ जाता।

सोवियत सचमे एक इम्पान बनानेकी मशीन प्राप्त करनेके बारेमें भारतने आर्थिक प्रयत्न तो पहले ही कर लिये थे। इस बदमरा भारी विरोध हुआ था। देशके प्रमुख व्यापारियोंने समाजवादी हुनियासे व्यापार करनेके परिणाम समझते देर न लगी। विद्युत गतिने बिजला ब्रिटिश इम्पान निर्माताओंके पास सीढ़ा पड़ानेके लिये पहुँचे। जिन्होंने पहले किसी प्रकारकी सहायता देना अस्वीकार कर दिया था, अब वे तैयार थे। लेकिन भारत सरकार तैयार नहीं थी, हालांकि टी. टी. कृष्णामाचारी जैसी कुछ सदस्योंने बिजलावाले सीढ़ेको स्वीकार न करनेकी स्थितिमें त्यागपत्र देनेकी धमकी दे दी थी।

नेहरूके कट्टर समर्थक योग्य आधुनिक वादी एपी अइमद फिदवईने इन परिस्थितिमें निकलनेका रास्ता यह भौंग करके ढूँढ़ निकाला, कि सरकारको अपनी

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

१९४८ में जोषित औद्योगिक नीति का पालन करना चाहिये। बहुत जालसे भुलाये इस कानूनको प्रकाशित किया गया। इसका सर्वजनिक क्षेत्र की वस्तु बनवाई गई। यह नया हुआ कि इस दिशा में की जाने वाली प्रगति के लिए सरकार उत्तरदायी है। सारे देश में इस पुनः प्रकाशित औद्योगिक नीति का भारी समर्थन किया और फलन सम्भीरता पूर्वक आर्थिक समस्याएँ विचार करने का मार्ग प्रशस्त हो गया।

पिछले कुछ दिनों में कई विदेशी अर्थशास्त्री भारतीय समग्र की सत्ता बलरत्न में पी सी बहाना नोबिस के निर्देशन में द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर विचार विनिमय करने में व्यस्त थे। वे लोग समुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और पोर्तुगल में आये थे। यह एक अजीब टीम थी। इनके सदस्य पूर्ववासी और ममादवादी देशों दुनिया में आने थे, लेकिन वे इस धारणा में एकमत थे कि केवल कुशलतापूर्वक तैयार की हुई वैज्ञानिक-विज्ञान योजना ही भारत को दारिद्र्य के उपर उभार सकती है।

उनका कार्य अद्भुत था। उन्हें एक ऐसी योजना मिली थी, जिसमें राज्य नियंत्रित तीव्र आर्थिक प्रगति के साथ ही साथ भारतीय निजी व्यापार और उद्योगों के हितों की रक्षा हो सके। आर्थिक योजना की प्रयोगशाला में भारतीय वर्गों के पक्ष में व्यवस्था यह विशेष रूप से व्यवस्थित किया था।

सोवियत संघ के इसान बाराखाने के प्रभाव और रफीक़ुल्लाह निद्वंद्व के सार्वजनिक क्षेत्र के जोरदार समर्थन ने विरमित होने वाली आर्थिक प्रगति के कारण यह कार्य अधिक सरल हो गया। वास्तव में भारत की भारी क्षति सब हुई जब कि २४ अक्टूबर १९४४ को अफ़ग़ानिस्तान इस अमाधारा व्यक्ति ने शरीर त्याग दिया। नेहरू अभी चीन में ही थे। उन्होंने ऐसे शक्तिशाली प्रचारकों को दिया, जो उनके भारत लौटने के दौरान बहुमूल्य प्रमाणित होना।

मानव सौटकर चीन की प्रगति में प्रभावित प्रकाशमयी नेहरू ने यह निर्णय किया कि देश के सामने समाजवादी गठन का लक्ष्य उपस्थित करने का समय आ गया है। बड़े व्यापारिक क्षेत्रों में व्यापक मगर प्यून देकर उन्हें विरक्षण भी दिलाया था। वे इसका हल पेश करने थे। लेकिन भारतीय वायुपट्टियों के साथ

महत्त्वपूर्ण घरे

यह बात नहीं थी। उन्होंने प्रजातांत्रिक साधनोंसे "बर्ग, जाति-हैन" समाजवादी समाजमें प्रतिष्ठित करने विषयक २१ दिसम्बरकी सरकारी घोषणाका "पाखंड" कह कर मखौल उड़ाया।

लेकिन यदि साम्राज्यवादी नीतियोंमें बढ़ते हुए मनभेदोंके उपरान्त केंब्रेसी आर्थिक विचारधारामें होनेवाले परिवर्तनों पर ध्यान दिया जाता, तो उनके दावे उनमें अनपूरण और दम्भपूर्ण प्रतीत होते। "सहकारी समानता," "मिश्रित अर्थ-व्यवस्था" और "कन्याएकारी राज्य" के स्थान पर केंब्रेसीवादी अब "समाजवादी" शब्दका प्रयोग करने लगी थी। जो अब तक पूँजीजीवियोंका अविश्वसनीय अनादिन शब्द था।

यद्यपि 'समाजवाद' में केंब्रेसीवादी सम्पूर्ण उग समाजमें नहीं था, जिसके लिये साम्यवादी पार्टीने अपनेको समर्पित कर रखा था, न इसका अर्थ मजदूरोंके जनतन्त्रही स्थापना थी। इरादा यह था कि इन प्रकारके मिश्रित समाजका निर्माण हो जिसमें परस्पर विरोधी विचारों और व्यवहारोंका मिश्रण हो सके। लेकिन नये नारेको 'पाखंड' की सुजा देकर उसकी मखौल उड़ाना एक महती भूल थी। केंब्रेसी विचारधारामें यह नई प्रगति थी, ऐसी प्रगति जिसके परिणाम स्वरूप देशमें अधिक परिवर्तन निश्चित थे।

१९४४ के आरम्भमें भारतमें जनताका ध्यान दो महत्त्वपूर्ण घटनाओंकी ओर केन्द्रित था। आग्रके चुनाव तथा अगस्तमें केंब्रेसी पार्टीका साठवा अधिवेशन। अपने अधिकार क्षेत्रमें दोनों बातें महत्त्वपूर्ण और परस्पर सम्बन्धित थीं।

नव निर्मित आग्र प्रदेशमें प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रके अन्दर केंब्रेसीवादी साम्यवादी पार्टीने था। यह एक महत्त्वपूर्ण बात थी। भारतीय साम्यवादी पार्टी विश्वासपूर्वक अपनी विजयकी भविष्यवाणी कर रही थी और उसके आत्म-विश्वासके विरुद्ध कांग्रेसी शिबिरोंमें निराशा व्याप्त थी।

इन दोनोंमें अगरी अधिवेशन पहले हुआ। पार्टीने आरबर्गजनक एकताके साथ अपना आदर्श 'समाजवादी ढंगका समुदाय' निर्धारित किया। यूगोस्लेवियाके

राष्ट्रपक्षने अतिथि रूपमें हमें भाग लिया था। यह सच है कि 'समाजवाद' समाजवादी बना दिया गया था। यह भी सच है कि 'दण्डक समुदाय' सुहावरेका प्रयोग हुआ था। समाजवादके परिचित शत्रुओंने नये नारेको भी विरोधका साधन बनाया और यह भी सच है कि भारतीय समाजवाद और अन्य प्रकारके समाजवादोंने अंतर दिखानेके भारी प्रयत्न किये गये। यह सच बातें तथा इसके अतिरिक्त भी अनेक दलीलें इस सत्यको उरजुतनाके बारेमें सुदेद दिखलानेकी रखी जा सकती हैं। तथापि कुछ ही समाजोंके अंदर मभी समाचारपत्र, रेडियो और अन्य प्रचारामक साधन इस समाजवादी ढंगका चरा करनेमें लुट गये।

समस्त देशके नरनागे उन पुस्तकोंमें समाजवादके बारेमें पढ़ने लगे, जिन्हें किसी भी साम्यवादीका अनुमोदन मिल जाता। सरकारी बर्मेचारी भी अब समाजवादी साहित्य पढ़ सकते थे। ऐसा कार्य पूर्व कालनें समस्त गुप्तचर विभागए ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेता और इन प्रकार भारतने अनेक प्रकारसे समाजवादपर विचार करना प्रारम्भ कर दिया।

आध्रमें कांग्रेसके चुनाव प्रचारने जोर पकड़ा। नेहरूने बहोंपर दौरा किया। उन्होंने लोगोंको बतलाया कि उन्होंने भारतीय गहरी जमी हुई साम्राज्यवादविरोधी परंपराओंपर आधारित एक ऐसी विदेशी नीति दी है, जिसका समो जगह आदर्श होता है। उन्होंने बतलाया कि यह वही नीति है जिसके बारेमें साम्यवादी विचारवा करते थे कि मैं उसका ईमानदारीसे पालन नहीं करूंगा। क्या मैंने उनकी मिथ्या-धारणाको प्रमाणित नहीं कर दिया है?

यह समझाओंके बारेमें उन्होंने अवादी अभिवेशनए महत्व लोगोंको मनमाया। उन्होंने अपने समाजवादी विचारोंके बारेमें होनेवाले साम्यवादियोंके उपहासका जिक्र किया। वे कहने लगे कि इसी प्रसंगकी बात वे लोग उनकी विदेशी नीतिके बारेमें किया करते थे। उन्होंने अर्थश्रेष्ठ क्षेत्रमें जो कुछ कर दिखाया, वही वह यह क्षेत्रमें कर डालेंगे। वे अपना कायदा पूरा करेंगे। इसके बाद उन्होंने प्रतिज्ञा की कि उनकी सरकार भारतमें दस वर्षके अंदर समाजवादको प्रतिष्ठित कर देगी।

महत्त्वपूर्ण वर्ष

इसकी प्रतिक्रिया तत्काल हुई। उनका प्रचार जोर पकड़ने लगा। 'प्रवक्ता' के सप्ताहकीय लेखोंका भी यह प्रमाणित करनेके लिये कांग्रेसने उपयोग किया कि भारतीय साम्यवादी कमलिनने दो कदम आगे बढ़ गये हैं और इन प्रकार बड़ी कुशलतापूर्वक, मध्यमवर्गको भी आने पक्षमें कर लिया। अंतमें जब चुनाव हुए तो कांग्रेस साम्यवादी पार्टीको उन्हींके सुन्दर गढ़में बुरी तरह हराकर विजयी बनी।

सरकारी क्षेत्रोंमें बड़ा आतन्दोलनाम मनाया गया, लेकिन एक बातकी अपेक्षा न की जा सकी। साम्यवादियोंको कुल मतोंके २० प्रतिशतमें अधिक मत प्राप्त हुए थे। यदि कांग्रेसके विरुद्ध १० प्रतिशत मत और बढ़ जाते तो परिणाम इसके बिल्कुल विपरीत होता अर्थात् साम्यवादी आध्रस्य निर्माण हो गया होता। यह एक ऐसा डंडा था, जो भारतीय पूँजीजीवियोंको बाईं ओर चलानेके लिये तब तक बाधित कर सकता था, जब तक कि प्रजातान्त्रिक ढंगमें मतदान सम्भव बना रहे। भारत छोड़ो हिन्दू देशमें आर्थिक समस्याओंको मुलम्मा देनेके लिये इसमें अधिक श्रद्धा मौक्य और बौद्ध-सा हो सकता था, क्योंकि न तो उन्हें डाला जा सकता था और न स्वाभाविक निष्कर्षोंकी बात देखी जा सकती थी।

कांग्रेसके इतिहासमें अवादी अविश्वासको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण युगांतर बिन्दु बतलाना कोई अनिश्चयोक्ति नहीं है। पूर्वकालमें कांग्रेसके अंदर विद्यमान अनेक वामपंथी गुटोंके निरंतर दबावके परिणाम स्वरूप समाजवादी उपचार सुझाया गया था। १९५५ तक कांग्रेसके अंदर ऐसा कोई गुट शेष न रह गया था, तथापि केवल उन्मूलनवादी विचारधाराने ही नहीं, बल्कि वामपंथी विचारधाराने भी प्रधानता प्राप्त कर ली।

यह परिवर्तन किम प्रकार हुआ? हम पहले देख चुके हैं कि अखिल भारतीय पूँजीजीवियों और क्षेत्रीय मध्यम वर्गीय पूँजीजीवियोंके हितोंका वैषम्य किस प्रकार लगातार बढ़ रहा था। हम देशकी भाषिक पुनर्रचनाकी पृष्ठभूमिमें कार्यरत आर्थिक प्रवृत्तियों को भी देख चुके हैं, जिनका जन्म मध्यम वर्गीय पूँजीजीवियोंकी वर्गीय आवश्यकताओंमें हुआ था। और हम यह भी देख चुके हैं कि किम प्रकार साम्राज्यवादी

नीति का विरोध जिसे जिसे सामने आना गया, वैसे ही वैसे इन सभी प्रवृत्तियों और प्रति प्रवृत्तियों परस्पर एक दूसरे पर अपना प्रभाव डाला ।

अवासी अधिवेशन के पश्चात् मध्यम पूँजीजीवियों के विचारों में प्रधानता प्राप्त होना प्रारम्भ हुई । उन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया कि यदि प्रौद्योगिक प्रगति के अभाव में अर्थव्यवस्था को बचाना चाहती है, तो इसका एक मात्र आशा समाजवादी व्यवहार ही है । उन्होंने भारतीय समाजवाद के तथाकथित प्रजातांत्रिक अंगों केवल इसी कारण रक्षात्मक किया कि जिसने बड़े व्यापारिक हितों से ही नहीं बरन मध्यम वर्ग के व्यापारिक हितों से भी विराम प्राप्त हो सके, क्योंकि वे भी निजी लाभ के क्षेत्र में राज्य हस्तक्षेप की शक्ति डरते थे ।

लेकिन उस क्षण इस महत्वपूर्ण तत्त्व को आमानी से भुला दिया गया कि “ समाजवादी ” शब्द बड़े पूँजीजीवियों की प्रधान आर्थिक शक्ति पर सिक लपाने का ही साधन है, जिसके परिणाम स्वरूप उन दिशाओं में प्रगति करने में सहायता मिलेगी जिसमें मध्यम पूँजीजीवियों का भला हो सके ।

वर्तमान प्रयत्न इतने मर्मजटापूर्ण हैं कि इस बात का आश्वासन दिलाया जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र का प्रवेश केवल उन्हीं दिशाओं में होगा, जहाँ निजी प्रयत्नों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की सम्भावना न हो । इसका अर्थ हुआ कि भारी उद्योगों की उन्नति राज्य अपने हाथ में ले लेगा । यही वह क्षेत्र है जिसे बड़े पूँजीजीवी स्वयं नियंत्रित करना पसंद करते ।

इन दिशा की ओर अग्रसर होने में सयन आवश्यक है । दर भी है । यह संक्रमण के ही तत्त्व हैं, विरोध रूप में जब कि पूँजीजीवियों का एक गुट समाजवाद के साथ कीड़ा कर रहा हो और कुछ समय तक अपने ही हित के कारण उसके बारे में पूर्ण रूप से ईमानदारी बरतना चाहता हो । केवल नेत्रहीन व्यक्ति ही सरकार की सजा देकर अवासी की अपेक्षा कर सकता है ।

इस नये दृष्टिकोण का प्रभाव अब तक न सुनसुके जा सकेवाले भूमि विपदक प्रश्न पर अत्यधिक पड़ेगा । साम्यवाद की जमींदारी के वैज्ञानिक रूप से समग्र विश्व का

महत्त्वपूर्ण घर्ष

रहा है, लेकिन निरंतर बढ़ते औद्योगीकरणके समय जमींदारोंकी पकड़का किस प्रकार सामना किया जाय, कांग्रेसके नेता इसे टालनेका बितना ही प्रयत्न करें, लेकिन इस समस्याकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। उद्योग और कृषि एक दूसरेके पूरक होने ही चाहिये, अन्यथा आर्थिक सर्वनाश अवरयभावी है। अवांछी सभानवादीकी यह बात ग्राह्य नहीं चाहिये। लेकिन इनके सम्बन्धमें आगे, अन्यत्र बतलायेंगे।

अब हम अन्य सामाजिक घटनाओंकी ओर ध्यान देते हैं, जिसका विवरण अधिकतर लोगोंको मालूम है। १८ अप्रैल १९४४ को एशिया और अफ्रीकाके प्रतिनिधि हिन्देशियाके बाडुंग नामक स्थानपर एक सम्मेलनमें उपस्थित हुए। वे साम्राज्यवाद प्रेरित एक नृशंस हत्याकी हत्यामें मिले। चीनी तथा अन्य प्रतिनिधियोंको ले जानेवाला काश्मीर 'प्रिंसेस' नामक एयर इंडिया इंटर नेशनल वायुयान आगच्छी लपटोंने घिरा हुआ प्रशांत महासागरमें डूब गया। यह अंतर्ध्वंस-कार्य, किरायेके दुराभिकर्ताने किया था।

तथापि इस गम्भीर दुःखद घटनाने बाडुंग सम्मेलनके मन्त्रको द्विगुणित करने-काही कार्य किया और यह भी बतलाया कि साम्राज्यवादके भविष्योपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इतिहासमें प्रथम बार एशिया और अफ्रीकाके दो महाद्वीप, इस जानके साथ कि उनके पास उपनिवेशवादी रोगको समाप्त करनेकी शक्ति है, कार्य-क्रमकी एक सामान्य योजना बनानेके लिये मिले।

चीन और भारतके मध्य जो दृढ़ मित्रता और अवरोध उस समय विद्यमान था, उसके बिना इस प्रकारका सम्मेलन कदापि सम्भव नहीं हो पाता। एशिया-अफ्रीका एकाकी धुरी यही थी। पश्चिमने इस धुरीको नष्ट करनेका प्रयत्न अकारण नहीं किया था। जिस वायुयानमें चू-एन-लीकी यादगारी सूचना थी, उस वायुयानको अंतर्ध्वंस करनेके यत्नके पश्चात्, उन्होंने सम्मेलनका अंतर्ध्वंस करनेका प्रयत्न किया।

संयुक्त राज्यके परराष्ट्र विभागने प्रयोगक अभिकर्ताके रूपमें पाकिस्तानके मुहम्मदअली और धी लक्ष्मके कोटलावालाको चुना। उनके पीछे फिलिपाइन, थाईलैंड और ईराक़रूपी इशारे पर नावनेवाली कटपुतलियों खड़ी की गईं। तथाकथित स्वतंत्र सत्तारके इस विचित्र प्रतिनिधि-दलने एक मुँह होकर सम्मेलनको ध्वस्त करनेके लिये साम्यवाद-विरोधी परिचित कूट युक्तियोंका प्रयोग किया।

कोटलावाला ने इस बात पर जोर डाला कि सभी साम्यवादी सरकारों में मास्चेक उपग्रह समझना चाहिये, और इसका शक्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन बांडुंग में होना चाहिये। यही वह बात थी जिसके द्वारा संयुक्त राज्य के परराष्ट्र विभाग ने यह आशा की थी कि विशेष रूप से अपने निरंकुश समाज में वाममार्गी शक्तियों के प्रवेश से भयभीत सामंती तथा अर्थसामंती राज्य के प्रतिनिधियों में मतभेद और गड़बड़ पैदा होने के साथ ही नेहरू भी उत्तमान में पड़ जायेंगे और फलस्वरूप भाग्य-चीन धुरी निर्बल पड़ सकती है।

यह अभिलषित विचारण थी। ऐसी कोई बात नहीं हुई। नेहरू और वू-एन-ली की राजनीतिज्ञान ने सम्मेलन की रक्षा कर ली। जिन चेजों ने कुछ आशा नहीं की, उन्होंने भी बुद्धिमानों से काम लिया। सह आस्तित्व के पाँच सिद्धांतों के आधार पर दस सूत्री अधिक विवरणात्मक घोषणापत्र प्रकाशित हुआ। यह एक मतने पास हो गया। वस्तुतः अन्तर्धर्म के इस प्रयत्न का प्रभाव उत्पन्न उन्होंने पर पड़ा। समस्त संसार में लोगों ने आश्चर्य-चकित होकर यह देखा कि विभिन्न सिद्धांत और राजनैतिक व्यवस्था-वाले राष्ट्र एक स्थान पर एकत्रित हुए, उन्होंने गरमागरम और लगभग अपराध बुद्धिवाद-विवाद किया और अपने सिद्धांतों के एक ऐसे घोषणापत्र पर सहमत हो गये, जिसने शांतिपूर्ण दृष्टिकोण और शांतिपूर्ण समाधान का आश्वासन मिलता था।

पंचशील अब २० राष्ट्रों ने मान लिया। यह संधार्य में तत्कालीन लाभ था। अब तक एकता में पड़े हुए लोगों के लिये, यह पुल के समान था। यह दोनों महा-द्वीपों को अधिक निकट स्पर्श में ले आया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब साम्राज्यवाद उनके साथ बारी बारी में क्रूर व्यवहार नहीं कर सकता था। उसे पूर्ण एशिया और अफ्रीका के प्रति उत्तुंगता भी होना पड़ेगा।

अनर्विरोध आवश्यक नियमान् ये। बांडुंग सम्मेलन में भाग लेनेवाले अनेक सदस्य युद्धकालिक दक्षिणपूर्वी एशिया संधिसंघटन के सदस्य थे, जिसका लक्ष्य चीन की सर्व-भौमता और स्वतंत्रता थी और जिसका समर्थन संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। अन्य लोगों की सक्रिय अभिरूचि मध्यपूर्व में सीयेरी ही प्रतिवृत्ति का दाद संधि में थी। जिसकी रचना ब्रिटेन ने की थी तथा जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका का आशीर्वाद प्राप्त था। उसमें सम्मिलित अधिकतर सदस्य राष्ट्र नानमाय के स्वतंत्र थे, लेकिन वाम्तव में ये संसार की एक या दूसरी साम्राज्यवादी शक्ति पर आश्रित थे।

महत्त्वपूर्ण वर्ष

लेकिन यह सम्मलेनके लिये किसी अन्तर्जनकी आवश्यकता नहीं थी कि बाहुगंगा अनुभव और भावना धीरे धीरे इन पारस्परिक विरोधोंका समाधान कर डालेगी और अफ्रीका और एशियावासियोंको समानरूपसे उन भूतन्त्राओंको तोड़नेके अवसर प्रदान करेगी, जिनके द्वारा वह अब तक पश्चिमी स्वामियोंने बंधे हुए थे।

औरनिवेशिक मुक्ति प्राप्त करनेके प्रयत्नोंका केन्द्रस्थल बने अफ्रीकाके सम्बंधमें यह बात विशेष रूपसे सत्य थी। वहाँ पर साम्राज्यवाद अपना मृत्युपाश कायम रखनेके लिये हठपूर्वक लड़ रहा था। इस बातके चिन्ह स्पष्ट दीख रहे थे कि यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रह सकती। क्या बाहुगंगा यह तय नहीं हो गया था कि एशिया और अफ्रीकाका दूसरा सम्मेलन अफ्रीकाकी भूमिपर होगा? यह बह निश्चय था, जिनमें एक चेतावनी सन्निहित थी।

अफ्रीका—यही वह स्थान था जहाँ बीसवीं शताब्दीके द्वितीय अर्धशताब्दी कहानी लिखी जानेवाली थी। राष्ट्रमंच द्वारा १९५४ में प्रकाशित डेमोग्रेफिक इयर बुकने अनुसार अफ्रीकामें केवल पाँच प्रदेश स्वराज्य प्राप्त थे, अर्थात्—मिश्र, इथोपिया, एंगोला, लाइबेरिया, लीबिया और दक्षिण अफ्रीका सब। शेष अफ्रीकामें जहाँभी जनसंख्या कुलकी ६१० थी, स्वराज्य नहीं था। अफ्रीकाके एक प्रदेशको “बेलजियम” अधिकृत, २१ प्रदेशको “फ्रांस” अधिकृत, ५ को “पुर्तगाल” अधिकृत और २० को “ब्रिटिश” अधिकृत अनुमोचित किया गया था। इन तीन घोषणाका वस्तुतः अर्थ यह था कि अफ्रीकामें लगभग २० करोड़ गुलाम उन पश्चिमी राष्ट्रोंकी निजी संपत्ति थे, जो हमेशा ‘स्वतंत्र जनता’ और ‘स्वतंत्र’ सत्ताकी बात करते रहते हैं।

यदि पश्चिमके साम्राज्य निर्माता यह मौखते थे कि अफ्रीकाको कायम रखा जा सकता है, तो वे बाहुगंगा सम्मेलनके नाम सेते ही कॉम्पनेके अनिच्छित और कर भी क्या सकते थे? उन्हें पता था कि एशियामें भिन्नता स्थापित करनेवाले अफ्रीकामें और उन्हें ध्यान देना पड़ेगा। यही अनुभव था जिसने शीत युद्धकी स्थितिको समाप्त करनेवाली शक्तियोंकी गति दे दी।

जो लोग ससारके परिवर्तनोंके सम्बन्धमें यही धारण रखना चाहते हैं कि वे अमर्यादित वैयक्तिक शक्तियोंके परिणाम स्वरूप होती हैं, वे लोग इस बातमें सहमत न होंगे। उनके सामने लिये हमें उन फटनाओंकी ओर पुन ध्यान देना चाहिये, जिन्हें “ बाहुगके निरर्थक विद्रोह ” कहकर टाल दिया गया था।

प्रधान मंत्री नेह्रूने पंचशतलके सिद्धांतोंका प्रचार करके उन देशोंका सम्पर्क पानेके लिये सोवियत संघ और पूर्वी यूरोपके अन्य सन्तानवादी देशोंका जूनमें भ्रमण किया। १५ जुलाईको १८ नोवुज पुस्तकर पानेवाले वैदिकीय विचारके राष्ट्रोंमें यह असेल की वे राजनैतिक साधनके रूपमें आणविक शस्त्रास्त्रोंका प्रयोग बढ़ कर दें। १९४५ के पोस्टडम सम्मेलनके पञ्चाल प्रथम बार १८ जुलाईमें जिनकावे होनेवाले बार राष्ट्रोंके शीर्षस्थ सम्मेलनमें स्थायी शान्ति प्राप्त करनेका प्रयत्न करनेकी प्रतिज्ञा की। इस विचार-विमर्शमें आवश्यकजनक सौहार्दता बनी रही।

बहुत होता शेष था। चीनने निम्नार्थमें घोषणा कर दी कि वह उन ११ अमरीकन उद्योगोंमें मुक्त कर देगा, जिन्हें भेदिया होनेके अदरारमें बंदी बनाया गया था। इस प्रकार दोनों देशोंके बीच गैरसरकारी बातचीतके लिये मार्ग साफ हो गया। सितम्बर १९४५ में सोवियत संघ और पश्चिमी जर्मनीने कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करनेके लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये। संयुक्त राज्य अमेरिकाने अक्टूबरमें सोवियत संघ और पूर्वी यूरोपकी यात्रा करनेवाले अमेरिकी-नोंके पार-पनोंके ऊपर लगे प्रतिबन्धको हटानेकी घोषणा कर दी। नवम्बर और दिसम्बरमें बुलगानिन और खुश्चेवने भारत यात्रा और अफगानिस्तानका दौरा किया।

१९४५ के अन्त तक प्रमुखरूपमें बाहुगके सम्पर्क १६ नये सदस्योंके राष्ट्रसंघमें प्रविष्ट होनेके कारण उस संगठनका शक्ति स्तुम्भन बहुत कुछ बढ़त गया। जापानके प्रवेश और फारमोसाके स्थानपर चीनी जन गण-तंत्रके सुरक्षा परिपक्वमें पहुँचने पर; निय परिवर्तनको संयुक्त राज्य अमेरिका अधिक दिनों तक नहीं टाल सकता था; बाहुग दल निश्चित रूपमें राष्ट्रसंघमें तत्पन्न निर्णायक स्थितिमें पहुँच जायगा।

आणविक शक्तियों शान्ति हेतु प्रयोग करनेके विषयमें होनेवाला अत्यधिक सकल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी अन्ततः महत्वपूर्ण था। प्रथम बार अणुओंके विस्फोटन और

महत्त्वपूर्ण वर्ष

सम्मिलनके भेदोन्तर और विश्वके लाभ हेतु इस अनीमित शक्तिके प्रयोग पर स्पष्ट विचार हुआ। भारतने इस सम्मेलनका सभापतित्व किया। यदि विज्ञान जिसपर युद्धमें विजय आधारित है, सीद्दार्दतामे प्रभावित हो जाय, तो निश्चित रूपसे शांति अधिक सुगम हो सकती है।

और यह प्रक्रिया १९५६ मे जारी रही। भारतमें अनेक विदेशी सभ्राज व्यक्ति आये, जिनमे सऊदी अरब और ईरानके शाह भी समिलित हैं। इंग्लैंडमें मलेनकोव, बुल्गारिन और लुइचेव पहुँचे। चीनने कम्बोदिया और जापान सरीखे राष्ट्रोंके उन प्रतिनिधियोंका आतिथ्य सत्कार किया, जिन्हें पहले सदेहनी दृष्टिमे देखा जाना था। मिश्र और पाकिस्तानने अपने आपको गणतंत्र घोषित कर दिया। सीमांत प्रदेशोंके आपार अधिक व्यापार होने लगा। मासुतिक विनिमय द्वारा लोगोंमे एक दूसरेको समझनेका शान बसा। अंतमे सामान्य स्थितिके चिन्ह दिखलाई देने लगे।

लेकिन सर्वथा यह बात नहीं थी। तनाव क्षेत्र चीनी तटमे बदल कर पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीकामें पहुँच गया था। साम्राज्यवादी रणनीतिके परि वर्तन और नये संकटका प्रमुख कारण अरब प्रदेशीय तेल था। अमेरिकिके पुराने तेल क्षेत्र शुष्क होने लगे थे। तेलकी माँग बढ़ रही थी। संयुक्त राज्य अमेरिका भी वास्तविक रूपसे तेलका आयात करने लगा था। पश्चिमी एशियामें विश्वका ८० प्रतिशत प्रमाणित तेल भंडार था। लेकिन इस अपेक्षावृत्त सुगमित औपनिवेशिक क्षेत्रमे भी विस्फोट होने लगे थे और परिणाम स्वरूप ये शेय एशियाके मित्रता स्थापित करनेमें लगे थे।

१६ मार्च १९५६ को साइप्रसकी व्यथाति पर होनेवाले विवादका उत्तर देते हुए प्रधान मंत्री एथोनी ईडनने लोकसभाके सामने वास्तविकता पर प्रकाश डाला था। उन्होंने कहा था कि “हमारा कर्तव्य अपने देशकी महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओं की सुरक्षा है... सबसे ऊपर तेल... हमारे देशवासियोंका कल्याण और यहाँ तक कि उनका जीवन भी साइप्रस पर आश्रित है, क्योंकि कि यह स्थान तेलके सत्संयोग हिलोकी रक्षाके लिये चीनी और सुनरीके समान खरा है। यह साम्राज्यवाद नहीं है। प्रत्येक सरकारका यही सुस्पष्ट कर्तव्य होना चाहिये और

इसे ही हम पूरा करना चाहते हैं।" एक सप्ताह पूर्व लंदनके डेली टेलीग्राफने इस परोस्थितिको मनेस्टे हुए लिखा था कि, "मध्यपूर्वकी नीतिक मुग्य उद्देश्य हमारी तैल पूर्णकी सुरक्षित करना है।"

कच्चा अफिरक और भूत अरब अरब येन यूरोप और येत अमेरिकाके लाभ हेतु जीवन रहनेको तैयार नहीं थे। लंदन और वाशिंगटन-वासियोंके लिये यह बात बहुत सत्यके समान थी और इसी कारण आरानुभूत रूपसे उन्होंने हाथ-पैर मारे। बगदाद सभित्त सनर्धन करनेवाले मयूकी मित्र, सऊदी अरब और सीरियाने भारी आलोचना की। इस समझे संबद्ध एक सदस्य ईरानने पुनः मोचना प्रारम्भ कर दिया। इसी बीच इस सभित्त सम्मिलित होनेके लिये दबाव डालते पानेके कारण जोर्डनने विरोध कर दिया और अपनी सहाय्य प्राप्त सेनाके पञ्चमचारी ब्रिटिश सेनापति "ग्लर पाशा" को डराइ पेंक।

जब पश्चिमने अरब राज्योंको इत्यादिके सैनिकीकरणकी धमकी दी, तब इस प्रयत्नको निरर्थक करनेके लिये उनकी प्रतिजिन्ना यह हुई कि उन्होंने समाज-वादी दुनियाँको ओर दृष्टिसे किया। मित्रने पुनः साथ मोविन्द सचमे शत्रु सहायताके समझौते पर बलाघोष कर डालो। सीरिया भी ऐसा ही करनेका विचार कर रहा था और यही दरा सऊदी अरबकी थी। और मऊदी अरबवासियोंके महान् आश्चर्य हुआ, जब उन्होंने देखा कि "नास्तिक" मोविन्द सच किसी भी प्रकारके उपबोधोंके बिना भी पर्याप्त आर्थिक सहायता देनेके लिये तैयार है।

पाकिस्तान भी समाजवादो दुनियाँसे पुन सार्के स्थापित करनेकी आवश्यकताके विषयमें सोचने लगा। उसके प्रगन मयूने चीन जानेका विचार प्रकट किया। एक सोविन्द व्यापारिक मंडल परम्पर सङ्ग्रह सनसौले पर विचारविमर्श करनेके लिये कर्चोचोने आया। राजनैतिक रूपमें भी सयुक्त राष्ट्रीय संघनोने मुक्ति पानेकी प्रक्रिया धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी।

संघवासियोंने इस नई भावनाका बड़े नाटकीय ढंगसे प्रदर्शन किया। आम चुनावोंमें मतदान करते समय उन्होंने साम्यवादके विनाशक जोन कोटलावालाको बुरा तरह पराजित कर डाला।

महत्त्वपूर्ण चर्चा

थोड़े राज्योंमें, एशिया और अफ्रीका वागियोंमें जो अब तक साम्राज्यवादी दवावके शिकार रहे थे, भारतकी ही तरह अपनी स्वतंत्रता प्रतिपादित करनी प्रारम्भ कर दी। राजतन्त्रामक सरकारें गणतन्त्रामक सरकारें तथा सामन्यवादी और कयाइली व्यवस्थावाले देश भी इसी ढंगकी आकांक्षाओंका पोषण कर रहे थे। इस बातकी भी पूरी सम्भावना थी कि कहीं नई इतलपल आर्थिक शक्ति पूर्ण होकर साम्राज्यवादको उसके मानसिक स्थान और अशान्ति स्थान देनेमें इनकार न कर दे और फल स्वरूप राजनैतिक आर्थिक और सामाजिक प्रगतिज्ञ द्वार उन्मुक्त हो जाय। भारतका कार्य १९५५ और १९५६ में इन महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाओंका अनेक दिशाओंमें नेतृत्व करना रहा।

बाहुंग सम्मेलनके समाप्त होते ही नेहरूजी सोवियत संघ और पूर्वी यूरोपकी यात्रा तथा १९५५ की समाप्तिके समय बुलगानिन और कुरुचेवकी भारत, बर्मा और आंगानिस्तानकी जवाबी यात्रा अभिन्न स्मरणीय घटनाये थीं। यह घटना समाजवादी दुनियाँके साथ भारतके सम्बन्धोंमें एक ऐतिहासिक परिवर्तन बिंदु है।

शीघ्रता पूर्वक प्रगतिशील समाजवादी देशोंके साथ व्यापारिक और आर्थिक सहयोग प्राप्त करनेके लिये कदम उठाये जाने लगे, सोवियत संघ समानता और पास्परिक सामग्री शतोंपर भारत द्वारा अनेकानि मिनी भी प्रगतिशील सहायता देनेके लिये तैयार था। कुरुचेवने विदेशी सहायताके इस सिद्धांतकी सुप्रीम सोवियतके सामने २६ दिसम्बर १९५५ के दिन दिये गये अपने भाषणमें यथेष्ट स्पष्टताके साथ व्याख्या की थी। उसका प्रमुख अनुच्छेद है कि—

“सोवियत संघ प्रत्येक देशको मित्रताकी भावनाके साथ और किसी प्रकारके उपबन्धोंके बिना आर्थिक एवं तांत्रिक सहायता देता है। हमारे पास अतिरिक्त पूँजी नहीं है।

“हमारी अर्थ-व्यवस्था योजनानुसार चलती है। हमारी अभिरूचि पूँजीके निर्यातमें नहीं है। और मालके निर्यातने सम्बन्धमें हम केवल उतना ही उदात्तन करते हैं, जितना हमारे लिये, हमारे मित्रोंके लिये और विदेशोंसे व्यापारके लिये आवश्यक हो।

“बुद्ध वस्तुओंकी तो हम अपने देशकी बढ़ती हुई आवश्यकताओंके लिये भी पूर्ति नहीं कर पाते, लेकिन अपने मित्रोंके साथ प्राप्य सामानको बाँट लेना

और इन प्रकार एक सापोंके टंगने उनको सहायता करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं।

“कुछ समझदार पूँजीजीवी आज कल अर्थ विवर्धित देशोंमें आर्थिक सहायता बढ़ानेके विषयमें बानचीन करते हैं। यह सच नहीं है। पूँजीवादी देशोंद्वारा ऐसी सहायतामें कोई आपत्ति नहीं है। नैतिक गुणों और सधियोंमें देशोंको परीक्षनेकी अपेक्षा यह अधिक अच्छी बात है।

“हम इन बातोंमें बहुत प्रसन्न हैं कि उन देशोंके साथ भारतके संबंध बहुत अच्छे हैं, जिनके साथ हमारे सम्बन्ध किन्हीं कारणोंसे कुछ खिंचे हुए और अनुमाह पूर्ण हैं। अपने मित्र, भारतके भाव्यमाने हम उनके साथ अपने संबंध सुधारनेकी आशा करते हैं।”

रुतु और मित्रोंमें भेद करनेके लिये भारतको इस घोषणाके साथ अगले सप्ताहमें राष्ट्रमन्त्र आइसनहावर द्वारा किये गये राष्ट्रभेदोंके समानान्तर अनुच्छेदकी केवल तुलना करनेकी आवश्यकता है। उन्होंने कहा था कि —

“हमें अपने पारस्परिक सुरक्षा कार्यक्रमको अधिक सुदृढ़ और सुरक्षित बनाना चाहिये। चूँकि अविर्कृत क्षेत्रोंमें दोस्ती और अमानिती परिस्थितियोंके कारण वहोंने लोग अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवादके विशेष शत्रु बन जाते हैं। इस कारण साम्यवादी धमकियों और प्रयत्नोंमें उनकी स्वतंत्रताकी रक्षाके लिये यह आवश्यक है कि आर्थिक उन्नति और सुरक्षा प्राप्त करनेमें उनकी सहायता की जाय।”

जैसे ही मिलाई इस्यात कारखानेका विवरण प्राप्त हुआ, वैसे ही इस कलक प्रचार होने लग्य कि सोवियत साम्राज्य और तांत्रिक सहायता किमी भी देशमें मिलेन और अमेरिकन निर्माताओंकी सुरक्षा नहीं कर सकती। समझत यह एक नवीनतम रूपांतर कारखाना बननेवाला था। इसके अतिरिक्त सोवियतसंघ जावेवाले एक भारतीय रूपांतर प्रतिनिधि मंडलने, जिसमें रुमरू पक्षपात करनेवाले तन्त्र बहुत कम थे, भारत सरकारको अपना प्रतिवेदन दिया और उसमें स्पष्ट रूपसे उन्होंने यह वक्तव्य कि सोवियत रूपांतर उद्योग अनेक रूपोंमें मधुसूक्त अमेरिकनके उद्योगों भी आगे है।

महत्त्वपूर्ण चर्चा

इस्पात के परचात अनेक क्षेत्रोंमें सर्पक स्थापित हुए, जैसे खान, नई खानोंकी खोज, तेल, औषधियों, जहाज और यहाँ तक कि भारी औद्योगिक प्रसार। खानपानीके साथ उद्योग गये यह कदम निरिचतरूपसे प्राप्त अमेरिकियों पर भारतकी आभ्युत्थानो समाप्त करनेकी दिशामें उद्योग गये प्राथमिक प्रयत्न थे। अब इस बातमें अधिक देर नहीं थी, जब कि भारतीय नेता इन नये सम्बंधोंको विवर्तित करेंगे और यहाँ तक कि साम्राज्यवादी मयारोहनकी सदैव विद्यमान धमकीका निराकरण करनेके लिये ममाजरादी देशोंके साथ सैनिक एवं अन्य आवश्यकताओंका विक्रय करना प्रारम्भ कर देंगे।

इस विषयमें यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात है कि सोवियत सचने काश्मीरके विषयमें भारतके बहुत कुछ अनुकूल मिद्धान ही अपनाया है। सोवियत-अफगान सम्बंधोंका पुनर्निर्धारण और पश्तून आन्दोलनकी जनतात्मिक भावनाओंकी माफ्फो द्वारा स्वीकृति भी विचारोंमें कानि उत्पन्न करनेवाली बात है।

भारतकी उत्तर-पश्चिमी सीमापर शक्तियोंका ऐसा पुनर्गठन पाकिस्तानको निष्क्रिय बनानेमें सहायता करता है। क्योंकि पाकिस्तान संयुक्तराज्य द्वारा रण सन्धि होकर स्वतंत्र इष्टिकोण अपनानेके इच्छुक भारतके लिये भारी अवरोधका कारण प्रमाणित हो सकता था। यद्यपि यह सच है कि ब्रिटेन और संयुक्तराज्य अमेरिका तथा पूर्वी और पश्चिमी भागोंका पारस्परिक सर्पक उस देशमें नई शक्ति उन्मुक्त कर रहा है, जिसके सहारे जालार-नीतिकी पद्धति सम्भवतया पाकिस्तान अपनेको मुक्त कर सके, लेकिन भारतके लिये तो सदैव भय रहता ही है, क्योंकि इस संग्रामने छुटकारा पानेके लिये वहाँ अब तक कोई वास्तविक सगटिल प्रयत्न नहीं हुआ है।

भारत सरकारके मामले हमेशा यह वास्तविकता आती है और पल्ल उगे सभी आशाने राष्ट्रमंडलीय सदस्यताको कायम रखने पर विवश करती है कि शायद अमेरिका द्वारा उत्तेजित पाकिस्तानकी दुःसाहसिक नीतिको शांत करनेमें आघात स्थितने ब्रिटेन अपने प्रभावका उपयोग करेगा। लेकिन अग्नीवाकी मिस्फोटक परिस्थितिले और उनके निराकरण हेतु भारत द्वारा ब्रिटिश हितों

मिश्र द्वारा स्वतंत्र नहर का स्वामित्व

अधिकधिक टकरानेवाली स्थिति ग्रहण करनेके कारण इस भेसलापर भी भारे तनाव पड़ रहा है ।

इस कारण मिश्र द्वारा स्वतंत्र नहर कंपनी का स्वामित्व ग्रहण करने का साहसिक प्रयत्न इस प्रस्ताव सचट उपस्थित करनेके प्रयत्नके बावजूद भी एक महत्वपूर्ण घटना है । सामान्यवाद द्वारा मंजूर तलवाये का मिश्र पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा । इससे केवल किसी कालके शायद पश्चिम और मसोदित पूर्वके सम्बंधोंमें लोभ ही बढ़ता है । आज स्वतंत्र की बात है, कल अरब स्थित तैल का प्रश्न हो सकता है । राष्ट्रीय प्रगतिके साथ विदेशी मुविधाओंकी समाप्ति जिन रूपमें सम्बंधित है, जैसा कि मिश्र और उनके आनवान बाँपके प्रकरणमें था, उनके फलस्वरूप समस्त एशिया और अफ्रीका में इसी प्रकारके बिचारोंको प्रोत्साहन मिलनेकी पूर्ण सम्भावना है । भारतमें यह बात विशेषतया लागू होती है, क्योंकि यहाँ विदेशी पूँजी अधिक है ।

जिन प्रकार चौथी शताब्दीके प्रथम दशका में एशिया की घटनाओं का प्रभाव समस्त प्रवृत्तियों पर पड़ा था, उसी प्रकार आज और अफ्रीका की घटनाओं के शताब्दीके द्वितीय अर्धशतमें प्रमुखता प्राप्त कर रही हैं । यह निर्णायक काल है, जो सामान्यवाद की मृत्यु देता सकेगा ।

प्रचुरताकी योजना

कर्मण्येवाधिकारस्ते, मा फलेषु कदाचन ।

—भगवद्गीता

स्वतंत्रताभी नीतिमें भारतको होनेवाले लाभको देखकर एशिया और अफ्रीका दोनोंमें प्रभावित होना ही पड़ा । प्रथम पंचवर्षीय योजना वालोंमें अपमानपूर्ण दवावके सामने आत्मसमर्पण बिना ही महत्त्वपूर्ण आर्थिक सफलता प्राप्त हुई थी ।

इसके कुल परिणामोंमें बड़ी प्रतिभासित होना था कि पाँच वर्षोंमें वास्तविक राष्ट्रीय आयमें १८ प्रतिशतकी वृद्धि हुई है । १९५२-५३ के मूल्यांकित आधार-पर यह अनुमान लगाया गया था कि राष्ट्रीय आय १९५०-५१ के रु ६,११० करोड़में बढ़ कर १९५५-५६ में रु १०,८०० करोड़ हो गई है । प्रति व्यक्ति आयमें ११ प्रतिशत और प्रति व्यक्ति उपभोगमें ६ प्रतिशतका सुधार देखा गया था ।

अनाजका उत्पादन २० प्रतिशत, रुईका ४५ प्रतिशत और तिलहनका ८ प्रतिशत बढ़ गया था । सिंचाईके महत्त्व कायों द्वारा ६० लाख एकड़ अतिरिक्त भूमि और लघु सिंचाई कायों द्वारा १०० लाख एकड़ अन्य भूमि सिंचित होने लगी थी ।

औद्योगिक उत्पादनका अंतरिम देशनाक १९४६ को १०० आधार मान कर १९५० के १०५ और १९५१ के ११७ के स्थानपर १९५५ में १६१ तक हो गया था ।

योजनामें प्रमुख बल कृषिपर दिया था, किंतु हिन्दुस्थान मशीन इल फैक्टरी, चित्तूरजन रेल इंजन कारखाना, पेरम्बूर सवारी डिब्बा कारखाना आदि अनेक उद्योगों द्वारा राज्यने भी औद्योगिक विकासमें प्रमुख भाग लेना प्रारम्भ कर दिया था,

निजी क्षेत्रके अन्दर विशेषरूपने उत्पादक माल और पूँजी मालके उद्योगोंकी स्थापनामें यथेष्ट नवीन विनियोजन भी हुआ था । भारता-नागल सरीखी बहु उद्देशीय आयोजनाओंकी प्रगति भी निरन्तर हो रही थी, जो सरकारकी विशदलक्ष्य

योजनाओंमें एक है। आठ वर्षोंमें सिचाई और बिजलीकी प्रगतिके लिये होनेवाला विनियोजन इसमें कई गुना अधिक था, जो अग्रोमें अपने सामान्य कालके २०० वर्षोंमें दिया था।

तीन इलाक़ कारखानों और एक भारी विद्युत कारखानेमें सम्बंधित प्रारम्भिक कार्य पूरा हो चुका था। चूंकि लागत दरमें १९५०-५१ के ४-६ प्रतिशतसे १९५२-५६ में ७-२ प्रतिशतकी वृद्धि होनेके परिणामस्वरूप मुद्रास्फीति का दबाव नहीं बना था, इस कारण अधिक आवश्यक कार्य प्रारम्भ करनेके लिये अब एक सुन्दर आधार मौजूद था। वास्तविकता यह है कि प्रथम योजनाकालके समाप्त होनेपर मूल्यांकन योजनाके आरम्भ होनेके समयमें १२ प्रतिशतकी कमी हुई थी।

निश्चिन्तरूपमें भारतीयोंका जीवनस्तर अब भी दुनियाके निम्नतम स्तरीय देशोंके अन्तर्गत था। अतः श्रमिक उपयोग, स्वीकृत स्वास्थ्य-स्तरमें कम था। प्रति व्यक्ति कपड़ोंका उपभोग युद्धपूर्वके स्तर पर था। आवास स्थान अत्यल्प थे और देशकी लगभग आधी जनताकी उपभोक्ता मात्रपर खर्च करनेके लिये वार्षिक ६-७ रुपये प्रतिमासमें अधिक नहीं मिल पाता था। घरोंमें पैदा रिये अनाज और घरोंमें बनी वस्तुओं सहित श्रमिक उपभोग रु. १२ से भी कम था। इसके अतिरिक्त देशमें नौसरोके अन्दर भी भ्रमराक्षिणी वृद्धिके साथ कदम नहीं मिला पा रहे थे। अस्तु योजनाके अन्य अंगोंकी आलोचना दिखानी ही गंभीर क्यों न हो, किन्तु प्रथम योजनामें प्राप्त होनेवाले लाभोंका महत्त्व कम नहीं किया जा सकता।

पौ सो महात्तमोर्मि एवं अन्य भारतीय राज्या राज्ञियोंने विदेशी अर्थ-शास्त्रियोंके एक दलके साथ पर्याप्त विचार विमर्श करनेके पश्चात् त्रिम द्वितीय पंचवर्षीय योजनाका प्रारम्भ बनाया था, उसके ऊपर १९५५ से आरम्भ होकर १९५६ तक, काफी विवाद होना रहा। तथापि इस निर्णायक विवादके विवरणपर विचार करनेसे पहले एक बार फिर उस समानान्तर आन्दोलन अर्थात् भाषावी पुनर्गठन मौल पर विचार करना जरूरी है, जो भारतीय राजनैतिक दृष्टिकोण केवल एक आन्तरिक

प्रशुरता की योजना

जनक रूप ही नहीं है, बल्कि देशकी अर्थ व्यवस्थाके साथ भी अत्यंत निकट रूपसे सम्बंधित है ।

✓ अक्टूबर १९५५ को राज्य पुनर्गठन आयोगका प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ । सामान्य तौरसे वर्तमान २७ राज्योंके स्थानपर उसमें कश्मीर सहित १६ राज्योंके निर्माणकी सिफारश थी । इस प्रतिवेदनके प्रकाशने, जिसके कुछ विवरणोंका किन्हीं क्षेत्रोंसे पूर्वज्ञान था, भारतके मुगल भागका पूर्ण ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया ।

सामान्य तौर पर सिफारशें स्वीकार्य थीं । यद्यपि भाषा और संस्कृतिकी कट्टर आस्थासे इटाकर सीमाओंके पुनर्गठनकी आवश्यकतापर जोर डाला गया था । तथापि तथ्य यह था, कि आयोगने सबसे अधिक भाषा और संस्कृतिमा ही ध्यान रखा था । जिन केन्द्रोंमें इन ओर ध्यान नहीं दिया गया, वही वट्ट विवादके क्षेत्र बन गये ।

द्विभाषिक रूप अग्रिय था । पंजाब-पैसू हिमाचल और महाराष्ट्र-गुजरातके लिये यही प्रस्तावित किया गया था और यही पर तनाव रोग ही पैदा हो गया, क्योंकि एक भाषाभाषी वर्ग सोचता था कि कहीं दूसरा वर्ग प्रभुत्व प्राप्त न कर सके । महाराष्ट्रवासियोंमें यह भय विशेष रूपसे व्याप्त था । आयोगका निर्णय था कि विदर्भ जो प्रमुख रूपसे मराठी भाषी क्षेत्र था, प्रस्तावित द्विभाषिक राज्यके बाहर रखा जाय, यद्यपि कच्छ और सौराष्ट्रके गुजराती भाषी क्षेत्रोंसे सम्मिलित कर लिया गया था । यह स्पष्ट था कि आयोगकी सिफारशों द्वारा विशुद्ध द्विभाषिक राज्यमें महाराष्ट्रवासियोंकी वास्तविक बहुमत प्राप्त करनेमें बाधित करनेका प्रयत्न हुआ था । अपने विरुद्ध, अन्यथा सोचनेवाले दलोंका, प्रमुख कार्य यह हो गया कि इन 'गठबंधन' को समाप्त कर दिया जाय । उन्होंने अब अपनी शक्तिका प्रदर्शन किया । हिन्दू और सिक्ख, महाराष्ट्रियों और गुजरातियोंमें मतभेद बढ़ गये ।

अन्य क्षेत्रोंमें इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ होनेवाला था । देशके प्रत्येक भाषिक दलने यह सोचा कि यदि पंजाब और बम्बई प्रदेशमें प्रतिवेदनकी इतनी उम्र आलोचना हो रही है, तो वह भी अपनी शक्तिके प्रदर्शन द्वारा उममें परिवर्तन

चा सकते हैं। एक सप्ताहके इतर या उधर किसी भूनिर्खंड पर अधिकार पानेके प्रयत्नको लेकर उनकी घुटनी दुई भागनामे खुन कर सामने आ गई। कमी-कमी तो यह मालूम पाना था, किनी गोबके भविष्यका प्रत्य तोहर ही भाई-भाई पारस्परिक युद्ध छिड़ जायगा।

प्रथम सशोधनोंको घोषणा हुई। मराठे और गुजराती जनग हो सकते थे, लेकिन ऐसी दशमे वम्बई शहर एक पृथक् इकाई रहेंगे। यह सुभाव, दृढपनी मराठोंके गल पर पड़नेवाले एक नमाचेंके सनातन मनमा गया।

वम्बई नगरको लेकर होनेवाला सर्ष अन्य सभी सर्षोंसे बढचढ कर था। महाराष्ट्रवातियोंके त्रिने यह उनके भविष्यका अर्थात एक सपूर्ण जातिकी आर्थिक मशुद्धिमा युद्ध हो गया। नेहरू ताने दिने महाराष्ट्रका भाग मान लिदा था, उस वम्बईके बिना महाराष्ट्रकी कमी शीघ्रतापूर्वक ठगने नहीं हो सकती थी।

सर्वोच्च और निर्जलन स्तरका महाराष्ट्रवासी दब-दबा शहरकी जीतनेके लिये संगठित हुआ। देशने शासद ही कभी ऐसी उत्तेजना और लालके दर्शन किये हों। इस भादनाके साथ-साथ यह मद्र विधानान या कि अगले चुनावमे कोंग्रिसको महाराष्ट्रसे एवं भी मत प्राप्त न हो सकेगा। स्पष्टता इन महत्तराली नगरके मधुपने भाषावादकी शक्तिको रेखांकित कर दिना, त्रिपक्ष गमना राजनैतिक स्वमे प्रच्छन्न होनेके खतरोंके बिना कोई नहीं कर सकता था। मुँह दिगनेके अनन्त प्रयत्न किये गये। यह कहा गया कि वम्बई नगर केन्द्र सांभल होना, लेकिन महाराष्ट्रकी राजधानी भी दग रहेगा। पालु कुछ वर्षों, शासद पांच वर्ष तक ही राजधानी क्यों रहना चाहिये? इसके स्थान पर बिदमे-महिन गुडगली गरीबी नगरी राज्यका निर्माण क्यों न हो?

वस्तुतः कोंग्रिसो नेगामो हूग वम्बई नगर विषयक मजदके सपूर्ण प्रयत्नोंको डेम्कर आया होना है, लेकिन इसका कारण ईदनेके लिये दूर जानेकी आवश्यकता नहीं है।

मुख्य गुजरातको, त्रिपक्ष शिग-केन्द्र अदलतावाद है, वम्बईके भांडव्यके दारने विचित भी बिना नहीं थी। नगरके दंग और गुन्गानियोंके मग होनेवाली छेड़-

प्रचुरता की योजना

छादरो भी प्रतिनिधित्व स्वरूप गुजरातमें महाराष्ट्रियनोंके साथ कोई हिंसात्मक बदला नहीं निकाला गया। अहमदाबादके गुजरातियोंको बम्बई स्थित अपने सहधर्मियोंके प्रति कोई वास्तविक सशस्त्रभूति नहीं है। वस्तुतः वे तो उन्हें अपने सभास्य शत्रु मानते हैं, विशेष रूपमें मारवाडी पूँजीके साथ उनके निकट संपर्कके कारण, उस संपर्कके कारण जिनके अवरोध हेतु अहमदाबादमें उन्होंने भाती प्रयत्न किया है। अगर बम्बई महाराष्ट्रमें चला जाता है, तो क्या हुआ? गुजरात काउलाको विकसित कर डालेगा।

बम्बईमें महाराष्ट्रसे पृथक् करनेका कारण यह था कि न केवल शहरके गुजरातियोंको उनकी आवश्यकता थी, बल्कि भारतके बड़े पूँजीजीवी और विदेशी पूँजी भी यही चाहती थी। कांग्रेस ऐसी माँगकी उपोक्षा कैसे कर सकती थी, विशेष रूपमें जब कि पार्टीमें इसी जरियेमें पैसा प्राप्त होता था। बड़े पूँजीजीवी अनेक बातें स्वीकार करनेको तैयार किये जा सकते थे, किन्तु अपने अत्यंत विमर्शित स्वार्थोंको महाराष्ट्रियन राजनीतिकी अनिश्चितताके भरोसे छोड़नेके लिये नहीं।

और इस प्रकार नेहरूको भी इस अन्यायको न्यायमिद मान्य करनेके लिये विवश किया गया। उन्होंने महाराष्ट्रियनोंकी माँगका समर्थन किया, लेकिन इस निर्णयको टालनेके बहाने ढूँढ़े। दक्षिण पंथियोंकी आवाज इस सम्बंधमें दृढ़ और अडिग थी, क्योंकि बम्बईमें अनेक हितोंका समन्वय होता था।

बम्बई विषयक कांग्रेसकी नीतिके मोड़ों और घुमावोंको न्याय-मिद करनेके लिये सभी प्रकारके तर्क उपस्थित किये गये। सर्वधर्मवास्तका तत्कालावधिमें बड़ा विचित्र था। क्योंकि कलकत्ता और अन्य अनेक नगरोंमें भी क्या इसी प्रकार सभी जानियें नहीं रहतीं। महाराष्ट्रियनोंके एक नगरसम नियंत्रण उन्हींके हाथोंमें सौंपते समय भयका वातावरण उपस्थित करनेका अर्थ केवल यही निकलता है कि वे अविरवसनीय थे।

केन्द्रीय अर्थमंत्री पितामणि देशमुखके त्यागपत्रके साथ-साथ इन प्ररनने प्रसुखता प्राप्त कर ली। द्विभाषावाद जिसका अर्थ संपूर्ण गुजराती और मराठी क्षेत्रोंको एक

ही राज्यमें सम्मिलित करना था, अनेक महानोंके बट्टे संघर्षके उपरान्त समझौते का आधार बना ।

अहमदाबादके नेता इस निर्णयमें प्रमत्त नहीं हैं । उनके लिये द्विभाषावाद का अर्थ है मराठीभाषी बहुसंख्य शासन । ऐसा बहुमत, जो महाराष्ट्रके आर्थिक हितोंकी स्थापना करेगा । सामान्य तौर पर बेमिन्न शक्ति का हृदय समझे जानेवाले, गुजरातमें ; देश बेमिन्न-विरोधी-भावनाओं का भण्डार लाज्ज दे रहा है । महाराष्ट्रियोंके निरुद्ध गुजरातियोंकी ओर झूठ नहीं है । केवल बेमिन्न नेताओं का विरोध हो रहा है, जिन्होंने गुजराती हितोंके साथ विस्वासापन्न किया ।

द्विभाषावादके प्रश्न पर स्वयं बम्बईके गुजराती एकमत नहीं हैं । जिसकी अधिकतर पूंजी वास्तविक गुजरातमें लगी हुई है, वे इस नये रूपके विरोधी हैं । उन्हें जो केन्द्रशासनित बम्बई पसंद था, क्योंकि उस व्यवस्थामें उन्हें केवल गुजरातमें ही नहीं, बरन् बम्बईमें भी लाभ प्राप्त करनेकी आशा दिसलाई पड़ी थी । क्योंकि उस दृष्टान्तमें बम्बई सारी एक अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की वे नियंत्रित कर सकते थे । वे गुजराती व्यापारी जिनका कार्य केवल नगरमें ही सीमित है, स्वभावतया इस द्विभाषिक रूपमें प्रमत्त हैं । तथापि अहमदाबादकी व्यापार शक्तिशाली है ।

अंतिम निर्णय कुछ भी हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि अंतमें भाषावादी तर्क की ही विजय होगी और एक गुजराती प्रदेश तथा बम्बई-सहित एक मराठी प्रदेशकी रचना होकर ही रहेगी । यदि इच्छाके निरुद्ध लोगोंपर द्विभाषावाद थोपा गया तो वह केवल एक अस्थायी निराकरण ही होगा, क्योंकि उसके साथ संघर्ष समय रहनेके बीच विद्यमान रहते हैं ।

अनेक लोग निराशाके साथ अग्ने हाथ ऊँचे करके यह भविष्यवाणी कर रहे हैं कि ब्रिटिशशासनकी एकात्मक अच्छाई अर्थात् भारतीय एकता पर पुनः संकट आ गया है । अन्य लोग भारतीय अन्तर्गत होने (वे हुए) जातीय संघर्षोंकी बात करते हैं । लेकिन ईमानदारीसे इन बातों को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि आंदोलनोंकी रीति एवं उनकी लड़ाई देशभारतकी विशेषगत्तों आगमें चोख कम किया ।

चिन्ता भी इस समझौते का वास्तविक कारण साम्प्रदायिक अथवा दलगत संघर्ष-बोणमें नहीं मिल सकता । इसका कारण आर्थिक था, पर आरक्षक की बात तो यह

प्रचुरता की योजना

है कि सांस्कृतिक और भाषिक अधिकारोंकी उन्माहपूर्ण रक्तक भारतीय साम्यवादी पार्टीभी अपने प्रचारमें इस तथ्यकी उपेक्षा करती प्रतीत हुई ।

जैसा कि पहले बतलाया गया है, भाषिक पुनर्गठनके प्रश्नपर पार्टीबोके भी मतभेद नहीं रहा । इस शताब्दीके आरम्भमें ही अनेकों बार इस मँगसो दुहराया गया था ।

१९०५ में बंगभगके अभिलोपनका सनर्धन करते समय ही कांग्रेसने इस सिद्धान्तको मान लिया था । इसके ३ वर्ष पश्चात् और बिहार-बंगालके वास्तविक विभाजनसे चार वर्ष पहले, एक पृथक् बिहार प्रदेश समिति बनाई गई थी । १९१७ में दो नई समितियाँ एक आंध्रके लिये और दूसरी सिंधके लिये बनाई गई ।

१९२० में कांग्रेसके नागपुर अधिवेशनमें पार्टीने अपना एक राजनैतिक उद्देश्य भाषिक पुनर्गठन निश्चित किया । १९२८ में होनेवाले सर्वदलीय सम्मेलनने इसकी सुविधुक्तता निम्नलिखित शब्दोंमें व्यक्त की, यदि किसी प्रांतमें अपनी ही भाषाके माध्यममें दैनिक वाय और शिक्षाका प्रबंध करना है तो उसका एक भाषिक क्षेत्र होना आवश्यक है । यदि वह अनेक भाषा-भाषी क्षेत्र रहेगा तो निरंतर कठिनाईयों होती रहेंगी । निश्चयन सांस्कृतिक विशिष्टता, परंपरा और साहित्यके अनु रूपही भाषा होती है । भाषिक क्षेत्रके अंदर यह सभी तत्त्व मिलकर प्रांतकी सामान्य उन्नतिमें सहायता करेंगे । यह दृष्टिकोण उस समिति का था, जिसके अध्यक्ष स्वयं जवाहरलाल नेहरू थे ।

१९२८ और १९४७ के बीचमें कांग्रेसने भाषिक सिद्धान्तका प्रतिपादन ३ अवसरोंपर किया था, अर्थात् १९३७ में बलुसतमें जब उन्होंने आंध्र और कर्नाटक प्रांतोंके निर्माणकी सिफारिश की थी, १९३८ में वर्षोंमें आंध्र, केरल और कर्नाटकके प्रतिनिधियोंकी आधामन देकर और १९४५-४६ में जब कांग्रेसने अपने चुनाव घोषणा पत्रमें यह प्रकाशित किया कि यथा समग्र सांस्कृतिक और भाषिक, आधारपर ही प्रशासनिक इकाईयें बनानी चाहिये ।

इस स्थितिमें एक विचिंतन किया गया । १९४५-४६ में प्रयुक्त “यथा सम्भव ” शब्दकी व्याख्या १९४८ में घर आयोग द्वारा की गई, जिसमें

बतलाया गया कि हिन्दी भाषिक क्षेत्रों को प्राप्त करनेमें पहले विन्तीय आत्मनिर्भरता, प्रशासनिक सुविधा और भाषी प्रगतिशील समता सरीखी परीक्षाओंमें ठानीएँ होना चाहिये। इसके अतिरिक्त भारतीय एकता और भारतीय सुरक्षा आदि के नये नारे भी ईजाद किये गये।

उपगमनके इस परिवर्तनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता संग्रामके दमन्य अवधिपरिहारक मतभेद और साम्राज्यवादी बाँटो और राज्य-करो नीतिके आधारोंको दूर करवा आवश्यक था, तब कमिशनने भाषिक पुनर्गठनकी आवश्यकताका प्रतिपादन किया था, उसे समय प्रत्येक भाषाएँ और भारतीय प्रतिनिधित्वक प्रत्येक क्षेत्रों, भाषा, संस्कृति और साहित्यमें सम्मिलित प्रश्नोंपर बल दिया जाता था।

ऐसा कि हम देख चुके हैं, हिन्दीने भी इस मौकके मूलाधार - अर्थात् व्यवस्था - का धारण न तो बल ही की और न हिन्दीने उस ओर ध्यान ही दिया। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि अंग्रेजी शासन समय था और अभी विदेशियोंने आर्थिक परिवर्तन करनेके अग्रिमोंको हलफान नहीं किया जा सका था।

लेकिन जैसे जैसे वह सत्ता निकट जाने लगी, भाषिक क्षेत्रों के दृष्टिकोणसे अखंडता और सुरक्षाके नारे लगाने लगे। व्यापारियोंकी अपनी आर्थिक शक्ति के लिये भार दोगा। १९४५-४६ में कांग्रेसके चुनाव घोषणा पत्रमें विशेषकर इन्हीं लोनों द्वारा "यथा सम्मान" वाक्य प्रयोग किया गया था, क्योंकि वे एकाधिकार प्रणालीके स्वयं देख रहे थे। और जब यह सत्ता हलफान हो गई, तो १९४८ में निपुण 'घर आयोग' ने यह स्पष्ट कर दिया कि दक्षिणपंथी कमिश्नरोंके जाँचने काम करनेवाले अखिल भारतीय बड़े पूँजीजीवी, भाषिक पुनर्गठन के निम्न तैयार नहीं हैं, क्योंकि ऐसा होनेके परचाय शक्ति - विकेन्द्रीकरणके कारण आर्थिक प्राप्तिपर उनके एकाधिकारी नियंत्रणको भार अवस्थित हो जायगा।

जब तक इन दक्षिणपंथियोंकी प्रगति नहीं रही और विद्वत्, वाद्य आदि विदेशी पूँजीके सामने आर्थिक प्राप्ति निरपेक्ष रहा, तब तक कांग्रेसके अंदर भाषिक मागकी दृष्टि जा सका।

प्रचुरता की योजना

यद्यपि इसका त्रिहोत्र आग्रहें ऐसे समय हुआ जब कि दक्षिणापथी अपने शक्तिशाली नहीं रह गये थे और जब साम्राज्यवादी सहायता सेल पूर्ण शुष्क दित्तताई पड़ने लगे थे अर्थात् जब केन्द्रीय सरकार आर्थिक प्रगतिम प्रमुग भाग लेनेका निश्चय कर रही थी। इस अवसरपर प्रत्येक भाषिक क्षेत्रने एक बार पुन यही विचारधारा जोर पकड़ने लगी कि आर्थिक क्षेत्रने उचित व्यवहारकी तभी आशा की जा सकती है, जब देशके पुनर्गठनका आधार ऐसा हो, जिसने समान अवसर प्राप्त होनेकी सभीको गारंटी मिल जाय।

ऐसे समय जब कि एक ओर द्वितीय पंचवर्षीय योजनापर बहस जारी थी, भाषापर राज्यकी मॉगस हिमात्मक रूपने थपक उठती कोई आसरण बात नहीं थी।

योजनामें तीन प्रगतिका संदेश था, उस प्रगतिका जिसे प्रत्येक भाषावार प्रांत अपने निचे बांटता था। उसके अंदर सभी सभावनायें मौजूद थीं, क्योंकि राष्ट्रीय एकता और दृढ़ताके हितमें केन्द्रकी अधिकृतम पिछे हुए क्षेत्रकी मांगोंपर ध्यान देना जरूरी था।

प्रत्येक भाषिक क्षेत्र अधिकतम सहायता प्राप्त करनेके लिये अपनी स्थिति मुद्द करनेमें दलबलित हो गये। ऐसे समय शोध और उत्तेजनारी ही आशा की जा सकती थी क्योंकि तेलगू और तामिल, मलयाली और मराठा, बंगाली और बिहारी, उडिया और कन्नड़, पंजाबी, गुजराती, राजपूत तथा अन्य लोगोंका भविष्य दैनिक लक्ष्य हुआ था। और म्हा ठीक कि प्रत्येक भाषिक क्षेत्रके अग्रिम कर्षोरी कहानीका अनेक रूपसे निर्धार्य करनेवाली बह सीनायें हनेवाके लिये बनी रहें।

यह बात भी भविष्यकी सूचक थी कि अखिल भारतीय पूँजीजीवियोंके लगभग प्रत्येक सदस्य द्वारा इसका विरोध हो रहा था, जिसे वे “भाषावादका रोग” कहते थे। उनका सामना करनेके लिये अपने अपने भाषिक क्षेत्रमें अच्छी तरह जमे हुए मध्यम पूँजीजीवियोंके सदस्य थे, जो पुनर्गठनके आंदोलनोंकी सक्रिय रूपसे सहायता कर रहे थे।

जहाँ कहीं भाषावादका अतिक्रमण हुआ है, वहाँ साधारणतया बड़े व्यापारियोंका हाथ दिखताई पड़ता है। उदाहरणके लिये, मुख्य मंत्री विधानचंद्र रायने पश्चिम

बंगाल विधान सभाके सामने यह प्रष्ट किया कि मानभूमि जिलेके बंगाली भाषी चंडिल और पतमाद ताल्लुकोंको पश्चिमी बंगालमें सम्मिलित करनेका कारण यह है कि राचिराली ग्राम अपने कारखानेके हितकी दृष्टिमें उन्हें बिहारमें रखना चाहते हैं और बेन्गीय सरकारने टाटाकी रॉल स्वीकार करनेके लिये मेरे ऊपर जोर डाला है।

तथापि मध्यम पूँजीजीवी मायावादके सम्बंधमें एक भिन्न प्रकारसे सोचते हैं। उन्हीसाके प्रधान मनोकंक्षे पनी द्वारा इन हिंसात्मक विद्रोहोंके नेतृत्वका दृश्य इतना विचित्र नहीं था। शीघ्रस्य महाप्राणीय पूँजीजीवियोंने अपने घरेलू अंदर बैठकर अनेक समस्याओं पर परस्पर धुरी तरहसे विभाजित आप्रके राजनीतिज्ञ ठेलगतानाभे शामिल करनेके लिये एकत्र होकर प्रयास करते थे, यह भी आक्षेपका विषय नहीं था। कर्तव्यके एक उपचुनावमें हारकर विधानचद रायने अपनी ममस्त शक्तिके बावजूद भी एकीकरणका विचार त्याग दिया, यह भी वास्तविकता प्रतीक नहीं था। इतना विस्तृत होनेके बावजूद भी उत्तर प्रदेशने अपनी सीमा विस्तारकी रंगवो आगे बढ़ना उचित समझा, हम यानकी भी पालनन कहकर उपेक्षा नहीं की जा सकती।

यह तो उस प्रवृत्तिकी थोड़ी-सी ही मूलकें हैं, जो भारतीय प्रगतिको किसी व्यक्ति द्वारा वर्तमान क्षणोंमें अनुमानित रूपसे आधिक रूपमें प्रतिबोधित करेगी।

यह बड़ प्रवृत्ति है, जो अखिल भारतीय बड़े पूँजीजीवियोंके असंतोषका ध्यान न देकर, क्षेत्रीय मध्यम पूँजीजीवियोंके हाथमें उपक्रमण सौंपती है। भारतकी प्रगतिके लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है। जो कुछ संदेह बाकी है वह भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना और उत्तर होनेवाले तीस और विनापूर्ण विवादको दृष्टिनेके परचाल समाप्त हो जायगा।

पी. सी. महानोबिस द्वारा निर्मित योजनाके प्रारूपके अंदर उत्तरोत्तर क्रममें अनेक परिवर्तन हुए और मई १९५९ में जो अंतिम रूप संसदके सामने प्रस्तुत किया गया, वह मूलकानिधी अपेक्षा अधिक बृहदाकार था। तथापि वस्तुविस्तार कुछ भागमें ही हुआ था, जब कि अन्य संज्ञोंमें उसे सक्षिप्त कर दिया गया था।

जीवन-स्तर सुधारमें सहायता देनेके लिये राष्ट्रीय आयको अब २५ प्रतिशत बढ़ानेकी योजना है, जब कि प्रथम योजनामें लक्ष्य ११ प्रतिशत थी।

प्रचुरता की योजना

“ तीव्र औद्योगिकरण ” का लक्ष्य घोषित किया गया है तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योग एवं उन्नयन की उन्नतिके लिये रु ८६० करोड़ आंके गये हैं । इस बात का विश्वास दिलाया गया है कि अगले पाँच वर्षोंमें लगभग ८० लाख नयी नौकरियों खोजी जायेंगी । और आमदनी तथा धन की असमानता घटाने की राह भी मँजूर है ताकि आर्थिक राजस्व अधिक समान वितरण सम्भव हो सके ।

दूसरे शब्दोंमें, प्रथम योजनाके विपरीत द्वितीय योजनामें उसके उद्देश्यों की अधिक स्पष्ट और निश्चित घोषणा की गई है । इसके अनिश्चित शारीरिक लक्ष्य भी प्रथम योजनाकी तुलनामें पर्याप्त कँचे हैं । वस्तुतः सार्वजनिक क्षेत्रमें आवंटित धन दुगुनेसे भी अधिक है जैसा कि निम्नांकित तुलनासे स्पष्ट है —

| | प्रथम योजना | | द्वितीय योजना | |
|-------------------------------------|---------------------|------|---------------|------|
| | (करोड़ रुपयोंमें) | | | |
| | | % | | % |
| १. कृषि और सामुदायिक विकास परियोजना | ३५७ | १५.१ | ५६८ | ११.८ |
| २. बिजली और विजली | ६६१ | २८.१ | ६१३ | १६.० |
| ३. उद्योग और उत्खनन | १७६ | ७.६ | ८६० | १८.५ |
| ४. परिवहन और संचार | ५५७ | २३.६ | १३८५ | २८.६ |
| ५. समाज-सेवा | ५३३ | २२.६ | ६४५ | १६.७ |
| ६. विभिन्न | ६६ | ३.० | ६६ | २.१ |

२३५.१ १००.० ४८०० १००.०

इसके अनिश्चित पिछले पाँच वर्षोंकी विनियोजन प्रवृत्तियों मोटे तौरसे देखते हुए तथा कुछ क्षेत्रोंके ज्ञान विनियोजन कार्यक्रमोंकी ध्यानमें रखते हुए, द्वितीय योजना कालके अंदर सार्वजनिक क्षेत्रमें लगाये जानेवाली लागतका सम्भावित स्तर रु २४०० करोड़ कहा जा सकता है, जिसका विभाजन इस प्रकार है —

६० (करोड़ों में)

| | |
|--|-------|
| (१) संगठित उद्योग और उत्पन्न | १७५ |
| (२) वाणान, बिजली व्यवसाय और रेलवेके अलावा अन्य परिवहन | १२५ |
| (३) निर्माण | १००० |
| (४) कृषि और मान तथा लघु उद्योग | ३०० |
| (५) सड़क | ४०० |
| | <hr/> |
| योग | २४०० |

इनमेंसे कुछ आकड़ोंसे समझने पर मालूम पड़ता है कि उत्पादनमें निम्नलिखित वृद्धि होगी — इस्पातमें १,२५०,००० टनसे स्थान पर ४,३००,०००, टलाई घंटोंके होनेवाले बच्चे लोहेमें ३८०,००० टनसे ७५०,००० टन, भवन निर्माण सामानोंमें १८०,००० टनसे ५००,००० टन, भारी इस्पात टलाईमें न कुछसे १५,००० टन, भारी कुहरणा (फोर्जिंग) में न कुछसे १२,००० टन, बच्चे लोहेके टलाई घंटोंमें न कुछसे १०,००० टन, रेल इंजनोंमें १७५ से ४००, ट्रेक्टरोंमें न कुछसे २००० सवारिकारोंमें १२,००० से २०,००० और मोटर जेतोंमें १२,००० से ४०,०००, जीप गाड़ियोंमें न कुछसे ५,०००, जहाज निर्माणमें ६००,००० टन (१९५१-५६) से ६००,००० टन (१९५६-६१) ।

१९६०-६१ तक औद्योगिक क्षेत्रोंमें प्राप्त होनेवाली प्रतिशत वृद्धि भी साधारण तौरपर यथेष्ट प्रभावशाली है । अधिकतर क्षेत्रोंमें शतप्रतिशतसे अधिक और कुछमें दो सौ से तीन सौ प्रतिशत तक वृद्धिकी योजना बनाई गई है । योजनाधनमें देशके अंदर बनाये जानेवाले औद्योगिक यंत्रोंके मूल्यमें भी ५-६ गुनी वृद्धि होनेकी आशा की जाती है ।

इसके अतिरिक्त भूमि सुधारके प्रभाव भी हैं, जैसे भूमि धारणकी अधिकतम सीमा निर्धारित करना, लगानमें कमी, सामंतवारी भूमि सम्बंधोंको निरमित करनेमें सहायता करनेका विचार और कृषि पुनरुत्पन्नमें नई सम्पादनाधिकाय गयी

प्रचुरता की योजना

सोलना यदि उत्साहपूर्ण इतर कार्यवाही की गई तो यह सीमित सुधार भी आमोख स्मृतावली कथ राखि यज सवने है, एक ऐसा सभ्य जो आगे चलतर नज केजोरी उर्जातमें भी सहायता दे सकता है। क्योंकि भारतमें आमोवे ही अग्रणी मृदूव उपज का आता माल प्राप्त होता है। विकासशील उद्योगोंकी सहायतामें भूमि र्थर उम्की उपजमें भारी परिवर्तन हो जायगा।

यह विलक्षण योजनावे (विलक्षण इमलिये कि पूँजीजीवियोंकी राजनैतिक सत्त्वाने इसे प्रस्तावित किया है) अनेक परस्पर विरोधी व्याख्याओंका केन्द्र रही है और रहेंगे। मुख्य रूपमें मत वैपरीत्य निम्नलिखित समस्याओं पर है, जैसे सार्वजनिक और निजी उद्योगोंका सपेक्ष हिस्सा काने और महत्व, योजनाके लिये धन प्राप्तिके स्रोतों, घाटेके वित्तप्रबंधनकी सुरक्षित सीमा, बेकारी, भूमि-सुधार, भारी उद्योगोंके प्रसारकी दर गतागतके लिये अनुमानित और उत्पादित धनका वितरण।

पी. जी. महालनोभिसे अग्रणी मूल योजनाके प्रारूपमें सार्वजनिक विकासकार्योंके लिये कुल रु ४,३०० करोड़ प्रस्तावित किये थे। औद्योगिक प्रसार कुल राशिका २६ प्रतिशत अर्थात् १,१०० करोड़ सोख लेना, जिसमें ज्योतके अरु १,००० करोड़की दाम्भिक या स्थिर पूँजी होनी। सरकारी सहायताके पलात्करण औद्योगिक विमिशोजनके निजी क्षेत्रमें रु ४०० करोड़ तक पहुँचनेकी आशा थी।

सर्वसाधारणके लिये योजना प्रारूपको प्रभावित करनेसे पहले ही बचियेमें विद्यमान प्रतिक्रियाकारी तन्त्रों द्वारा इसकी आलोचना आरम्भ हो गई। औद्योगिक प्रसार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रमें नियामक स्थिति प्रदान करनेके योजकके प्रयत्नमें उन्हें भारतीय एकाधिपति शिल्पोंके लिये एक सपना दीया।

सार्वजनिक क्षेत्रमें गठ करना तो लागत सहीहूत कर लिया गया था। साथ ही क्षेत्रीय मन्थन पूँजीजीवियोंमें इस विचारधाराका कोई विशेष विरोध नहीं किया। इस कारण अनेक पूँजीजीवियोंमें इसी विषय पर आना ध्यान केन्द्रित किया, जिसपर उन्हें मध्यमवर्गीय समर्थन प्राप्त होनेकी आशा थी।

अपन ही घाटेके वित्तप्रबंधनके सारोंमें रेखांकित किया गया। यह तर्क उपस्थित किया गया कि आर्थिक आकाङ्क्षापूर्ण परियोजनाओंका परिणाम निराश्रित

घन होना और फलस्वरूप मुद्रास्फीति और तानाशाही नियंत्रण-व्यवस्था स्थापित होगी। मध्यम पूँजीजीवियोंके जब अपने लाभपर प्रतिक्रियाओं सम्भालना दिखता है परी, तो उन्होंने भयमूल होकर अन्वीक्षात्मक योजनाके आरूपको आगे बढ़ानेमें समर्थन देना बंद कर दिया। योजनाको संकुचित करनेकी माँग उभर आने लगी।

इसके बाद दूसरा दाय लगाया गया। यह दोष दिया गया कि सार्वजनिक क्षेत्रके प्रस्तावित प्रसार द्वारा निजी क्षेत्रको गर्दनिया देकर निकला जा रहा है और इस कारण वैयक्तिक उद्यमियोंको विचारके लिये पर्याप्त स्थान प्राप्त न हो सकेगा। सार्वजनिक क्षेत्रकी ऐसी निन्दा नीतिनिष्ठापूर्ण नहीं बड़ी जा सकती, क्योंकि इस बातकी सम्भावनाओंपर सर्वसाधारणका ध्यान आकृष्ट हो चुका था और उसने मध्यम पूँजीजीवियोंको भी प्रलोभित कर लिया था। एक तीरसे दो शिखर मारनेके विचारसे यातायात और विशेषरूपसे रेलवेके आवंटनको आलोचनाका एजन्डा विषय बना लिया गया था। वैयक्तिक उद्यमोंका लाभ और व्यापार-विस्तारका अवसर देनेके लिये यातायातकी दमन आवश्यक थी। यदि रेलवेकी संपूर्ण आवश्यकताएँ पूरी कर दी जायें तो सार्वजनिक क्षेत्रके अन्य उद्योगोंके लिये बहुत कम राशि बचती और फलस्वरूप योजनाको संकुचित करना पड़ता।

मध्यम पूँजीजीवी, जो अपनेको राज्य नियंत्रित वित्तीय विभागोंद्वारा व्यक्तिगत उद्यमोंके लिये अधिक धन आवंटित करवानेकी योजना पहलेसे ही बन रहे थे, स्वाभाविक रूपसे अपना भाग बचानेके इच्छुक थे। अब तो नवगठित भाषिक दमियोंकी सरकारों और विचारकों द्वारा अधिक दबाव डलवाये जा सन्नेकी सम्भावना थी। इन प्रकार व्यक्तिगत क्षेत्रको औद्योगिक विभागके लिये अनुमानिक रूपसे अधिक बड़ा भाग देने जानेकी माँग, जोर पकड़ने लगी।

व्यापारिक सत्ताकी आयके महत्वपूर्ण सारन, बीमा कंपनियों और व्यक्तिगत संचालित बैंकोंके आकस्मिक और अप्रसंगिक राष्ट्रीयकरणसे टाटा-विहला स्त्रीके एकधिकारियोंके हाथमें मध्यमवर्गको डालनेके लिये एक अन्य रास्ते रीष दिया यद्यपि बीमा व्यवसायके राष्ट्रीयकरणका प्रभाव एकधिकारी तत्वोंपर ही पड़ा था और भाषिकने इसके द्वारा मध्यम पूँजीजीवियोंको अधिक सरकारी धन प्रस्तुत किये

प्रचुरता की योजना

जा सनेने की आशा थी, तथापि यह धारणा सकलतापूर्वक उत्पन्न की जा रही कि जब तक द्वितीय पंचवर्षीय योजनामें पर्याप्त परिवर्तन नहीं होता, तब तक बंद समस्त पूँजीजीवी वर्गके हितोंके लिये भयानक एक कारण रहेगी।

• योजनाके प्रारूपमें प्रथम महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। इस बातकी घोषणा करनेके साथ-साथ कि लक्ष्योंको पूर्व निर्धारित करके योजनाके वित्तीय स्रोतोंकी खोज करनेमें भूल की है, प्रतिक्रियावादियोंमें इस भौतिक योजनाकी “ साम्यवाद से प्रभावित ” कहकर आलोचना की और इस बातपर बल दिया कि औद्योगिक लक्ष्योंकी कम किया जाय। परिवर्तन आरम्भी हुए। यातायातके आवंटनमें रु १०० करोड़में अधिक वृद्धि की गई अर्थात् इस राशिमें रु १५० करोड़में बढ़ाकर रु १३८५ करोड़ कर दिया गया। इस प्रक्रियामें सार्वजनिक विनियोजनका कुल योग रु ४३०० करोड़में बढ़कर रु. ४,८०० करोड़ तक पहुँच गया। भारी उद्योगोंकी यथेष्ट कटौती सहनी पड़ी और रु २०० करोड़ लागतवाले मशीन निर्माण-उद्योग कार्यक्रमको हटा ही दिया गया। अन्य परिवर्तन छोटे मोटे थे।

व्यवहारिक शब्दोंमें इसका परिणाम तोत्र भारी औद्योगीकरणको रोकना, भविष्यमें नई नौकरियोंकी सम्भावना घटाना तथा बड़े पूँजीजीवियोंके जीवन-कालमें घटाना था।

विरोध गम्भीरतासे धान बेकारीकी समस्या पर पूरा ध्यान न देना था, जिसकी और प्रारूपके रचयिताओंने अपने आलोचकोंका ध्यान आकर्षित किया था। देशकी अर्थव्यवस्थाके तत्सम्बंधित आन्दोलनोंके पैर सरकारी विभाजनमें यह चेतावनी सन्निहित है -

| वर्ष | कामगार | अश्रित बेकार |
|------|--------|--------------|
| १९०१ | ५०१ | ४६६ |
| १९११ | ४६६ | ५०४ |
| १९२१ | ४८६ | ५१४ |
| १९३१ | ४७० | ५३० |
| १९४१ | ३६६ | ६०१ |

वस्तुतः पूर्ण लाभकारी कार्योंमें लगे दोनों कामगारोंकी समस्या का अनुमान कृषि विपक्षक और कृषिके अलावा अन्य क्षेत्रोंमें मिलकर मिल रहा था।

समस्याका केवल ऊपरी स्पर्श

| वर्ष | कृषिविपणन क्षेत्र | कृषिके आलावा अन्य क्षेत्र |
|------|-------------------|---------------------------|
| १९०१ | ११.० | १०.६ |
| १९११ | ३४.५ | १५.१ |
| १९२१ | ३३.२ | १५.४ |
| १९३१ | २६.२ | १७.८ |
| १९५१ | २८.६ | ११.३ |

यह भी स्वीकार किया जा चुका है कि सामान्य तौर पर प्रत्येक १००० ग्रामनिर्भर व्यक्ति ऐसे २,५०० अन्य व्यक्तियोंका पालन करते हैं, जो लाभकारी कार्योंमें नहीं लगे हुए हैं। बरनी हुई जनसङ्ख्याकी दृष्टिसे लगभग १०,०००,००० अतिरिक्त स्थान निकालनेका मूल लक्ष्य भी समस्याका केवल ऊपरी स्पर्श ही था। योजनाके परिवर्तनोंसे बेकारी - निवारणके लक्ष्यसे अधिक दूर कर दिया है।

नौकरोंके लक्ष्योंसे कमी की तरफ दुहरा दिया गया है अर्थात् ११०-१२० लाखों स्थानोंमें घटाकर ८० लाख कर दिया गया है। निम्न विवरण निम्न प्रकार है—

(संख्या लाखोंमें)

| | |
|--|------------------|
| १ निर्माण | २१.०० |
| २ मिनीर्ड टींग मिजली | ०.४१ |
| ३ रेल | २.४३ |
| ४ अन्य सार्वजनिक एवं सार्वजनिक | १.०० |
| ५ उद्योग और मजदूरी पदार्थ | ७.५० |
| ६ कुल मिलाकर लघु उद्योग | ४.५० |
| ७ वन, मछली, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और अन्य सम्बंधित परियोजनाएँ | ४.१३ |
| ८ शिक्षा | ३.१० |
| ९ स्वास्थ्य | १.१६ |
| १० अन्य मानव-सेवाएँ | १.४२ |
| ११ सरकारी सेवाएँ १ से ११ तक | ४.३४ |
| | ५१.६६ |
| १२ जोसें व्यापार और वाणिज्यको शामिल करते हुए अन्य बाँचे दर - योजना ५२ प्रयोजित | २७.०४ |
| कुलयोग | ७६.०३ या ६ लाख ० |

प्रचुरता की योजना

सम्भवतया हमने अधिक अवसर वे प्रस्तुत भा नहान कर सकत य, क्योंकि औद्योगिक उन्नतिही प्राथमिक स्थितिमें अधिक नौकरियोंकी गुमाइश नहीं रहनी । इसमें तो समस्याके दीर्घकालीन निराकरणमें सहायता मिलनी है । वैज्ञानिक योजना निर्माणकी सदैव यही समस्या रही है । इन समयका एक गलत प्रयत्न आगे चलकर परिस्थितिमें उलफा सक्ता है तथा बेकारीकी समस्याको सुधारनेके स्थानपर बिगाड़ सक्ता है ।

उत्पादक कार्य प्राप्त करनेके लिये ध्रमको जिन वस्तुकी आवश्यकता है, वह है कामके औजार और उपस्कर । अधिकस्तित देशमें इन्ही वस्तुओंकी कमी होनी है । यही कारण है कि बेकारी-समस्याके दूरवर्ती निराकरण हेतु पूँजी प्रतिष्ठानोंका इतना भारी महत्व है ।

पूर्वकालमें विकसित देश पिछड़े देशोंमें पूँजी उधार देकर उन्नतिमें सहायता करनेके लिये तैयार रहते थे, लेकिन तभी जब कि इसमें उनका हित-साधन होता हो । इस तरह, जिन खनिजोंकी जहरत स्वयं औद्योगिक देशोंकी पड़ती थी, उनके उत्खननके लिये तथा ऐसे ही और कच्चे सामानके विमाम, उसको ढानेवाले यालायात और कच्चे सामानमें बने उत्पादनको राखानेके लिये नये बाजार खोलनेकी पूँजी और उपस्कर उधार दिये गये । यह सर्व विदित है कि अधिकस्तित देश ऐसी पूँजी जिन शर्तोंपर और जिन सामाजिक मूल्यपर प्राप्त कर सके ।

यदि प्रगतिका लक्ष्य प्राथमिक रूपसे जनताका ही लाभ हो तो पूर्णरूपेण भिन्न प्रकारकी योजना बनानी चाहिये । उसे भारी उद्योग और मशीन निर्माणमें कृषि और उद्योग दोनों ही क्षेत्रोंमें मशीन और अच्छी टेक्निककी सहायतामें विभिन्न क्षेत्रोंकी उत्पादकतामें क्रमिक वृद्धिभी और अपसर होना चाहिये । भविष्यमें ऐसी प्रगतिके लिये योजना प्राप्तमें गहरी नींव रखी गई है, जिसमें सुकेत है कि वास्तविक पूँजी रचना और स्थायी उत्पादक संपत्ति बनानेके लिये रु १,४०० करोड़की उद्ब्यय किया जायगा, जिनमें निरंतर उन्नतिका आधार प्राप्त हो सके ।

लेकिन सरकार पर सभी प्रकारके दबावका प्रभाव पडा और इस प्रक्रियामें कुल लागत रु ४,६०० करोड़में ऊपर निम्न गई है तथा उसके और भी अधिक घटनेमें पूरी आशा है । भारतवासियोंकी सामर्थ्यमें देखते हुए यह बहुत कम है, लेकिन सरकारके वर्तमान प्रायः साधनोंमें देखते हुए बहुत अधिक है, क्योंकि सार्वजनिक और राजनैतिक वचन-बदला और उत्तमतामें वह सीमित हो जाती है ।

यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि यद्यपि आयोजित उद्घृत्यमें बार-बार कृति की गई थी, तथापि उसका लक्ष्य योजनाके मूल उद्देश्यको आगे बढ़ाना नहीं था । अब जिन भारी व्ययका प्रस्ताव किया गया है, उसमें पूँजी निर्माणको व्यवस्था मूल योजनाकी प्रभावित राशिमें भी कम है, जो आर्थिक प्राप्तिको निश्चित करेगी ।

लेकिन समस्त चेतावनीकी ओरमें ओम्ब्रे बढ़ दिये हुए विजयी प्रतिक्रियामें इस प्रश्न पर सन्देह जागी रहा कि रु ४१,०० करोड़में बढाकर रु ४६,०० करोड़ किया जानेवाला उद्घृत्य किन प्रकार निराल किया जाय । स्वभावतया इसका मुख्य उद्देश्य राज्य संचालित औद्योगिक प्रमाणको अवरोधित करके निष्क्रिय करना तथा अर्थ-व्यवस्थाके औद्योगिक आधारको अतर्धस्त करनेके लिये विनियोजनका ऐसा ढंग योजना था, जो पैसेवालोंकी आवश्यकताओंको पूरा करनेके लिये सभी तरहके उपभोक्ता सामानको अधिक प्रस्तुत करनेका विश्वास दिलाने जानेके कारण अधिक आकर्षक मालूम पड़े, लेकिन जो वास्तविक उन्नति और अधिक उत्पादक नीकरीके अवसर घटाना हो ।

योजनाके अंतमें जितनी नीकरियोंका विश्वास दिखाया गया है, उसमें यथापूर्व स्थित कायम रखने और बेकारीकी समस्याको अधिक न बिगड़ने देनेके अतिरिक्त और कुछ नहीं है । जिन नये स्थानोंको बनाना है, उनके विवेचनमें यह पता चलता है कि अर्थ-व्यवस्थाके वर्तमान ढाँचे पर कोई खाम प्रभाव नहीं पड़ेगा और अन्य उत्पादक या अनुपादक व्यवसायोंमें लगे हुए लोगोंके अनुपातमें कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा ।

ध्यान देने योग्य बात है कि अविज्ञान काय दिलानेकी एकमात्र मदकी सख्या १२—“ व्यापार और वाणिज्यको शामिल करते हुए अन्य कार्य हैं । ” विद्वानों जन-

प्रचुरता की योजना

गणनाके समय विभिन्न व्यवसायोंमें लगे हुए आदमियोंका भी विवरण लगभग इसी अनुपातमें था। वस्तुतः इस अनुपातको जनगणनामें ही लिया गया है और नौकरीके अवसरोंका अनुमान भी इसी आधार पर लगाया गया है कि यह अनुपात अपरिवर्तित बना रहेगा।

प्रगतिके लिये यह आवश्यक है कि लोगोंको उत्पादक कार्योंमें अधिकारिक सहाय्यमें लगाया जाय और अनुपादक कार्यों तथा व्यापार और वाणिज्यके क्षेत्रमें भोज भोज करनेवाले लोगोंका अनुपात निरंतर घटाया जाय। जब कि योजनाके प्रारूपमें व्यापार और वाणिज्य प्रत्येक स्थानके विपरीत औद्योगिक क्षेत्रमें दो स्थान रखे गये थे, वहाँ योजनाके अंतिमरूपमें यह अनुपात उलट दिया गया और अब व्यापार और वाणिज्यके दो स्थानोंके मुकाबलेमें औद्योगिक क्षेत्रमें स्थान रक्खा गया है।

इस योजनामें नौकरीके स्थानोंका लक्ष्य न्यून और अपर्याप्त होनेके साथ साथ काफी बढाकर दिखलाया गया है। नये बनाये जानेवाले स्थानोंमें अनेकोंके रूप परिवर्तित स्थान होनेका संदेह है।

उत्तमनमें पड़े तथा नये भाषाधी राज्योंमें भारी शक्ति प्राप्त होनेकी उत्पत्ति करनेवाले मध्यम पूँजीजीवी हैरान थे कि किस ओर कदम बढ़ाया जाय। यदि वे सरकार चालित भागी औद्योगिक कार्यक्रमसे रद्द करनेसे मँगका समर्थन करते हैं तो उन्हें अपने क्षेत्रमें चलाये जानेवाले सरकारी उद्योगोंमें प्राप्त होनेवाले लाभोंमें वंचित होना पड़ेगा। वस्तुतः उन्हें अपने आपकी बड़े-बड़े निजी संचालकोंकी धुनके भरोंमें मौपना पड़ जायगा।

योजनाके विषयमें होनेवाली आलोचनाका प्रतिफल करने, और उमके ज्हागरो रोकनेके लिये नेहरूने एक नयी औद्योगिक नीतिकी घोषणा की। यह समय अर्थात् अप्रैल १९५६ बड़ा मीनेका था, क्योंकि इस समय मतभेद पूरे जोगों पर थे।

इस प्रस्ताव द्वारा १९४८ की पूर्व घोषणामें सुधार किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र सूचीमें कुछ नये उद्योगोंकी जोडा गया। तथापि यह कहा गया कि व्यक्तिगत क्षेत्रको

शक्तिपूर्ण होने दिया जायगा और विशेष परिस्थितियोंमें उन्हें उन क्षेत्रोंमें भी कार्य करनेकी अनुमति दे दी जायगी, जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्रके लिये अनुरक्षित कर दिया गया है।

इस प्रस्तावका छोटे-बड़े सभी व्यापारिक क्षेत्रोंमें हार्दिक स्वागत हुआ। यह स्वागत केवल इन मुक्तिमें होनेवाली प्रगतिताका सूचक था कि अन्ततः सरकार अपने संचालन क्षेत्रमें सीमित करनेके लिये विवश कर दी गई। क्योंकि उस समय अभिस्तर लोगोंकी यही धारणा थी कि भारी परिवर्तनोंकी योजना बन रही है। इस प्रस्तावका अर्थ यह आशयमान माना गया कि राज्य-संचालित सार्वजनिक क्षेत्र, व्यक्तिगत उद्यमियोंके कार्योंपर कोई रोक नहीं लगायेगा। क्षेत्रीय मध्यम पूँजी जीविशेषेण बोधा कि उन्होंने सरकारको बहुत आगे न बढ़नेकी चेतावनी देकर बहुत दौड़ किया है।

लेकिन एकाधिकारी तत्त्वोंने अपना आक्रमण जारी रक्खा। उन्होंने रेलवे और यातायातके लिये अधिक आर्गुमेंटकी इस आधारपर मोंग की, कि तीव्र विनामशूल अर्थव्यवस्थाकी आवश्यकताओंकी पूर्ति हेतु वर्तमान सुविधायें अपर्याप्त हैं। इसके लिये रु ४०० करोड़ अतिरिक्त दिये गये थे। फिर भी वे सन्तुष्ट नहीं थे। योजना आयोगमें त्यागपत्र देनेकी भी धमकी दी गई थी। यातायातके लिये इतनी भारी बिनाका रागण कुछ तो स्वार्थ पूर्ण था, क्योंकि निजी क्षेत्रमें यातायातकी प्रगतिके पथान नये बाजारोंमें लाभकी सम्भावनायें दीर्घी तथा बुद्धि बढ़ भी वर्य्य था कि वह एक ऐसा परदा था, जिसकी आदमं उन्हें देशकी राज्य संचालित तीव्र औद्योगिक प्रगतिके अन्तर्गत करनेकी आशा थी। यह अभियान जारी है लेकिन अब यह धाना पड़ गया है। वास्तविकता अब पूर्ण स्पष्ट दीजती है।

यदि रेलोंके पास द्वितीय योजनाकी आवश्यकताओंको पूरा करनेके लिये धन नहीं है तो वह रियायतें और लुट्टीके दरम्यान रियायती बापकी टिकट जारी करके इन भारी लुट्टान महाना क्यों स्वीकार करती हैं। वे वातानुकूलित डिब्बोंकी सुख्या बढ़ाने तथा पूर्ण वातानुकूलित गजने जारी करनेके प्रश्न पर इतना ध्यान देनेका क्या

प्रचुरता की योजना

कारण बनता सफ़ते है, जिसे युरोपीय पर्यटकोंने विलाम-यात्राया श्रेष्ठतम माधन बनताया है । क्या रेलद्वारा तीथारी यात्राया प्रमथ योजनाके अनर्गत यातायातका परमार्थि नार्थ नियत किया गया है । क्या दिनों-दिन बढती अनुशासना बर्तमान सुविधाओंके पूर्ण प्रयोगनो अवरोधित नही करती । दुर्गती लाइन निजानेरी क्या आवश्यकता है, जब कि आमानोमे लगाई लूप भी वही कार्य कर सकती है । यदि चीन अपने देशमे स्थित सीमित रेल मार्गोंपर अधाधुन व्यवस्थित नित ही अपनी अर्थ-व्यवस्था और व्यापारको उत्तति कर सक्ता है, तो भारतसे क्या बाधा है ।

यह प्रश्न और इसी प्रकारके अन्य प्रश्नोंका आमानोमे उत्तर न्नी दिया जा सकता । माध ही परिवहन और संचारके लिये पूर्ण स्वीकृत व्यय अर्थात् ₹ १३८५ करोड़ या यों कहिये कि कुल उद्ध्यय का लगभग २६ प्रतिशत, किमी एक कागके लिये अधिकतम आवंटित गरि है, और फलस्वरूप योजनाके अन्य भागोंसे कुर्ग तरह सटना पक्क है । अत्रेजेने १०० वर्षोंमे भी रेलोंपर इतना अधिक व्यय नही किया जा ।

एक अन्य आराक्षित आयुध, अन्य मोर्चोंके लिये अधिक, आवंटनका माग है तथा १९५६ में मूलखाद्यान्नोकी मूल्यवृद्धि इस मोर्गके प्रमाण स्वरूप प्रस्तुत की गई ।

सभी इष्ट प्रशस्ती कूटनीतिओंका उपयोग हो रहा है । यहीं तक कि तमसहित “स्वतंत्र व्यवसाय मंच” की ओर से समाचारपत्रोंमे साधनवीन पृत्तीगतियोंकी दुरावस्था दिगत्तानेके लिये पितापनोंके द्वारा बर्दभरी पुकार उठाई जात है । इस ‘मंच’ के प्रमुख पृष्ठपोषक भारतीय एकाधिपति और विदेशी व्यापारिक संस्थान है । जाने सामें ये अधिकतर मध्यम बगरी भी ले लेते हैं, क्योंकि अपनी सधर्तनमें ये लोग सोचते है कि जिन क्षेत्रमे प्रवेश करनेकी ओर उनकी आंख लगी हुई है, उनमें सरकारी दखलती रोकनेके लिये कुछ न कुछ अवरोध आवश्यक है । ‘गठबंधन’ कितने दिन रहते है, यह इसी बात पर आधारित है कि बड़े पूंजी-जीवियों और विदेशी व्यापारियोंकी इनकार गुणारियोंका वास्तविक उद्देश्य, योजनाके प्रतिपादक मिनती जन्दी रोलते है, क्योंकि सीमेटका राज्य द्वारा व्यापार करते

योजना के उद्ध्यय की विचीय पूर्त

और राज्य संचालित इसान वितरण कायको हाथमें लेनेमें छोटे-मोटे औद्योगिकोंमें अनेक लाभ प्राप्त हो सकने हैं ।

इस आक्रमणकी गभीरता इसी बातमें स्पष्ट हो जाती है कि आरम्भमें क्या विचार थे और अब उनका विनता अंश क्या है । भारतीय और विदेशी अर्थशास्त्रियोंका एकमतसे समर्थन प्राप्त महालनोबिस द्वारा निर्धारित योजना-नीतिमें सभी भारी उद्योगों तथा अन्य महत्वपूर्ण उद्योगोंकी सार्वजनिक क्षेत्रके लिये आरक्षित कर दिया गया था । योजनाके प्रारम्भमें उद्योग हेतु आवंटित रु १,४०० करोड़मेंसे रु १,००० करोड़ सार्वजनिक क्षेत्रके लिये और रु ४०० करोड़ निजी क्षेत्रके लिये नियत किये गये थे । इन रु ४०० करोड़मेंसे भी आधी राशि लघु एवं कुटीर उद्योगोंके लिये थी । लेकिन अब उत्खनन एवं उद्योग हेतु सार्वजनिक क्षेत्रीय विनयोजनाको घटाकर रु ८६० करोड़ करनेका निश्चय हुआ है, जब कि निजी क्षेत्रमें एतदर्थ आवंटन बढ़ाकर रु ७०० करोड़ कर दिया गया है ।

दुसरी बात है कि देशके वैज्ञानिक योजना समर्थक महालनोबिस द्वारा रचित मूल योजनाके प्राहणके पक्षमें जनमतका निर्माण न कर सके । यदि वे ऐसा करते तो इस बातकी पूरी आशा थी कि एकधिकारी हितोंके नेतृत्वमें किये जानेवाले आक्रमणके नामसे सरकारको घुटने न टेकने पड़ते । साम्यवादी पार्टी भी सम्भावित आन्दोलनोंको रोकनेके लिये सामंशिक जनमत संग्रहकी आवश्यकताओं न देख सरी ।

अन्तर्गतत्वा, यह आन्दोलनपूर्ण भी प्रथम योजनाकी अपेक्षा प्रगतिशील थी । और इसका एक मात्र कारण यह है कि योजनाका स्वल्प अविक्र मुस्पष्ट है तथा राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्थाके मूल केन्द्रोंपर कम्परा या शोघ्रनसे नियंत्रण प्राप्त करनेकी आवश्यकताकी अधिकतर स्वीकार कर लिया गया है ।

इस बृहत् योजनाके उद्ध्ययकी विनीय पूर्ति कैसे होगी ? वर्तमान संभवनाओंकी गतिमत रचने हुए, आइये, उन पर विचार कर लें ।

प्रचुरता की योजना

| | रु (करोड़में) |
|---|---------------|
| १ चालू राजस्वमें वृद्धि | ८०० |
| (क) (१९५५-५६) में विद्यमान करों दरमें | ३५० |
| (ख) अनिश्चित कर | ४५० |
| २ जनतामें श्रृंखला | १२०० |
| (क) वाजार कृष्ण | ७०० |
| (ख) अन्य वस्तुएं | ५०० |
| ३ अन्य आय-व्ययके साधन | ४०० |
| (क) विमान कार्यक्रममें रेलोंका अनुमान | १५० |
| (ख) निर्वाह निधि तथा अन्य कोष | २५० |
| ४ विदेशी साधन | ८०० |
| ५ घाटेका वित्तप्रबंधन | १२०० |
| ६ रिक्तता जिसकी पूर्ति स्वदेशी साधनोंसे अनिश्चित उपायों द्वारा करनी है। | ४०० |
| | योग ४८०० |

द्वितीय योजनाके लक्ष्य प्राप्त करनेके लिये रु १,२०० करोड़ तक घाटेके वित्त-प्रबंधन और रु ८०० की विदेशी सहायताका विश्राम किया गया है। इसे रु २,००० करोड़ तक 'रिक्तताकी पूर्ति' कह सकते हैं। इसके साथ रु ४०० करोड़की बतलाई गई 'रिक्तता' को जोड़नेसे कुल योग रु २,४०० करोड़की हो जाता है। अर्थ-शास्त्रियोंका विश्रवास है कि योजनाके लागू होनेके परचा इस राशिमें संशेष्ट वृद्धि हो जायगी। इसे हूँदना ही पड़ेगा, अन्यथा देशको गम्भीर आर्थिक संकटका सामना करना पड़ेगा।

तथापि यह धारणा बनानेका कोई कारण नहीं दीखता कि यह राशि अथवा इमने अधिक राशि अग्रगण्य होगी। घाटेके वित्तप्रबंधनकी नीति निश्चित करने अनावश्यक अनाज्ञा-पूर्ण नहीं है, बरने कि सरकार आवश्यक उपाय करनेसे तैयार हो। जहाँ तक विदेशी सहायताका प्रश्न है, शानि और सम्भावनासे परिपूर्ण नवीन अन्तर्ग्रीय

वायुमंडल निश्चित रूपसे आर्थिक सहायता प्राप्तिको सुनिश्चित बनाता है, विशेष तौर पर उम्र समय जब कि भविष्य सपने यह स्पष्ट घोषणा कर दी है कि भारतीय भागोंको पूरा किना आसना ।

‘रिक्तता को पूर्ति’ चिन्ता कोई कारण नहीं है, बल्कि चिन्ता इस बातकी ही है कि मूल्यों पर नियंत्रण रखनेके लिये क्या आवश्यक उपाय लिये जायें । घाटोंके वित्प्रबंधनका दुःप्रभाव विदेशी महानता तब तक दूर नहीं कर सकती, जब तक कि योजनाके मूल उद्देश्यकी बलिदान न कर दिया जाय । इस बातसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिये ।

आजकल मातृ तोष हलसे ही कम है । साथ ही औद्योगिक विस्तार हेतु किया जानेवाला भागी परिव्यय प्रणालिको प्रारम्भिक अवस्थामें उपभोक्ता वस्तुओंकी उत्पत्तिमें कोई विशेष रुद्धि नहीं कर सकता । मुद्रास्फीतता भय सतत विद्यमान है । योजना-प्रमुख इस बातकी सम्झनेका कोई प्रयत्न करते नहीं दिखलाई पड़ते कि अन्त-आयातमें विदेशी विनिमयके अव्यय द्वारा अथवा योजना कार्यक्रमके अन्य भागोंमें उलट फेर करके भित्त-उद्योगके लक्ष्य प्रसार द्वारा अन्न और वस्त्रके मूल्यों और निर्याद मूल्यपर, रोक नहीं लगाई जा सकती । जन साधारणके जीवनकी न्यूनतम आवश्यकताओंकी पूर्तिको सुनिश्चित करनेके लिये वे कन्ट्रोल लागूने और विवरण पर नियंत्रण करनेकी आवश्यकताको अनिश्चित बाल तक स्थगित नहीं करते रह सकते ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजनाके सम्बन्धमें अकराण्यो लक्ष्य करते हैं कि जब किमों भारतीय परिवारमें बचन होनी है तो परिणाम स्वरूप सबसे पहले बच्चेका कष्ट ब्रह्मा है और उसके पश्चात् वीमारियोंको दूर करनेके लिये भेषजों एवं औषधियोंकी और आप्रण होना है । यदि हम इस अस्पष्ट सिद्धांतको स्वीकार कर लें, तो भी इस बातकी कष्ट गारंटी है कि लोगैसी आवश्यकताके अनुस्यू कपडे और औषधियों उन क्षेत्रोंका उत्पादन की आयेगी जिनपर लोगोंके व्यक्तिगत अधिकार हैं ।

बचने ही प्रश्न से लीजिये । उत्पादनमें भारी वृद्धि होगी, लेकिन यदि पूर्व अनुभव, विशेषरूपसे युद्धकालीन अनुभव सकेन्द्र हों, तो इसी बातकी संभावना है कि कष्ट-उद्योग अच्छे प्रकारके और ऊँचे मूल्यके कपड़ोंके बनानेके विषयमें ही

प्रचुरता की योजना

सोचेंगे, क्योंकि इसमें अधिक लाभही गुंजाइश होती है। इस उद्योगकी प्रतिमानित ढंगके सन्ने कपड़े बनाने पर बिकरा करनेके सभी प्रयत्न निष्फल हो चुके हैं, क्योंकि मिलानालिकोंके लाभ उद्योगकी प्रगति और तत्प्राप्त 'भले मानसोंके समझौतोंके पालनमें बचनेकी बढ़ानेवाली इन प्रयत्नोंको निरर्थक कर देती है।

कपड़-उद्योगके अधिपतियोंकी गणनामें सन्ने और टिग्राऊ कपड़े बनानेकी आवश्यकता महसूस करनेके कोई चिन्ह नहीं दिखलाई देते। शेरार बानारके आरुखों पर दृष्टि डालनेसे यही प्रतीत होता है कि प्रचुरता प्राप्त होनेवाली है। इसमें आरुखोंकी कोई बात नहीं है, क्योंकि प्रतिमानित कपड़निर्माण तथा उत्पादनमें अन्य प्रकारसे नियमित करके बखोंके मूल्य घटानेकी बात तो दूर रही, मरकार इस बातकी सुनिश्चित करनेकी न तो इच्छा ही रखती है और न वह ऐसा कर ही पाती है कि दर आयोग द्वारा निर्धारित उचित लाभ पर कपड़ा बिके।

योजक हायरग्रा और खादीके उत्पादन द्वारा दरमं कपड़ोंकी पूर्ति बढ़ाना चाहते हैं और साथ ही साथ यह भी दिखलानेमें सफल हो जाते हैं कि परिणाम स्वल्प लागें आदिमियोंको काम मिल जायगा। यह सही कदम है, जिसे औद्योगीकरणकी ओर अग्रसर होनेकी प्रक्रियामें किसी पिछड़े हुए देशमें लेनेका पूरा अधिकार है। तथापि यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि हाथसे बने और खादीके कपड़ोंका मुख्य अन्तर्ग मिलोंमें बने कपड़ोंमें अधिक होता है। दूसरे शब्दोंमें देना भी और बरखा इस स्तर पर अधिक तथ्यकी उपेक्षा नहीं कर सकता कि हाथसे बनी चीज मशीनोंमें बनी चीजोंकी अपेक्षा कभी सस्ती नहीं हो सकती। योजक यदि चाहते हैं कि द्वितीय योजना कालमें बननेवाली अतिरिक्त कयशक्तिका कुछ उपयोग वर्तमान में हो, तो उन्हें राजसहान्य बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन यह बात तब तक पर्याप्त नहीं हो सकती जब तक कि इन दोनों क्षेत्रोंका उत्पादन नियमित वितरणकी किसी सामान्य योजनामें विनियमित न हो जाय।

इसके अतिरिक्त हायरग्रा और खादीके कपड़ोंके उत्पादनमें अभिवृद्धि करनेवाले लाखों आदिमियोंको स्वयं अपने लिये उम सामानकी आवश्यकता होगी, जिसे वे अपनी कयशक्तिके अभावमें अब तक प्राप्त नहीं कर पाते थे। निश्चित रूपसे वे केवल कपड़ों और औपधियोंमें ही संतुष्ट नहीं होंगे। समृद्धिके दर्शन करने-

कुपै से निकलकर खाई में कूदना

बाने अमीण क्षेत्रों में भारी समस्या केन्द्रित होने के कारण संभावना यही है कि उनके विचार क्षेत्रों के अच्छे औजारों और उपकरणों को प्राप्त करने की ओर उन्मुख हों। यदि मजबूत ठीक तरह से होती है तो गैरों में अनिच्छित धन प्राप्त होने से उपरान्त योजनाओं को इन मौक़ों पर गंभीरतापूर्वक सामना करना पड़ेगा। इसके अनिच्छित धन को उत्पादकताओं में प्रवाहित करने के लिये संगठित प्रयत्नों की आवश्यकता है, जिसे अब तक हाथ में नहीं लिया गया है।

भेषजों और औषधियों का प्रश्न तो एक उदाहरण स्वरूप है। राज्य रोगाणुनाशक और शुचिमोक्षक आदि भेषजों के सस्ते उत्पादन को हाथ में ले सकता है, लेकिन अब तक हमने अधिक विदेशी साधनों के आधार पर बनमान आवश्यकताओं को पूरा करने की ही योजना बनाई है। यदि इस मद के अंतर्गत होने वाले अज्ञान की अनुमानित मूल्य देखें तो यह रकम ₹ २० करोड़ प्रतिवर्ष के लगभग बैठेगी और खरीदने में समर्थ होने पर औषधियों के बाजार में भीड़भाड़ करने वाले लाखों व्यक्तियों के आने पर क्या होगा? और इस मौक़ा पर प्रदर्शित करने के लिये स्वास्थ्यवेधक क्यों है? ऐसे अनेकों उदाहरण दिये जा सकते हैं।

अधिकतर भारत में सामाजिक व्यवहार के ढंग और आचारे जितने उलझे हुए हैं, उनको देखते हुए योजनाओं की सभी संगठनात्मक गति हो सकती है, क्योंकि पाठ्य विनियमन सब तक मर्यादा शक्ति ही रहेगी, जब तक कि कर्म-शक्तियों निर्देशित और नियंत्रित करने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया जाता। सुतलित मन्त्रिण ने योजनानुसार विज्ञान-विशेषों का अधिकतम ध्यान रखते हुए यह कार्य जानबूझ कर करना आवश्यक है। मुद्रास्फीति विषयक सभी ज्ञान व्यवहारों को केवल इन बुद्धिहीन आधार पर त्यागने का अर्थ, कि इनके प्लस-मिनास सैनिटीकरण होता है, कुपै से निकलकर खाई में कूटना है।

यदि मुद्रास्फीति का एक बार भी प्रारम्भ हो गई तो वह योजनाओं की उप-हास्य बनाने का दानेगी। राजस्व और अनिच्छित कर के लक्ष्य व्यय में कम पड़ जाईंगे। सामान की कमी प्रभावमूल्यों में वृद्धि होगी। परिवार के आवश्यक पर दबाव पड़ने में केवल बुद्धि आधारित को प्रेरणा मिलेगी। एक बाण में दूसरी का पोषण

प्रचुरता की योजना

होगा। और यदि मानसून असफल रहे और अससकट उपस्थित हुआ, तो सामान्यरूपसे अग्रमन्वित अत्यधिक कठोर और निरंतुरा उपचारोंसे काममें लाना पड़ेगा। खतरा यही है कि कहीं निर्धनता ग्राम न हो सकनेवाली ऐसी परिस्थितिका सामना होनेपर सरकार भयभीत होकर और योजनाको रद्द करनेके बारेमें न सोचने लगे।

इन्का तथा इनमें सम्बन्धित अन्य तथ्योंका सामना न करनेका मुख्य कारण प्रथम योजना और उससे प्राप्त सफलताओंका ऊपरी विवेचन है। अधिकतर लोग इस बातपर विश्वास करते हैं कि भारत अपने लिये प्रचुरताका नया मार्ग बना रहा है। परन्तु मानसूनोंके अमानान्य रूपमें अच्छे रहनेको बधाई देनी चाहिये, जिसके कारण प्रथम योजना प्रसुप्ततामें अपने स्वरूपी कायम रखनेमें सफल हो सरी। फिर औद्योगिक प्रसारकी ओर भी ध्यान केन्द्रित नहीं किया गया। कोरियामें होनेवाले प्रत्यावर्तनके समय प्रथम योजना संचालित हुई और इस कारण अर्थ-व्यवस्था सीमित रूपमें किये जानेवाले घाटेके वित्तप्रबंधनका सामना कर सरी। इन्का होते हुए भी एक बारके केवल एक अनावृष्टिमें ही समस्त लाभ समाप्त हो सकते थे।

सौभाग्यवश यह नहीं हुआ। विशेष तौरपर कृषिके लाभ मुट्ठ हुए और इस प्रकार एक वास्तविक योजनाकी नींव पड़ गई। वास्तविक ? हैं। योजना वैज्ञानिक ढंगमें ही बनो थी, वह परस्पर विरोधी विचारोंका समुहमान ही न था। महात्तनोबीस और उनके साथियोंका यही स्पष्ट उद्देश था। योजनाके प्रारूपके साथ जो अन्याय हुआ है उसे सुधारनेके लिये भी अधिक देर नहीं हुई है।

तथापि यह तभी संभव हो सकता है, जब कि आलोचक वित्तीय प्रश्नोंमें सम्बन्धित विषयोंके लगावसे ऊपर उठकर मौलिक प्रश्नोंपर ध्यान केन्द्रित करें। योजनाकी व्यापक साधन खोजते समय इन प्रश्नपर मतभेद होना कि गरीबों और अमीरोंमें किम्पर कर लगाया जाय, वास्तवमें भ्रमपूर्ण है।

विशेष तथा विकीर्ण आदिके जरिये गरीबों पर तो उनकी समताके अनुमान भी पूरा कर लगाया जा रहा है। राजस्वका प्रमुख भाग भी प्रत्यक्ष करोंमें ही प्राप्त होता है। जहाँ तक रईसोंका प्रश्न है, उनमें बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, परन्तु कराधान

यन्त्री न्यूनताओंके कारण यह बात अमम्भव हो जानी है। अतुल्य यह बनलाना है कि बड़े आदमियों पर जिनका अधिक कर लगाया जाता है, उतना ही अधिक वे उसे टालते हैं। जब तक इस टालनेकी जेलमें ढालने योग्य अपराध घोषित नहीं किया जाना, तब तक इस बातकी कोई सम्भावना नहीं है कि हमें इस क्षेत्रने योजनाके लिये साधन प्राप्त हो सकेंगे।

अगले पाँच वर्षोंमें कराधान यंत्रके आदर्श बन जानेकी बहुत कम आशा है। निधिके बिना सरकार विदेशी सहायता द्वारा इस रिक्तताकी पूर्तिरा प्रयत्न करेगी। मुद्रास्फीतकी प्रवृत्तियोंके विकल्पित होते ही घाटेके वित्तप्रबंधनको गेक जायगा। विदेशी ऋणोंकी खोज होगी। सुरक्षेके विभिन्न औद्योगिक राष्ट्रोंमें अस्सर्विस्मित देशोंके साथ 'मित्रता प्रतिधेगिता' करनेकी ओ मोंग रखी है, वह अपना प्रभाव ढालेगी।

संयुक्त राज्यस परराष्ट्र विभाग इस बातको स्वयं स्वीकार करता है कि सोवियत संघ गिड़डे हुए जैनोकी सहायताके लिये एक विशाल सहायता योजना बना रहा है, साथही इस बातकी भी बार-बार चेतावनी दी जाती है कि अमेरिकाकी भी इस प्रयत्नकी धराजरी जरनी चाहिये। यदि अपेक्षित विदेशी सहायता प्राप्त नहीं हुई, तो भारत भी मिश्रके राष्ट्रयुक्त नामिका अनुगमन कर सकता है, जो अपने देशमें स्थित विदेशी पूँजीको हस्तगत करके आवश्यक निधि पाना चाहते हैं।

अतोग्गवा भारतीय प्रगतिकी योजना सुदृढ होनी चाहिये। उसे नियंत्रित और समन्वित करना चाहिये। भारत स्वयं अपने प्रयत्नोंका शरोत्ता करके यह सब कर सका है।

किसी सीमा तक प्रथम योजनाके अनुभवसे हमें यह शिक्षा मिलनी चाहिये थी। देशके विभिन्न भागोंमें तरह-तरहकी जमीनोंके भेद उर्वरकी कितनी आवश्यकता है, इस प्रश्नकी साथ साथ विवेचना किये बिना ही दैत्याकार सिंदरी उर्वरक कारखाना खड़ा कर दिया गया। प्रतिवर्ष बनमहोमवका आयोजन होता है। हजारों व्यक्ति नये वृक्षोंका रोपण करते हैं, जो बिना पानी और देख रेख नष्ट हो जाते हैं। यह हरियाली-पट्टी जो हमारी भूमिकी रक्षा करनेमें समर्थ है, जन्मते ही नष्ट हो जाती है। समारकी कुछ मुद्रात्मक वैज्ञानिक प्रयोगशालाओंका निर्माण हुआ है, परंतु

प्रचुरता की योजना

वैज्ञानिकों के कार्यको राष्ट्रीय आवश्यकताओं में शायद ही कभी संयुक्त किया जाता हो । हमने विशाल चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना बना डाला, लेकिन इस बातको भूल गये कि बाष्प इंजनों का स्थान अब ट्रिजिल इंजनने ले लिया है । इम्पल्ट और सीमेंट दोनों की ही कमी है, किन्तु हम उसे उन विलास पद्धतियों और विशाल कारखानों के बनाने में नष्ट कर रहे हैं, जिन्हें सहजा राष्ट्रीय महानशीलता में परे है । हम मोटर जोड़ने की मशीनों का आयात करते हैं, किन्तु समस्त देश में बिछेरकर केवल उनकी क्षमता के ४० प्रतिशत का ही उपयोग कर पाते हैं, किन्तु किसी सीमा तक संयुक्त करने के उपरान्त हम मोटर और मोटर टेलों में आत्मनिर्भर बन सकते थे । सभी उद्योगों के कारखानों और वाम धर्मों उत्पादन बच सकता है, लेकिन इस अवस्था को मिटाने की कोई चिन्ता ही नहीं करता, जब कि विदेशी विशेषज्ञों ने अनेक प्रतिवेदनों में इस असंतोषप्रद परिस्थिति की ओर ध्यान आकृष्ट किया है । पिछले एक या दो वर्षों के अंदर कुछ उद्योगों के उत्पादन में ५० से १०० प्रतिशत तक वृद्धि हुई है । जहाँ तक बहु प्रयोजनीय प्रयोजनाओं में प्राप्त बिजली का प्रश्न है, उसका उपयोग होता है, पर सदैव सर्वोत्तम लाभ हेतु नहीं । यह सूची लम्बी और अनंत है ।

जब तक कि योजनाओं और प्रशासकों के पुराने आराम तलारी के दृष्टिकोणों में दूर करने का कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया जाता, तब तक संतुलन, सहयोग और स्वरूप की इस न्यूनता की कहानी का द्वितीय योजना-काल में पुनरावर्तन होता रहेगा । भारत की प्रज्ञा और वसोयत चाहे जैसी हो, लेकिन इस कार्य को सफल करने का केवल एक ही मार्ग है । योजनाओं लागू करने और उनके विवेचन के प्रत्येक स्तर पर लोगों को साथ लेना ही चाहिये । दैनिक कार्य और संपर्क से अर्जित होनेवाला उनका अनुभव, उनकी आवश्यकताएँ, उनका ह्यन ही है, जो इस दिशा में अभ्यास घेरकरी का कार्य कर सकता है ।

अप्रेजोने इस भूखंड पर देश का धन चूमने के लिये शासन किया । उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि जनता क्या सोचती है । स्वतंत्र भारत का प्रशासन भी राष्ट्रीय जीवन के किसी भी स्तर पर वादविवाद किये बिना ही योजना बनाता है

और नीति निर्धारण करता है। राजनैतिक पार्टियोंके नेताओं और समूह सदस्योंके बीच होनेवाला समझौता ही प्रजातन्त्रमें सब कुछ नहीं है।

शौरभ्य व्यक्ति लाल पीलेके भेदोंमें क्या जान सकते हैं? दफ्तरमें क्लर्कोंमें यह बात पूछिये। उनके पास अनेक उपचार हैं। यदि कालेबाजार पर रोक लगाना जाली है, तो सामान भिन्नता एक समस्या हो जाती है। सचिवान्तर्गतके तर्क वितर्कों द्वारा इस समस्याका निराकरण होनेकी कोई सम्भवना नहीं है। क्या इन कार्यवाहियोंकी शिफार अन्ततः अपने हितोंकी रक्षा करनेके लिये विवश नहीं किया जा सकता? कंट्रोलोंके अस्तकाल होनेका कारण यही है कि जनता इस बात पर विश्वास नहीं करती कि कंट्रोल उनके हितार्थ लागू किये गये हैं। यदि एकत्रिण. धन प्रकट नहीं होता तो गाँवोंमें जाकर किसानों पर इस बातके लिये जोर डालिये कि यदि वे दूरस्थ सरकार द्वारा जारी किये गये ऋणमें अनुदान नहीं देना चाहते, तो उन्हें अपनी बचत नलकूपों आदिमें लगानी चाहिये। यह कुछ समझमें आनेवाली बात है। जहाँ उन्हाही सुगठक इस बातकी समझ लेता है, वहाँ इसका परिणाम भी निकलता है। कामगारोंके लिये काटीनोंका निर्माण करना है, पर यह क्या जरूरी है कि उनका रूप बही हो जो पश्चिममें दीखता है? अपनी कल्याण हेतु आवश्यकताओंको नियंत्रित करनेके स्वयं कामगारोंके कुछ विचार हो सकते हैं। विद्येयसूत्रमें उक्त सन्देश जब कि भेज, कुर्मी, गुलदस्तों आदिमें परिपूर्ण काटीनका बनावरण उनके धर नामगारी दुर्भाग्यपूर्ण विलम्बे पूर्णरूपेण भिन्न है, जहाँ उन्हें सोनेके लिये भी पर्याप्त स्थान नहीं होता! मदनमोहन मालवीय के विचारोंमें विज्ञान शायद बनाना क्यों चालू रखते हैं? अच्छा हो यदि इस विधिके निर्माण धानके खेतोंमें घुटनों पानीके अंदर खड़े-खड़े एक दिन मिटानेके पश्चात् यह प्रश्न अपने अपने पृष्ठों। 'मदनमोहन' नगरोंमें नष्ट किये जानेवाले करोड़ों रुपये यदि रैल्वेके तानाबों या मनोरंजनके अन्य साधनोंमें लगाये गये होते तो ऐसे विधान बनानेकी आवश्यकता न पड़ती, जिन्हें पालन करनेकी अपेक्षा तोड़नेकी ओर अधिक ध्यान दिया जान है।

छोटी बातोंमें ही बड़ी बातोंकी ओर बड़ा जाता है, लेकिन आरम्भ सदैव छोटी बातोंमें ही होता है। यह निरर्थक मिथ्या प्रतीत होता है, किन्तु योजनाके प्रति

प्रचुरता की योजना

जागरूक नेताओंको इसे स्वीकार करना पड़ेगा। अब तक जनतासे सदैव कुछ बातें पूरी करनेके लिये कहा जाता था। जैसे कम बच्चे पैदा करना, एक समयका भोजन छोड़ना, धर्मदानमें भाग लेना या किसी नेतासे देखकर उसका उत्साह बढ़ाना। अब वह समय करीब आ चुका है, जब कि ऐसी योजनाके सम्बन्धमें उनकी राय मँगी जाय जो उनके बच्चोंके और नानी-पोतोंके जीवनकी प्रभावित करनेवाली हैं।

द्वितीय योजनाकालके अंत तक संपूर्ण ग्रामीण भारतमें स्थापित होनेवाली सामूहिक विद्यम परियोजनाओं द्वारा इस दिशामें जो कुछ सफलता प्राप्त हो पाई है, वह इस परीक्षणोद्योगमें लेनेवाले उन अनेक अधिकारियोंकी प्रकृतिके कारण नष्ट होनेसे संकटमें है, जो स्थिर विचार और मर्ब रोगाणु औपचिन विश्वास करनेवाले नये ढंगके दम्तरसाह बनना चाहते हैं और जो दर्शकोंको ऊपरी सिद्धियोंका प्रदर्शन करनेको अधिक लालायित रहते हैं, वनिस्वन इसके कि आगामीमें न दीखनेवाले मौलिक परिवर्तनोंकी ओर ध्यान देते। जिस प्रक्रियाका आरम्भ नीचेमें हुआ उसके ऊपरसे आज़ा देनेवाली बननेका भय है। किन्तु स्वतंत्रता और अवसर मिलने पर सामूहिक विद्यम परियोजना निहित हितों द्वारा प्रेरणात्मक शक्ति और प्रजा तानिक योजना निर्माणकी उत्तोलक बनाई जा सकती है।

देशके प्रत्येक विचारधारावाले लोगों द्वारा द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकी प्रशंसा की गई है। निहित स्वार्थों द्वारा की जानेवाली आलोचना पर्याप्त है, किन्तु उन्होंने अनेक प्रगतिशील तत्वोंकी उपेक्षा की है। लेकिन देश जो आर्थिक मार्ग अपना रहा है, उसके सम्बन्धमें १९४७ के बाद प्रथम बार द्योत महमति दीयती है। दूसरे शब्दोंमें कार्यके लिए ऐसा आधार विद्यमान है जिससे अनेक गम्भीर न्यूनताये चाहे दूर न हो सकें, किन्तु वास्तविक प्रगति की सम्भावनाओंका मार्ग अवश्य खुल जाता है।

छामियाँ अनेक हैं। निजी क्षेत्रोंकी अनावश्यक रियायत दे दी गयी है। विदेशी हितों पर बहुत कम प्रभाव पड़ा है। राजस्वके जरियों जैसे संगठित निजी उद्योगके लाभ पर हाथ भी नहीं लगाया गया है। तीव्र औद्योगीकरण पर रोक लगानेका प्रयत्न किया गया है। निरंतर श्रमिकों एकमात्र गारंटी अर्थात् वंचनिर्माण-उद्योग स्थापित करके तीव्र औद्योगीकरणकी नींव डालनेकी आवश्यकताको भी संभवतः

अन्दी तरह नहीं समझा गया है। कृषिमें पुनर्जागरण लानेके लिये अत्यंत आवश्यक प्रश्न अर्थात् जोतनेवालेको जमीन देनेका प्रश्न अब भी हल नहीं हुआ है। बेकारीको दूर करनेका मुश्किलमें ही प्रयत्न हुआ है, और जीवनस्तरमें कोई विशेष सुधारकी आशा नहीं दी जाती, जैसी कुछ लोग पहले आशा कर रहे थे।

लेकिन योजनामें परिवर्तन होगा। सूचना है कि कुल उद्ब्ययको बढ़ाकर ५,३०० करोड़ कर दिया गया है। यह अंतिम अंक नहीं है, क्योंकि योजनाको कार्यान्वित करनेके साथ-साथ सरकारको औद्योगिक प्रगतिके लिये भारी विनियोजन करना पड़ेगा। देशके शासकोंके लिये और कोई मार्ग नहीं है। क्योंकि उन्हें जनताके समर्थनका आश्रित होना ही पड़ता है। भारतको बतला दिया गया है कि यह योजना, प्रचुरताकी योजना है। जब प्रचुरताकी सम्भावना धूमिल पड़ने लगेंगी, जैसा होना भी चाहिये, तब कैंग्रेसपाटीके ऊपर बड़ा भारी दबाव पड़ेगा, जिसके परिणामस्वरूप योजनाका विस्तार होगा।

जनजीवनकी आर्थिक सफलतायें भारतको जैसे जैसे प्रभावित करेंगी, वैसे ही वैसे यह दबाव बढ़ता जाएगा। उनकी प्रगति चित्कर्षक है और सीधेही आन्दोलनजनक हो जायगी। अब यह पता चला है कि चीन १९६२ के अंत तक १२० लाख टन इस्पातके उत्पादनकी आशा करता है। १९६७ में चीनके इस्पात उत्पादनकी २०० लाख टन तक बढ़ जानेकी सम्भावना है; अर्थात् १९५४ में ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी तथा द्वितीय महायुद्धके दरम्यान हुआ जितना उत्पादन था, उससे अधिक।

दिल्लीको भी अप्रसर होनेके लिये विदेशी पूँजी और भारतके बड़े एकाधिकारी तत्त्वोंके अधीन रहनेवाले लाभ-साधनों पर आक्रमण करना पड़ेगा। भारतीय कंपनी अधिनियमके अंतर्गत सरकारने यथेष्ट शक्तिसे अपने आपको पूर्वसुसज्जित कर रखा है। बैंक, जूट, चाय बगान, उत्खनन हित, तेल, सीमेंट और वस्त्रोंको सम्भवतया, राज्यनियंत्रणका सामना करना पड़े। अभी निजी क्षेत्रमें बने रहनेवाले लोहा और इस्पात हितोंकी निरंतर अप्रभार होनेवाले राज्यक्षेत्रके सामने आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। यही दशा आयात निर्यात व्यापारकी होगी।

विदेशी हितोंमें तो अभी मुश्किलमें हाथ लगाया है। अब तक जो कुछ हो सका है, वह केवल यह कि इन फर्मों पर 'भारतीयकरण' करनेके लिये दबाव डाला गया

प्रचुरता की योजना

है, किन्तु यह प्रक्रिया भी बहुत धीमी है, जसा कि निम्नलिखित आंकड़ोंसे मालूम पड़ता है :-

विदेश-नियंत्रित कर्मोंमें नौकरी
अधिक वेतन पानेवाला वर्ग

| | रु. ५००-६६६ | | रु. १००० और अधिक | |
|------|-------------|---------|------------------|---------|
| | भारतीय | अभारतीय | भारतीय | अभारतीय |
| १६४७ | २२२५ | १६१६ | ५०४ | ५८४४ |
| १६५० | ४२३८ | १२६६ | १४०६ | ६८७१ |
| १६५२ | ५६६७ | १०३३ | २२६० | ७१०४ |
| १६५४ | ७४६६ | ६५० | ३३४६ | ७००८ |
| १६५५ | ८१६६ | ५४८ | ३६६५ | ६८१० |

ये आंकड़े भुलावेमें डालनेवाले हैं, क्योंकि वेतन पर्याप्त आधार नहीं है। किसी भारतीय कार्यचारीको १००० रुपये या उससे भी अधिक मिल सकते हैं, लेकिन अन्य भर्तोंको भी जोषनेके उपरांत सम्भव है उसका स्तर, अधिकार क्षेत्र और कुल आय अवरतम विदेशी कर्मचारीके भी बराबर न हो। और कुछ पदकर्मोंमें तो अभारतीयोंके पास शीर्षस्थ स्थानोंके २/३ से भी अधिक हैं, जैसे बगानमें (८६.६ प्रतिशत), जूटमें (८६.६ प्रतिशत), बैकिंगमें (७८.१ प्रतिशत), व्यापारमें (६८.४ प्रतिशत), सामानकी दुकानें और यातायातमें (६६.६ प्रतिशत)। इस परिस्थितिसे आगे पीछे समझ करना ही पड़ेगा।

अन्य दबाव, भूमि समस्याके निराकरणकी आवश्यकताको रेखांकित करते रहेंगे, जिसे सिर्फ चक्करी द्वारा या कर घटाकर हल नहीं किया जा सकता। यह समस्या तो भूमि सम्बंधोंमें मौलिक परिवर्तन चाहती है; विशेष तौर पर ऐसे समय जब कि राज्यनिर्देशित औद्योगिक प्रसार हो रहा हो। और भूमिहीन कृषि मजदूरों तथा निर्धन और मध्यम विध्वंस कृषकोंके पास भूलाधिकार रहने उनकी उपेक्षा कौन कर सकता है? सरकारी तौर पर यह स्वीकार किया गया है कि सम्पूर्ण कृषि-योग्य क्षेत्रके १५-५ प्रतिशत भाग पर ६० प्रतिशत किसानोंका अधिकार है। जब

कि ५ प्रतिशतके पास ३४ प्रतिशत जमीन है (स्वयं उनके नाममें। यदि उनके सम्बन्धियोंके नामकी बैनानी जमीनको भी सम्मिलित किया जाय तो यह अनुपात बहुत अधिक हो जायगा।)

१९५७ के आन तक ५०० करोड़ एकड़ भूमि एकत्र करनेका लक्ष्य रखनेवाले भूदान आन्दोलनके नेता आचार्य विनोबा भावे, इस बात पर बल देते हुए बार बार कहते हैं कि, "भूमि तो केवल प्रतीक है। भूमिमें लोगोंकी विमुक्ता शक्ति हो जाती है। इसके कारण आनविश्वास प्राप्त हो जाता है। इसने नया विश्वास प्राप्त होता है। यह इस विचारको बल प्रदान करती है कि जल और वायुके समान भूमिपर भी सबका अधिकार है और इसका समानोंमें वितरण होना चाहिये।" भूदान इस समस्याका उत्तर भले ही न हो, किन्तु इसका प्रतिपादन निश्चिन्त रूपमें इस दानका सूचक है कि भूमिमुक्ताकी न तो उपेक्षा की जा सकती है और न इस कार्यको स्थगित किया जा सकता है।

केवल योजनाके सामने पड़नेवाले अशक्त स्थलोंमें शक्तिपूर्ण बनानेके लिये ही नहीं बरन देशके कमिक विद्यमानके सुनिश्चित करनेके लिये भी राज्य द्वारा धीरे-धीरे अपने कियक्षेत्रका विस्तार करना भी निर्णीत बात है। आज एक भाषायी क्षेत्र आर्थिक लाभोंके लिये दूसरेके साथ प्रतियोगिता कर रहा है।

कल कच्चे माल विशेष रूपसे ईंधनकी मुक्तभत्ताके आधार पर दक्षिण, उत्तर द्वारा उनतिके बड़े भाग हथियानेके विरुद्ध भ्रमण बढ़ेगा। और जब बहु-उद्देशीय परियोजनाओंमें उन्मादित होनेवाली संपूर्ण विजली प्राप्त होने लगेगी, तब सार्वजनिक क्षेत्र ही उसे प्रमुख रूपसे खरा होनेकी परिस्थितिमें हो जायगा।

समसामयिकोंके बावजूद भी यही मुख्य प्रवृत्तियों स्पष्ट दिखलाई पड़ती हैं। वे भारतीय प्रगति का रूप निर्धारित करेंगी। इन परिवर्तनोंकी गति अनेक कारणोंपर विशेष तौरसे आन्तराष्ट्रीय परिस्थिति पर आश्रित है। अब धनीभूत होनेवाले शक्तिपूर्ण सम्बन्धोंके प्रसारसे भारतमें सहायता मिलेगी और उसे समाजवादी दुनिर्णय ऐसी सहायता सुलभ हो जायगी, जिससे अपने कभी कल्पना भी न थी थी।

प्रचुरता की योजना

अनेक योजनाओंके अंदर होनेवाली आर्थिक प्रगतिके चरणोंका योजना आयोगने मोटे तोरपर उल्लेख किया है। महालनोबिसने ठीक ही कहा है कि योजना बनाते १०, २०, ३० या इसमें अधिक वर्षों तक राष्ट्रीय आर्थिक प्रगतिका स्वरूप अपने सामने रखना चाहिये। निम्नलिखित तालिकामें प्रायोजित कार्यक्रम बतलाया गया है।—

| | | | | | |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| आय एवं विनियोजनमें वृद्धि, १९५१-७६ | | | | | |
| (१९५२-५३ के मूल्योंके आधार पर) | | | | | |
| प्र. योजना द्वि योजना त्रि योजना च. योजना प. योजना | | | | | |
| (११-१६) (१६-६१) (६१-६६) (६६-७१) (७१-७६) | | | | | |
| अवधिके अंतमें राष्ट्रीय आय | | | | | |
| (६ करोड़ोंमें) | १०,८०० | १३,४८० | १७,२६० | २१,६८० | २७,२७० |
| वास्तविक विनियोजनका योग | | | | | |
| (६ करोड़ोंमें) | ३,१०० | ६,२०० | ९,६०० | १४,८०० | २०,७०० |
| अवधिके अंतमें राष्ट्रीय आयका | | | | | |
| विनियोजनमें प्रतिशत | ७३ | १०० | १३७ | १६० | १७० |
| अवधिके अंतमें जनसङ्ख्या | | | | | |
| (लाखोंमें) | ३,८४० | ४०,८० | ४३,४० | ४६,५० | ५०,०० |
| विक्रान्तोन्मुख पूँजी, निर्माणका | | | | | |
| समानुपात | १८८.१ | २३१ | २६२.१ | ३३६.१ | ३७०.१ |
| अवधिके अंतमें प्रति व्यक्ति आय | | | | | |
| (रुपयोंमें) | २८१ | ३३१ | ३९६ | ४६६ | ५४५ |

संगठित प्रगतिकी यह सम्भावनाये हैं जो स्थानीय और विदेशी दोनों प्रकारके बड़े व्यवसायोंको भयभीत कर देती हैं। इसी कारण द्वितीय योजना पर उग्र विवाद होता है। यदि वायदा नहीं तो कमसे कम प्रचुरताके बीदाणु तो इसमें विद्यमान हैं ही।

यही बीयाणु थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री नेहरूसे यह कहनेकी प्रेरणा दी, कि “ कोई फौज किसी देश या स्थानके कोने-कोनेमें सैनिकोंको नियुक्त करके उस पर अधिकार नहीं करती । वह तो उसके समस्त युद्धोपयोगी स्थलों पर नियंत्रण प्राप्त करके अधिकार प्राप्त कर लेती है । इन युद्धोपयोगी स्थलोंमें ही फौज उस समस्त भूभाग पर नियंत्रण करती है । किसी पहाड़ी पर स्थापित की जानेवाली तोप फौजको समीपवर्ती क्षेत्र पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करनेमें समर्थ बनाती है । ठीक इसी तरह हमें भी अपनी अव्यवस्थाके सभी महत्वपूर्ण स्थलोंमें सभाजना है, जिसमें एक सर्वग्राही राष्ट्रीय योजनाके अंतर्गत निजी और सार्वजनिक दोनों ही क्षेत्रोंमें कार्य सुचारु रूपमें संचालित हो सके ।

यह ठीक कहा गया है । जिन लोगोंने योजनाकी ओरसे इस डरके कारणसे ओलें मूर ली हैं कि वह उनके उलटे-सीधे कट्टर सिद्धांतोंको अव्यवस्थित कर देगी, उन्हें इसकी सत्यता अधिकधिक स्पष्ट होती जायगी । भारत किसी अजनबी मार्ग पर कदम नहीं बढ़ा रहा है, किंतु वह शायद मानव जातिके इतिहासमें सबसे बड़े नादनीय युगकी शक्तियों द्वारा अभिभूत हो रहा है ।

पूँजीवादका युग समाप्त हो रहा है । यद्यपि ऐसा करनेमें वह अनिच्छा दिखा रहा है । समाजवाद, संपूर्ण सत्कारका स्वीकृत भविष्य निर्धारित हो चुका है । भारत इन्हीं शक्तियोंसे प्रभावित हो रहा है । कभी वह आश्चर्यजनक स्पष्टताके साथ आगे बढ़ने लगता है । दूसरे अक्सरोंपर विभ्रम और असलम्यस्तता दीकती है । किन्तु कैसे अक्सर होना चाहिये इस प्रश्नका मन वैपरित्यक्तालव और अमालुपिकतासे उन्मुक्त समाजके निर्माणकी जनेच्छाको परिव्याप्त नहीं कर सकता ।

टिप्पणी :- भारतीय योजनाविषयक अधिकतर सामग्री “ इकोनोमिक विकली ऑफ बीम्बे ” से उद्धृत की गई है ।

सौहाद्रता का प्रसार

किसी राष्ट्र या जातिके लिये यह सोचना कि वह केवल कुछ दे ही सकती है और उसे शेष संसारमें कुछ लेनेकी आवश्यकता नहीं है, अविवेकपूर्ण है। यदि एक बार किसी राष्ट्र या जातिमें यह सोचना प्रारम्भ कर दिया, तो वह स्थिर होकर पिछडने लगता है तथा अंतमें नष्ट हो जाता है।

—जवाहरलाल नेहरू

भारतके द्वितीय योजनागत कार्यारम्भ करते समय स्वदेश और विदेश दोनोंमें राजनैतिक वातावरण निम्ने आश्चर्यजनक रूपमें बदला हुआ है। तनाव और सङ्घर्षको प्रतिबन्धित करनेवाले पाँच वर्ष जो प्रथम योजनाकालमें राष्ट्रीय प्रगतिमें भयंकर बाधा थे, अब शोभनापूर्वक भूतकालीन बात बनने जा रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे कहीं हो, अधिक सुविधापूर्वक सोच ले रहा है। हम यह देख चुके हैं कि यह प्रगतिशील कैसे विकसित हुई, किंतु वर्तमान समयमें हम उसी परिपूर्णताके दर्शन करते हैं। कुछ स्थलों पर किम्वदंति दिखनाई पसंदी है जब कि अन्य स्थलों पर साहमयपूर्ण हलचल। परंतु निश्चिन्नरूपसे व्यक्ति और राष्ट्र निरंतर एक दूसरेके समीप आ रहे हैं।

हम परिवर्तनको स्पष्ट शब्दोंमें समझानेके लिये हमें निकट प्रतिदिन होनेवाली घटनाओंका ही सर्वेक्षण करना पड़ेगा। साम्राज्यवादी शक्तियोंमें यह देख लिखा है कि वे अब आधे विश्वको अपनी कार्यप्रणाली स्वीकार करनेके लिये बेवकूफ नहीं बना सकते। नन्हें कम्बोडियाको भी उनसे यह कहनेका साहस हो गया कि अपने हाथ उसकी गर्दनपरसे हटा लें। दुरुस्थ आइसलैंड भी वामपक्षी सरकार चुनकर यह प्रतिज्ञा करने लगा कि उसके देशसे सभी विदेशी विज्ञान-स्थल हटा लिये जायें। सऊदी अरब भी अंतमें यह समझने लगा कि मद्रमूमिमें स्थित तेल, असीमित सुवर्णस्य प्रदायक है और उसे इसका उपयोग अपने बीरान देशकी

उन्नतिके लिये करना चाहिये, वही सुवर्ण जो अब तक संयुक्त राज्तीय डालरोंमें चमक पैदा करता रहा था। मिथ भी साहसके साथ सार्वभौमताके साथ समझौता करनेवाली सहायताको ठुकराना है और इसके स्थानपर प्रतीकारात्मक कार्यवाही करता है। ठठरी अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशियामें स्थित साम्राज्य लडसड़ा रहे हैं। साक्षों व्यक्ति राष्ट्रीयता, गौरव और स्वतन्त्रता प्राप्त करनेके लिये प्रयत्नशील हैं।

ज्योंही शीतयुद्धका अंत होना है, त्योंही आणविक कूटनीति और उसके तरीकोंके प्रति अमेरिकावासियोंमें भी घृणा व्यक्त होने लगती है। साम्यवादी दुनियाँ अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तनोंके दर्शन करती है। साम्यवादी पार्टियों अपनी विधि और अपनी भूलोंका पुनरावलोकन प्रारम्भ कर देती हैं। मानवीय इतिहासमें सम्भावनता सर्वाधिक विवादास्पद स्थालिन युगका एक अपरिचित स्पष्टताके साथ पुनरावलोकन होने लगता है। साम्यवादी समाजको उन बुराइयोंमें डन्मुक्त करनेका दृढापूर्ण अभियान प्रारम्भ हो जाता है, जिन्होंने अनेक कार्यक्षेत्रोंमें अब तक स्वतंत्र और निर्बाध विचारोंकी गति रुद्ध कर रखी थी।

‘कैमलिनके व्यक्तियों’ को आवृत्त करनेवाला किसी समयका रहस्य भी हट जाता है। वे अब सप्तरात्रियोंसे मिलने निकल पड़ते हैं। चीनमें, चू एन-ली व्यापक कई शैकको अब ऐसा युद्ध अपराधी नहीं बतलाते, जिसपर मुन्दमा चलना आवश्यक है। इसके विपरीत वे अपने ज्ञात शत्रुको प्रत्यक्ष बार्ताके लिये आमन्त्रित करते हैं। यह उत्तेजनपूर्ण समयके चिन्ह हैं क्योंकि भय समाप्त हो रहा है, विश्वास पुनर्जीवित हो उठ है।

वस्तुतः सब कुछ ठीक नहीं है। पूर्वकालीन बसीयत मौजूद है, जो अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर रही है। अरयाकम्पी उत्तर अतलांतिक सवि सगठनके बंधनोंमें डन्मुक्त होनेका प्रयत्न करते समय भी प्रामीची अलजीरियावासियोंके विरुद्ध एक बर्बरतापूर्ण युद्ध करनेमें जुटे हुए हैं। ब्रिटिश लोग यही कार्य बोलिविया, साइप्रस और मलायामें कर रहे हैं। मोका मिलनेपर अमेरिका भी बड़ा लड पटकारने लगता है। कभी नेहरूको घृणा करने लगता है और कभी अपने पिदुओंके गुणगान करने लगता है। और आणविक एवं उदजन अर्जोंका अविशेषपूर्ण परीक्षण

सौ हा द्र ता का प्र सार

आती है। परिणामस्वरूप रेडियो सक्रियतासे बाथुमडलमो दूषित करके, इस भूमेडलपर जीवजगतके भविष्यके लिये खतरा कर दिया गया है।

किंतु समारमें होनेवाले परिवर्तनको रोग नहीं जा मरना। वे घनत्व और क्षेत्रमें बढ़ते ही जायेंगे। इस बातको समझनेके लिये यह जानना आवश्यक है कि सोवियत संघीय साम्यवादी पार्टीकी २० वीं कांग्रेसमें क्या हुआ। यह बात भारतीय परिस्थितिसे यथेष्ट दूर भले ही मालूम पड़े, किंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। यह ऐसी घटना थी जो अगली अनेक दशाब्दियों तक भविष्यकी घटनाओंका रूप निर्धारित करती रहेगी।

मित्रोत्थामें होनेवाले बीसवीं कांग्रेसके सुले अधिवेशनमें ओजेफ स्टालिनकी निन्दा और तदुपरान्त एक गुप्त अधिवेशनमें सुदचेव द्वारा उसके अपराधोंको अनुमोचित करने पर, संसारभरके न निर्फ संसदीय आंदोलनोंकी ही वरन् इस आंदोलनकी लक्ष्मण रेखाके बाहर स्टालिनके अधीन सोवियत संघकी आश्चर्यजनक आर्थिक एवं सैनिक सफलताओंको देखकर उसकी प्रशंसा करनेवाले लाखों आदमियोंकी भी एक भारी धक्का-मुक्का लग्य।

जबसे लेबरेंटी बेरियाको बंदी बनाया गया था, तभीसे यह स्पष्ट हो गया था कि कुछ न कुछ न्यूनता आवश्यक है। उस पर आरोपित अपराधमूचीमें अप्रत्यक्ष रूपसे स्टालिन भी आ जाते थे, क्योंकि उसकी मौनस्वीकृति बिना इसकी ज्यादातरियाँ नहीं हो सकती थी। व्यक्तिवादकी जब आलोचना होने लगी तब यह धारणा विकसित हुई और आगे चलकर इसकी परिणति यूगोस्लावियाके टोटोके विपक्षी समस्त प्रकरणकी निन्दामें हुई।

साम्यवादी निदान्तशास्त्रियोंने सोवियत नेताओं द्वारा अपनी भूल सुधारके साहसी ढंगका स्वागत किया, क्योंकि शीत युद्धके तनावपूर्ण वातावरणमें ऐसी भूलोंका होना आसान था। किन्तु किसीको यह भान नहीं था कि आगे क्या होनेवाला है। फिर भी यह हात हो चुका है कि १९५५ में सोवियत संघका दौरा करते समय प्रधान मंत्री नेहरूको यह बात स्पष्ट रूपसे बतला दी गई थी कि स्टालिन-विपक्षक कल्पनाकी अस्वीकृतिके लिये कदम आयोजित हो रहे हैं और उनके नामसे प्रसिद्ध होनेवाले संदेहपूर्ण ढंगोंकी समाप्ति किया जायगा।

उदलान्ध अभिलेखोंके अध्ययनसे यह पता चलता है कि सोवियत संघके नेताओंने क्रमिक पुनर्निर्धारण और पुनः शिक्षाका निरचन किया था। वे स्टालिन विषयक कल्पनापर सम्मुख और नास्तिकीय आक्रमण नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ऐसा करने पर स्टालिनके नामके साथ निरुद्ध सम्बंधित सोवियत संघके निर्माणचलने पालन की जानेवाली नीतिकी उपयुक्तताके विषयमें सदेह व्यक्त किये जानेकी सम्भावना थी।

१९५४ और १९५५ में विशेष रूपसे आर्थिक विकासके क्षेत्रमें प्रचारित किये जानेवाले नये सिद्धान्तोंसे असन्ध प्रमाणित करनेके लिये स्टालिनके लेख उद्धृत किये जाते थे। कुछके प्रति तर्क स्वरूप स्टालिनके आदेशोंकी ओर ध्यान आकर्षित किया जाता था। दिसम्बर १९५५ तकमें स्टालिनके जन्मोत्सवके अवसरपर निश्चित शब्दोंमें उनकी सेवाओंके प्रति कृतज्ञता शक्ति की गई थी। कुछ महीनों परवान होनेवाली बीगर्बी कमिश्नमें इस कटुमन्थकी अभिव्यक्तिकी आकस्मिकताका अर्थ यही है कि साम्यवादी पार्टीके आन्तरिक संघर्षमें प्रचारात्मक परिवर्तन हो गया था और पूर्ण सत्यकी रीतिसे यथेष्ट बल प्राप्त कर लिया था। किन्तु सिद्धान्तोंकी सीमाके अन्तर्गत काम करनेवाली पार्टीमें, यदि वे सिद्धान्त साथ ही साथ किसी ऐसे व्यक्तिके नामसे सम्बंधित हों, जिसकी कटु आलोचना हो रही है, ऐसा परिवर्तन स्वाभाविक ही है।

तथ्योंकी रीति की जाती है और स्टालिनके सिद्धांत और व्यवहारको शुद्ध करनेके प्रयत्नमें इनका विभिन्न प्रकारसे अर्थ लगाया जाता है। कुछ लोगोंका कहना है उन डिक्टेटरमें निरुद्ध सम्बंधित होनेके कारण मोलोटोव और कानोविच, आत्म रक्षणके हितार्थ इस आक्रमणको निष्क्रिय करेंगे, मिखोयानका मत इसके पूर्णरूपेण विरुद्ध है, और बुलगानिन तथा सुरुचेव न्यून स्थितिका प्रतिनिधित्व करते हैं और यही जो स्टालिन सिद्धान्तोंमें प्रभाविन कार्यकर्ताओंका विचार है। अन्य व्यक्तियोंका कहना है कि नवीन शक्ति अर्थात् सुरुचेव, अपने धुगरवादी दृष्टिकोणके अनुसंग वस्तु-ओंसे परिवर्तित करनेके लिये, इस आक्रमणसे बड़ा चतकर दिखना रहे हैं, जिससे समाजवादी राज्य निर्माण और उसे साम्यवादमें परिवर्तित करने विषयक स्टालिन नीतिमें सदेह उत्पन्न हो जाय।

सौ हा द ता का प्र सा र

साथ ही ऐसा दावा करनेवाले लोगों में भी कमी नहीं है, जो कहते हैं कि इस आक्रमणका लक्ष्य विशुद्धरूपसे स्टालिनके व्यक्तिगत गुणों की आलोचना है, कोई वास्तविक सुधार नहीं सोचा जा रहा है क्योंकि चौथी और पाँचवीं दशकियों में ऐसी विशेष परिस्थितियों विद्यमान थीं जिनके कारण पार्टी लोकतंत्र की अवहेलना सम्भव हो सकी। ऐसे भी तत्व विद्यमान हैं जो किसी परिवर्तनके अस्तित्वको स्वीकार ही नहीं करते। वे यह सिद्धान्त प्रेषित करते हैं कि लोगोंको विश्वास दिलानेके लिये सोवियत नेताओंने सनारके सामने एक नया रूप उपस्थित करनेका निश्चय किया है। जिनके लिये दोष सहज रूपमें स्टालिनके मल्ये मग्न जा रहा है। इसमें बहुत बड़ा सन्नम है, क्योंकि अभी पूर्णकथाना भेद खुलना बाकी है। विदेशों में स्थित साम्यवादी नेताओं की प्रतिक्रिया में यह सन्नम स्पष्ट रूपमें दिखलाई पड़ता है। बोसवीं कांग्रेसके समय सार्वजनिक रूपसे होनेवाली स्टालिन विषयक परिशुद्धियोंको उन्होंने स्वीकार कर लिया, किन्तु जब पुरचेवका गोपनीय प्रतिवेदन उन्हें मिला तो उनकी प्रतिक्रिया क्रोध और कटुतापूर्ण थी। उन्होंने यह दावा किया कि यह वचन्य स्टालिनवाद की मार्क्सवाद की व्याख्या नहीं है, उनका कहना था कि सोवियत साम्यवादियों ने इस परिवर्तन की प्रष्टभूमि में स्थित कारणों का स्पष्टीकरण करना चाहिये और प्रत्येक मतवैपरीत्य को केवल ध्वन और श्याम में देखने की सुपरिचिन और नैपश्यपूर्ण प्रवृत्ति को समाप्त कर देना चाहिये।

इटली के लोग्लियहीने पार्टी संगठन, मम्मिलिन अपराध, एक सिद्धान्तके परिणामस्वरूप दूसरे में पहुँचना तथा सोवियत पार्टी को होनेवाली अपूर्व हानि-विषयक मौलिक प्रश्न खड़े किये। फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका में स्थित पार्टियों की विचारधारा की भी यही दिशा थी। यदि इस विषय में भारतीय पार्टी डिलमेल थी और नेहरू पर मनमन्त्र सप्रशक्तादरा दोषारोपण किया था, तो उसका कारण यही था कि उसका सैद्धांतिक स्तर सदैवसे नीचा रहा था तथा पश्चिमी देशों के साम्यवादी-यों की तरह उसे विकसित पूँजीजीवियों के भारी बौद्धिक आक्रमणका कभी सामना नहीं करना पड़ा था।

अंततोगत्वा यह कहा जा सकता है कि यदि भारतीय नेतृत्व में नहीं तो कबसे कब सनार भर में विशेषरूपसे चीन एवं अन्य समाजवादी राज्यों में जहाँ अनेक अंशों में

स्यालिनयुगकी भूलोंका आवर्तन हुआ था, साम्यवादी नीतिका पुनरावलोकन हो रहा है। विभिन्न दृष्टिकोण व्यक्त किये जा रहे हैं, क्योंकि विरोधी समस्यार्थे एकमात्र 'सम्यक्वादमे' आगे निकल जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय वादविषयक विचार, साम्यवादी पार्टीयोंके पारस्परिक सम्बन्धका रूप, जनगणतन्त्र राज्योंमें विभिन्न वर्गोंकी स्थिति तथा मार्क्सवादसे अन्य सम्बंधित सिद्धान्तोंको लेकर भीषण तर्कवितर्क हो रहा है। इसका उत्तर आमानीसे नहीं मिल सकता। टीटोवादी यूगोस्लाविया भी इसका आदर्श प्रतिमान नहीं बन सकता। सम्भवतया भूतकालीन नीतियोंको सुधारनेमें अनेक अशुद्धियों हो जायेंगी, लेकिन इन कष्टोंके उपरांत प्रकट होनेवाला समाजवाद अधिक स्वस्थ और शक्तिशाली होगा।

साम्यवादी पार्टी और उसके नेताओंका उपश्रम करना, जिनके मनोरञ्जनका साधन है ऐमे 'मैंने तुमसे यही कहा था' दलके लोगोंका कुप्रयत्न भी करणान्वय है। वे समारथे कुछ सुंदरतम मस्तिष्कोंकी स्यालिनके भुनावेका शिवार हो जानेके कारण उनकी निन्दा करनेसे नहीं चूकते। उनका कहना है कि सोवियत कूटनीतिके दशारों पर चलनेवाले ऐमे लोग स्वयं गद्देमें उतर चुके हैं और कभी अपनी प्रमिष्टा पुन स्थापित नहीं कर सकेंगे।

यदि पहलेमे अधिक बड़े अंशके लिये यह दोषारोपण स्वीकार्य भी हो, तो भी सत्य इसके पूर्ण भिन्न ही है। कोई भी साम्यवादी सोवियत सभ्य प्रशंसा और आदर तथा गणना इस कारण नहीं करता कि वह किसी तरहका कपटी पंचम दलीय है, बरन इसलिये कि उसका विश्वास है कि स्वयं कम्युनिस्ट पार्टीका संगठन एवं उसकी परंपरा प्रज्ञानत्र और स्वतंत्रताके दुरुपयोग के विरुद्ध एक मात्र बीमा है। अन्धन निष्ठावान नागरिकों द्वारा निर्मित जनताकी पार्टीमें स्पष्ट विचारविमर्श और निष्पक्ष चुनावोंको सम्भवतया अवच्छेद नहीं किया जा सकता। दुरुपयोग अवश्य होगा, परन्तु अस्थाधी और उसी सीमा तक जिन सीमा तक कि पार्टीसदस्य उदासीन रहेंगे।

इसके अतिरिक्त पार्टी संगठन, अनुशासन एवं गोपनीयताके यह सिद्धान्त सभ्य, क्रांति और निर्माणवाक्यक प्रयत्नोंकी परीक्षामें खरे उतर चुके हैं। यदि मुस्कदमे और शोधन (पर्व) प्रक्रियामें चालू हुई तो उनके प्रति रोक प्रदर्शित किया गया,

सौ द्वा द्वा ता का प्र सार

किन्तु वह आवश्यक थे। इस प्रकार सार्वजनिक उन्नतिके हितमें व्यक्तिगत अवरोधों को दूर किया गया। और प्रगति नाटकीय, प्रेरणात्मक एवं प्रामाणिक आवश्यक रूपसे बहों हुई थी।

इस नीतिके कुछ रूपों को बहुतसे लोग अच्छी तरह नहीं समझ सके; जैसे प्रसिद्ध क्रांतिकारियोंका शारीरिक नित्यारण, सुपरिचित व्यक्तियोंका आत्मिक अलोपन, भिन्न मन प्रदर्शित करनेका साहम करनेवालोंके प्रति अधिक संदेह और अविश्वास, कठोर आदर्श अपनानेके लिये कलात्मक प्रयत्नोंका गला घोटना, इतिहासके पुनर्लेखनकी प्रवृत्ति, और उमे उतरनेका प्रयत्न आदि विरवसांप्राज्यवादके वर्तमानपूर्ण आक्रमणोंमें समाजवादके गढ़को सुरक्षित करनेके लिये इन सभी बातों पर तथा इसके अतिरिक्त अनेक बातोंपर विचार किया गया।

यद्यपि सोवियत संघको इन प्रक्रियाओंने अनेक बहुमूल्य साधियोंको खो दिया, परंतु साम्यवादी आंदोलन फैलता गया और हर जगह लाखों आदमी इसे स्वीकार करते गये। समाजवादी दुनियामें साम्यवादके सादस और ईमानदारीपर विश्वास प्रकट किया जाने लगा। लोगोंकी यह दृढ़ धारणा थी कि पूँजीजीवी समाचारपत्रोंमें जिन अपराधोंका उन्हें उल्लेख था, उसमें उन्होंने भाग नहीं लिया होगा।

किन्तु उनका यह विश्वास गलत था। विवेकको त्याग दिया गया था। वास्तविकता यह थी कि सोवियत पार्टीसंगठन एक व्यक्तिके इशारेपर गलत या सही उसीके उद्देश्योंकी पूर्तिमें बराबर लगा हुआ था। अत्याचारोंने किसी समय निडर समझे जानेवाले व्यक्तियोंको भी शांत कर दिया था। प्रमुख प्रश्न यह है कि यह सब कैसे सम्भव हुआ।

पार्टीसंगठनके नियम लेनिनने बनाये थे। उनका यह विश्वास था कि सबसे अधिक अनुशासित और निश्चयान राजनैतिक सतरी अर्थके रूपमें साम्यवादी पार्टीको संगठित किये बिना मजदूर राज्यकी स्थापना अशक्य है। उन्होंने 'प्रजातांत्रिक केन्द्रीयवाद' का सिद्धान्त निरस्त, जिसके अनुसार सभी प्रवृत्तियोंपर पार्टीके अंदर ही संतुलन करके वैज्ञानिक एवं बुद्धिसम्मत नीति निर्धारित करनेकी आज्ञा थी,

किन्तु सभीमें यह अपेक्षा की जाती थी कि वे बहुमत द्वारा निर्धारित निर्णयों पर इमानदारीमें पालन करें। पार्टीके विषय गोपनीय समझे जाते थे। भयंकर सपर्षके दरम्यान किसी राज्यको जीत कर वहाँ पर सत्तारके मजदूरोंको प्रेरणा देने योग्य समाजवादी टाचेको परिपुष्ट करते समय ऐसा करना जरूरी भी था। यही कारण है कि वहाँ लौहवत अनुशासन चालू था।

इतना होते हुए भी शताब्दीके मोड़के समय ट्रॉट्स्की और प्लेखेनोव सरीखे अनेक नेताओंने लेनिनके पार्टी संगठन विषयक दृष्टिकोणके विरुद्ध चेतावनी देते हुए यह कहा कि हमका परिणाम एक व्यापक शासन होगा, किन्तु लेनिनके वाक्योंमें ही सार्यक समझ गया। पार्टीके आन्तरिक जनतंत्रके यह स्वयं बहुत उत्साही अभिभावक थे और बहुमत द्वारा निर्णित नीतियोंके अनुरूप आचरण करते समय सदैव विरोधी अल्पमतको अपने साथ ले लिया करते थे। जारशाहीका अंत हुआ। लेनिनकी पार्टीने अपनी सार्यकता प्रमाणित कर दी थी।

क्रांतिके प्रथम वर्षोंने निर्बाध कीर्तिपूर्ण स्वतंत्रोदयके दर्शन दिये। यह सनस्त नवजात मजदूर राज्य लगभग प्रत्येक क्षेत्रमें मनुष्यकी प्रगति का अग्रवर्ती परीक्षक बन गया। किन्तु लेनिन यह देखनेके लिये जीवित न रह पाये कि सत्ताहेतु सपर्ष करनेवाली पार्टीके लिये उन्होंने जो नियम और आचरण निर्धारित किये थे, वे राज्यके ऊपर पूर्ण अधिकार स्थापित करनेके उपरांत भी पार्टीके लिये उनमें ही उपयोगी हैं या नहीं। वे इसके लिये बहुत चिंतित थे, यह बात ३० वर्ष उपरांत खुद्वेव द्वारा उनके अंतिम मृत्युलेखको प्रकट करनेसे ज्ञात हुई है।

साम्यवादका विवेचन करते समय सोवियत साम्यवादी अब यह दावा करते हैं कि यह वर्ष १९३४ में ही शरभ हो गया था। फिर भी १० साल से अधिक पूर्व लिखे लेनिनके मृत्युलेख एवं पत्रोंको छिपानेकी घटना ही पार्टीके आन्तरिक जनतंत्रके अंतर्गत प्रारम्भ था। यह प्रतिलेख पार्टीके कार्यकर्ताओंको भी नहीं दिखलाये गये थे। आगे चलकर उनके अस्तित्वके दावेकी भी झूठी बात कह कर उपेक्षा कर दी गई। यह तर्क किया जा सकता है कि किसी पार्टीके लिये मृतक नेताके आदेशों पर पालन करना आवश्यक नहीं है, किन्तु उनके छिपानेके प्रयत्नको तो अच्छा नहीं कहा जा सकता।

सौ हा दृ ता का प्र सार

उस समय क्या हुआ यह बात अब सर्वसाधारणकी जानकारीमें है। व्यक्तिगत रूपसे स्तालिनको दोषी ठहराना, यह दावा करना कि उनकी अप्रतिष्ठित शक्तियों काढ़-ने ही पार्टीको बदनाम कर दिया था, यह मुमकिन देना कि उन्हें जनता द्वारा प्रशस्ति नीतियोंके निर्धारक प्रकट करनेमें भूल हो गई थी (ऐसी भूल जिनके कारण वे भविष्यमें अपनी निर्द्वंद्व स्थितिअ प्रयोग स्वस्थ विरोधको अलक्षित करनेमें कर सके), यह पवित्र आशा व्यक्त करना कि यह बात भविष्यमें नहीं होगी, क्योंकि पार्टीके आंतरिक जनतंत्रको पुनर्स्थापना हो चुकी है, वस्तुतः मार्क्सविषयक स्तालिनवादी विचारोंका हास्यास्पद स्वरूप है।

अब यह स्वीकार किया जाना है कि सिद्धान्त और कार्यक्रम ऐसा प्रक्षेपण केवल सोवियत संघमें ही नहीं बरन राजमत्त धारण करनेवालों अन्य पार्टियोंमें भी प्रकट हुआ था। इसके अतिरिक्त पूँजीवादी संसारमें सघर्षरत अनेक साम्यवादी पार्टियोंके नाशका मूलकारण भी यही सप्रदायवाद था और इसमें भारत भी सम्मिलित है। क्योंकि भारतीय साम्यवादी नेता कुछ भी कहें किन्तु वास्तविकता यह है कि भारतीय साम्यवादी पार्टीका इतिहास भी गुटसंघर्ष और वैयक्तिक भगवोंसे परिपूर्ण है। इन्होंने पार्टी जनतंत्रका मखौल कर रखा था तथा एक ओर सुंदर साठसी सदस्यता-को उदासीन एवं बिचित्र कर दिया था। परिस्थितिअ यही रूप है जिसने पूर्णतया बदनाम नेताओंको शक्तिशाली बने रहनेमें सहायता दी है। ऐसी स्थितिमें यदि वे सोवियत संघके अनुभवसे उपयुक्त शिक्षा ग्रहण करनेका विशेष प्रयत्न नहीं करते तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं है।

वस्तुस्थिति यह है कि जनतंत्र समाजवादकी आत्मा है। अपने कार्यके प्रत्येक क्षेत्रमें साम्यवादी पार्टीको इस आदर्शके विकीर्ण करनेका प्रयत्न करना चाहिये। उन्हें नीतिके निर्धारण और पालन दोनोंमें सर्वसाधारणको पूर्ण रूपसे भाग लेनेके लिये प्रोत्साहित करना चाहिये। प्रारम्भमें आलोचना और स्व-आलोचना पर कोई रोक नहीं होनी चाहिये। उन्हें सदैव इस बात पर जोर रखना चाहिये कि पूँजीवादी जनतंत्रके विपरीत यहाँ पर सभी नागरिकोंको इस अधिकारका समान प्रयोग करनेका अवसर है। समाजवाद द्वारा उपदेशित आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता ऐसे आयुध हैं, जिनके द्वारा नवीन जनतंत्रका परिवर्धन एवं प्रसार होता है।

मौलिक संशोधन की आवश्यकता

सोवियत संघ और अन्य समाजवादी देशों में जो प्रयोग हुआ उसकी जड़े निकट पूर्वकालीन अवशेषों में ही नहीं जमी हैं, बरन कुछ दोरपूर्ण विद्वानों में भी निहित हैं, जिनके आधार पर इस नये समाजकी रचना हुई थी। महत्त्वपूर्ण स्थितियों में रहनेवाले लोगों से अब भी पूर्ववत् भारी मान दिया जाता है। अपने नाम के साथ सम्बंधित नीतियों की सफलता द्वारा उन्हें व्यक्तिपूजारी महत्त्व देनेवाली अविकर जनता की वैयक्तिक स्वाभिमुख प्रशंसा हो जाती है। समुचित प्रशंसा के सम्बन्धीन भक्तिकी अवस्थामें सम्पूर्ण अविकर दिखलाई नहीं पड़ता। इसके अतिरिक्त नौकरशाही शासन की परंपरा, वैयक्तिक पक्ष पर निर्भरता और गणियों तथा भूलों से द्विजाने की आवश्यकता से उन शक्तियों की गति मिल जाती है, जिनका अब एक व्यक्ति की या सामूहिक तानाशाही में होता है।

साम्यवादियों से इन प्रवृत्तियों में बचने के लिये सदैव सतर्क किया गया है, किन्तु इन चेतावनियों से उपयोग ही क्या है, जब कि पार्टी के संगठन में तथा समाजवादी सोसाइटी की स्वतंत्रता विषयक धारणों में निरक्षरवाद के बीज विद्यमान हैं।

यह कहना कि सम्यकवाद और उसके अवशेषों से पूरी तरह से बच किया जा चुका है और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, समस्या की उपेक्षा करना है। मार्क्सवाद ऐसे योग्य व्यक्तियों का निर्माण जारी रखेगा जो व्यक्तिगत संघर्ष के समझौते से ओरसे विरक्त होते हुए भी ऐसे विचारों से ललू करने का अविकर चाहेंगे, जिन्हें वे ठीक समझते हों। जनता का समर्थन प्राप्त होने पर उनके लिये अपने साथ मतभेद रखनेवाले समान योग्य व्यक्तियों के अपना दृष्टिकोण बदलने के लिये तैयार न होने पर अंत करना सरल कार्य होगा। यदि लेनिन ने विरोध के बावजूद भी अपने रहस्य अपने विचारों के समर्थक प्राप्त कर लिये तो इसका अर्थ यह नहीं कि स्थिति भी अपने ने मिल मत रखनेवाले व्यक्तियों के प्रति अपने ही सहनशील बने रहेंगे। सर्वद्वारा उन्हें स्थापित करने में असफल होने पर स्थिति ने आतंकवादी सहारा लिया। इसकी पुनरावृत्ति हो सकती है।

समाजवादी समाज की साम्यवादी पार्टियों अपने अंदर किसी बड़े या छोटे स्थिति के उदय से रोकने के लिये सस्थागत नियमों में मौलिक संशोधन की आवश्यकता समझते हैं। किन्तु संशोधन की यह प्रक्रिया निरिचल रूप में धीमी है।

सौ हा द्र ता का प्र सार

स्वतंत्रताके व्यक्त उल्लंघनोंको समाप्त किया जा रहा है । मुसद्मोंको पवित्रता-को पुनः स्थापित किया जा रहा है । समाजवादी जनतंत्र और उसके व्यवहार-विषयक सही-पूर्ण धारणाओं पर उभर विवाद हो रहा है । कुछ पार्टियोंकी गति दूसरोंकी अपेक्षा अधिक तीव्र है, किन्तु मौलिक निद्वानोंमें आंतरिक संशोधनकी सम्भावना नहीं है । अनुभव द्वारा यह जोंच विसर्पणी होगी और नयी धारणाओंकी जन्म देगी ।

क्या पूँजीजीवियोंके निर्वाचनों और समझौतोंको एक साथ रद्द करना उचित होगा अथवा उनमें कुछ स्वीकारात्मक गुण हैं, जिनकी रक्षा करके उन्हें विह्वलित किया जा सकता है ? क्या साम्यवादी पार्टी राष्ट्रीय हितकी समस्याओं पर गुप्त रूपसे विवाद करके निश्चित करनेकी प्रणाली जारी रख कर पार्टीके बाहरवाली जनताको विपरीत प्रवृत्तियोंको स्वयं समझ कर निर्णय करनेके अवसरसे वंचित करना जारी रख सकती है ? क्या पार्टी संसदको सदैव किसी नीतिविषयक विरोधके जनताके सामने प्रकट करनेमें रोक रूनी चाहिये और क्या उसे अपने दृष्टिकोणको उस समय भी प्रचारित करनेकी स्वतंत्रता हो सकती है, जब कि बहुमतमें निर्णय इस विधानके विरुद्ध हो ? क्या समाजवादी वैधानिक न्यायविभागकी पूर्ण स्वतंत्रता आवश्यक सम्झनी है और यह कैसे प्राप्त की जा सकती है ? क्या जनताको सम्बंधित मामूहिक संगठनोंके द्वारा ही अपने अनुमोदन और अनुमोदनको व्यक्त करना चाहिये और क्या किसी संगठनको ऐसे दृष्टिकोणको प्रचारित करनेमें अधिकार है, जो निर्धारित नीतिके विरुद्ध हो ? क्या लेखकों, कलाकारों और गायकोंको यह बनलाना आवश्यक है कि उन्हें क्या लिखना या क्या प्रदर्शित करना चाहिये या लोगोंको उन्हें संरक्षण देनेकी स्वतंत्रता रहनी चाहिये ? प्रसिद्ध व्यक्तियोंद्वारा निर्मित समितियोंका शासन लोक-तांत्रिक कैसे हो सकता है जब कि समितियों स्वयं निहित स्वायत्ती पोषक बन सकती हैं ? नैतिकप्रवृत्ति अर्थशास्त्रोंके शासनको रोकनेके लिये आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक संगठनोंका विकेंद्रीकरण किस सीमा तक होना चाहिये, जिनमें विभिन्न क्षेत्रोंके कार्यक्रमोंकी नीति निश्चित प्राप्त अनुभवोंके द्वारा निर्धारित की जा सके ?

यह उन अनेक प्रश्नोंमेंसे कुछ हैं जिनपर विवाद हो रहा है । यह प्रश्न निरर्थक प्रतीत हो सकते हैं, किन्तु वास्तवमें ऐसे नहीं हैं । हम ऐसे समाजमें निवास करते हैं, जहाँ शक्ति आधिकारिक केन्द्रित करके विभिन्न दिमापी न्यायोंके हाथमें

सारी जा रही है। पूँजीजीवी छोटे प्रभावकारी उपचार प्रस्तुत करनेमें असमर्थ रहे हैं, क्योंकि पूँजीजीवी समाज मौलिक समानताओं अपसंचर करता है, जो प्रजातन्त्र एक मात्र आधार है। अतएव समाजवादी राज्यके सम्मुख यही प्रमुख धर्म है।

कुछ लोगोंका यह तर्क है कि राज्यधन और नौकरशाहीका इतना अधिक प्रसार करनेवाली और जन्मसे ही स्वतन्त्रताको हिंसा द्वारा नष्ट करनेवाली व्यवस्थाने ऐसे कार्य संपादनकी कल्पना करना भी बेकार है। वे इस बातसे भूत जाते हैं कि यदि पार्टीकी सोनाभोंने अपने भयंकर आतंकवादी कानूनों विद्यमान होना तो इतने शक्तिपूर्ण प्रयत्न सम्भव न हो सकते, जिनके द्वारा एक पिछड़ा हुआ समाजवादी देश कुछ दशान्दधियों ही आधुनिक औद्योगिक राज्य बन गया है।

सभी उपलब्ध प्रमाणोंने यह मालूम पड़ा है कि स्टालिनके डंगोंने तिरफे पार्टीको पूर्ण निर्माणवाक शक्तिके रूपमें ही अग्रसर कर दिया। यह सच है कि विन्ही क्षेत्रोंमें राष्ट्रीय अध्ययनका शारीरिक उत्प्रेदन हुआ, यहूदी संस्कृति पर प्रहार हुआ, पार्टीके बाहरी तत्वोंकी परेशानियों हुई और भय एवं सदेह चारों ओर व्याप्त था, किन्तु इन आतंकवादी प्रक्रियाओंने जनताकी अपेक्षा पार्टीकी अधिक हानि उत्पन्न पड़ी।

यदि ऐसा नहीं होता तो स्टालिनका नाम संविधान जनताकी एकताका प्रतीक नहीं बन पाता और न लोगोंको ऐसे अनिश्चित करनेके लिये विश्वास बिना जा सकता, जिन्हें विरोधी आलोचक भी महत्वपूर्ण एवं अविनाश मानते हैं। पुनः यदि वास्तविकता भिन्न होती तो क्षतिपूर्ण परिणामोंने निर्भव रहते हुए आत्मानिक साथ स्टालिनको हटाना सम्भव होता।

स्वतंत्र प्रेक्षक भी समाजवादी देशोंके अंदर नीतियोंको कार्यान्वित करनेमें जनताके सामूहिक सहयोगकी पुष्टि करते हैं। इसी सहयोगके मननानंद कार्य पूँजीवादी मन्त्रालयके प्रतिपादक नहीं दिखना सकते। इनके अतिरिक्त साम्राज्यवादी राष्ट्रोंमें जैसा आतंक फैला होगा है और उसकी तुलनामें समाजवादी देशोंका आतंक बहुत कम मालूम पड़ेगा।

सौ दा द्र ता का प्र सा र

साम्राज्यवादको कायम रखनेके लिये बितने लाख आदिमियोंको गुपचाप हनाल कर दिया गया ? ओटों पर स्वतन्त्रताके नारोंके साथ बितने हजार आदिमियोंको अब भी पश्चिमी दूरस्थ प्रदेशोंके मैनिबों द्वारा मीनके घाट उतारा जा रहा है ?

साम्राज्यवादियोंको बेरिया-विस्तरके साथ अंतिमरूपसे स्वदेश वापिस लौटानेके पहले बितने हजार आदिमियोंको अभी और नष्ट होना पड़ेगा ? यह प्रश्न पर्याप्त हैं। हम लाखों व्यक्तियोंकी तो गिनती ही नहीं कर रहे हैं, जिन्हें उपनिवेशोंमें बीमारियों और अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों के कारण नष्ट होना पड़ा या जो नष्ट हो रहे हैं।

समाजवादी देशोंने लोभनत्रको फलने-फूलनेका आधार प्रस्तुत कर दिया है और समाजवादी स्वतन्त्रताके क्षेत्रको विस्तीर्ण करनेवाला युग परिवर्तित होगा, जिसके फलस्वरूप जनमाधारणकी प्रज्ञा और निर्माणशक्त प्रयत्नोंपरमे बंधन हटते जायेंगे। हम बात पर सदेह करनेवाले व्यक्तियोंको एक महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार करना चाहिये, जिस पर अभी ध्यान नहीं दिया गया है। समजवादको आज प्रथम बार सगरकी एक व्यवस्थाके रूपमें स्वीकार कर लिया गया है, एक ऐसे समुदायके रूपमें जिसकी ओर मानवजाति अप्रसर हो रही है। दोष निरूपणके समस्त प्रयत्न भी इस तथ्यको नहीं छिपा सकते।

पूँजीवादकी अवनति हो रही है। वह अपने स्वयंके अंतर्विरोधोंमें डल रहा है। निर्धन व्यक्ति पूँजीका उत्पादन करते हैं, किन्तु अपेक्षाकृत दरिद्रतामें ही उन्हें जीवन-यापन करना पड़ता है। प्रमुख रूपमें जन्म और उत्तराधिकार द्वारा धन प्राप्त करनेवाले अधिक धनवान होते जाते हैं। जहाँ अंतर्विरोधोंको नहीं मुलभूत जा सकता, वहाँ तनावकी स्थिति पैदा हो जाती है। यद्यपि पूँजीवाद प्रत्येक संकटको दबानेके लिये समाजवादी विचारों द्वारा निर्धारित उपचारोंका प्रयोग कर रहा है, किन्तु फिर भी वे बढ़ते ही जायेंगे। मरुक्त राज्य अमेरिका कुछ भी कहे पर वह भी इस दबावका अनुभव कर रहा है और यह दबाव बढ़ता ही जायगा।

अभी अधिक दिन नहीं हुए जब एक व्यंगचित्रमें समाजवादी प्रतिपादकको एक अजीब मक्कीके रूपमें निराशाओंका गढ़ लादे दिसलाया गया था। वह लम्बे

वालोंका, बिना हजामत बिचे बुरो शकलवाला, चिन्तेन, अनराधो, क्रूर और उपयुक्त अवसरपर बड़ी बिचे जाने योग्य जानवर प्रतीत होता था। विद्वकी अधिकतर जनमुख्याकी समझमें अब ऐसी मूर्ति नहीं आ सकती। वे समाजवादी हैं और उन्हें इस मूर्तिके साथ कोई समानता नहीं दीय पड़नी। आजकल पूँजीवादके उपदेशगोष्ठो विचित्र प्राणी समझा जाता है। इतिहास गतिशील है। जीवनके मूल्य बदलते हैं। और सम्भव है, थोड़े दिनों परबान् ऐसे विचारकोंको डाकटरी विवेचन योग्य नमूने समझा जाने लगे।

वर्तमानकालका यह प्रमुख तथ्य है, ऐसा तथ्य जिसके कारण समाजवादी सम्बन्धो सप्रदायवाद, नौकरशाही और भ्रष्टाचारकी समस्याओंके साथ मन्त्रमुक्त करनेमें सहायता मिलनी है, क्योंकि उन्हें अब यह डर नहीं है कि पूँजीवादी विचारधाराको पुनर्जीवित करनेमें इच्छा रखनेवाले लोगों द्वारा इन क्षेत्रोंके परोक्षणोंका उनके विरुद्ध उपयोग किया जा सकता है। अंतिम विवेचनासे यह पता चलता है कि अनेक छोटे-बड़े देशोंमें समाजवादका आस्तित्व तथा भारत सरीखे देशोंमें नया समाजवादी प्रयोग इस बातकी एक नई गारंटी है कि समुचित दृष्टिकोण, गलतियोंको दूर करनेकी अविच्छा, कट्टर और अवैज्ञानिक दृष्टिकोण मरद्व नहीं बना रह सकता। क्या सोवियत संघके दुःखपूर्ण भयंकर और क्रूर अनुभवोंका अन्य समाजवादी सरकारों द्वारा शिक्षा ग्रहण करनेके उद्देश्यसे यथेष्ट ध्यानपूर्वक अध्ययन नहीं हो रहा है? यह भावना और सोवियत नेताओंकी स्वकीय आलोचना ऐसी बातें हैं, जिनसे उनके अनुभवोंकी शिक्षा ग्रहण करने चाहिये।

लेनिनकी शिक्षाओंकी ओर प्रतिभमन, निम्नार्थ अविधानपूर्ण वर्तमान वामपक्षी पार्टियोंमें एक बीरके स्थानपर दूसरेकी प्रतिष्ठा लगाया जाता है, साम्यवादी विचार और व्यवहारके मूल सिद्धान्तोंकी ओर वापसीका सूचक है। लेनिनका पुनर्अध्ययन करते समय, यदि उन्हें अनावश्यक रूपसे उद्धृत करनेका अपरिष्कृत दंग अग्रगण्य जाना है, तो यह मालूम पड़ेगा कि इन अतिम पद्यभ्रष्टाका कारण लेनिनके विचारोंकी पहलेसे पूर्णतया भिन्न युगमें अस्तित्व दुर्भाग्य है। स्वयं लेनिनवादके मूलमें पहुँचकर सामाजिक प्रगतिके प्रति मानसवादी दृष्टिकोणके पुनर्निर्धारणका और इसके उपरान्त उसमें संशोधन करके निर्माणानक सुधार

सौ हा द्र ता का प्र सा र

करनेका एकमात्र विवेकपूर्ण मार्ग है। यदि सगठन-विषयक दोषपूर्ण विचारोंको खारज करनेके लिये लेनिनको उद्धृत किया जाता है, तो इस बातको सहन नहीं किया जा सकता। इसकी उपमा स्वोक्त्यर्थ होनेके लिये स्टालिनको उद्धृत करनेमें दी जा सकती है।

स्पष्टतः भारतीय नेहरूने इस बार भी इस ऐतिहासिक विकासको समझनेकी प्रशंसा दिखलाई है। बीमवीं बेयिमके निर्णय समारकी समस्याओंपर क्या प्रभाव डाल सकते हैं, इस बातको अच्छी तरह समझनेके पश्चात् नेहरूने सोवियत नेताओंके साहसी कार्यमें समर्थन प्राप्त करनेके लिये राजनैतिक स्तर एक निश्चयात्मक अंतर्राष्ट्रीय अभियान आरम्भ कर दिया है।

वे राष्ट्रमंडलके राजनीतिज्ञोंमें इस अभियानको सफलतापूर्वक चला रहे हैं और उन्हें यह बात माननेपर विवश कर रहे हैं कि सोवियत व्यवस्थाको 'उदार' बनानेके लिये महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय कदम उठाये गये हैं। यह स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिकाके विरुद्ध है। वे सभी लोगोंमें इस विषयपर बातचीत कर रहे हैं तथा उन पर सोवियत सचके प्रति अपना दृष्टिकोण बदलनेके लिये जोर डाल रहे हैं।

सोवियत युव तथा शोष समाजवादी ससारमें होनेवाली यह प्रगति नेहरूको उन देशोंके तथा भारतके मध्यस्थित अन्यत्र गम्भीर मनभेदोंको दूर करनेके प्रयत्नोंका प्रतिनिधित्व करती मालूम पड़ती है। उनका विचार सदैव यही रहा है कि साम्यवादके ढंग ही बुरे हैं अर्थात् अपेक्षित 'तत्त्व' को प्राप्त करनेके वे 'तरीके' जिनकी विवेकपूर्ण युक्तयुक्तता वे नहीं बतला सकते। नेहरूके विचारोंमें अब भारी परिवर्तन हो गया है। अब वे अपने देशके करोड़ों व्यक्तियोंके ही नहीं बरन समार भरके उन करोड़ों व्यक्तियोंके भी प्रतिनिधि हैं, जो विश्वमें समाजवादी युग लानेके लिये किसी दिन साम्यवादियोंमें संयुक्त हो जायेंगे।

इस समय भी जब कि यह पक्षियों लिखी जा रही है, अब तक विरोधी समझे जानेवाले वामपक्षियों और साम्यवादी पार्टियोंमें अर्थात् अविकल्पक कटु शत्रुओंमें समझौतेकी बात-चीत जारी है। सभी देशोंमें यह सामान्य दृश्य है। प्रभाव और शक्तिसे पूर्ण ऐसे भी अनेक आदमी हो सकते हैं, जो इन प्रशक्तियोंका विरोध करेंगे,

सौ ह्यद्र ता का ना रा 'पंचशील'

क्योंकि वे हममें अपने वर्गयुक्त समाजके लिये एक खतरा देखते हैं, किन्तु हम सौहार्द्रताका प्रचार होता ही जायगा ।

'पंचशील' ये दो भारतीय शब्द जिन्हें नेहरू-बू घोषणाके समय उसाके साथ निरर्थक बहकर टाल दिया गया था, आज सौहार्द्रताका नारा बन गये हैं । यही दो शब्द सदैवके लिये अंतर्राष्ट्रीय वचनानी शब्दावलीमें सम्मिलित कर लिये गये हैं । हमें यह देखना चाहिये कि वे समाजको इतने मार्थक क्यों दीखते हैं ।

पंचशील क्यों ?

जलने अंगारोंकी एक बँदल आई, जियमें मृनक्षोंका रक्त और
अस्थियाँ मिली हुई थीं। धुएँ और विलक्षण लपटोंने उनकी
आमाको दरा दिया। आकाश गर्दमकी खालके समान धूमिल
हो रहा था। —

—कालीदाम

क्याइली मनुष्योंमें हजारों बंधे पहले रहनेवाले पूर्वजानीन मनुष्योंके सामने
अगम या पेदरी छानकर लिपकर अपने विचार व्यक्त करना सीखनेमें पहले भी,
सदैव यही प्रमुख प्रश्न रहा होगा कि क्या वे अपने माथियोंके साथ शान्तिपूर्वक
रहकर जीवन-यापन कर सकते हैं ?

अनेकों राज्यादियोंमें तद्विपरक तर्कों और अनुमानोंकी गूँज रही है। पूर्व-
जानीन अनुभवोंके आधारपर अधिकतर दार्शनिक और इतिहासकार इस निराशापूर्ण
निर्णयपर पहुँचे हैं कि मनुष्यकी प्रकृति ही उसे अन्यायकी बननेपर विवश करती
है। दूसरे लोगोंने अधिक आशापूर्ण दृष्टिकोण अपनाया, किन्तु उनकी सख्ता कम
थी और वे यह हद विश्वास भी उत्पन्न न कर सके, क्योंकि भूल और वर्तमान
जानीन प्रमाण उनके दृष्टिकोणको निरर्थक सिद्ध करते थे।

भिन्न भिन्न राजनैतिक व्यवस्थावाले देशोंके शान्तिपूर्ण सहस्रमन्त्रिका प्रश्न तो
दरअमन कभी उत्पन्न नहीं था। इसका प्रमुख कारण यह था कि घोड़ेने अक्वनोंको छोड़कर
माद-माथ रहनेवाले अनेक संगठित मनुष्योंकी सामाजिक व्यवस्थामें सदैव लगभग
मनामता रही। स्वतंत्र कुपकों, गुलाम-धारियों, कुलीन तंत्रियों और मामलोंके अनेक
समुदाय बने और गिरे। फिर पूँजीवाद आया और उसके परिवर्द्धित रूपके सामने
अधिकतर विचारोंके कारण पुगनी व्यवस्थाओंको घुटने टेकने पड़े। प्रथम पूँजीवादी
राज्य १७ वीं शताब्दीके परमान् सामन्तवादी राज्योंके साथ बाजार और कच्चे
मालके निचे बुद्ध करने लगे। आगे चलकर उन्नीसवीं शताब्दीमें विश्वको परस्पर

विभाजित करनेके प्रयत्नको लेकर उनमें आपसमें युद्ध हुए। इनमें एशिया और अफ्रीकाके सार्वभौमिकतावादी राष्ट्रोंपर प्रभुत्व स्थापित करना अंतर्निहित था, क्योंकि यह स्थान सास्ते अन्न और कच्चे मालके माधन थे। यह परस्पर लूट थी और साथ ही साम्राज्यवादी युद्ध उद्भव था।

इस संपूर्ण अर्थजिने कभी इभी शान्तिवा भी शासन रहा, किन्तु इस शान्तिमें प्रवृत्त अर्थजिने समारकी अन्य दालनों पर विजय प्राप्त करनेमें पूर्व ‘विश्वमन्न’ या ‘सोम लेने’ के अर्थुस्थ थी। आजकल जिसे सहस्रास्तित्व कहते हैं, यह समस्त तो उन दिनों विवादके लिये भी नहीं थी। सम्भवतया आधुनिकीयक दृष्टिके समान बेटवारके प्रयत्न पर ही लोकोय ध्यान केंद्रित था।

किन्तु समाजवादी आशोकनके प्रसार और समुक्त सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक नामक मजदूरोंके प्रथम राज्यके अभ्युदयके साथ ही इस परिस्थितिमें आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। अपने विस्तृत साम्राज्योंपर अधिभूत पूँजीवादी राष्ट्रोंने समाजवादके अभ्युदयमें अपने अमीमित लाभके मायनोंके लिये एक मजबूत उत्तरेके दर्शन लिये।

तथा छोटे-मोटे पारस्परिक ज्ञानी समस्त शक्तिकी एकीकृत करके, अंतर्गतोंके मिटाकर साम्राज्यवादियोंने मजदूर राज्यको नष्ट करनेका प्रयत्न किया, जिसे वे समाजवादरूपी नासूरका केन्द्र समझने थे। इसके विरुद्ध समाजवादने सर्वमाधारणको औपनिवेशिक और पूँजीवादी दासतामें मुक्ति दिलानेके लिये निरंतरताके साथ अपना लक्ष्य ‘साम्राज्यवादका अंत’ घोषित कर दिया।

दो मिदान, जिनमें एक पुरानी और लूटने बनी थी तथा दूसरी नई और ओपसी थी, परस्पर टकरानेके लिये आगे बढ़ रहे थे। परिणामस्वरूप जो तनाव उत्पन्न हुआ उससे समस्त विश्व प्रभावित हो गया। अंगरेजे, तीमरे और चास्कीसर्वे कपोस इतिहास भी इसी नारी सचपैकी कहानी बतलाता है। यही सचपै अन्न तक जारी है। सहस्रास्तित्वके द्वारा श्मीके रूपपरिवर्तनका प्रयत्न हो रहा है।

यह कैसे सम्भव हुआ जब कि ये दोनों मिदान अन्न भी एक दूसरेके विरुद्ध सचपैरत हैं? यह बात आत्मानोने समझी जा सकती है। भविष्यमें युद्धको स्थानीयकरण करने या किनी अन्य क्षेत्रोंमें सीमित करनेकी वस्तु नहीं

पंच शील क्यों ?

समझा जा सकता। आणविक और उद्‌जन रासायनिक विस्तार के साथ युद्ध का स्वर ही परिवर्तित हो गया है।

आणविक और उद्‌जन युद्ध कहीं भी हो, विन्तु वह समस्त समारको रेडियो सक्रियता के परिणामस्वरूप होनेवाले कश्चों में आच्छादित कर देगा। समाचारपत्र प्रतिदिन हमें यह बतलाते हैं, कि क्या हो सकता है। बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता आदि तत्स्थ नगर किसी अन्य स्थान पर होनेवाले आणविक युद्ध द्वारा नष्टानाबूढ़ होनेमें बच सकते हैं, विन्तु रेडियो सक्रियता रूपी विष के शिकार तो हो ही जायेंगे, जिसके पूर्ण प्रभाव अभी विज्ञान हमें नहीं बतला सका है।

दूरे राज्यों में, सर्वनाशी अथवा प्रत्येक जीवित मानव के लिये विनाश कारण बन गये हैं, क्योंकि वे राष्ट्रों और सिद्धान्तों के अंतर नहीं समझते। इन मध्य शताब्दी का यह महत्वपूर्ण तथ्य है।

आइये, उन थोड़ी-सी बातों पर विचार कर लें, जिन पर स्वयं वैज्ञानिक सहमत हैं। अधिकतर लोगों का यही विचार है कि आणविक और उद्‌जन आधुनिक युद्ध तक जो १०० छोटे-मोटे परीक्षण सोवियत संघ, प्रशांत महासागर और संयुक्त राज्य अमेरिका में हुए हैं, उन्होंने समस्त समारको भयंकर रेडियो सक्रियता से आच्छादित कर दिया है। मानवजाति और वनस्पति जीवन पर उनके प्रभाव का अनुमान लगाने में अभी अनेक दशाब्दियों लगेंगी। सम्भवतया अमेरिका महाद्वीप सबने अधिक अरुचिन हैं, क्योंकि प्रशान्त महासागरीय द्वीपों के लिये अरुचिन भयंकर विस्फोटों के अतिरिक्त यहीं पर अधिकतर परीक्षणालम्भ विस्फोट हुए हैं। अब यह धारणा बल प्राप्त करती जा रही है कि उन्होंने समस्त जीव-जगत को बड़ा भारी नुकसान पहुँचाया होगा। ऐसा नुकसान जिसे प्रारम्भ में खोजना सरल नहीं है।

इसकी शिक्षा स्पष्ट है। जीवधारियों की मौसमी एवं अन्य परिस्थितियों में होनेवाले परिवर्तन के अनुरूप बनने में हजारों वर्ष लग गये। यदि सूर्य के प्रकाश तथा जल एवं वायु की अंतर्वस्तु के अन्यत नाशुक अनुत्पन्न में कुछ हलचल होती है, तो उनके ऊपर आश्रित जीवों पर उनका असर पड़ना अनिवार्य है। एक बार हलचल होने के पश्चात् कोई आसानी से इस बात की भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि आगे क्या होगा। जैविक परिवर्तन होंगे जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है।

शांति - प्रयत्नों की आवश्यकता ॥

कुछ वैज्ञानिक जलवायु में सभी स्थानों पर स्पष्ट रूप से परिवर्तन होनेवाले परिवर्तनों को इंगित कर रहे हैं। यह परिवर्तन सम्भवतया मनुष्य निर्मित दैत्याकार विस्फोटों के परिणाम स्वरूप हुए हों, जिनके विषय में कहते हैं कि वे ऊपरी वायुमंडल में हलचल पैदा कर सकते हैं।

इस तनाव में सामान्य कभी आने के बावजूद भी आणविक और ठोस नभिकीय अनुसंधान के ऊपर गोपनीयता का आवरण चढ़ा हुआ है। इन पर भी उद्बुधन वम विस्फोटों के विषय में अब कुछ तथ्य उपलब्ध हो गये हैं। हम जानते हैं कि इन विस्फोटों पर कार्य करनेवाले वैज्ञानिक उनकी भौतिक शक्तों को देखकर स्तब्ध रह गये हैं। सेबिड के एक श्रम में ही विस्फोट के दरम्यान सूर्य के अंतरांगों के बराबर गर्मी उत्पन्न हो जाती है। इस सिद्धि की सम्भावना पर कुछ वर्षों पहले किसी को विश्वास न होता।

आणविक वैज्ञानिकों ने गणना करके अब यह दृष्टिकोण बना लिया है कि एक ही स्थल पर बारबार विस्फोट सम्भवतया इतनी अधिक रेडियो-सक्रियता उत्पन्न कर सकते हैं कि शायद पृथ्वी पर जीवन रहना भी असम्भव हो जाय। यह भी सच है कि इन सिद्धान्तों का समान योग्य वैज्ञानिक ही खंडन अथवा परिष्कार कर रहे हैं, किन्तु सभी लोग इस बात में सहमत हैं कि हम लोग ऐसे अग्रिमों से खेलना नहीं सह सकते, जिनकी शक्तों अभी तक न तो अच्छी तरह समझा जा सका हो और न उसकी गणना ही की जा सकी हो।

इस कारण मौलिक रूप से यह बात समझना अत्यंत आवश्यक है कि इन दिनों समार जिस संपर्क में देख रहा है, वह उन लोगों के बीच में है, जो व्याप्त अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को विचार-विमर्श करके तय करना चाहते हैं तथा दूसरे लोग जो इसका फैसला युद्धस्थल में करना चाहते हैं। अब यह संपर्क साम्यवाद और साम्यवाद विराधियों का संपर्क नहीं है। समार के दृष्टिकोण में यह परिवर्तन आणविक युद्ध के परिणामों की अच्छी तरह समझने के कारण सम्भव हो सका है। वस्तुतः साम्यवाद के कट्टर विरोधी भी शान्ति प्रयत्नों में सम्मिलित हो रहे हैं अथवा उन्हें सम्मिलित होने की आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं। २० वर्ष पहले यह वातावरण सम्भव नहीं हो सकता था।

पंचशील क्यों ?

जिस समय आणविकशक्तिपर सयुक्त राज्य अमेरिका ही एकाधिपत्य था, उस समय बंदूकबाजीमें प्रयत्न रहनेवाले एडमिरल और जनरल भी, जो युद्धके द्वारा साम्यवादियोंको नष्ट करनेपर तुले हुए थे, इन नये प्रत्यावर्तक मित्रीनोंके प्रयोगसे फिफक रहे थे। अब यह परिस्थिति और भी अधिक उलझ गई है, क्योंकि ऐसा कोई एकाधिपत्य शेष नहीं रह गया है तथा सोवियत विज्ञानने केवल इन्हीं पर दक्षता प्राप्त नहीं कर ली है, बल्कि आणविक अनुसंधानमें भी संसारमें आगे निकल गये हैं। इसने प्रथम उद्घाटन बमका विस्फोट किया है, एक ऐसा शस्त्र जिसकी विस्फोटक शक्ति अनेकों लाख टन टी० एन० टी० के बराबर है तथा जिसमें हीरोशिमा और नागासाकीको हिला देनेवाली आणविक प्रक्रियाको संकुचित कर दिया गया है।

इस कारण सभी लोग अब यह बात अच्छी तरह समझ गये हैं कि साम्यवाद या पूँजीवादसे मित्रोपर आक्रामक आणविक आभयान द्वारा विजय प्राप्त नहीं की जा सकती तथा इन दोनों सिद्धांतके समर्थकोंका सद्अस्तित्व आवश्यक है, क्योंकि इस समय इस बातकी कोई सम्भावना नहीं कि इनमेंसे कोई भी इस पृथ्वीको छोड़कर शून्यमें किसी अन्य नक्षत्रपर निवास करने चला जाय इन दोनोंसे साथ साथ एक दूसरेके पार्श्वमें रहते हुए लोगोंको यह निश्चय करनेकी स्वतंत्रता देनी पड़ेगी कि कौन-सी व्यवस्था उनके भविष्यका निर्माण करेगी।

इन बातकी स्वीकारता ही निरंतर विस्तृत होनेवाली शांतिकी भावनाओंका आधार है, जिसने युद्धके इच्छुकोंको पूरी तरह एकांगी बनानेका बीड़ा उठा लिया है। भारतने इस भावनाको विस्तीर्ण करने और उसे शक्तिपूर्ण बनानेका भारी प्रयत्न किया है। सयुक्तराज्य अमेरिकाके उच्चतम क्षेत्रोंमें भी यह दृष्टिकोण दिखलाई पड़ता है। महाशक्तियोंके निर्णयके लिये युद्धका टग लगानेके यह प्रथम चिन्ह हैं।

महाशक्तियों में भी हैं और हजारों। सयुक्तराज्य अमेरिका द्वारा जो साम्राज्यवादका एकमात्र आधार रह गया है, इनमेंसे प्रवेक्ष्यता मावधानोंके साथ पोषण किया जाता है, इस परिवर्तनको चित्तवे अमेरिका तथा उसके पृष्ठपोषक अन्य प्राचीन तर साम्राज्यवादोंके पारस्परिक तीव्र संबंधों और विरोधोंको आच्छादित कर रखा है। समाजवादी समारको मुंह करनेके प्रयत्न निष्क्रिय बना देते हैं।

इस मुद्दाके साथ-साथ प्रशासनिक उदारताने न केवल साम्राज्यवादी शक्तियोंके पारस्परिक तनावको अधिक उत्तेजित कर रखा है, वरन् कनालुमार स्वतंत्रता और मार्क्सवादिमिस्त्राके दर्शन करनेवाले एशिया और अफ्रीकाके पूर्वकालीन उपनिवेशोंकी भी स्थितिमें अधिक सुदृढ़ कर दिया है। साम्राज्यवादी दवावके मामले वे अब अपने आपको अरक्षित नहीं पाते हैं। अब उनमें भयाभिभूत नहीं किया जा सकता। इन क्षेत्रों और बाजारोंको साम्राज्यवादी दुनियोंके भाग बननेमें बचानेके लिये साम्राज्यवादको मखमली हुम्ननाशोंका प्रयोग करके देखना चाहिये।

भूभागोंपर शारीरिक अधिकार आजकल लाभप्रद टंग नहीं रह गया है, जिसके द्वारा साम्राज्यवाद समृद्धि प्राप्त कर सकता। भूकालमें इसमें लाभ प्राप्त हुआ था किन्तु अब वधोले दलित किया जानेवाला जनसमूह इसे सहन नहीं कर सकता। हिन्द चीन, मलाया, वीनिया और उत्तरी अफ्रीकाकी घटनाओंका साक्षात्कार कीजिये। यह सब उपनिवेशोंमें काममें लाये जानेवाले कीमतों दु माहमिक कार्य हैं, जिनकी अमपनना निश्चित है।

अब साम्राज्यवाद सरकारोंको पथभ्रष्ट करनेका पद्वेन रक्ता है, उनकी इच्छाका पालन करनेके लिये तैयार देशोंपर आत्योंकी बर्षा की जाती है। प्रथमिक रूपसे ऐसे कूटनीतिज्ञोंको खोज होती है जो अपनी शक्तिका दुष्ययोग करनेके लिये तैयार हों। उसके उपरान्त ऐसे व्यक्ति अपने देशकी सरकार बेचनेमें सहायता करते हैं। इस प्रकार जनताको भुलावेमें डालनेका प्रयत्न किया जाता है तथा सिंगमेदरी और च्याम-वाई-शोक सरीखे लोगोंको “स्वतंत्रताके कारण” में खाने आपकी उत्सर्जित कर देनेवाले जनप्रिय नेताओंके रूपमें प्रदर्शित किया जाता है। यह प्रक्रिया सस्ती है और कभी कभी प्रभावशाली प्रमाणित होती है, किन्तु फिर भी यह साम्राज्यवादी व्यवस्थामें परिस्थान सफ्ट (भारी अनुपातिक अंतरका सफ्ट) का समाधान नहीं कर पाती।

पूर्वकालीन औपनिवेशिक लोकके वामियोंको स्वतंत्रता, प्रजातन्त्र और प्रगतिके भावनात्मक रूपोंमें कोई आकर्षण नहीं है। उन्हें अन्न, रोजगार चाहिये और चाहिये उन्हें सुरक्षा। साम्राज्यवाद सहायता प्रस्तुत करता है, किन्तु ऐसी सहायता

पंचशील क्यों ?

नहीं जिनमें पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो सके, भारी उद्योग स्थापित हो अथवा इन क्षेत्रों में स्वावलम्बी बनने में सहायता मिले ।

इसके बदले में जो वस्तु प्रस्तुत की जाती है वह है रैनिफ सहायता, जो सहायता नहीं, बल्कि पूर्व अप्रयोज्य साधनों के ऊपर भारस्वरूप है । युद्धक विमानों और टैंकों से निर्मूल्य लेना भले ही आकर्षक प्रतीत हो, किन्तु उनकी देखभाल कीजें करेगा ? इस कार्य में भारी व्यय होता है और पूर्वसालीन औपनिवेशिक समारके किसी भी देश के पास इतने साधन नहीं हैं कि इस दो जानेवाली महायत्ना की परेश भी कर सकें ।

स्वभावतः साम्राज्यवाद एशिया और अफ्रीका वामियों को अपेक्षित सहायता प्रस्तुत करना असंभव समझता है । ऐसी सहायता के द्वारा पश्चिम के हाथ से उसके एशियाई बाजार निकल जायेंगे और फिर ऐसा कौनसा क्षेत्र बचेगा, जिसका उद्बोधन हो सके । फिर साम्राज्यवाद किसके ऊपर धनी और शक्तिपूर्ण बन सकेगा ?

इसके अतिरिक्त साम्राज्यवाद ने प्राप्त होनेवाली सहायता निजी क्षेत्रों में अर्थात् एकाधिपतियों के संगठनों से आती है । वे ऋण स्वरूप ऐसा धन देते हैं, जिसमें उनका सामान, यत्र और उनकी जानकारी विक्रय की जा सके । और वे विनियोजन की सुरक्षा, लाभकारी व्याज की दर तथा अधिकतर पक्षपातपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा करते हैं । ध्यान में देखने पर यही मालूम पड़ता है कि इन शर्तों का अर्थ राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का उत्कर्ष है, जिसे सहने के लिये नवस्वतंत्र जनता तैयार नहीं है ।

यह परिस्थिति ऐसे समय विद्यमान है जब कि समाजवादी समार, विशेष तौर पर सोवियतसंघ पिछड़े देशों द्वारा अपेक्षित राष्ट्र निर्मात्री सहायता देने की स्थिति में है । यह ऐसी सहायता है जो बिना किसी उपद्रव के पारस्परिक लाभ की शतापर प्राप्त हो जाती है । पुनः यह ऐसी सहायता है जिसकी तब तक सैकड़ों गुना बढ़ने की आशा है । जब तक कि युद्ध नहीं होता और अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्ध सहस्रान्तरिक के पौंच मिश्रणों द्वारा नियंत्रित होते रहते हैं ।

साम्राज्यवाद के लिये यह सम्भावना अत्यंत भयावह है । यदि पंचशील का आधिपत्य रहा तथा समाजवादी समार की वर्तमान गति में प्रगति होती रही, तो वह निश्चि

शीत युद्ध की नीति में परिवर्तन

भविष्यमें ही पिछड़े क्षेत्रोंकी आर्थिक उन्नतिके लिये अपेक्षित साधनोंको प्रस्तुत करनेमें समर्थ हो सकेगा। क्या साम्राज्यवाद आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रमें होनेवाले इस संघर्षमें बचकर जीवित रह सकता है ?

संयुक्त राज्यका परराष्ट्र विभाग इसका उत्तर इन्होंने प्रयत्नशील है। जनवरी १९५६ में ब्रसेलने अपने देशके राष्ट्रप्रीन प्रतिनिधिमंडल द्वारा उनके सामने प्रस्तुत किये हुए एक वक्तव्यको प्रकाशित किया था। उसमें कुछ स्पष्ट बातें कही गई थीं। उसमें लिखा था कि “वर्तमानकाल किमी दिन इतिहासमें साम्यवाद और स्वतंत्रताके मध्य होनेवाले संघर्षके महत्वपूर्ण परिवर्तन बिंदुके रूपमें मान्यता प्राप्त कर सकेगा। यह स्पष्ट रूपमें शीतयुद्धकी नीतिमें परिवर्तन प्रतीत होता है, जिसके अंदर आर्थिक और सामाजिक समस्याएँ सम्भुल आ गई हैं... इन नई परिस्थितियोंने सोवियत रणनीयतका प्रभाव देखा है। हम यह जानते थे कि सोवियत संघ संसारके दूसरे भागोंमें सैनिक तथा राजनैतिक अवरोधोंको प्रस्तुत करनेको आज हेतु आर्थिक और सामाजिक साधनोंका प्रयोग कर रहा है। इनके उदाहरण भारत, मिश्र और ब्रामा में देखे जा सकते हैं। ... हम अर्थव्यवस्था देशोंकी आर्थिक उन्नतिके क्षेत्रमें प्रतियोगिता कर रहे हैं, क्योंकि यह क्षेत्र प्रतियोगिता पूर्ण है। इस संघर्षमें हार उठनी ही भयंकर हो सकती है जिसकी शम्बीकरणकी दोषमें हार।”

यह उन लोगोंकी स्वीकारोक्ति है जिन्होंने ५०० खरब डॉलर मूल्यकी विदेशी सहायता जुलाई १९४५ से जून १९५५ तक अपनी नीतिके प्रतिष्ठित करनेके लिये व्यय की है और फिर भी अब यह सोचते हैं कि वहाँ हार न जायें। अजीब होते हुए भी यह बात सच है। इसकी व्याख्या हम तथ्यमें विद्यमान है कि युद्धोत्तरकालीन सहायता और कणका लगभग एकतिहाई भाग आर्थिकके स्थानपर सैनिक या तथा अमैनिफ सहायता और कणका लगभग ३।५ भाग पश्चिमी यूरोप और जापानके के विस्तृत देशोंको भेजा गया है।

अनुमान किया जाता है कि पिछड़े क्षेत्रोंको दी जानेवाली वास्तविक सहायता लगभग १० खरब डॉलर वार्षिक है तथा सोवियत संघ इस राशिकी प्रतियोगिता बड़ी सरलतासे कर सकता है।

पंचशील क्यों ?

जहाँ तक प्रविधिक सहायताका प्रश्न है, सोवियत संघ की स्थिति अधिक सुविधाजनक है, १९५२ में सोवियत संघ और संयुक्त राज्य दोनों में ३०,००० इंजीनियर स्नातक बने थे। किन्तु १९५५ में संयुक्त राज्य में २३,००० स्नातक बने जब कि सोवियत संघ में बनेवाले स्नातकों की संख्या ६५,००० हो गई।

शिक्षा के ढंग में अंतर का ज्ञान जिनमें यह बात संभव हो सकी, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लिये जानेवाला एक अन्य सर्वेक्षण में हुआ। इसमें यह मालूम पड़ा कि जून १९५५ में माध्यमिक स्कूलों द्वारा स्नातक बनाये जानेवाले दस लाख सोवियत विद्यार्थियों में से प्रत्येकने ५ वर्ष भौतिकशास्त्र, १ वर्ष नक्षत्रशास्त्र, ४ वर्ष रसायनशास्त्र, ५ वर्ष जीवविज्ञान, १० वर्ष रेखागणित, बीजगणित और त्रिकोणमित्र सहित गणित का अध्ययन किया था, जब कि “इस संख्या के लगभग एक तिहाई से भी कम अमेरिकन उच्च शालाओं में निकलनेवाले स्नातकों ने अधिक से अधिक १ वर्ष रसायनशास्त्र पढ़ा था।” यह आंकड़े इस बात के सूचक हैं कि आनेवाले वर्षों में जब पिछड़े क्षेत्र अपनी सहायता के लिये प्रविधिकों की खोज करते हों, तब क्या आशा की जा सकती है।

संयुक्त राज्य अमेरिकाने अब इस बात का अनुभव करना आरम्भ कर दिया है कि एशिया और अफ्रीका में की जानेवाली सोवियत सहायता की उपेक्षा नहीं की जा सकती। इस बात का पता सोवियत संघ की चालू छठी पंचवर्षीय योजना पर होनेवाली अलोचनाओं में लगता है। १६ जनवरी, १९५६ को प्रभावशाली पत्र “न्यूयार्क टाइम्स” में मास्को में चेलेज़ शीर्षक के महत्वपूर्ण संपादकीय लेख में यह व्यक्त किया गया था कि आर्थिक प्रतियोगिता अब अर्धविकसित देशों की जानेवाली सहायता के प्रश्न से भी आगे बढ़ गई है —

“अपनी छठी पंचवर्षीय योजना में ..मास्को यह प्रमाणित करने का प्रयत्न करता है कि उसकी सर्वांगीण आर्थिक व्यवस्था स्वतंत्र अर्धव्यवस्था को उत्पन्न कर सकती है। नयी योजना यह प्रदर्शित करने का प्रयत्न करती है कि “ऐतिहासिक समय के न्यूनतम भाग में शक्तिपूर्ण आर्थिक प्रतियोगिता करते समय सोवियत संघ अनेक विकसित पूँजीवादी देशों में विशेष तौर पर संयुक्त राज्य में होनेवाले प्रतिव्यक्ति

उत्पादनसे आगे बढ़ जाना चाहता है। सुतार भरके अविकसित देशोंमें बसने वाले करोड़ों व्यक्तियोंके मामले मारको यह प्रदर्शित करना चाहता है कि उनकी व्यवस्था न्यूनतम समयमें समृद्धिशाली भविष्य निर्माण कर डालनेका विश्वास दिला सकती है। सोवियत संघमारको समझनेके उपरान्त हमारे आर्थिक जीवनके प्रतिनिधियोंको यह जानना चाहिये कि यहाँ पर स्वयंसे निर्गत होनेवाली तीव्र प्रगति ही इसका एकमात्र उत्तर है।”

पूँजीवादका स्वर भय और घबराहटके कारण निश्चित रूपसे कापने लगा है, क्योंकि सैनिक उद्योगों पर आधारित साम्राज्यवादी देशोंकी अर्थव्यवस्थाके लिये शान्ति का अर्थ खतरा है। उनकी अभिरुद्धि अचानक है, क्योंकि यदि उन्हें भोजन स्वयं युद्ध नहीं मिलते तो उनको मिटना पड़ेगा।

इस नाशकी सीमाना रेखाओंको युद्धके भावों, और धूसे पर विश्वास करनेवाली कूटनीतिके संचालनसे धूमिल बनानेका प्रयत्न हो रहा है। किन्तु वाशिंगटनके रणनीतिज्ञ पंचशील युगके एक अन्य महत्वपूर्ण पहलूकी औरसे देखकर हैं, जिसका सुन्दर आधार इस तथ्यमें निहित है कि सैनिक टेक्नीकी नवीनतम प्रगतिके कारण संयुक्त राष्ट्रके युद्धास्त्र उद्योग ही निरर्थक हो जायेंगे, जिनपर उनकी समृद्धि निर्माण हुआ है।

इन विषयमें सम्बन्धित कुछ आधुनिक प्रतिवेदनों पर विचार कीजिये, संयुक्त राज्यके कुछ प्रसिद्ध पौजी आलोचकोंको यह विश्वास हो गया है कि समाजवादी देशोंके सैनिकव्ययमें भारी कमीकी घोषणाका कारण आणविक युगमें रिया जानेवाला सेनाओंके गठनमें परिवर्तन है। वे हमें बतलाते हैं कि सोवियत संघ एवं उसके साथियों ने ऐसे नये हथियार तैयार कर डाले हैं, जिन्हें इतनी विशाल बाहिनीकी आवश्यकता नहीं है। ‘प्रज्ञपात्र युद्ध’ शब्द इस नई रणनीति एवं उसके ढंगोंकी व्याख्याके लिये प्रयुक्त किया जाता है।

सोवियत संघने इस बातकी यद्यपि सरकारी पुष्टि नहीं की है, किन्तु ब्रिटेनमें होनेवाली मौननायक यात्राके दरम्यान सुरक्षेकी तत्विषयक ठीक महत्वपूर्ण हैं। ब्रिटिश समुदायी बेड़ेके प्रचलित नौविक अक्रमोंको सम्बोधित करते हुए

पंचशील क्यों ?

उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार आधुनिकीकरण कूजर बेचनेके लिये तैयार है, क्योंकि अब उनकी स्थिति यानी बाइक पोतोंके बराबर रह गई है।

बहु तर्कमम्मत बात है कि आणविक शक्ति युद्ध सन्धधी रुद्धिप्रस्त विचारोंको अस्तव्यस्त कर दालेगी, किन्तु हमने भी महत्वपूर्ण बात यह है कि समाजवादी सेनाओंने निफाले जानेवाले लाखों सैनिक बेकारोंकी सहाय नही बढ़ायेंगे, बरन उत्पादक कार्योंमें अपना स्थान ग्रहण करके समाजवादी सत्तारको एशिया और अफ्रिकाकी सहायताके लिये अधिक नई शक्ति प्रदान करेंगे। इन परिवर्तनोंको समाजवादी व्यवस्थामें बहुत अधिक प्रयोगमें आनेवाली स्वचालन सरीखी नवीन औद्योगिक टेक्निक्से सम्बन्धित करनेपर हम यह पाते हैं कि अर्थव्यवस्था क्षेत्रोंकी सहायता देनेकी सम्भावना कितनी अधिक है।

ऐसी सहायता देना सोवियत नीतिका मूलमंत्र है, जिसे प्रोलेटेरियन अंतर्राष्ट्रीयवादकी सला दी जाती है। लेनिनने समझाया भी था कि अमली अंतर्राष्ट्रीयवादमें राष्ट्रोंकी समानताकी औपचारिक स्वीकृतिसे भी कुछ अधिक की आवश्यकता है। समानताके सिद्धांतमें शक्तिपूर्ण राष्ट्रों द्वारा शक्तिहीन राष्ट्रोंकी आर्थिक और सांस्कृतिक विकासके लिए-अभावशाली सहायता भी सन्निहित है। आजकल समाजवादी दुनियामें इसी धारणाको अधिक प्रचारित किया जा रहा है। वहीँकि जनसमाजसे यह कहा जाना है कि एशिया और अफ्रीकाकी सहायता करना उनका कर्तव्य है। यह ऐसा दृष्टिकोण है जिसे समझनेकी आशा पूँजीवादी सत्तार कभी नहीं कर सकता।

निष्कर्ष रूपमें पंचशीलका अर्थ यह है कि खुशबूका 'मित्रताकी प्रतियोगता' का नारा अब अंतर्राष्ट्रीय कार्यमूची पर पहुँच गया है। इस प्रतियोगताके दो ढंग हैं-सोवियत ढंग और अमेरिकन ढंग। एशिया और अफ्रिकामें सोवियत ढंगकेही समर्थन और पक्षपात प्राप्त करनेकी आशा की जा सकती है।

हमका कारण हँदने के लिये अधिक दूर नहीं जाना पड़ेगा। सोवियत का राष्ट्रहित शान्तिमें, विश्वको परस्पर विरोधी शक्तियोंमें विभाजित न होनेकी बातपर जोर चलानेमें तथा इतिहास द्वारा यह निर्णित करने में निहित है कि कौन-सी व्यवस्था अन्यपर विजयी होती है। पूँजीवादी सत्तारके लिये हिनों के ऐसे संयुक्तीकरणको रोकना लगभग असम्भव होगा।

यह बात उस समय अपेक्षाकृत अधिक सम्भव है जब पंचशोलका बानावरण पूँजीवादी सभारको पंगुरारी मंदीकी संभावनासे संप्रभु कर रहा हो । निजी उद्योगोवाली अर्थव्यवस्थाके लिये उत्पादनकी अभिवृद्धि और मंदीके अनुभव नये नहीं हैं । और आजकल पूँजीवादी देश प्रमुखतया बालर भूमिमें घटनेवाली घटनाओं पर आधित हैं ।

सभी लोग इस बातसे महमत हैं कि यह अभिवृद्धि सदैव नहीं रह सकती । आधुनिकी दौड़को रोकना ही पड़ेगा । इसमें आत्मनाशके बीज विद्यमान हैं । संयुक्त राज्यके सरकारी मूत्र भी ' सतर्कता ' और निराशावादके परिणामस्वरूप उत्पन्न होनेवाली अवसादी (मंदी) प्रवृत्तियोंकी बात कहते हैं और जनताको बड़ी सरलतासे स्मरण दिखाने हैं कि " उत्पादन और कर्ममें समय-समय पर असंतुलन होना निश्चित है । "

दूसरे शब्दोंमें सहसा वृद्धिकी कम्हर मंदी द्वारा पूरी हो जाती है ।

जब यह बात मान ली गई है कि संयुक्तराज्य अमेरिकामें अभिवृद्धि उपस्थित करनेवाले बार कारण अर्थात् सैनिक व्यय, गृहनिर्माण, भारी उद्योगोंके धर्त्रोच्च परिवर्तन तथा मोटरों और गेजेटोंका विक्री हेतु उत्पादन, अपना चरम बिंदु पारकर चुके हैं । श्रमि, नौकानयन, नौकानिर्माण तथा अन्य पुगने उद्योगोंमें पहलेसे ही अवसन्नता आ गई है । यदि सुख नहीं होता तो यह पूर्व विवर्णित पूर्ण अभिवृद्धि कैसे जारी रह सकती है ?

पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाके इमवन् तरीको बदलनेके लिये संयुक्त राज्यों स्वराष्ट्रीय और परराष्ट्रीय नीतिमें महत्वपूर्ण परिवर्तनोंको करनेकी आवश्यकता पड़ेगी । इन दिनों कोई वास्तविक शक्ति इस लक्ष्य प्राप्तिऔ ओर अनुसुख नहीं प्रतीत होनी । रिपब्लिकन पार्टीकी पराजय और डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा शक्तिप्रदणके कारण आक्रामक रूपमें भले ही कमी आ जाय, किन्तु स्त्रजवेस्तीय मार्गोंओ अवरोधहीन नहीं किया जा सकता । संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके निवासी जिस जंगलमें फँस रहे हैं, उसमेंसे निकलनेका मार्ग केवल इसी नीति द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है ।

पंचशील क्यों ?

आज कल आणविक और प्रक्षेपक शस्त्रोंकी भीषण वास्तविकता समस्त राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नीतियोंपर अपना भारी प्रभाव डाल रही है। किसी आंदोलनको चलानेका प्रयत्न करना अथवा इन नई शक्तियोंके पूर्ण महत्वको समझे बिना परिस्थितिका विवेचन करना निरर्थक ही कहा जा सकता है।

वस्तुन अब तक आदर्श समझे जानेवाले मूल्यों और धारणाओं पर आणविक युगका पूर्ण प्रभाव समझनेमें अभी कुछ समय लगेगा। यह वह युग है जिसमें पहली बार मनुष्यके सामने जीवनकी परिस्थितियोंमें पूर्णतया बदलने या विज्ञान और सभ्यता द्वारा शताब्दियोंमें क्रमिक रूपसे निर्मित सभी वस्तुओंकी पूर्णतया नष्ट करनेका विकल्प रखा गया है।

विज्ञान अंतमें उस बिंदु पर पहुँच गया है जहाँ वह ऐतिहासिक प्रक्रियाका रूप निर्धारित करनेके लिये तैयार है और उन प्रक्रियाओंके प्रेरक सामाजिक समूहोंको करीब करीब नियंत्रित करेगा। इसे समझनेके लिये हमें दूर जानेकी आवश्यकता नहीं है।

आणविक शक्ति उपयोगके तत्कालीन प्रश्नको ही ले लीजिये। उपयोगका ढंग कुछ बठिन नहीं है। विज्ञानने इस समस्याका उत्तर पहलेमें ही खोज लिया है और जो उत्तर अब भी अस्पष्ट हैं, वे यथामय स्पष्ट हो जायेंगे। अविधिओंको अब यह प्रश्न सनस्त कर रहा है कि आणविक शक्ति निर्माणके परचात बचनेवाले रेडियो सक्रिय वर्ज्य पदार्थ का निर्वर्तन किस प्रकार किया जाय।

यह वर्ज्य पदार्थ लगभग २०० वर्ष तक रेडियो सक्रिय रहता है। उसके निर्वर्तनके अनेक मार्ग सुझाये गये हैं। कुछ लोग विशेष द्रव्योंमें रखकर समुद्रके अधिकतम गहरे भागोंमें इसे डुबोनेका इस आशासे विचार कर रहे हैं कि वे द्रव्ये शायद वर्ज्यपदार्थके रेडियोमक्रिय रहने तक न गल सकें। अन्य लोग ऐसे द्रव्योंमें दूरस्थ शून्यके अन्दर आग लगानेकी बात सुझाते हैं।

उसके निर्वर्तनकी कौसी भी योजना बनाई जाय, किन्तु एक विशेष निष्कर्ष निश्चला जा सकता है। किसी निजी समूहको आणविक शक्ति बनाने या उसे व्यवहृत करनेका कार्य नहीं सीसा जा सकता, क्योंकि वे उसका लागत

मूल्य घटाने और समान सस्तरमें जीवनको खतरा उपस्थित करनेवाली रेडियो सक्रिय वस्तुओंके निर्गतनके लिये आवश्यक अत्यंत खर्चीली व्यवस्थामें लाभ प्राप्त करनेका प्रयत्न करेंगे ।

उन्मुक्त व्यवसायका “लाभ” सदैव मुख्य भेक रहा है और आणविक शक्ति लाभ उठानेके लिये प्रयुक्त की जानेवाली वस्तु नहीं है । इस कारण राज्यको विवश होकर प्रत्येक क्षेत्रमें आणविक प्रगति का नेतृत्व करने और उसे स्वयं नियंत्रित करनेके लिये विवश होना पड़ेगा, यह ऐसी कार्यवाही है जो स्वामाधिक रूपसे पूँजीवादको रोकेगी और फलस्वरूप समाजके ढाँचेको प्रभावित करेगी ।

हमारे जीवनकी प्रत्येक छोटी-सी छोटी बातके प्रभावित करनेवाली समस्या का यह केवल एक ही पहलू है । यदि पञ्चशील द्वारा युद्ध अवैध घोषित हो गया तो संसारकी शांतिपूर्ण प्रगतिमें तीव्रताके लानेके लिये अधिकाधिक आणविक शक्ति प्रयोगमें लाई जा सकेगी और उसके उपयोगपर होनेवाला आवश्यक नियंत्रण अधिकाधिक क्षेत्रोंको यह विश्वास दिलाता जायगा कि व्यक्तिगत लाभ कमानेके बहुत बड़े स्थायी मार्गको अपनानेवाला पूँजीवाद अब सामयिक नहीं रह गया है ।

ऐसी युद्ध नीतियोंपर निर्मित आत्मविश्वासमें ही संसार युद्ध द्वारा अप्रभावित जीवनकी सम्भावनाकी कल्पना कर सकता है । फिर भी यह धड़ाना करना कि शांति हमने पा ली है, निरर्थक है । एक गलत प्रयत्न, एक विवेकहीन कार्य हमें पुनः युद्धकी कगार पर खड़े कर सकता है । आजकल सतर्क रहनेकी सबसे अधिक आवश्यकता है ।

शत्रुता और कटुता उन्मूलन करनेके लिये खुले और अविश्रुत तरीकोंसे काममें लानेकी अब बहुत कम आशा है । अधिक सूक्ष्म और गुप्त रणनीतियाँ सोचकर निकाली जायेंगी । इन तरीकोंमें हर स्थानपर दीखनेवाली शान्ति की विस्मयशील और एकीकृत भावनाओंमें अलगाव उत्पन्न और उलझन पैदा करनेका प्रयत्न किया जायगा । वास्तवमें हम ऐसे समयमें प्रविष्ट हो रहे हैं, जिसे कूटनीतिक सम्बन्धोंका सर्वाधिक नाजुक अवसर कहा जा सकता है ।

एक ओर पूँजीवादी समाज है और दूसरी ओर समाजवाद । लाखों व्यक्तियोंने चुनाव कर लिया है और लाखों व्यक्तियोंको अभी यह करना शेष है । किन्तु

पंचशील क्यों ?

मानवजातिके भारी बहुमतकी यह दृष्टि है कि यह चुनाव शाक्तिके बलावरणमें करना चाहिये, जहाँ एक व्यवस्था दूसरीकी प्रतियोगना कर सके, जहाँ किसी अन्य प्रकारकी 'विवशता' के स्थानपर पूँजीवादी और समाजवादी प्रयत्नोंके परिणाम ही अपना अपना पक्ष समर्थन करेंगे ।

साम्राज्यवादी शक्तियाँ सम्भवतया इस ढरके कारण पंचशील पर हस्ताक्षर न करेंगी कि वही उस अवस्थामें उन्हें अपने उपनिवेशोंको खाली करना न पड़ जाय और दूसरे भूभागोंमें स्थित दुर्दृष्टियोंको छोड़कर आणविक और प्रक्षेपक शक्तिके असीमित साधनोंपर निर्मित शाक्तिके स्वस्थ तर्कोंका सामना न करना पड़े किन्तु वे कुछ भी करें, उन्हें यह ज्ञात है कि साथ उनके साथी इन दुःसाहसिक क्रियाकलापोंमें डर गये हैं और उन्हें भी शान्तिकी आवश्यकता है ।

यह ऐसी भावना है जो विभाजक रेषोंको तोड़ कर हम नक्षत्र पर स्थित लोगोंकी एकताके सूत्रमें बाँधती हुई निरंतर बढ़ती रहेगी ।

राजनेतिक शतरंज

मुझे अस्थिरसे स्थिरकी ओर ले चलिये,
मुझे अंधकारसे प्रकाशकी ओर ले चलिये,
मुझे मृत्युसे अमरत्वकी ओर ले चलिये ।

—उपनिषद्

स्वतंत्रताके १० वें वर्षमें प्रवेश करते समय भारत अपनी आंतरिक नीतियों और विदेशी सम्बंधोंमें होनेवाले अनेक परिवर्तनोंके दर्शन कर सकता है। उसकी स्थिति इतनी सरलतासे और लंगमप अभ्युदय रूपसे सुशोभित और परिवर्तित हुई है कि वर्तमान समस्याओंका अध्ययन करनेवाले अनेक योग्य विद्यार्थी भी उसके कारणोंका अच्छी तरह पता लगाने में असफल रहे हैं। अनेकों बार उन्होंने अपने अनुमानोंको स्वीकृत तथ्योंके पूर्णतया विपरीत पाया है।

फिर भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरूकी स्थिति समझना अत्यंत आवश्यक है। गणबल इतनी अधिक फैली हुई है कि प्रत्येक महत्वपूर्ण अवसर पर किसी कार्यको आरम्भके लिये एक मात्र नेहरूका ही आसरा देखना पड़ता है। उन्होंने कांग्रेसकी वर्तमान विचारधाराको सबसे अधिक प्रभावित किया है और ऐसा करनेमें अपने देशवासियोंकी स्वस्थतम भावनाओंका प्रतिनिधित्व किया है।

राजनैतिक सुषर्षमे उन्होंने अपने विरोधीमें भी अधिक नीतिज्ञताका परिचय देकर उनकी प्रतिद्वंद्वितापूर्ण प्रशंसा प्राप्त की है।

विरव-समस्याओंके वर्तमान प्रमुख तत्व 'पंचशील' के प्रतिपादक और सह निर्धारक तथा पिछड़े गरीबीसे सन्नत प्रदेशकी श्रेष्ठ आत्माके रूपमें आजकल वे अपने दमके समाजवादका प्रचार करते हैं, जिसके बारेमें उनका दावा है कि वह भारतका रूप ही परिवर्तित कर देगा।

पूर्व अध्यायोंमें हमने कांग्रेसकी नीतिके कम्पि विज्ञानका तथा किम प्रकार विदेशी और घरेलू राजियों द्वारा उसका रूप निर्धारित हुआ, इन बातोंका अच्छी तरह सर्वेक्षण

राजनैतिक शतरंज

क्रिया है। अब उन तत्वोंमें पारस्परिक सम्बंध स्थापित करना आवश्यक है। इसके अभावमें सम्भावित प्रगति विषयक भविष्यवाणी करना या भारतको आगे बढ़ानेवाली आवश्यकताओंके लिये सार्वजनिक समर्थन प्राप्त करना सम्भव नहीं हो सकेगा।

यह स्पष्ट है कि वर्तमान युगमें कोई अकेला व्यक्ति इतिहासचक्र निर्माण नहीं कर सकता। जो व्यक्ति परिस्थितिको तत्काल समझ सकते हैं और जिन्हें बहुसंख्यक जनताका समर्थन प्राप्त है, वे ऐतिहासिक प्रक्रियाको अच्छाई या बुराईकी तरफ किसी अंश तक ही प्रभावित कर सकते हैं। स्वहितरत सघर्षशील वर्ग ही, जो कभी समझौता करता है और कभी दुराग्रह करता है, प्रगतिका रूप निर्धारित कर सकता है। वे योग्य व्यक्तिको भी अपने पक्षमें लेनेका प्रयत्न करते हैं। इसी प्रभूमिके आधारपर नेहरू और उनके द्वारा नेतृत्व प्राप्त पार्टीको समझना आवश्यक है।

आश्चर्यकी बात तो यह है कि इस जीवित तन्त्र पर अर्थात् भारतीय समाजमें वर्गोंकी स्थितिके विवेचन पर, कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। भूतकालमें भोतिज्ञानपूर्ण सीमित प्रयत्नोंके स्मरणहेतु सामान्य धनवान् सूत्रोंका प्रयोग किया गया है जो तत्त्वियवक वाद्य बन्पना है। भारतवासियोंको भी कभी इस बातकी शिका नही दी गई कि प्रत्येक वर्गकी क्या विशिष्ट स्थिति है, उन्हें किस संघर्षोंका सामना करना पड़ता है और उन आक्रान्ता संघर्षोंको निष्क्रिय बनानेकी उनमें कितनी क्षमता है। जब तक यह नहीं होता, भारतकी विदेशी नीतिके परिवर्तनोंको अथवा देशकी आन्तरिक आर्थिक प्रगतिको अच्छी तरह समझना असंभव है। इस दिशामें अग्रसर होनेसे पहले यह आवश्यक है कि १९४७ में सत्ता हस्तान्तरण कालमें अब तककी घटनाओंका सर्वेक्षण करनेके परवाना जो निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं उन पर सक्षिप्त विचार कर लिया जाय।

सत्ता हस्तान्तरण तक राष्ट्रीय आंदोलन एवं उसके विस्तारकी प्रमुख एवं महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रिटिश साम्राज्यवादमें होनेवाले इस संघर्षका नेतृत्व सामूहिक रूपसे पूँजीजीवियोंके हाथमें था। समस्त औपनिवेशिक पूँजीजीवियोंमें यही लोग सर्वाधिक विकसित थे और उन्होंने जनताको अपने साथ लेकर अंतमें सत्ता प्राप्त कर ली।

इस कारण यह बात आशानुकूल ही थी कि १९४६-४७ में आजाद हिंद फौज और रावल भारतीय नौसेनाके अभूतपूर्व स्वदेशाभिमान प्रदर्शनके परिणाम-

स्वरूप शीर्षस्थ बिन्दुपर पहुँचनेवाले विद्रोहको देखकर भारतीय पूँजीजीवी और ब्रिटिश साम्राज्यवादी दोनों भयभीत हो गये। उन दोनोंके हित वैधानिक सत्ता हस्तांतरणमें संयुक्त थे।

यदि जनताका नेतृत्व साम्यवादी पार्टी अर्थात् किसानों-मजदूरोंके हाथमें संयुक्त रूपसे रहा होता, तो एक पूर्णतया भिन्न और उन्मूलक परिवर्तन दृष्टिगोचर होते। तथापि मजदूर और किसान देशके विभाजनका अवरोध करनेकी परिस्थितिमें नहीं थे। वे उसके असहाय साक्षी और शिकार बने हुए थे।

इस संकटकालमें तथा इसके पहले भी राजामहाराजाओं और तालुकेदारोंका वर्ग व्यवहारसे साम्राज्यवादके प्रति अपनी मित्रता प्रदर्शित कर रहा था। सामुदायिक दंगोंके अवसर पर यह वर्ग सक्रिय रूपसे इस सीमा तक मीनानुकूलता दिखलाने लगा कि उसकी स्थिति अधिक उत्तेजक स्वरूप हो गई। नये पूँजीजीवी शासकोंसे स्थान ग्रहण करनेके वहाने उनके लिये ऐसा करना सम्भव हो सका। इस वर्गका इन सामुदायिक दंगोंमें दिया गया महयोग पुनः सत्ता प्राप्त करनेका अंतिम प्रयत्न था।

यद्यपि यह सच है कि देश-विभाजनमें पूर्व पूँजीजीवियोंके एक महत्वपूर्ण भागमें भी सामुदायिक संघर्षकी ज्वालाको प्रज्वलित करनेका प्रयत्न किया था, किन्तु एतदर्थ आयोजित दंगोंका उद्देश्य मुस्लिमलीगसे संघर्ष करते समय अस्थायी लाभ प्राप्त करनेका एक अल्प प्राप्त करना था। इसका प्रमाण यह है कि उन्होंने नेताओंके बादमें दंगोंकी धर्मनिरपेक्षता समाप्तिके लिये, प्रशमनीय धर्मनिरपेक्षताको प्रतिष्ठित करनेके लिये तथा अल्पसंख्यकोंके अधिकारोंकी गारंटीके लिये प्रशमनीय कुशाचानुपूर्वक कार्य किया। फलस्वरूप सामंतवादी तत्व तथा उनके सार्वजनिक मित्र अर्थात् हिन्दू परिषद, सच, महासभा आदि एक दूसरेमें प्रयुक्त हो गये। गांधीजीको इस संघर्षमें अपना स्वयंका बलिदान करना पड़ा।

पाकिस्तानका नदृशा पूर्ण भिन्न था। वहाँ पर सामंतवादी नेताओंने निर्बल पूँजीजीवी तत्वोंकी अपने साथ लेकर प्रशासन पर अधिकार कर लिया। उन्होंने पाकिस्तानकी बाकिरीसे पूर्णतया मुक्त करनेके लिये दंगोंको और लूटमारको प्रेरणा दी। इस कूटनीतिने 'जेद्दाद' के नामपर समस्त मुस्लिम जनताको अंधा

राजनैतिक शतरंज

बनाकर सगठित कर दिया। साथ ही धनी हिन्दू विस्थापित निष्क्रमणके अवसरपर अनेकों लाख एकड़ उपजाऊ भूमि और बहुमूल्य जायदाद छोड़कर भागे, जिसका दाव लगाया जा सकता था।

इसके अतिरिक्त कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद आदि रियासतोंके नरेशोंकी सदेहास्यद वीर्य भी मनोरंजक थी। वे भारतीय प्रगतिवादी विरोध इस आशासे कर रहे थे कि जिससे वे अपनी विशिष्ट परिस्थिति द्वारा भारत और पाकिस्तानकी शानुताका लाभ उठा सकें। जब इन सामन्ती गद्दोंपर भारतने अधिकार कर लिया, तब इन नरेशोंकी शक्ति पूर्णतया भंग हो गई।

सरदार पटेलने अपनी विलयन योजना द्वारा रियासती भारतकी शल्यक्रिया करवाली। कांग्रेस पार्टीय दक्षिणी पार्ष्वके अप्रतिहत नेताके रूपमें उन्होंने वैधानिकताके साथ देशी रजवाड़ोंकी समाप्त करके “एक पंच दो काज” कर लिये। प्रथमतः उन्होंने रजवाड़ोंके अंदर सार्वजनिक सुधारोंकी सम्भावनाको समाप्त कर दिया। दूसरे उन्होंने क्षतिपूर्ति स्वरूप शासकोंकी बड़ी भारी पेंशन (थ्रिवी पर्व) दे दी, जो किसी न किसी दिन पूँजीजीवी व्यापारिक प्रतिष्ठानोंके कोषोंकी भरने वाली थी।

राजनैतिक अधिकारोंने वंचित होकर अनेक दस नरेशोंने वित्तीय गठबन्धनोंका सहारा टोना और अधिकतर भारतीय एवं विदेशी पूँजीको संयोजित करनेमें बीमके दलाल बननेमें सफल हुए। कुछ नरेश अब भी कांग्रेस प्रशासन विरोधी जनताके असंतोषका लाभ उठाकर उनका तख्ता पलट अपना राजनैतिक प्रभाव स्थापित करनेके स्वप्न देख रहे थे। पश्चिम और मध्यभारतमें उनके ढलवाये गये। इन तर्कोंका चुनावके अवसरपर कांग्रेसके विपक्ष प्रयोग करना था। इस तरह जनताको यह सुभाषा गया कि ऐसी परिस्थितिमें उनके राजनैतिक सीमावर्धक करवानेके लिये नरेशोंका ही विश्वास किया जा सकता है।

पूँजीजीवियोंकी शक्तका अधिक सुदृढीकरण उस समय हुआ, जब कि संपूर्ण भारतके लिये एक संविधान अपनाया गया, जिसमें एक अन्य सामंतवादी आधार अर्थात् जमीनदारियोंकी नष्ट करनेकी दिशामें कदम उठाये गये। पुनः क्षतिपूर्ति की गई। इस धन द्वारा जमीनदार भी पूँजीवादी रूपक बन गये और व्यवसायी सत्तासे लाभकारी समझते करने लगे।

इसके अन्तर्गत इन सुधारोंके वर्ग गौवशालोंके वर्ग-सम्बन्धोंपर यह प्रभाव पड़ा कि ऐसे धनी किसानोंके सत्या बढ गई, जो प्रतिवर्ष कुछ बचत कर सकते तथा साथ ही संपूर्ण कृषक समाजके कुछ योग्य किसी सौम्य तक कम हो गये। पूँजीजीवियोंके अधिक ग्रामीण समर्थन प्राप्त करनेका मंदिर इंगित रहता है, क्योंकि वे यह बात अच्छी तरह जानते हैं कि भौमिक लुभावो अभी शान करना शेष है।

गणतन्त्रकी उद्घोषणाके पश्चात् पूँजीजीवी सामूहिक रूपसे पूर्ण राजनैतिक सत्ताका उपभोग कर रहे हैं, यद्यपि भारतमें लगी विदेशी पूँजीके साथ जो प्रमुखतया ब्रिटिश पूँजी है, आर्थिक सत्ताका हिस्सा बँटनेपर उन्हें विवश होना पड़ना है। इस परिस्थितिमें दो अंतर्विरोध होने स्विसंगत हैं।

प्रथमतः सामूहिक रूपसे पूँजीजीवियोंमें और ब्रिटिश निहित स्वार्थोंमें स्पष्ट संघर्ष होखता है। भारतीय व्यवसायकी इन दिनों भी आन्तरिक अर्थव्यवस्थाके महत्वपूर्ण खंडोंपर व्याप्त रहनेवाले ब्रिटिश व्यवसायके माथ प्रतियोगिता करनी पड़नी है। जैसे जैसे विदेशी पूँजी यह प्रदर्शित करती है कि उनकी रुचि भारतमें अधिकने अधिक धन खींचनेमें है और देशके वास्तविक विकासमें गड़बड़ा करनेके लिये तैयार नहीं है, वैसे ही वैसे यह तनाव बढता है।

द्वितीय, इसी अंतर्विरोध पर एक अन्य अंतर्विरोध आधारित है। वह है, प्रत्येक “व्यावसायिक दैने” में दखल रखनेवाले अन्तर्गत भारतीय बड़े पूँजीजीवियों और अपने भाषिक क्षेत्रोंमें जमे बहुसंख्य मध्यम पूँजीजीवियोंके लक्ष्योंमें संघर्ष। क्योंकि यह लोग टाटा-विहला आदि बाहरी लोगोंकी अनधिकृत दस्तेदारीमें प्रसन्न नहीं हैं और स्वयं अपने लिये लाभके एकांगी क्षेत्रका निर्माण करना चाहते हैं। वे उस स्थितिकी प्राप्ति के लिये सचपंरत हैं, जिस पर आवश्यक अन्तर्गत भारतीय बड़े पूँजीजीवियों और उनके विदेशी सहयोगियोंका एकाधिकार है।

और साम्राज्यवादके निस्वार्थ सहायताार्थ अग्रस्तुत होने पर अर प्रशासनकी आर्थिक विग्राम कथोंका नेतृत्व करने पर विवश होना पड़ना है, नच यह क्षेत्रीय मध्यम पूँजीजीवी, किसी विरोध क्षेत्रमें न आनेवाले टाटा-विहलाओंमें संघर्ष करनेके लिये आरम्भिक बदन स्वरूप इस देशकी भाषिक पुनर्रचनाकी मौग

राजनैतिक शतरंज

का सक्रिय समर्थन करने लगते हैं। आर्थिक विकास हेतु एक सार्वजनिक क्षेत्र घोषित किया जाता है, क्योंकि वह बड़े एकाधिकारियोंकी शक्तिपर आक्रमण करता है तथा अपने अपने क्षेत्रको विकसित करनेके लिये एक प्रतिष्ठित मध्यम उद्यमियोंके प्रयत्नमें उन्हें सहायता देनेका विश्वास दिलाता है। यह बड़ी अच्छी लाभदायक राजनीति है।

इनका लेखा जोखा पर्याप्त है। अब इस आंतरिक समर्थनमें निहित भारतीय पूँजीजीवियोंकी समस्याओंपर भी विचार करना चाहिये। भारतीय प्रगति का यह अभूतपूर्व अंग है।

इन दोनों वर्गोंके सही लक्ष्योंको ध्यानमें रखना चाहिये। अखिल भारतीय बड़े पूँजीजीवों जो किमी विशेष क्षेत्रमें सीमित न हों, उनकी कार्यवाहियों समस्त देशमें फैली रहनी हैं। वे ऐसे क्षेत्रोंमें भी दखल देते हैं जो सामान्यतया बहुत मदत्तहीन प्रतीत होंगे। इसके अतिरिक्त वे अपने निजी 'बर्गों' का भी नियंत्रण करते हैं और अभी थोड़े दिनों पहले तक बीमा समवायोंको भी संचालित करते थे, जिसको ४० प्रतिशत पूँजी उन्हें उपलब्ध रहती थी। इस वर्गका निर्माण प्रमुख रूपसे मारवाड़ी व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा हुआ है, किन्तु टाटा और बम्बईके गुजरातियों सरीखे कुछ अन्य लोग भी इसमें सम्मिलित हैं। इन दोनोंकी पूँजी भी ऐसे क्षेत्रोंमें लगी हुई है, जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। यह बड़े व्यवसायी विदेशी पूँजीमें संयुक्त हैं और विदेशी व्यवसायियोंके लाभकारी संगठनों का सदैव लाभ उठाना है। वे कांग्रेस पार्टीके शक्तिपूर्ण दक्षिणी पार्षदोंके सदैव पृष्ठपोषक रहे हैं।

क्षेत्रीय मध्यम पूँजीजीवी केवल अपने भाषिक क्षेत्रोंमें ही कार्यरत रहते हैं। अहमदाबादके समृद्धिशाली गुजराती रुई नियंत्रकोंके समान छोटेसे दलके अतिरिक्त इस समूहके पूँजीजीवियोंकी प्रगति बहुत सीमित रही है। सामान्यतया उन्हें शक्तिशाली मारवाड़ी फलोंकी सरस्रता का आसरा ताकना पड़ता है। वे भारतके मारवाड़ियोंको और बम्बई नगरके गुजराती और पारसियोंको देशके किसी विशेष क्षेत्रमें संयुक्त नहीं समझते।

जब इनके पास अपना कार्य करनेके लिये धन होता है, तब अहमदाबादके गुजरातियोंकी तरह तत्व भी स्वतन्त्र रहते हैं। इनका भविष्य विदेशी स्वार्थोंके साथ समझौता करनेमें निहित नहीं है, क्योंकि वह शायद ही कभी उन्हें प्राप्त होता हो। उनका भविष्य तो इस उपमहाद्वीपके सम विकासमें तथा उनके निजी क्षेत्रोंके मौलिक उद्योगोंकी उन्नतिमें निहित है, जिससे वे इन पर अधिकार कर सकें और अन्य आर्थिक उद्योगोंको विकसित कर सकें।

पूँजीजीवियोंके बड़े और मध्यम, दोनों वर्ग साम्राज्यवादसे बलपूर्वक प्राप्त की गई स्वतन्त्रताकी रक्षाके लिये दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, क्योंकि अन्य कोई स्थिति अपनानेसे वह स्थिति उनके वर्ग हितोंके लिये सकट स्वरूप हो जायगी। दोनों इस बातमें सहमत हैं। विश्व पूँजीवादी विकासकी इस विलम्बित स्थितिमें राज्यकी सहायताके बिना भारतके आर्थिक पुनर्निर्माणका कार्य वे सम्पन्न नहीं कर सकते।

और यहीपर कठिनाई है। एक ओर बड़े पूँजीजीवी समस्त देशके लिये एक शक्तिशाली केन्द्रीय प्रशासन चाहते हैं, जिसमें उन्हें पैसा और आर्थिक प्रगतिशील सम्भावनाओंको हस्तगत करने तथा उसे उपबोधित करनेका अवसर मिल जाय। जब कि दूसरी ओर मध्यम पूँजीजीवी अपना प्रभुत्व स्थापित करनेके लिये भाषिक राज्यों और उनकी संयोजक कड़ीके रूपमें केन्द्रीय प्रशासन चाहते हैं, जिससे उनकी आवश्यकता पूरी हो सके। वे चाहते हैं कि राज्य स्वयं राष्ट्र निर्मात्री प्रायोजनाओंका प्रहस्तान करे, क्योंकि बड़े पूँजीजीवियोंकी शक्तिको सीमित रखकर प्रायोजनाओंको विभिन्न क्षेत्रोंमें आवंटित करनेकी उनकी गुहार मुनवानेका यही एक मात्र मार्ग है। इसका अर्थ अन्य उद्योगोंके विकास हेतु अधिक इस्पात, सोमेट, कोयला और दूसरे मौलिक पदार्थ प्रस्तुत करना है।

यद्यपि कौन्सेल दैन पर दक्षिण पश्चिमोंका नियंत्रण कायम है, जो बड़े पूँजीजीवियोंका पक्ष समर्थन करते हैं और जो “विभाजक” प्रवृत्तियोंके विरुद्ध गारंटोम्बरूप एक शक्तिशाली एकात्मक राज्यकी कल्पना करते हैं, तथापि उन्मूलकवादी नेहरूके रूपमें क्षेत्रीय मध्यम पूँजीजीवियोंको बड़े पूँजीजीवियों पर दबाव डालनेवाला एक आदर्श उत्तोलक प्राप्त हो गया है।

राजनैतिक शतरंज

4

उनकी विशाल जनप्रियता, उनकी आश्चर्यजनक राजनैतिक दक्षता, अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितिके परिवर्तनकी पूरी तरह समझनेकी उनकी योग्यता तथा प्रजातांत्रिक भारतीय समाजवाद प्राप्त करनेके उनके विचार जो जानबूझकर अनुसूल अवसरों-पर अस्पष्ट रखे जाते हैं, उन्हें इन तत्वोंका पूर्ण प्रवक्ता बना देती है।

नेहरू इस वर्गके कोई सजीव उपकरण नहीं हैं, वरन एक ऐसे प्रतीकालमय प्रभाव-शाली पुण्य हैं, जिनका आविर्भाव इतिहासमें समय-समयपर होता ही रहता है। अपने विचार और व्यवहारमें वह निश्चित रूपसे क्षेत्रीय हितोंमें आगे हैं। वे अधिक विस्तृत क्षेत्रीय विचारों और आकांक्षाओंको व्यक्त करते हैं, विन्तु वे क्षेत्रीय मध्यम पूँजीजीवोंके स्पर्षके अन्यतः अनिवार्य अंग हैं।

इस बातसे दो प्रश्न पैदा होते हैं। प्रथम तो यह कि कॉंग्रेस उनके प्रधान तत्व उन स्पर्षोंका प्रतिनिधित्व क्यों नहीं करते, जहाँमे वह आते हैं? द्वितीय यह कि पूँजीजीवियोंके यह दोनों वर्ग स्वेच्छापूर्वक समाजवादके विचारोंका समर्थन कैसे करते हैं?

प्रथम प्रश्नको ले लीजिये। कुछ स्थानोंमें अनुत्तरदायी रूपसे कॉंग्रेसको गुजराती निहित स्वार्थोंके अधिकरण स्वरूप बतलानेकी प्रथा रही है। इसमें एक भिन्न निष्कर्ष प्राप्त होता है अर्थात् यह कि वैसे पूँजीजीवी गुजगामी हैं। वास्तविकता यह है कि कॉंग्रेस संगठन पर प्राथमिकरूपसे गणकी घाटीके राजनैतिक हित व्याप्त हैं। अर्थात् उत्तर प्रदेश और बिहार नामक उस विस्तृत हिन्दी-भाषी क्षेत्रको जिमने अनेकों राजाधियोंमें इस उपमहाद्वीपको प्रभावित और नियंत्रित करनेका प्रयत्न किया है।

इस राजनैतिक विचारधारा वाले लोगोंके साथ गुजरात और तामिलनाडु वाले भी संयुक्त हैं। क्षेत्रीय पूँजीजीवियोंमें यह वर्ग सर्वाधिक विकसित और आत्मनिर्भर हैं। यह लोग बड़ी भूमिकके साथ ही भाषाभाषी भावनाओं का समर्थन करते हैं, क्योंकि उन्होंने केवल अपने क्षेत्रोंमें नहीं, वरन अन्य क्षेत्रोंमें भी शक्तिका आनन्द उठाया है। तामिलनाडुका आंध्र और केरलपर नियंत्रण था। गुजरात महाराष्ट्रको नियंत्रित कर रहा था। स्पष्टतया सीमाओंका पुनर्गठन उनके लिये इतनी आकर्षक बलु नहीं थी।

अब समाजवादी नारोंको सरलतापूर्वक अपनानेका दूसरा प्रश्न आता है। पिछले दम बर्षोंमें कांग्रेसने सहकारी सर्वतंत्र, कल्याणकारी राज्य, निश्चित अर्थव्यवस्था समाजवादी ढंग और आजकल समाजवादी समाज आदि अनेक राजनैतिक दृष्टिकोण क्रमशः अपनाये हैं। किन्तु उसने सदैव यही कहा है कि इन मिद्दान्तोंमें वह सामान्यमें कुछ भिन्न अर्थ ग्रहण करती है और आजकल भी वह यही कह रही है। नेहरूके शब्दोंमें 'हम अपने निजी ढंगसे ही काम करना पसंद करते हैं।'

इस परिस्थितिकी वास्तविकता यह है कि विरुद्धके पूँजीवादी विचारोंमें ठेसते हुए भारतीय पूँजीजीवीयोंने राजनैतिक शक्ति यथेष्ट विलम्बमें प्राप्त की है। इस कारण उन्हें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाको विकसित और नियंत्रित करनेके लिये किसी सीमा तक राज्यका सहभागी होना स्वीकार करना पडा। इस कार्यभागको स्वीकार करनेके विषयमें हमने बड़े और मध्यम दोनों वर्गोंके दृष्टिकोणोंके अन्तर्गत पर विचार कर लिया है, किन्तु दोनों ही वर्गों समाजवादके अस्पष्ट सूत्रके अन्तर गम्भीर पूँजीवादके केन्द्रीय तथ्यको सम्मिलित करनेके लिये तैयार थे। क्या अनेक पूँजीवादी देशोंने कुशल आर्थिक प्रशमन हेतु उद्योगोंके सार्वजनिक क्षेत्र स्थापित नहीं किये हैं?

भारतमें भी पहले यही सोचा गया था कि चूँकि ऐसे कदम लेने जरूरी हैं। इसलिए उन्हें राजनैतिक रूपमें अपनाना चाहिये। जनताको यह बतलाना चाहिये कि कांग्रेस समाजवादकी समर्थक है। ऐसा करनेसे वामपक्षियोंका दौंव उनके हाथमें आ आयागा।

जहाँ एक ओर यह हो रहा था, वहाँ दूसरी ओर भारतीय समाजवादके अभूतपूर्व रूपको समझनेके लिये यथेष्ट प्रयत्न किये गये। उसे प्रजातांत्रिक बनाना था। उसे केवल उन्हीं क्षेत्रोंमें लागू करना था, जहाँ निजी प्रयत्न अपेक्षित कार्य पूरा न कर सकें। किसी भी वर्गके हितोंका बलिदान किये बिना ही उसे प्राप्त करना था। बड़रता और सैद्धांतिकता नापसंद थी। ऐसे विचारोंने ही समाजवादको 'समाजवादी' बना दिया तथा अत्यंत आशाके विरुद्ध क्षेत्रोंसे भी समर्थन प्रदान करवा दिया।

राजनैतिक शतरंज

यदि भारतीय जनता की उन्मूलनवादी आवश्यकताओं को प्रतिभासित करना अनिवार्य न होता, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि समाजवादी ढाँचे के विषयमें कभी चर्चा भी न होती। अवादी समाजवाद का स्वर क्या उसी समय कैसा नहीं उठपा गया था, जब कांग्रेस को आधुनिक चुनावों द्वारा सम्मानित करने लगी थी। एक बार इस नारे को उठाने के परचान् प्रत्यावर्तन लगभग सम्भव-सा ही प्रतीत होने लगा।

कम से कम पूँजीजीवी तो ऐसे प्रत्यावर्तन के लिये तैयार नहीं थे। समाजवादी बातचीत से प्राप्त होनेवाला तीव्र राजनैतिक लाभ, पर्याप्त क्षतिपूर्ति करते थे। जनमत का सामान्य उन्मूलनवादी रूप देखने लगा था, किन्तु कांग्रेस को यह पूरा विश्वास था कि वह इन उन्मूलनवादियों पर अपनी पकड़ कायम रख सकती है।

जब अवादी समाजवादियों द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकालमें अधिक तीव्रतर होने लगी, तब पूँजीजीवियों के मध्य फूट पड़ना आरम्भ हो गया। यद्यपि बड़े पूँजीजीवी तत्त्वों ने लोगों के सामने अपना भय पूर्णतया अभिव्यक्त नहीं किया था किन्तु विशालोन्मुख सार्वजनिक क्षेत्र के बारेमें पुनः फिर सोचने लगे थे। उनका यह आक्रमण उम्र समय आरम्भ हुआ, जब उन्हें यह विश्वास होने लगा कि समाजवादी देशों के साथ प्रशासनिक स्तर पर निरंतर बढ़नेवाला मरकरों के बीच होनेवाला व्यवहार देश के आर्थिक जीवनमें सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुखता प्रदान कर देगा।

किंतु अब अवसर निकल गया था। इन विचारों ने वह पकड़ ली थी, इसके अतिरिक्त मध्यम पूँजीजीवी सार्वजनिक क्षेत्र को तब तक समर्थित करने के लिये तैयार थे, जब तक कि वह उनके अधिकारों का ही हनन न करने लगे। किन्तु आज भी यह कहना उचित नहीं होगा कि पूँजीजीवियों का कोई भी वर्ग समाजवाद शब्द का वास्तविक अर्थ अच्छी तरह समझता है। समाजवाद विषयक उनकी समझ आज भी लगभग उतनी ही है, जितनी अवादी कांग्रेस के अवसर पर थी।

फिर भी इसका अर्थ यह नहीं कि कांग्रेसी समाजवाद भोलेपनी टट्टी है। बृहत् क्षेत्रीय राज्य पूँजीवाद को स्वीकार करके एक पिछड़े देशमें लागू करने के तथ्य का ही

केवल एक ही परिणाम निकलता है अर्थात् वास्तविक समाजवादके मार्गको प्रशस्त करना । पिछड़ी अर्थव्यवस्थाके तर्क ही इस परिवर्तनके लिये विपरीत कर देंगे ।

उदाहरणार्थ भारतीय राज्य पूँजीवादके विरुद्ध पूँजीवादी देशोंके तटस्थ व्यक्तियोंके समान समझना मूर्खताकी बात होगी । ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिकामें राज्य-पूँजीवाद निजी स्वत्वाधिकारोंसे विभक्तित्व होता है । उन देशोंकी व्यवस्थाकी प्रमुख विशेषता यह है कि वह स्वदेशी और विदेशी सभी लोगोंका उद्बोधन करती है । वहाँ राज्यपूँजीवाद साम्राज्यवादी और प्रसारवादी लक्ष्योंकी साधना करता है तथा शक्ति-शाली और पूर्ण विकसित एकाधिकारों द्वितीयको सहायता देता है ।

भारत तथा भारत समीचे अन्य अर्द्धविकसित देशोंकी परिस्थिति पूर्णतया भिन्न है । यहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्रमें सम्मिलित होनेवाला राज्यपूँजीवाद तीव्र आर्थिक विकास सम्भव बनाना है और ऐसा करते समय साम्राज्यवादियों और उनसे सहयोगियोंकी आर्थिक पकड़ों टोला करके राष्ट्रीय स्वतन्त्रताको आश्रय देती है । इसलिये भारतीय प्रवृत्तियोंकी देखकर विदेशी पूँजीका सुरी तरह आतंकिता होना अकारण नहीं है, क्योंकि भारत निष्कर्ष रूपसे आर्थिक प्रगतिके हितार्थ उनकी पूँजी हस्तगत करनेका प्रस्ताव रख सकता है ।

फिर वर्तमान समयमें जब पिछड़े देशोंकी सरकारें आर्थिक उन्नति का नेतृत्व करने लगती हैं, तो उनकी सहायताका एक मात्र आधार समाजवादी संसार रह जाता है । पूँजीवादी व्यवस्था समाजवादकी ओर उन्मुख देशोंके अंदर किसी नये कार्यकी दायमें लेना भयानुक्त समझते हैं । समाजवादी संसारकी ओर पिछड़े देशोंका ऐसा रुझान, राज्यपूँजीवादकी प्रगति का अग्र बनानेमें सहायता देता है ।

इन सब बातोंका यह अर्थ नहीं है कि कॉम्रेन्सालिटी या पूँजीजीवियोंके मध्यम वर्गसे इन सब बातों पर विचार कर लिया है । वे अब भी राजनैतिक प्रक्रियाके नियमोंका उल्लंघन करनेकी धारा करते हैं । किन्तु उन्हें द्वितीय भोजनाक्षलमें यह ज्ञात हो जायगा कि ऐसा होना सम्भव नहीं है । उस समय कुछ लोग इन नीतियोंका पालन करेंगे, जब कि अन्य लोग इनके साथ विरुद्धावृत्त करेंगे ।

राजनैतिक शतरंज

बड़े और मध्यम पूँजीजीवी वर्गोंके पारस्परिक तथा उनके द्वारा अपनाये जानेवाले दृष्टिकोण-संदर्भमें इस विवेचनाको बल प्राप्त होता है।

भारतीय एकाधिकारियोंके हित साम्राज्यवादी अंतर्राष्ट्रीय पूँजीके साथ अनेक प्रकारमें संयुक्त हैं। वे राष्ट्रीय स्वतंत्रताके मूल्य पर तो नहीं बरन जिम प्रसार कोई बनिया एक विवेचनाका दूसरेके विरुद्ध उपयोग करता है, उसी तरह गठबंधनोंको आर्थिक सुन्द बनानेके लिये विश्वकी समस्याओंमें इस देशकी महत्वपूर्ण स्थितिमा लाभ उठायेगे।

किन्तु अपने अपने भाषिक क्षेत्रके शक्तिधारी मध्यम पूँजीजीवी इतना सब नहीं करेंगे। साम्राज्यवादी गठबंधनका अर्थ बड़े एकाधिपतियोंकी नई शक्ति प्रदान करना है। यह विकसित मध्यम वर्गके हितमें नहीं है। किन्तु साथ ही मध्यम पूँजीजीवी साम्राज्यवादमें संपूर्णतया सम्बन्ध विच्छेद करनेमें भिन्नकते हैं। यह वे तभी कर सकते हैं, जब कि वे अपने आपकी मजदूर वर्गके हितोंके साथ संयुक्त कर लें और चीनके समान नये प्रकारकी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था अपनानेके लिये तैयार हों। इस विषयमें उन्होंने अभी सोचा भी नहीं है, क्योंकि सकट अभी इतना गम्भीर नहीं है, जो उन्हें ऐसा करनेपर विवश करे। किसी भी समय ऐसे परिवर्तनकी कल्पना करना बहुत बड़ी बात होगी।

साम्राज्यवादके प्रति इस दृष्टिकोण अपनानेके कारण पूँजीजीवियोंके मध्यम और उच्च दोनों वर्गोंकी हिमी नीमा तक समान क्षेत्र प्राप्त हो जाता है। राष्ट्रमंडलीय शृंखलाभी रक्षा की जाती है, किन्तु यहाँ यह बान ध्यान देने योग्य है कि यौद्धिक दलमें और साम्राज्यवादी दलमें अपने आपकी अलग करनेके पश्चात् राष्ट्रमंडलसे भी पृथक् होनेका विचार सामने आने लगा है। विदेशी व्यवसायकी शक्ति समाप्त करने, एशिया और अमीकामें एक शक्ति क्षेत्रका निर्माण करने तथा समाजवादी संगठनों को सम्मिलित करते हुए एक व्यापारका क्षेत्र निर्माण करनेकी आवश्यकताके फलस्वरूप यह विचार उत्पन्न हुआ है।

बड़े अखिल भारतीय पूँजीजीवी ऐसे भयप्रद परिवर्तनोंके विरुद्ध हैं। वे नेहरूको भयकर सकटके समान समझते हैं। तटस्थता तो ठीक थी, किन्तु स्पष्ट

स्वतंत्रता, समाजवादी सत्तारसे व्यापार, वार्शिंग्टनघ सृष्ट प्रतिघात तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धोंके मित्रातस्वरूप पञ्चशीलता निरुत्तर प्रतिपादन पचानेके लिये बहुत भागे पड़ेगा। बड़े पूँजीजीवी कुछ कलकी ही उपज थोड़े ही हैं। वे अच्छी तरह जानते हैं कि इन नीतियोंका देशकी आतंरिक प्रगृत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

पीठ पीछे चाहे कितनी भी आलोचना की जाय, आर्थिक योजनाओंका महत्व घटाया जाय, उन्मुक्त गेष्टियों उलामनके बीज बोयें, किन्तु इनमेंसे कोई भी बड़े उद्योगपनियोंके निजी गढ़ोंकी सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा निये जानेवाले अतिक्रमणसे रक्षा नहीं कर सकते। यदि हम केवल द्वितीय योजनाके प्रति अपनाये जानेवाले सार्वजनिक स्वागतकी दृष्टिसे ही देखें, तो यह वास्तविकता नहीं दिखलाई पड़ेगी। यह स्वागत तो स्वाभाविक है। एकाधिकारी तत्व विकासशील अर्थव्यवस्थासे गेष्ट लाभ प्राप्त करनेकी सम्भावना देखते हैं। सम्भाव है मध्यमवर्ग सार्वजनिक क्षेत्रीय नवीन आयोजनाओंके अंदर विक्रमित होनेवाले लघु उद्योगोंकी उन्नत करनेके निवे तत्काल ही धन प्राप्त न कर सके और इस कारण सदैवके समान अपने बड़े भाइयोंका आसरा ताके।

पुनः राष्ट्रीय औद्योगिक विकासनिगमकी निधि बड़े पूँजीजीवी हस्तगत करना चाहते हैं। अन्य वित्तीय निगमोंको भी ऐसे अनधिकृत दखलमे बचनेके लिये भारी सवर्ष करना पड़ेगा। वित्तीय निगम विषयक नैदातिक विरोध तो प्रारम्भ हो गया है। इस समय विश्व बैंक निर्देशित औद्योगिक ऋण और वित्तियोजन निगम तथा राष्ट्रीय औद्योगिक विकासनिगम पर नियंत्रण स्थापित करनेमें एकाधिपति सफल हो गये हैं, किन्तु राज्योंमें प्रतिआक्रमण आरम्भ हो गया है। उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल दोनों प्रदेशोंमें कांग्रेसपाटीय नेताओंकी गम्भीर आलोचनाका सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने निधि नियतन कार्यके पर्यवेक्षणकी विदला और जालान-को आला दे दी है। द्वितीय योजनाके अग्रसर होनेके साथ ही साथ यह प्रतिआक्रमण भी फैलेगा।

दमरे शब्दोंमें हम कह सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तत्कालीन भविष्यसे आगेकी ओर देखे तो पूर्णरूपेण भिन्न सम्भावनायें सामने आती हैं। जैसे ही मध्यम पूँजीजीवियोंने अपने सन्नमको समाप्त किया, वे राज्योंकी अपनी सदेह-रहित प्रभाव-

राजनैतिक शतरंज

शाली स्थितिके सहारे वित्तीय निगमोंकी निधि पर एकाधिकार प्राप्त करनेके लिये कृतसकल्प हो जायेंगे। साथ ही केन्द्रीय सरकार द्वारा लाइसेंस देनेमें तथा इसी प्रकारकी अन्य सुविधाओंके विषयमें बड़े पूँजीजीवियोंके प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहारकी वर्तमान व्यवस्थाको समाप्त करनेके लिये कदम उठाये जायेंगे।

जब मध्यम वर्ग देखेगा कि सार्वजनिक क्षेत्रीय इस्पात आदि मौलिक उद्योगोंके कारखाने टाटा आदि निजी कारखानोंकी अपेक्षा अधिक उत्पादन कर रहे हैं, तब उन्हें अधिक विश्वास आ जायगा, क्योंकि एक बार ऐसा होनेके पश्चात् उनके विरामशी अधिक सम्भावना होगी।

इसके अनिरीक्त बड़े-बड़े निजी उद्यमी अपनी शक्ति खो देंगे। उदाहरणार्थ उस समय सरकारसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वे टाटाको इस्पातका मुख्य अधिक ऊँचा कायम रखनेके लिये सरकारी सहायता दें, जब कि वे स्वयं इस पदार्थका अधिक भाग उत्पादन कर रहे हों। टाटा तथा अन्य लोग इन खतरोंमें परिचित हैं। और इसी कारण वे विश्ववैक ऋणको महायताने उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं। किन्तु उनके लिये यह हरनेवाला मघर्ष है।

तथापि यह निष्कर्ष अभी प्राप्त नहीं हो सके हैं। समस्त देशमें अभी निराशा और विरक्ततामें पूर्ण लक्षु उद्योगपतियों और व्यवसायियोंका राज्य है, जो बड़े पूँजीजीवियोंके समान शक्ति और प्रशंसनीय प्रतिष्ठा प्राप्त करना चाहते हैं और जो अपने प्रतिद्वन्द्वियोंके निबटनेके लिये सेन तैयार करनेमें अधिक व्यस्त होते जा रहे हैं। वे लाभोंके अंदर आपादमस्तक डूबकर आगामी वर्षोंकी स्वयं अपना ही बनाना चाहते हैं, ऐसे वर्ष जिनमें वे बड़े पूँजीजीवियोंसे वित्तीय अत्यंतत्रमे मुक्त हो सकें।

यहाँ एक चेतावनी आवश्यक है। संपूर्ण भारतीय निश्चिन्त स्वार्थोंके अत्यंत उल्लभन और कपटतासे पूर्ण व्यवहारोंकी देवनेपर यह मालूम पड़ेगा कि अशिक्षित भारतीय बड़े पूँजीजीवियोंका एक छोटा वर्ग अवसर मिलने पर क्षेत्रीय मध्यम पूँजीजीवियों या अन्य लोगोंकी नीतियोंसे फीका कर सकता है। कुछ बड़े पूँजीजीवी विदेशी पूँजीसे निकट सम्बंधित नहीं हैं और न उनका व्यवसाय संपूर्ण उप महाद्वीप पर फैलाही है।

उन्होंने किसी विशेष क्षेत्रमें गहरे व्यवसायिक सम्बन्ध विकसित कर लिये हैं और विरमिन् सार्वजनिक क्षेत्रमें भी निरन्तर प्रगति की सम्भावनायें देखते हैं। इसके विरुद्ध कुछ मध्यम तन्त्र विदेशों प्रतिष्ठानोंमें आवद्ध हैं। वे इस ढंगमें अनुरिक्त फैले हैं कि जिससे वे बड़े पूँजीजीवियोंके छोटे सहकर्ता बन जाते हैं। इसके अनुरिक्त एक ऐसा भी भाग है, जो अपने वर्गके साथ चलते हुए भी मुख्य प्रगतिवा अस्थायी विरोधी है, उसे देखकर निम्नता है एवं सभ्रममें पड़ जाता है।

यह युगांतरमालीन चिन्ह है। पूँजीजीवियोंके इन दोनों दलोंका पारस्परिक नष्ट और तनाव अधिकाधिक व्यक्त होता जा रहा है और मध्यम व्यक्ती होनेके साथ ही साथ तीव्र होता जायगा। संपूर्ण भारतमें अपना व्यवसाय करनेवाले पूँजीजीवी क्षेत्रीय पूँजीजीवियोंकी प्रधानता रोकनेके लिये अधिक उद्वेगपूर्वक प्रयत्न करेंगे। फिर एक स्थिति ऐसी भी आयेगी जब उनके सामने सख्त उपस्थित हो जायगा। उन समय इन कठिनाइयों पर विचार पानेके लिये वे कुछ भी करनेसे न चूकेंगे।

इस बातकी पूरी पूरी सम्भावना है कि बड़े एकाधिपतियोंके अनुरोध और धृष्टाचारी तत्व अपनी कार्यवाहियोंकी साम्राज्यवादी पद्धतियों और प्रतिक्रियाओंमें अधिकाधिक संयुक्त करते जायेंगे तथा समाजवादी पद्धतियोंका सामना करनेके लिये हिन्दू महासभा तथा अन्य तानाशाही उदारवादी (रिवाइलिस्ट) दलोंका अधिक महारा खोजेंगे। यह भी सम्भव है कि पूँजीजीवियोंके भेदभाव बढ़ने पर स्वयं कांग्रेसके विरोधी दलोंके बीचमें बड़ी खाई पड़ जाय।

भारतीय राजनैतिक शतरंजकी एक प्रमुख दृश्य विशेषता अर्थात् सत्कारी नीति की द्विकिचाहट, सरकारी सिद्धान्त एवं व्यवहारकी अनेक प्रतिकूलतायें पूँजीजीवियोंके द्विकिचाहट, तथा आन्तरिक शक्तिसन्तुलनका सुबाध एवं सचर्प प्रदर्शन करते हैं। आजकी अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि मजदूरों और किसानों पर आधारित स्वदेशाभिमान की प्रगतिशील एवं प्रजातांत्रिक तत्व पूँजीजीवियों अथवा कांग्रेस पार्टीमें होनेवाले इस सचर्पकी सक्रिय और स्वीकारात्मक रूपमें गम्भीरता करें।

भूतकालमें इस कार्यकी बुरी तरह उपेक्षा की गई है। किन्तु अब आगे आनेवाले भविष्यमें इसकी यह उपेक्षा जारी नहीं रह सकती।

सार्वजनीन एकता

स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। जब तक मुझमें चेतना है, मैं वृद्ध नहीं हो सकता, कोई अस्त्र हम इच्छाको काट नहीं सकता, कोई अग्नि इसे जला नहीं सकती, कोई जल इसे भिगा नहीं सकता और न कोई वायु इसे सुखा सकती है।

— बाल गंगाधर तिलक

काँग्रेस पार्टी की समस्याओंमें हस्तक्षेप करना कठिन है क्योंकि इस कार्यके लिये वही भारी समर्थदारी और पर्याप्त नमनशीलताकी आवश्यकता है। स्वतन्त्रता-संग्रामकी कहानी भी इसी खान पर जोर डालनी है।

काँग्रेस सामान्य पूँजीजीवी पार्टीके समान नहीं है, वह ऐसा संगठन है, जिसकी परंपरामें अभी स्वदेशाभिमान विद्यमान है। इस संगठनने अपनी नीतिके ऊपर से वही भारतीयोंका निवेदन इटानेके लिये भारी प्रयत्न किया है। भूतकालमें, प्रमुखतया महात्मा गांधीके प्रभावके कारण, इस पार्टीने जनतामें निष्ठ रूपके कायम रखना तथा अपने कार्यकर्त्ताओं और नेताओं पर पर्याप्त सादगी और समर्पणकी भावना कायम रखनेके लिये जोर डाला।

और चूंकि यह पार्टी अभी राष्ट्रीय स्वदेशाभिमानी दलोंके सम्मेलनके रूपमें विकसित हुई थी, इस कारण आवश्यकतानुसार अपने विरोधियोंकी नीतियोंसे पूर्णतया अलगानेमें कोई कठिनाई अनुभव नहीं करती। इस कूटनीतिका चतुराईके साथ अनेकों बार प्रयोग किया गया है। देशमें व्याप्त असंतोष और निराशाके बावजूद भी सुसंगठित राजनैतिक संस्थाके रूपमें काँग्रेस ही ऐसा एकमात्र राष्ट्रीय संगठन है, जिसमें राजनैतिक शलशरोंका सामना करनेकी क्षमता है।

यह सलाहकै क्या है ?

हमने हिन्दू राष्ट्रवादिक संगठनोंकी स्थिति पर विचार कर लिया है। देशके विभाजनके अनुगामी महानोंमें यह भय था कि वही वे संगठन महत्वपूर्ण राज-

नैतिक शक्ति नष्ट न जायें । किन्तु सांप्रदायिक दलोंके अवसरपर उनकी उत्तेजक भागीदारी उनके राजनीति-विषयक उद्घाटनकारी मिथान, जनताके समुख उपस्थित प्रमुख आर्थिक प्रश्नोंकी गंभीरतापूर्वक हल करनेकी उनकी अस्वीकृति तथा उनके एक साथी द्वारा महात्मा गांधीकी इत्थानी वास्तविकताके सत्ताके लिये क्षर्पण करनेवाले सांप्रदायिक गठबन्धनकी सम्भावनाओंसे ही पूरी तरह भ्रमग्रस्त कर दिया ।

किन्तु महात्मा और उनके साथियोंने राजनैतिक जीवनमें सिर्फ थोड़े समयके लिये ही पलायन किया है । भारतमें संप्रदायवाद अब भी अनेक स्तरोंमें फैला हुआ है । जैसा कि पहले बतलाया गया है, कांग्रेसके आंतरिक स्तरोंके तीव्रतर होनेके साथ ही माय हम बात की पूरीपूरी सम्भावना है कि वही कांग्रेस पार्टीके असंतुष्ट अन्धबुद्धि दक्षिणपंथी तथा विक्षोभित भारतीय समाजवादके आक्रमणके सामने प्रत्यावर्तित होनेवाले मारवाडी एकाधिपतियोंके निःशस्त्ररूप महात्मा पुनर्जीवित न हो गया ।

धन तथा अन्ध प्रचारकी सहायताके लिये महात्मा अब भी इन तत्वोंका आश्रय लेती हैं । वर्तमान समयमें भी महात्माके दुर्बोधतावादमें और कांग्रेसके अंदर विद्यमान यशकदा पुरोहितमंडल टंडन और संपूर्णानंद सरोखे व्यक्तियोंकी अभिभूत करनेमें समर्थ नेहरूकी शक्तिको लक्ष्यकारनेवाले अनेक गुटोंके विचारोंमें बड़े-छोटे समानता है ।

कांग्रेसमें विरोधी स्तरोंके तीव्रतर होनेके प्रत्येक अवसर पर महात्मा और उसके साथी आगमें कूद पड़ते हैं । गोदा तथा राजगुप्तगुप्तनके प्रश्नोंको लेकर सम्प्रदायवादों प्रमुख आक्रमणों विचारपूर्वक नेहरूके विरुद्ध स्थानान्तरित करनेके उद्देश्यसे वामपंथियोंके साथ हो गये । उन्होंने ऐसी स्थिति उस समय अपनाई । सामान्य धारण यह थी कि वे शक्तिपूर्ण, संगठित, हिन्दुभारतके समर्थक हैं । वे वामपंथियोंके आक्रमणोंकी भी मदैव लक्ष्य-भ्रष्ट करनेमें इस कारण सफल हो गये, क्योंकि पहलेमे ही दुर्बलतामें पड़े वामपंथियोंको उत्तमज्ञानमें उन्हें कुछ कठिनाई नहीं हुई ।

संप्रदायवादी और साम्यवादी दोनों ही सामान्यरूपमें नेहरूकी कट्टर आलोचना करते हैं और परिणामस्वरूप राष्ट्रीय नीतिके सभी स्वीकारात्मक पहलू आलोचना के विषय बन जाते हैं । साम्यवादी इस सङ्घर्षमें सम्मिलित तो नहीं होते, किन्तु

सार्थ ज नी न ए क ता

वे उन मंचों पर विद्यमान रहते हैं, जिन पर गोदाके सम्बंधमें पंचशीलका उपहास होता हो, जहाँ समाजवादी उपायोंकी अपर्याप्तताके कारण नहीं, बल्कि इस कारण धमियाँ उड़ाई जाती हों कि यह कॉंग्रेसको पीटनेका उपयोगी डंका है। प्रत्येक तथाकथित समुक्त मोर्चे पर साम्यवादियोंका स्वर सम्प्रदायवादियोंके स्वरके नीचे डूब जाता है।

बस्तुतः विभिन्न हिन्दू सांप्रदायिक संगठनों द्वारा प्रचारित नीतियों में अंतर है। उदाहरणार्थ जनसुख मीके पर विमान आदोलनोंका नेतृत्व करनेका प्रश्न हाथमें लेनेके लिये तैयार रहता है। इन विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा वामपंथियोंके नामपर शक्ति प्राप्त करने तथा बुद्धिहीन लोगोंको धमकानेके लिये राजनैतिक जाल फेंकनेकी आशा की जाती है। जब कार्यका अवसर आता है तो सम्प्रदायवादी एक संगठित दलके रूपमें एक आवाजसे कार्य करनेके लिये तैयार रहते हैं।

जब तक भारतीय जीवनका मुट्ठा सामाजिक पुनर्गठन नहीं होता, तब तक हिन्दू सम्प्रदायवाद मंदिर इस देशमें भारी सकटस्वरूप रहेगा। सांप्रदायिक नेताओं द्वारा साम्प्रदायवादके अभिकर्ता उसेजक स्वरूप कार्य करनेकी सानुकूलताके कारण यह सकट और भी अधिक बढ़ जाता है। नेहरू द्वारा इस दिग्गमें बारबार दी जानेवाली चेतावनी निराकार नहीं है।

फिर प्रजा समाजवादी पार्टी भी है। यह पार्टी दक्षिणपंथी समाजवादियों और प्रजाओं अर्थात् कॉंग्रेसमें अग्रगण्य होकर अलग होनेवालों या उन्मूलनवादियों का एक अजीब गठबंधन है। इस पार्टीमें अनेक आदरणीय व्यक्तियोंकी निष्ठा प्राप्त है और इसके कार्यकर्ताओंमें ऐसे सक्रियतावादी हैं, जो सभी प्रतिमानोंके अनुरार सुंदर राजनैतिक वर्गमें शामिल किये जा सकते हैं। समाजवादी दल इस पार्टीकी प्रमुख शक्ति है।

इस पार्टी पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। कारण यह है कि यद्यपि इसे यथेष्ट समर्थन प्राप्त है, किन्तु इसकी शक्ति बिखरी हुई है और इसकी घोषित नीतियोंमें स्पष्टरूपसे असंबद्धता और अस्पष्टता दिखाई पड़ती है। इस पार्टीकी स्थिति समझनेके लिये इसकी पृष्ठभूमि पर दृष्टिगान करना आवश्यक प्रतीत होता है।

१९४८ तक समाजवादी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके अंदर रहकर एक संगठित इकाईके रूपमें कार्य करती थी। जहाँ एक ओर साम्यवादी १९४२ के अंदर कांग्रेसमें निकाल दिये गये, वहाँ समाजवादियोंने नामिक अधिवेशनके पश्चात् अपने आपको कांग्रेससे बिलग कर लिया। इस नई पार्टीकी रचनाके कारण हूँदना कठिन है। सम्मेलनमें अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए जयप्रकाश नारायणने निम्नलिखित बात कही थी —“ लोकतंत्रमें विश्वास रखनेवाले तथा देश और राज्यके प्रति निष्ठावान, जनप्रिय विरोधी दलकी अनुपस्थितिका परिणाम निश्चिन्त रूपमें सर्वहारावादको प्रोत्साहन देना है।”

वास्तविकता यह है कि १९४८ के अन्दर बी टी रणदिवेके नेतृत्वमें साम्यवादी पार्टी अवैध परिस्थितियोंमें कार्यरत थी और दुःसाहसिक नीति द्वारा सरकारको उलटनेका प्रयत्न कर रही थी। देश विभाजनके उत्तरगामी वर्षोंमें देशके अन्दर व्याप्त असंतोषके साथ इस ताब्यने मिलकर समाजवादके नेताओंको यह सोचनेके लिये प्रोत्साहित किया कि उनकी पार्टी एक स्वतंत्र, वैध, विरोधी दलके रूपमें कार्य कर सकेगी। इसके अनिश्चित यह भी सोचा गया कि इन विरोधी कार्यवाहियोंके द्वारा असंतुष्ट तब साम्यवादको ओर जानेसे रोके जा सकेंगे। समाजवादी सदैव साम्यवादके कट्टर शत्रु रहे हैं। तीसरे वर्षोंमें वामपंथी एकताके दुर्भाग्यपूर्ण प्रयत्नने उन्हें अपने समर्थकोंके एक बड़े भागसे वंचित कर दिया था। साम्यवादियोंने समाजवादियोंको अपने अंदर बिलीन कर लिया। और “जन-संग्रामके” अवसर पर निश्चित रूपमें यह बहुत अधिक बढ़ गई।

पूरणतया साम्यवाद विरोधी स्वतंत्र समाजवादी पार्टीकी रचनाका तत्कालीन परिणाम सार्वजनिक संगठनमें फूट और हड़तालकी कार्यवाहियोंको निष्क्रिय करना हुआ। वाममार्गियोंके सभी दलों द्वारा परस्पर विरोधी कार्योंका परिणाम यह निकला कि देशकी सर्वाधिक संगठित ट्रेड यूनियन ‘श्रॉल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन’ भी निर्बल हो गई। यह संपर्क कांग्रेसको सन्तुष्टिके लिये जारी रहा तथा उन्होंने वाम मार्गियों द्वारा कामगारों और किसानोंमें उत्पन्न की गई उदासीनता और प्रचारभ्रष्टाका लाभ उठाकर अपना सार्वजनिक संगठन मजबूत कर डाला।

सार्वजनिक एकता

जहाँ एक ओर साम्यवादी पार्टीने अपनी शक्ति का सञ्चित कार्यवाहियोंमें अप्रत्यक्ष किया, वहीं समाजवादियोंने महत्वपूर्ण समस्याओं पर स्पष्ट स्थिति ग्रहण न करके अपनी बरवादी की। अशोक मेहता और राममनोहर लोहियाके समान शीर्षस्थ नेता तो वर्गसपर्यंक अस्तित्वको ही अस्वीकार करने लगे। १९४६ में पटनाके अंदर होनेवाले पार्टीके सातवें अधिवेशनमें अशोक मेहताने कहा कि “उम देशमें जहाँ ‘लोकतन्त्र’ विद्यमान हो, वर्गसपर्यंक कोई विरोध आवश्यकता नहीं है।” लोहियाने भी लगभग इसी प्रकारकी बातें की।

इसमें भी अधिक आश्चर्यजनक बात विश्वममस्या सम्बंधी समाजवादियोंकी स्थिति थी। १९४० में मद्रास अधिवेशनके अंदर जयप्रकाश नारायण बोल उठे कि “अमेरिकामें ‘न्यू डील’ के अंदर कल्याणकारी राज्यकी दिशामें जो प्रगति प्रारम्भ की गई थी, वह अभी निर्विरोध जारी है।” लोहियाने ‘सपर्यं’में प्रकाशित अपने एक लेखमें लिखा, “मैं अमेरिकाको यह बनाना चाहता हूँ .. भारतमें उसके सर्वोत्तम मित्र समाजवादी हूँ।” और अशोक मेहता विश्वासपूर्वक यह घोषित कर उठे कि “अमेरिकामें दैनिक तैयारियोंके ऊपर पूरा दबाव भी जीवन-स्तरको गिरानेमें असफल हो जाता है।”

समाजवादी नेताओंकी साम्यवादविरोधी विचारधाराने उन्हें नेहरूकी विदेशी नीति और राष्ट्रीय निराश्रयता प्रतिपादनके प्रयत्नोंमें विरोधी बनाने पर विवश कर दिया। चीनकी मित्रता दुर्भाग्यपूर्ण समझी गई और शीत युद्ध पर प्रभाव डालने वाली तटस्थताकी भी आलोचना होने लगी। समाजवादियोंने सक्रिय रूपसे नेहरू और तटस्थताको अपने आक्रमणका लक्ष्य बनानेवाले अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रूड यूनिपन और बुद्धिजीवी समूहोंका समर्थन करना प्रारम्भ कर दिया।

ऐसे दुर्बोध दृष्टिकोणों और कार्यवाहियोंके परिणाम स्वरूप समाजवादी पार्टीके अंदर विद्यमान वामपक्षी दलने विद्रोह कर दिया जिसमें अरुणा आसफअलीके समान प्रमुख नेता भी सम्मिलित थे। अन्य चुनावोंके निकट आनेके साथ साथ यह खाई अधिक चौड़ी होती गई। इस समय सभी प्रकारकी विरोधी प्रवृत्तियाँ प्रगट होने लगीं।

तथापि चुनावोंके लिये पार्टीने इस आशाके साथ तैयारी की कि वह कमसे कम ८०० विधान सभाई और १०० लोक सभाई सीटों पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे। उनका प्रचार एक मजाक रहा। उन्हें दोनों स्थानों पर कमसे १२६ और १२ सीटोंमें मनुष्ट होना पड़ा और साथही विरोधी नेताका पद अवैधताके पस्वान्त इन्ही दिनों प्रगट होनेवाली साम्यवादी पार्टीके लिये छोड़ना पड़ा।

पूर्वकालीन अभ्यासका सर्वसमन परिणाम कृपक मजदूर प्रजा पार्टीके साथ असंगत सम्मिलन हुआ, जो कॉम्रेसी विदेशियों द्वारा निर्मित पार्टी थी। प्रचाममानवाद जिसे अनेक नेताओंने लोकतन्त्री समाजवादकी सजा दी थी, इस सजाधकी दूर करनेमें असमर्थ रहा। वस्तुतः समाजवादके साथ गांधी दर्शनके योगने इस गड़बड़को अधिक उलझा दिया। आगामी वर्षोंमें यह पार्टी उपहासास्पद बन गई। राजनैतिक उपदेशक इस पार्टी द्वारा मिसलाए जानेवाले समाजवादको देखकर आश्चर्यचकित थे। यूरोपीय और एशियाधी समाजवादियों सहित समस्त समार द्वारा प्रशस्ति देहू की विदेशी नीतिना प्रजा समाजवादी उपहास करते थे। विकासशील सार्वजनिक क्षेत्रको एकाधिपति हितों पर कुयाराधान करनेवाला नहीं माना गया, बल्कि उसे सर्वहारी एवं टनारखाही सकटके समान समझा गया। इसके अतिरिक्त प्रजा समाजवादियोंके ‘लोकतांत्रिक गवेषणा दल’ और ‘स्वतंत्र एशिया समिति’ सरोखे समुदायोंके साथ अधिनाधिक स्पर्कके फलस्वरूप वे राष्ट्रीय जीवनकी मुख्य धाराओंमें दूर पड़ते गये।

पार्टी कार्यकर्त्ताओंका बड़ा भारी दल ‘समाजवाद टन्मुख’ कॉम्रेसकी ओर अथवा साम्यवादकी ओर अप्रसर होने लगा। अन्य लोग अपने सधन द्वारा निष्क्रिय हो गये। जयप्रकाश नारायण भूदानके अरर अपने समाजवादको भी भूल गये। अशोक मेहता और लोहिया साम्यवादी शरुविपयक प्रलापमें अपनी शक्तिको अव्यव्य करने लगे।

अगला परिवर्तन उनमें दार पड़ना थी। लोहियाने ‘सुरक्षा वाल्व’के रूपमें एक नई समाजवादी पार्टीकी रचना कर वाली और वर्गसधर्षमें अपना विधाम प्रतिष्ठित लिया। मधु लिगयेने पुनर्मूल्याकन प्रारम्भ कर दिया। जिनके फलस्वरूप वे अशोक

सार्थजनीन एकता

मेइताके प्रतिष्ठित नेतृत्वके साथ अधिकाधिक संपर्कमें आते गये । प्रजापार्टीवाले कांग्रेस छोड़ने पर स्वयं आधर्यान्वित थे ।

आज जब द्वितीय आम चुनाव होने जा रहे हैं । समाजवादी और प्रजापार्टीवाले यह नहीं समझ पाते कि उन्हें क्या करना चाहिये । पिछले चुनावके परिणामोंने उन्हें निर्णायक रूपमें यह बतला दिया कि साम्यवादी मोर्चेके उम्मीदवारोंका विरोध करके तथा इस प्रकार वामपक्षी मतोंको विभजित करके पार्टीको किसी प्रकारका लाभ नहीं पहुँचना । यही कारण है कि वे आजकल कांग्रेसको हरानेके लिये विरोधी दलोंके साथ चुनाव समझौते करना चाहते हैं ।

इन प्रस्तावित समझौतोंके ऊपर आजकल गमनागम बहम हो रही है, किन्तु इस पर विचार करनेसे पहले साम्यवादी पार्टीकी स्थितिको समझना आवश्यक है, क्योंकि उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । मित्र और शत्रु दोनों ही स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस सत्ताके लिये यही सर्वाधिक भोषण लक्ष्य है ।

अनेक भयंकर और भारी गलतियों के बावजूद भी साम्यवादी पार्टी की शक्ति बढ़ती जा रही है । दक्षिणके कुछ भागोंमें, उदाहरणार्थ, केरल और आंध्रमें इस पार्टीको यथेष्ट शक्ति प्राप्त हो चुकी है । बंगालके अंदर कांग्रेसकी सगणनाको असत्य प्रमाणित करती हुई यह पार्टी निरंतर अग्रसर हो रही है । महाराष्ट्रके अंदर भी प्रमुख शक्ति होनेकी सम्भावना है । यह उस पार्टीके स्वाम मोर्चे है, किन्तु देशके अन्य भागोंमें भी इसके समर्थक चारों ओर फैले हुए हैं ।

यद्यपि जनता साम्यवादी पार्टीको और सदैव मार्ग प्रदर्शनार्थ उन्मुख होती है, तथापि उन्हें एक ऐसे नेतृत्वका सामना करना पड़ना है, जो उनकी समस्याओं की तरह नहीं समझ पाता । बारम्बार एक पूराका पूरा प्रदेश कार्यवाई करता है किन्तु उन्हें गहन नीतियोंके परिणामस्वरूप सन्निकट साथ प्रत्यावर्तित होनेके लिये विवश होना पड़ता है । तेलंगाना, आंध्र, गोवा तथा राज्य पुनर्गठन-विषयक कुछ मामलोंमें यही कहानी बारम्बार दुहराई गई है । संसदके अंदर भी साम्यवादी प्रवृत्ति अपना चिन्ह छोड़नेमें अग्रसर हुए हैं ।

साम्यवादी पार्टी का अवरोधित विकास

ऐसा क्यों होना है ? पार्टीके अंदर अनेक निस्वार्थी, निष्ठावान और बुद्धिमान अछूत कार्यकर्त्ता विद्यमान हैं। उनका इतिहास अनेक निराशापूर्ण परिस्थितियोंमें साहम और धीरमाके प्रदर्शनमें परिपूर्ण है। ऊपरी तौरमें पार्टीके अवरोधित विकासका कोई स्पष्ट कारण नहीं दिखलाई पड़ता। फिर भी इनका कुछ कारण तो होना ही चाहिये।

पार्टीके विलम्बित जन्ममें भारी गलतियोंके पावबंद भी नेताओंके अन्तरंग मंडलके अपरिवर्तित रहने में, वास्तविक अध्ययनकी आवश्यकताकी अपेक्षामें और तुरिपूर्ण संगठन विपन्न तरीके अंगीकार करनेमें उपरोक्त परिणामकी कुछी विद्यमान है। इन सामान्य कारणोंके अधिक प्रभावशाली होनेका कारण यही है कि उन्हें कैम्पिस पार्टीके कुराज नेताओंका सामना करना पड़ता है, जो इस विषयमें न तो चिंतित हो हैं और न विरक्त।

भारतके अंदर साम्यवादी पार्टीकी नींव यूरोप और एशियाकी इन्हीं पार्टियोंके निर्माणके बहुत दिनों बाद तीसरे बंपोंमें रखी गई। इसका कारण मजदूर वर्गके अल्पसंख्यकता नहीं थी। चीन सरीखे निम्नरे देशमें भी नागरिक और सैनिक दोनों ही क्षेत्रोंमें साम्यवादी बीगवे बंपोंमें ही राष्ट्रीय शक्तिके रूपमें प्रतिष्ठित हो चुके थे। छोटेमें हिन्देशियाके सम्बन्धमें भी यही वास्तुस्थिति थी। फिर भारतमें मार्क्सवादी कार्यवाइयोंके इतने विशिष्ट आरम्भका क्या कारण था ?

अन्य औपनिवेशिक देशोंमें भारत दो मुख्य बातोंमें भिन्न था। प्रथम बात तो यह थी कि ब्रिटिश शासक गाँवों और नव विकसित नगरोंके बीच एक ऐसी सांस्कृतिक और सामाजिक खाई बनानेमें सफल हो गये जिसका चीन या दक्षिण पूर्वी एशियाकी देशोंमें अस्तित्व ही न था।

भारत और चीनके पारस्परिक अंतरोंका कारण अन्य बातोंके साथ-साथ औपनिवेशिक उद्देहनके पृथक पृथक तरीके वगैरह भी था। भारतमें ब्रिटेनका तो देशके भीतरी प्रदेशों तक प्रविष्ट होकर नगरों और रेल्वेकी महायन्त्रोंसे प्रशासनिक ढाँचेको सुदृढ़ कर सके। संपूर्ण देशमें उन्होंने नगरोंको अगल भारतीय जीवनका लगभग केन्द्र ही बना डाला। चीनके अंदर विदेशी शक्तियोंने अपनी कार्यवाहियों तटीय

सार्ध जनो न एकता

प्रदेशमें सीमित रखकर देशके भीतरी भागोंकी सम्पत्तिके उद्दोहनका साधन बंदरगाहोंको बनाया । इस कारण चीनके विस्तृत आंतरिक प्रदेशके सामंती जीवन पर भारतकी तरह विशेष प्रभाव नहीं पड़ा ।

इस अंतर का दूसरा कारण अनेक साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा उद्दोहित होनेके बावजूद भी इनकी पारस्परिक प्रतिद्वंद्विताका ह्यभ उद्यमर चीन द्वारा किसी अंश तक अपनी स्वतंत्रताकी रक्षा थी । भारतमें ऐसी बात सम्भव न हो सकी, क्योंकि इस देशमें ब्रिटेनवासियोंकी पकड़ मुट्ठ थी, जिमने उसे अंतराष्ट्रीयधाराने दूर फेंक दिया । साथ ही साथ उन लोगोंने भारतीय विचारभाराको पुनर्गठित करनेकी नीति भी अपनाई । इस नीतिको प्रमुख उपासक मेकाले था । वह भारतीयोंको इस प्रकार शिक्षित करना चाहता था, जिमसे वे पूरे अंग्रेज बन जायें । इस नीति द्वारा यथेष्ट लाभ प्राप्त होनेकी आशा थी ।

साथ ही ब्रिटेनके अधीन रहकर भारतने चीनकी अपेक्षा अधिक तेजीसे तरकीबी थी, जिसका उद्दोहन अनेक परस्पर विरोधी शक्तियों कर रही थी । परिणामस्वरूप भारतमें अपेक्षाकृत, विकसित और व्याप्त स्थानीय पूँजीजीवियोंका उदय हुआ । यह वर्ग ब्रिटिश ढंग पर शिक्षित व्यवसायियोंके नेतृत्वमें अन्य औपनिवेशिक पूँजीजीवियोंकी अपेक्षा अधिक विकसित हो गया । आश्चर्य यह है कि दोनों विश्वयुद्धोंमें प्राप्त होनेवाले लाभोंके परिणामस्वरूप इस वर्गकी उन्नति हुई और इस प्रकार इन्होंने अपने विदेशी शासकोंके अनेकों राजनैतिक सिद्धांतोंको अपना लिया ।

चीनमें देशके आंतरिक विस्तृत भागपर प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करनेवाली कोई केन्द्रीय सत्ता नहीं थी । यह संपूर्ण विस्तृत प्रदेश निरचयात्मक रूपसे धौद्धिक सरदारोंके प्रभावमें था । भारतमें परिस्थिति भिन्न होनेके कारण नगरोंकी जनसंख्या प्रत्येक प्रकारकी कार्यवाहियोंका केन्द्रस्थल बन गई । किन्तु अंग्रेजों पदे लिखे नवोदित पूँजीजीवियोंके अधीन ' नियंत्रित प्रगति ' पर सदैव जोर डाला जाता था ।

परिणामस्वरूप दोनों देशोंमें साम्यवादके रूपमें भी विभिन्नता आ गई । चीनी साम्यवादियोंकी प्रसिद्ध लम्बी यात्रा उस देशमें केन्द्रीय सत्ताकी अनुपस्थितिके कारण ही सम्भव हो सकी । भारतमें तदनु रूप प्रगतिकी आशा करना मूर्खतापूर्ण

था। यहाँ पर दिल्ली सरकार अपनी शक्तों को केन्द्रित करके ऐसे विद्रोही प्रयत्नों को विनष्ट कर सकती थी। १८५७ के विद्रोह में अंग्रेजों ने उपयुक्त शिक्षा ग्रहण कर ली थी।

यद्यपि आत्मरक्षा और हिंसा जारी रही, किन्तु शत्रुओं के प्रतिबंधन तथा उन्हें काममें लाने के लिये संगठित होने की असम्भावना ने भारतीय राष्ट्रीयता को सर्वश्रेष्ठ अपनी विशिष्ट प्रणाली अपनाने पर विवश कर दिया। प्रारम्भिक अवस्थामें नगर और गाँवों के बीच की खाई को दृष्टिगत रखते हुए हमका रूप निर्धारित हुआ था। नगरों के अंदर प्रेरणा देनेवाला जोन स्टुडेंट मिल, हंस और थामस पिने सरीखे व्यक्तियों की विचारधाराने, एडिप्रस्त अग्रगतिशील गाँवों का स्पर्श भी नहीं किया था। इन्हीं नगरों के अंदर वर्तमान शताब्दी के आरम्भ में गाँवों तथा राजनैतिक कार्यवाही में उनकी कार्यविधि विषयक किसी प्रकार की वास्तविक चिन्ता किये बिना ही भारतीय देशभक्तों ने अपने कार्यकलाप प्रारम्भ कर दिये।

अंग्रेजी सविधानवादी उल्लंघन जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यों पर व्याप्त थी और जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक, लाजपत राय आदिके कातिवारी उन्नाहको 'अतिवादी' कह कर अस्वीकार कर दिया था, वास्तव में मध्यम वर्गीय राजनैतिक कार्यवाही में सार्वजनिक समर्थन की उपेक्षा का परिणाम था। अंग्रेजों ने सौदेबाना करने की थी, उनसे समझौता करना था। यहाँ तक कि ब्रिटिश मुकुट का भी आदर करना था। ऐसा करने के उपरान्त यह विश्वास किया जाता था कि स्वराज प्राप्त हो सवेगा।

प्रथम विश्वयुद्ध के अवसर पर भारतीय राष्ट्रवाद के निर्माणकाल में अंग्रेजों का विरोध करने के लिये केवल आत्मरक्षा दियोंने कमर बसी। परन्तु देश में व्याप्त गर-ब और निराशा को दूर करने के लिये नवीन कातिकारियों की आवश्यकता थी। मध्यम वर्गीय युवकों में इनका आकर्षण होना चाहिये था, किन्तु प्राँवों के समान ही युवकों ने भी ग्रामों और नगरों के बीच की खाई यथेष्ट चौड़ी थी, जिसका पाटना कठिन दीख पड़ता था। विदेशी बोलो, पश्चिमी पोशाक, विदेशी शालों की नकल और स्वतंत्रता के स्वयंमेव प्राप्त होने की आशा ने सुविधामित बुद्धिमानों को जनता के साथ

सा र्व ज नी न ण क ता

संयुक्त होनेमें वंचित कर दिया। 'बाले साहब' या 'बोग' (पश्चिमी रंगमें रंगे देशी सभ्यों) के उपहानास्पद रूपदर्शनके लिये अधिक दूर जानकी आवश्यकता नहीं।

चीन एवं अन्य उपनिवेशों में वयपि इसी तरहके दृष्टिकोण दिखलाई पड़ते थे, किन्तु वहाँ पर उनका प्रभाव भारतके समान नहीं था। जिस समय भारतीय राष्ट्रवादी ब्रिटिश मुकुटके प्रति अपनी स्वामिभक्तिका परिचय दे रहे थे, चीनमें मन-यान-सेनके साइसी नेतृत्वमें वहाँकी जनता विद्रोह कर उठी थी।

तथापि भारतके अंदर विद्यमान खाई भी अंतमें पटनेवाली थी। गांधीजी मंत्रपर उपस्थित हुये। उन्होंने सविधानवादी अस्थिरात् से इस सर्पको उठाकर जन आंदोलनकी मुक्त भूमि पर लाकर खड़ा कर दिया। ऐसा करते समय उन्हें नगरोंकी कृत्रिम श्रेष्ठताकी भावनाको दूर करनेकी आवश्यकता महसूस हुई। उन्होंने गँवोंको अपने कार्यका आधार बनाकर सर्वसाधारण पर प्रभाव डालनेवाली समस्याओं पर ध्यान केन्द्रित किया।

चंपारन और बारदोलीके किसानोंके मध्य सत्याग्रहकी परीक्षा हुई। लाली यात्राके समय साधारण नमक ही सर्पसंज्ञा प्रतीक बन गया। और इस प्रकार सफलताके अधिक सफलताकी और यह सर्प अग्रसर होना गया। थोड़े ही समयमें गांधीजी नगर निवासी मध्यम वर्गीय देशभक्तोंके दृष्टिकोणको बदलनेमें सफल हो गये। स्वयं अपने तथा अपने अनुयायियोंके लिये वस्त्र और आचारके कठोर नियम निर्धारण द्वारा वे इस खाईके पड़ावको अधिक शक्तिशाली बना कर भारतके करोड़ों लोगोंकी अपार शक्ति उन्मुक्त कर सके।

करोड़ों लोग उनके चरण-चिन्होंका अनुसरण करने लगे। वे उनमें सभी तरहके सतोचित गुणोंका वाग बनलाते थे। उनके कटुतम शत्रु विंस्टन चर्चिल भी यह नहीं जानते थे कि 'अर्धनग्न फकीर' कहते समय वे गांधीजीकी समस्त उपमहा-द्वीपकी प्रेरणा प्रदायक शक्तिका बालविक भेद प्रगट करते हैं।

वे लगभग नग्न रहते थे। वे इस देशमें सबसे अधिक विनीत प्रणीत होते थे। लाखों व्यक्ति ओटों पर उनके नामका उच्चारण करते हुए ब्रिटिश आतंकका सामना

करते थे। किन्तु बोलशेविक क्रांतिसे प्रभावित मध्यम वर्गीय युवकोंने उनके लगेजी-धारी रूपमें पुराने कालकी ओर प्रयाण या उदारवादके दर्शन किये। यद्यपि चालीसवें वर्षोंमें साम्यवादी नेता पी० सी० जोशीने सम्भवतया प्रथम बार उन्हें 'राष्ट्रीयता' की सजा दी थी, किन्तु उन लोगोंको तो उनमें उपरोक्त रूपके ही दर्शन हो रहे हैं। वे राजनीतिमें विघ्न चाहते थे, जब कि गांधीजी समराज्यकी बात करते थे। कस्बियोंमें देशकी वैज्ञानिक दृष्टिकोणकी पहचान भी अधिक जरूरत थी, किन्तु केवल सिद्धान्त-रूपमें ही नहीं, जब तक उसे जनताका समर्थन प्राप्त न हो।

मार्क्सवादी विचारक भारतके राजनैतिक समुदाय पर बीसवें वर्षोंमें आये, जब कि स्वतंत्रता संग्राम पर मध्यम वर्गीय नियंत्रण था, जो गांधीजीके सत्याग्रहके नये तरीकेसे प्रेरणा प्राप्त कर रहे थे। उन्होंने गांधीजीके अमाधारण प्रभावका विवेचन करनेकी प्रयत्न नहीं किया, बल्कि यत्रतः इस दृष्टिकोणको स्वीकार कर लिया कि जब तक मजदूरोंको स्वतंत्रता संपर्क नैतृत्व करनेके निचे संगठित नहीं किया जाता, तब तक यह विचार केवल कल्पना मात्र बना रहेगा। उन्होंने मजदूरोंको संगठित करना प्रारम्भ कर दिया किन्तु दशाद्वियोंके औपनिवेशिक इतिहासमें प्रतिबन्धित होकर अपने प्रयत्नोंको प्रमुख रूपसे नगरोंमें ही सीमित रखता। यही नागरिक केन्द्र भावधर्मके अनेकों वर्षों तक उनके मोर्चे रहे।

प्रारम्भिक मार्क्सवादियोंने कॉम्रेड पार्टी पर कुछ प्रभाव डाला, इस बातको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। किन्तु इस प्रभावका उनके स्वयंके हितमें संगठन नहीं हुआ। किसानोंके प्रश्न पर उन्होंने कभी गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं किया। जिसदिह समस्त वाममार्गियोंने ग्रामीण क्षेत्रों और रियासतोंमें कॉम्रेडके समर्थक बनानेमें योग दिया किन्तु नेतृत्व गांधीजीके अनुगामियोंके ही हाथमें रहा, जो वर्षोंके प्रयत्न स्वरूप वैदिक और भावनात्मक रूपमें किसानोंके अधिक निकट आ गये थे।

चीनमें कम्युनिस्टोंके बावजूद भी जनताके नेता यथेष्ट कुशल थे। वहाँ बीसवें वर्षोंमें ही माउन्टेन्-लुंग शानिपूर्वक किसानोंकी समस्याका अध्ययन करके पार्टीकी सफलताकी कुंजी हूँद रहे थे, जिसे कुछ दिनों पश्चात् उन्होंने और साम्यवादी पार्टीने आगे बढ़ाया। भारतमें नवनिर्मित साम्यवादी पार्टी नगरी तक सीमित रहनेकी

सार्धजन एकता

बीमारीने ही कष्ट पानी रह्यो। भारतीय परिस्थितिमें हमी अनुभव लागू करनेका यह बड़ा अपरिष्कृत ढंग था।

इस परिस्थितिकी सभालनेके लिये कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया गया। तथापि चालीसवें वर्षोंमें इस गलतीकी खोजना कठिन हो गया, क्योंकि परिस्थितिकी पाठाने विमानोंकी समस्याको अपने हाथमें ले लिया था। धीरे धीरे 'जनसंघर्ष' की भूलोंके यादगूद भी ग्रामीण मोर्चोंका विराम हुआ। सबसे अधिक शक्तिशाली रूप सेलंगानामें प्रकट हुआ।

किन्तु यह कहानी अत्यन्तही थी। परिस्थितिने कबड्डी बढ़ा दी। बी. टी. रणदिवेके नये नेतृत्वने उपेक्षाके साथ कुछ मोर्चोंको एक ओर फेंक कर नगरोंके सगठन पर पुनः और डाला और अनेक अनुसूद्ध वर्गगत मिद्वातोंको प्रथम दिया। इसका अर्थ यह निकलता था कि साम्यवादी बीर व्यक्तिगत रूपसे नगरोंमें शहीद होकर लोगोंको जातिनी प्रेरणा दे सकते थे। इसी तरहकी कुछ भावनाओंमें भारतके पुराने क्रांतिकारी बह गये थे और कार्यकर्ता भी यह अनुभव करते थे कि कहीं कुछ गलती हो गई है। थोड़े ही दिनों पश्चात् उन्हें माउन्टेन्सुंग की गलतियोंका पाठ ऐसे समय सुननेको मिला जब चीनी क्रांति सफलताके द्वार खटखट रही थी।

परिणाम यह हुआ कि दिनोदिन विकसित होनेवाली विमान सभाओंको अपनी मील मरनेके लिये छोड़ दिया गया। यदि विमान आंदोलन चलाये गये तो उसके कारण नगरों तथा वहीं सीमित मजदूर वर्गके जरिये राजनैतिक उन्नतिकी थोपनेके लिये अपनाई जानेवाली एक अस्थाई काल थी। इस उलझनके कारण साम्प्रतिक "जनपाटी" का उदय रुक गया तथा उसका नेतृत्व एक छोटे और परिवर्तनविरोधी दलके हाथमें आ गया, जिनके मिद्वात और विवेचना सदैव परिस्थितिकी आवश्यकताओंमें कम रहती थी।

जहाँ कहीं आप्रकी तरह ग्रामीण क्षेत्रोंके आर्थिक संकटको सुलभानेका प्रयत्न किया गया, कृषक, बौद्धिक क्षेत्र तीव्रतापूर्वक विकसित हुए, चाहे नगरवासी मजदूरोंके सगठन संबंधी विचारोंकी पूरी तरह प्रतिष्ठित करनेके कारण उनकी अग्रिम प्रगति रुक गई हो।

सार्वजनिक संगठनों का अंत

ग्रामीण मजदूरोंके संगठन बनानेकी आवश्यकता पर जोर दालना ठीक था, लेकिन इतने सीमित रूपमें नहीं जिससे किसानोंकी एकता ही नष्ट हो गई। इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। परिणामस्वरूप आपके ग्रामीण क्षेत्रोंमें भी कंप्रेस शक्तिशाली बनी रही।

फिर भी जब कभी मजदूर और किसान संगठनोंकी स्वस्थ और सुनुलित प्रगति हुई है, साम्यवादी पार्टीने अपनी शक्ति प्रदर्शित की है। रणवीराल और युक्तिमें अनेक गलतियों करनेके बावजूद भी वे ऐसा करनेमें सफल हो सके हैं। १९४२ और १९४८ के मध्य वह बात विरोध तौरपर सत्य थी। ग्रामीण और नगरिक दोनों ही क्षेत्रोंमें जनसंगठनोंका अविभाज्य हुआ। मजदूर, किसान, युवक, मध्यम वर्गीय कर्मचारी और यहाँ तक कि पूँजीजीवी वर्ग भी सक्रिय हो उठे। उन दिनों नन्ही-सी साम्यवादी पार्टीकी सदस्यता भी ४००० से बढ़कर १००,००० तक पहुँच गई। यह शक्ति इतनी अधिक थी कि हमने राष्ट्रीय राजनैतिक, सामाजिक और साम्प्रदायिक समस्याओंपर अपना चिन्ह अवैतनिक कर दिया।

आजकल चारों ओर उदासीनता और संशय व्याप्त है। वास्तविक महत्त्व सोने तथा किसान सभाओंके दुर्बल होकर तिर-तिर होनेके फलस्वरूप सार्वजनिक संगठनोंका अंत हो गया। जहाँ कहीं वे अब भी बने हुए हैं वहाँ वे सच्चीर्ण एव अनार्थिक सिद्धांतोंमें पड़े तड़कत रहे हैं और साम्यवादी पार्टी अपने क्रियाकलापोंके जरिये नहीं बल्कि मतियोंके झंझटके जरिये अपना प्रभाव कायम रखना चाहती है। इन प्रातिमूलक विचारोंसे त्यागकर अपने कार्य कलापोंको अध्ययन तथा अन्वेषणमें मगुल करनेके उपरान्त ही पुनर्जीवन सम्भाव हो सकेगा।

इसमें कोई विलक्षणता नहीं है क्योंकि जब किसान मजदूरोंका संगठन जाएगा सार्वजनिक आधार ही निर्भर हो, तो सभी स्तरोंपर पूँजीजीवियोंके प्रचलित तरीकों द्वारा नियंत्रण स्थापित करनेकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है। उस समय 'जन-संगठन' किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूहके द्वाारा पर नाबनेवाले बन जाते हैं, निहित स्वार्थ विकसित होने लगते हैं, नीतिनिर्माणमें लोकतान्त्रिक अनिव्यक्ति और

सार्ध जनी न एक ता

सार्धजनिक सहयोग अव्यवहार हो जाता है। उसका एक अग्रगण्य बच रहता है जिसका समय कुसमय सक्रियताकी जरूरत होनेपर उपयोग हो सके।

वाममार्गी पार्टियोंने इन पूँजीजीवी प्रभावोंको पूरी तरह दूर करनेकी आशा करना एक आदर्शवादी कल्पना है, किन्तु इस परिस्थितिको समाप्त करनेके लिये जिन संगठनोंका निर्माण हुआ था, उनमें ही इस बातका प्रचार एक गम्भीर समस्या है। यह बात डेड युनियनोंके सम्बन्धमें ही नहीं बरन अखिल भारतीय शांतिमेलन तथा भारत-चीन और भारत-सोवियत मित्रता समितियोंके सम्बन्धमें भी सही है। सम्भवतया उनकी वृद्धिके लिये ऐसा अनुकूल अवसर कभी नहीं आया, किन्तु वे सकीर्ण तथा भारतका उचित प्रतिनिधित्व न करनेवाले संगठनों तक ही सीमित हैं।

मिथ्या सिद्धान्तों और गलत आदर्शोंके फलस्वरूप मजिद्व कौशल द्वारा नोले संचालनकी बीमारीकी यहाँ तक अपेक्षा हुई कि साम्यवादी पार्टी भी आजकल इन्ही प्रभावोंमें परेशान है। इसी बीमारीने संप्रदायवादका परिपोषण होगा है। बनरजा कॉंग्रेस (१९४८), मद्रास कॉंग्रेस (१९४४) और पालघाट कॉंग्रेस (१९४६) के प्रलेखोंका अध्ययन करनेमें यह पता चलता है कि भारतीय साम्यवाद शीर्षस्थ गुटबाजीके स्वर्णमें पथभ्रष्ट हो गया, अभी तक कोई तर्कसंगत राजनैतिक या आर्थिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सका तथा इस आंदोलनकी कोई यथार्थ संगठित प्रगति न हो सकी। आश्चर्य तो इस बातका है कि इनका सन होते हुए भी पार्टीको सर्वाधिक निष्ठावान मदस्वतार समर्थन प्राप्त है।

जिसी सीमा तक कॉंग्रेस पार्टीकी नीतियाँ भी इस सन्नम एव कारण हैं। नेहरू की परराष्ट्रनीति तथा द्वितीय योजनाके अंतर्गत आज़मन देशकी आर्थिक समस्याओंकी आर्थिक ध्यानपूर्वक सुलझानेके प्रयत्नने प्रशासनिक सन्तुष्टि तथा विरोधी पार्टीके पारस्परिक विमममतिके कारणोंको संकुचितकर दिया है। वस्तुतः साम्यवादी नेतृत्व ही अचरक यह निश्चय नहीं कर पाया है कि किस प्रकार आगे बढ़ा जाए ? कॉंग्रेसको ' सशर्त समर्थन ' देनेमें यह भय है कि कहीं अपेक्षाकृत बड़ी पार्टीकी उलझनोंमें डूब कर स्वयं अपनाही आस्तित्व न भिंट जाय। विरोध आकर्षक

दीखता है, किन्तु यह बात सिद्धान्त-विस्मय है। इस प्रकार यह सैद्धांतिक अग्रगम्यता उपस्थित हो गया है।

१९५७ के आरम्भ में होनेवाले सामान्य चुनावोंके कारण यह आवश्यक है कि साम्यवादी पार्टी एक तर्कसंगत स्थिति अपना ले। वामपक्षियोंकी ओरसे सभी तरफों परस्पर विरोधी मोर्चे उभर आ रही हैं। कुछ लोग 'वामपक्षीय एकताभी' बान करने हैं, कुछ 'राष्ट्रीय मंच' पर जोर देने हैं, जब कि कुछ अन्य लोग 'कॉंग्रेस-साम्यवादी गठबंधन' की बान करने लगते हैं। यह सिद्धान्त निरूपण प्रमुखतया शीर्षस्थ स्तर पर हो रहा है, क्योंकि साम्यवादी तथा अन्य वामपक्षीय पार्टियोंके कार्य-कर्त्ताओंमें दरअसल अपने विचार व्यक्त करनेका कभी अवसर ही नहीं दिया जाता।

आजकल भारतके राजनैतिक बानावरणका रूप कैसा है? प्रथम सामान्य चुनावोंका विवेचन करते समय हम देख चुके हैं कि ऊपरी धरानुपर राजनैतिक प्रतिद्वन्द्विता होनेके बावजूद भी देशकी प्रमुख पार्टियोंने राष्ट्रके लिये एक निश्चित न्यूनतम कार्यक्रम अपनाया स्वीकार किया था। कॉंग्रेस पार्टीभी स्वदेशी और विदेशी नीतियोंके परिणामस्वरूप इस आकर्षक परिवर्तनको अधिनाधिक शक्ति प्राप्त हुई।

उदाहरणार्थ, आजकल कॉंग्रेस और साम्यवादी पार्टियोंमें अधिकृत शोषणमें समझौतेकी काफी गुंजाइश है। विदेशी मामलोंमें साम्यवादी केवल ब्रिटिश राष्ट्रमंडलमें विद्युत होनेकी तथा समाजवादी समारमें अधिक निकट संपर्क स्थापित करनेकी मांग ही पेश कर पाते हैं। स्वदेशी मामलोंमें साम्यवादी द्वितीय योजनाका समर्थन करते हैं, किन्तु उद्योगोंमें अधिक पूंजीविविनियोजित करने पर जोर देने हैं, क्योंकि वे उन्हें पूर्णतया राज्य संचालित बनाना चाहते हैं। जहाँ तक माधन खोजनेका प्रश्न है साम्यवादी उन साधनोंकी ओर इंगित करते हैं जिनका अभी तक स्पर्श भी नहीं किया गया है, जैसे विदेशी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों और वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रोंमें प्राप्य लाभ। भौमिक समस्या पर दोनोंमें मतवैपरीत्य है किन्तु आजकल दोनों पार्टियाँ ऐसी भाषाका प्रयोग कर रही हैं, जिसमें जनताको सामान्यतया बहुत कुछ समानता दिखलाई पड़ती है।

सार्ध जन एकता

देशके राजनैतिक जीवनकी इन दोनों प्रमुख प्रवृत्तियोंके अभिसरणका प्रयत्न कांग्रेसमें अभी तक अच्छी तरह जमे हुए प्रमुख व्यापारियोंके प्रतिक्रियावादी प्रतिनिधियों तथा साम्यवादी पार्टीके कहरपयियों द्वारा प्रतिरोधित हो रहा है। उनकी प्रक्रिया पूर्णतया सुस्पष्ट है। प्रतिक्रियावादी, कांग्रेस द्वारा समर्थित नीतिमें भ्रम उत्पन्न करने और उसे साम्यवाद विरोधी रूपमें प्रदर्शित करनेका कोई अवसर नहीं चूकते, कहरपयी जाबजूस कर भेदोंको बड़ा चड़ाकर दिखाने हैं तथा समानताभी अवहेलना करते हैं।

साम्यवादी पार्टी द्वारा स्वतंत्र भारतके परिवर्तनशील वर्ग-गठबंधनोंके सञ्चिकरण विवेचन, पूँजीजीवियोंके आंतरिक सुधारोंका लाभ उठाने तथा स्वदेशाभिमानों और राष्ट्रीयतावादी वर्गोंके साथ मजदूरी स्थापनकी सम्भावना खोजनेकी अस्वीकृतिके अंदर कहरपयियोंकी अनेकानेक उतोत्तक मिल जाता है। यह घोषित किया जाता है कि पूँजीजीवियोंमें फूट पड़ी ही नहीं है।

साम्यवादी शक्तिके भी कदाचित् इसी कारण दर्शन हो जाते हैं कि देशमें जमींदार मौजूद हैं और उनमेंसे अनेकों कांग्रेसमें हैं। मदुराईमें निर्धारित पार्टी कार्यक्रमों की अखण्डित रूपमें कायम रक्खा जाता है, यद्यपि अनुभव ने स्पष्ट पहले ही उसे असमर्थ प्रमाणित कर दिया था। उसका पुनर्व्यवस्थापन शेष है।

व्यवहारमें यह बात अधिक स्पष्ट दिखालाई पड़ती है। आगामी चुनावोंके प्रसंगमें साम्यवादी नेतृत्व कांग्रेस सरकारमें यथासम्भव परिवर्तन चाहता है। इस लक्ष्यकी प्राप्ति हेतु साम्यवादी पार्टीने, कृपलानी, अशोक मेहता और जयप्रकाशकी प्रजा-समाजवादी पार्टीके साथ ही साथ लोहिया की साम्यवादी पार्टीमें भी मिलकर संयुक्त मोर्चा कायम करनेकी चर्चा की है। किन्तु प्रजा समाजवादी या समाजवादी पार्टीकी वर्तमान कांग्रेसमें किसी भी रूपमें अधिक प्रगतिशील नहीं समझा जा सकता। वे वर्ग सुधारकी बात भले ही करें, लेकिन साम्प्रदायिक जनसुधारको भी तो इसी प्रकारकी बातें करते हैं। वास्तविकता यह है कि कांग्रेसकी अपेक्षा वे साम्यवादी पार्टीके अधिक विरोधी हैं।

वे नेहरू की विदेश नीति, विशेषतः पर समाजवादी संसार की ओर उनके चुनाव के अधिक विरोधी हैं। उसे भारत में सर्वहारा साम्यवाद की प्रगति के सहायक समझते हैं। उन्हें यूरोपीय दक्षिण पंथी समाजवादियों के अनुस्यू नेहरू आचरण अधिक पसंद आयेगा, जो सीमाव्यवस्था अपनी नीतियों के पुनर्व्यवस्थान में स्वयं व्याप्त है। दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है कि उनके लिये कॉम्रेस के बद-पक्षियों की अपेक्षा नेहरू अधिक बड़े सकट हैं।

जहाँ तक आर्थिक नीति का सम्बन्ध है, वे द्वितीय योजना की यह कह कर आलोचना करते हैं कि इस अर्थ-व्यवस्था में सर्वहारा के बीच विद्यमान है। विदेशी निहित-स्वाधो और उनके स्थानीय मध्यमियों अर्थात् बड़े व्यापारियों के नारा की सम्भावन उन्हें नहीं दिखलाई पड़ती। वे अनेकों प्रकार के तथाकथित सामाजिक सुधार देते हैं, जो समाजवाद की तीन प्रगतियों सहायता देने के स्थान पर उसे अवरोध करते हैं।

अंत में वे उन विभिन्न 'स्वतंत्र' दलों के प्रति अपना समर्थन प्रदर्शित करते हैं, जो अमेरिकन परराष्ट्र विभाग की नीतियों के प्रेरणा प्राप्त करते हैं तथा राष्ट्रीय आंदोलन के प्रगतिशील अंश के प्रतिस्पर्धी हैं।

अंत में, साम्यवादी नेता इन तथाकथित वामपंथी पार्टियों के साथ कॉम्रेस विरोधी, संयुक्त मोर्चा स्थापित करने की बात करते हैं। ज्योंही ऐसे चुनाव गठबंधनों का प्रचार होने लगता है, इनको निष्प्रभाव करने के लिये कॉम्रेसी नेता प्रजासमाजवादियों के साथ सलाह करने लगते हैं। वे उनके सामने यह दलील पेश करते हैं कि इन दोनों दलों के अंदर 'गांधीवाद' सामान्य रूप में विद्यमान है। कॉम्रेसियों अथवा साम्यवादियों की सुझाव प्रजासमाजवादियों के लिये उपयोगी राजनीति है। वे सत्ता के इस स्पर्ध में अपने आप को अनिवार्य समझने लगते हैं और सामकरी गठबंधन स्थापित कर सकते हैं। जहाँ तक कॉम्रेसी प्रतिक्रियावादियों का प्रश्न है वे विरोधी राज्यों के संगठन को रोकने के लिये चिंतित हैं और एतद्ध नाथ नाचने से तैयार हैं। किन्तु यह समझना बहुत कठिन है कि साम्यवादी पार्टी किस संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त करने की आशा करती है।

सार्थ ज नी न ए क ता

यदि साम्यवाद, प्रजा-समाजवाद और समाजवादका संयुक्त मोर्चा बन गया तो उसकी क्या नीति होगी ? उस समय क्या वे इस बातपर विरवान उत्पन्न कर सकेंगे कि काँग्रेसकी विदेशी नीति और द्वितीय योजना एक धोखेनी टट्टी है ? यदि ऐसा करनेका इरादा नहीं है तो वैयक्तिक साकारका नारा किस आधारपर उठया जा सकता है ? इसके अनिश्चित प्रश्न यह भी है कि काँग्रेसियों अथवा प्रजासमाजवादियों अथवा लोहियाके अनुगामियोंमें कौन अधिक समाजवादी है ? क्या वर्ग संघर्षके सिध्दा सिद्धान्तोंका उच्चारण मात्रही समाजवादकी आवश्यक परीक्षा है ?

इस विषयमें अधिक गहरा उतरने पर लोगोंको इस वास्तविकताका पता चलता है कि काँग्रेस ही अधिक बड़ी जनसंस्था है और प्रजासमाजवादियों एवं समाजवादियोंकी अपेक्षा कामगारोंका उसे अधिक समर्थन प्राप्त है । यह बात प्रामाण्य मोर्चेके साथही साथ युवक संस्थाओं और सांस्कृतिक गोटियोंके सम्बंधमें भी सही है । इसमें कोई संदेह नहीं कि काँग्रेस पूँजीजीवी वर्गके हितोंका प्रतिनिधित्व करती है । तथापि कोई गम्भीर राजनैतिक विचारक इस सुभावनासी अपेक्षा नहीं कर सकता कि स्वतंत्र राष्ट्रवादी पूँजीजीवी अर्थात् भाषाणी क्षेत्रोंके मध्यम पूँजीजीवी तथा कुछ बड़े पूँजीजीवी, सामाजिक नवनिर्माणमें महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं । यदि इस बातको मान लिया जाय तो फिर साम्यवादी नेताओंको काँग्रेससे भी कम प्रगतिशील शक्तियोंके साथ गठबंधन करनेके लिये कौन विवश कर सकता है ?

क्या इसका कारण निदानीहीन और अविचारपूर्ण अवसरवादिता है जो अपने आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदर्शित करती है ? क्या इसका कारण पूर्वकालीन अपरिपक्व रहना है जो वर्तमान समयमें पूर्ण वेगमें प्रवाहित है ? क्या इसका कारण यह धारणा है कि काँग्रेस ईमानदार प्रजातांत्रिक विचारधाराके दांधरेने बाहर है ? अथवा इसका कारण सिर्फ सामान्य भय ही है जो सत्परा गला घोटता है ?

सम्भवतया इसका कारण इन सभी बातोंका सम्मिश्रण है, जिसने साम्यवादी नेताओंके सामने वर्तमान समस्या खड़ी कर दी है । किन्तु अन्य सभी उलझनोंमें अधिक विधान परिषदोंमें शक्ति प्रदर्शन पर अत्यधिक बल देनेकी आवश्यकता है, जिसने साम्यवादी पार्टीको ऐसी गलत स्थिति ग्रहण करने पर विवश कर रखा है ।

किसी समस्याको उसके समग्र रूपमें देखनेके स्थान पर एकांगी संवेदणकी यह बीमारी बहुत पुरानी है ।

भारत अपने इतिहासके एक अन्यतम सङ्कटपूर्ण समयके बीचसे गुजर रहा है । वयष्ट सपन्नता मिल चुकी है, किन्तु यदि वर्तमान परिस्थितिके अनेक स्वीकारात्मक पहलुओंमें समन्वय न हुआ तो यह तट भी हो सकती है । यंत्रकन यह तर्क उपस्थित करना, कि प्रगतिरा एकमात्र मार्ग यही है कि स्वस्थ प्रतिनियोंका नेतृत्व करनेवाली सरकारकी अधिक तीव्र आलोचनाकी जाय, उसी तरहसी विचारधारा जिम्मे जर्मन साम्यवादियोंको हिटलरकी नवोदित नाजीवादी शक्तिकी उपेक्षा करनेपर विवश कर दिया, जो वाइमर गणतन्त्रके विनाश हेतु सज्जित हो रहा था । वर्तमान समयमें हम इस शक्तिकी तुलना उम्र भावनामें कर सकते हैं जिम्मे ईरानकी द्यूडेह पार्टीको मुसद्दीक का ऐसे समय त्याग करनेपर विवश कर दिया, जब उन्हें अपने देशवासियोंके समुक्त समर्थनकी आवश्यकता थी ।

भारतीय साम्यवादियोंके भूतकालमें इन्हीं विचारोंकी प्रतिध्वनि पाई जाती है । जनसम्पर्ककी अपरिचित नीति, मुस्लिम लीगी पृथक राष्ट्रकी अविवेकपूर्ण माँगका इस आधार पर समर्थन कि यह माँग राष्ट्रीय धामनिर्णयकी भावनाको प्रतिभासित करती है, इस बात पर बल देना कि शक्ति हस्तान्तरण दरअसल हुआ ही नहीं, नेहरूकी, यदि कुछ नहीं तो कमसे कम उनके विषयमें फैले मुद्दावादी भ्रमके निवारणार्थ बहु आलोचना आदि बाहें उस नीतिके अतर्गत आती हैं, जो आमतौर पर होती हैं । हालाँकि यह अजीब परिस्थितिकी ओर उन्मुख है । किसी परिस्थितिको उसके यथार्थ रूपमें अध्ययन करनेके लिये तैयार न होनेके कारण यह महत्वपूर्ण सङ्कट उत्पन्न हुए हैं ।

वर्तमान वास्तविकता क्या है ? कश्मिकी आन्तरिक पतिक्रिया इनकी उत्तरदात्री है कि यदि अक्सर मिल जाय तो नेहरूके नेतृत्व ने प्राप्त लाभोंकी नष्ट कर डाले । जो लोग इस परिस्थितिकी मनन करनेके लिये तैयार हैं उनके सामने अनेक सभावनायें आती हैं । इस देशकी धात्र भी उस निविरके अंदर गणना की जा सकती है, जो समानवादकी दिशामें होनेवाली सफल एवं लोकतांत्रिक प्रगतिरा

सार्धजनोन्पकता

विरोधी है। यह जान चाहे जिन समय यथायक हो सकती है। निर्वाचन कालीन अथवा विधायकों के मित्रताहीन संयुक्त मोर्चे इस बात को नहीं रोक सकते। केवल सुसंगठित और जागृत सार्वजनिक शक्ति ही ऐसा कर सकती है।

यह भी अविकारिक स्पष्ट होना जा रहा है कि चाहे अब या कुछ दिनों पीछे साम्यवादी नेतृत्व को इस परिस्थितिका अच्छी तरह सामना करना पड़ेगा। नेहरू और कांग्रेसका समर्थन या विरोध करनेका प्रश्न नहीं है, जैसा कि सामान्यतया समझा जाता है। प्रश्न है उन राष्ट्रीय आंदोलन के सुगठित विरोधी दल के रूप में कार्य करनेका, जो स्वतंत्रता संघर्ष की यमीयतता रक्षक तथा अभिभावक और भाग्यवांशियों की आत्मा है। प्रतिक्रियावादियों को इसी स्थिति में भय है, क्योंकि यह स्थिति पूर्ववांशिन दिवालिया नीतियों की ओर प्रतिगमन के विरुद्ध एकमात्र हथ और प्रभावशाली गारंटी है।

सुगठित वामपक्ष के कार्यकर्ताओं की सदैव यह बलवती इच्छा रही है, ऐसी स्थिति अपनावे। यह ऐसी लगन है जो प्रत्यावर्तन और अस्थानिके समय भी उन्हें साहस और सुरक्षता प्रदान करती है। इस लगन के प्रति नेताओं ने विश्वासघात किया है, जनशक्ति प्राप्त करने के लिये होनेवाले आंदोलनों को बारबार पथभ्रष्ट किया है तथा संस्थागत कौशलों द्वारा नेतृत्व अपने ही हाथ में रक्खा है।

संघातिकता इस तथ्य को नहीं छिपा सकती कि कांग्रेस, प्रजा-मोशलिस्ट और लोकद्विवाकी समाजवादी आदि सभी पार्टियों में वास्तविक वामपंथी मौजूद हैं। इन सुगठनों में प्रतिक्रियावादियों का अस्तित्व भी इतना ही सही है। ऐसी परिस्थिति में साम्यवादी पार्टी का कार्य सरकार बदलना नहीं है, बरन ऐसे जनसमर्थन का निर्माण करना है जो पार्टी मिलों को तोड़ कर विधायकों और विधान सभाओं के बाहर लोगों में मनाजवादी भारत के निर्माण की प्रेरणा दे सके।

इन कौशलों द्वारा लोकमभा और विधान सभाओं में सीटें भले ही प्राप्त न हों, किन्तु उसका परिणाम अधिक प्रभावशाली और सुदृढती होगा अर्थात् सही नीतियों के प्रति अधिक सामूहिक समर्थन और सार्वजनिक सपके सम्भव हो सकेगा। ऐसा सुसंगठित सामूहिक समर्थन, विश्वासघात, विप्लव व्यक्तित्वों में अभ्यवित रह कर सत्ता प्रणाली की निश्चिततम गारंटी है।

साम्यवादी पार्टीके समुच्च उपस्थित विकल्प भी समझना जरूरी है। क्योंकि जिस समय कांग्रेस पार्टी तीव्र सक्रमणशील है, उस समय यही एकमात्र शक्तिशाली एवं परिपक्वोन्मुख पार्टी रह जाती है। यह ऐसी शक्ति है जिसका प्रभाव राष्ट्रीय नीति निर्धारणपर अवश्य दिखलाई पड़ेगा। क्योंकि सत्रम और अस्थिरता पार करके अब यह पूँजीजीवी समस्याकी मध्यस्थता करनेमें समर्थ हो गई है।

जब तक लोकतांत्रिक प्रक्रियाको दूषित नहीं किया जाता अथवा उनकी उपेक्षा नहीं होती तब यह मध्यस्थता शांतिपूर्ण और निर्माणात्मक बनी रहेगी। यदि साम्यवादी पार्टी तथा अन्य वामपंथियोंने जनताकी एकताको पुनर्गठित करनेमें गलतियोंका पुनरावर्तन करके सकटमें डाला अथवा तीव्र परिवर्तनशील परिस्थितिकी रूढ़िगत विवेचना की, तो इस बातका पूरा डर है कि कहीं राष्ट्रीय आंदोलन प्रतिक्रियाकी सहरमें प्रभावहीन न हो जाय।

प्रगति और वामपंथी उन्नतिकी सम्भावनायें चाहे कितनी ही अच्छी क्यों न दिखलाई पड़ती हों, किन्तु भारतीय परिस्थितिमें यह सकट सदैव विद्यमान रहेगा।

न व क्षि ति ज

आकाश की भौतिक प्रकृति निर्मल है, किन्तु उस ओर निरंतर देखते रहनेके परिणाम स्वरूप दृष्टि धूमिल हो जाती है और जब आकाश इस प्रकार दूषित दिखलाई पड़ता हो, बुद्धिहीन प्राणी यह नहीं समझ पाते कि इस दोषका कारण उनके मस्तिष्कके अंदर ही विद्यमान है।

— सरह

प्रत्येक देशमें और हर प्रकारके लोगोंमें सिद्ध पुष्ट और दूरदृष्ट हुआ करते हैं। पूर्वकाल और वर्तमानसे शिक्षा ग्रहण करके ये अब तक अनेकित घटनाओंकी भविष्यकालीन प्रक्रियाओंको समझनेके लिये अनुभव प्राप्त करते हैं। ऐसे अनुमान और अध्ययनके लिये भारत एक उपयोगी क्षेत्र है। सम्भवतया समारमें किसी अन्य देशके निवासियोंने अपने आपमें इतनी आश्चर्यजनक परिस्थितिमें नहीं पाया होगा। और जब विश्वकी घटनाओंका निर्माण करनेवाली शक्तियोंके समुदाय उपस्थित तत्कालीन स्वरूपमें उसी तुलना की जाय तो यह बात अधिक स्पष्ट दिखलाई पड़ती है।

संयुक्त राज्य अमेरिकामें जागरूक व्यक्ति मेकार्थीके अनुयायियोंकी दी जानेवाली जानकारीसे प्रभावित हो सकते हैं, प्रजातांत्रिक विचारोंवाली जनता परराष्ट्र विभागके अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारोंमें सुतापित हो सकती है, किन्तु उन लोगोंने अब ऐसे भ्रमोंका कारण खोजना आरम्भ कर दिया है। यदि समृद्धि उनकी चेतना कुटिल कर देती है, अतः नाश करनेमें समर्थ नीतियोंको निष्प्रभाव करनेके प्रयत्नमें उन्हें नपुंसक बन देनी है, तो उनमें ऐसे समझदार लोग भी हैं, जो यह जानते हैं कि आगे या पीछे सत्य सामने आ ही जायगा। प्रतिदिन यह आवरण बुरा होते जा रहे हैं। शीतयुद्धकी नीतियों उन्हीं लोगों पर प्रभावित हो रही हैं, जिन्होंने उन्हें आरम्भ किया था। ऐसे वातावरणमें फ्रेंकलिन डिलानो रूजवेल्टके विचार अधिक सुदृढ़ और तीव्र होकर पुनः चिजयी हो सकेंगे।

राष्ट्राध्यक्षोंकी अंतर्राष्ट्रीय टाई द्वारा भ्रष्ट और अपचारित भेद विभेद अतलातिक महामागरके उस पार रहनेवाले अपने मानिकोंके इशारों पर नाचने लगा है। उसका

साम्राज्य सजुचित हो रहा है और यदा-कदा उसका छोटा या बड़ा टुकड़ा 'साम्राज्यवादी सनवान' के प्रवर सामीप्य द्वारा हथप जाता है। स्वदेश में लोकजन और उपनिवेशों में नृशंस निरकुशताके उपदेश अब उन्हें प्रेरणा नहीं दे पाते हैं। ब्रिटेन वामियोंको स्वच्छदीप पर बाधित लौटना ही चाहिये। तभी उन्हें इस बातकी शिक्षा मिल सकेगी कि अपनी भूमि पर कैसे रहा जाता है।

जहाँ तक प्रत्यक्ष प्रश्न है यह परिवर्तन आरम्भ हो गया है। आजकल अमेरिकाके अंदर हम इस 'महा शक्ति' द्वारा अपना शृंगार कायम रखनेके अनिम उन्नत प्रयत्न देख रहे हैं। किन्तु उस बहुमूल्य प्रदेशवासी मजदूरोंने अब यह अच्छी तरह समझ लिया है कि यह साज शृंगार, उनके अनेक स्वप्नोंकी पूर्तिके मार्गकी सिर्फ बाधक श्रृंखलायें ही हैं। संपूर्ण स्कावटें बर होनी आ रही हैं। वास्तविक और स्थायी मार्गकी उद्घोषणा करनेवाली एक नवीन शक्तियुक्त बाणी सुनाई पड़ रही है।

जर्मनी और जापानने अपनी दैन्यकार औद्योगिक शक्ति संचित रखकर, मूल्यवान नैतिक दुःसाहसके परिणामस्वरूप प्राप्त वृष्टियों को पूरा लिया है। उनकी अनेकों समस्याये हैं, किन्तु इल उनके पास ही है। वस्तुतः पूर्व और पश्चिमके इन साम्राज्यपरोहे अब अपनी प्रगतिके लिये शांति पर आश्रित रहना पड़ता है। उनका भविष्य अब साम्राज्यवादी कौशलोंने नहीं, बरन् अंतर्राष्ट्रीय तनाव और विदेशी हस्तक्षेपके तर्जों द्वारा आन्यदिन है।

तथोद्दिन चीन आशाका भारी साधन है। इन प्राचीन पुरुषोंने अपरिमित विषमताओंने सघर्ष किया है, किन्तु अब एक विशाल देशको आधुनिक औद्योगिक राष्ट्रोंमें परिवर्तित करनेके लिये दत्तचित्त होकर प्रयत्न कर रहे हैं। १९६२ तक आर्थिक उन्नतिमें वे शेष एशियासे आगे निकल चुकेंगे। वे ऐसा करनेमें समर्थ हैं, क्योंकि उन्होंने मनुष्य निर्मित दुखों और संकटों पर विजय पाने योग्य आधुनिक शक्ति लिये हैं। कोई स्कावट, कोई भूल, अब उनकी इस प्राप्तिसे नहीं रोक सकती।

अपने समाजको स्थालिनवादी तरीके के दोषोंसे मुक्त करनेके पश्चात् सोवियत जनता की प्रगति अपेक्षाकृत अधिक निर्णायक होगी। इस तरीके ने उनके तथा पूर्वी यूरोपमें उनमें सम्बद्ध लोगोंके जीवनको व्याकट कर रखा है। इस विवृति पर विजय पानेके

न व क्षि ति ज

लिये समय और साहस अपेक्षित है। कार्य भारी है और मार्गमें अनेक कठिनाइयों भी हैं।

इन सकलमण्डलीन निर्णायक समयमें जन्म लेकर तथा ऐसे भविष्यमें जो अनेकों समुन्नत लोगोंका भूतकाल हो, अपनी विलम्बित यात्रा प्रारम्भ करते समय स्वतंत्र भारत इन समस्त सवेगों और अनुभवोंका आधात सहता है। एक समय था जब भारतने सिंधु तथा उनकी सहायक नदियोंके कक्षारमें सभ्यताकी उन्नतिका नेतृत्व किया था। आजकल वह दूसरे देशोंमें ग्रहण करता है और प्रतियोगिता करनेमें दूसरे व्यक्तियोंके अनुभवको निर्माणत्मक रूपमें विवर्धित करता है।

इन प्रक्रियाका भारतके मित्र पुरुष और भविष्य दृष्टा अपने अपने दृष्टिकोणके अनुसार अर्थ निकालते हैं। हमें तो सर्वोत्तम विवेकपूर्ण एवं सार गर्भित अर्थ प्रदूषण करना चाहिये।

भारत गोचरयुगसे आणविक युगमें पदार्पण कर रहा है। ऐसे समय अनेक मूच्यों और रुद्धियों, धारणाओं और आदतोंमें क्रांतिकारी परिवर्तन होना स्वाभाविक ही है। किन्तु यदि अनुभवोंका वृद्ध उपयोग हो, तो यह नि सन्देह कहा जा सकता है कि दूसरे राष्ट्रोंके समान बलिदान किये बिना ही यह सकलमण्डलीनताके साथ सगादित हो सकेगा। राष्ट्रोंके अनुरूप बलिदानोंकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह सच है कि वर्तमान पीढ़ीको कठिन श्रम करना पड़ रहा है, किन्तु उन्हें यह तो मालूम ही है कि यह प्रयत्न ऐसे समाजके निर्माणसे संयुक्त है, जो परिचित पूँजीवादी जगलमें पूर्णतया भिन्न होगा। वर्तमान युगका यही प्रबल तथ्य है, एक ऐसा तथ्य जो समस्त दृष्टिकोण और प्रक्रियाओंका रूप निर्धारित करेगा।

आज इन देशके अंदर गभीर भाषायी तनाव हो सकते हैं। कल उत्तर और दक्षिणके बीचमें अंतर पड़ सकते हैं। परन्तु देशकी स्वतंत्रता और सार्वभौमताके विरुद्ध अनेक अंतराष्ट्रीय पद्धतियोंकी रचना हो सकती है। इसमें भी अधिक शोचनीय घटनायें सम्भव हैं, फिर भी यह निश्चित है कि वर्तमान सभ्रम और अनिश्चितता उसी प्रकार समाप्त हो जायगी जिस प्रकार रातकी समाप्ति पर दिनका आगमन होता

है। हम ऐसे युगमें निवास कर रहे हैं जिनमें प्रत्येक क्षेत्रके अंदर रुढ़िगत अराजकताके ऊपर विज्ञान और वैज्ञानिक आयोजनार्थें सुदृढतापूर्वक विजयी होती जा रही हैं।

हम देख चुके हैं कि भारतकी स्वदेशी और विदेशी दोनों नीतियोंकी अशुद्धि स्वतंत्र राष्ट्रीयताके प्रथम दशकमें किस प्रकार वर्तमान युगीन तथ्योंद्वारा निर्धारित हुई है। जैसे जैसे अधिक और राजनैतिक क्षेत्रके अंतर विगलित होते जायेंगे, वैसे वैसे यह निर्माणत्मक क्रिया अधिकाधिक बेग और ओज पूर्ण होती जायगी। इस तरहका सकोच पूर्वशालीन औपनिवेशिक समारम्भमें अधिक दिखलाई पड़ता है, जहाँ कुत्तोंकी तरहका भगदना श्रव निरर्थक प्रतीत होता है तथा उसकी प्रभावकारी ढंगमें प्रचलित करने वाला कोई भारी मुन्धवस्थित दल नहीं है। इसके अनिश्चित यदि ऐसा कोई प्रयत्न हुआ तो समाजवादी सत्ताकी प्राविधिक प्रगति तथा उसकी अमीकी एवं एशियाकी सहायता देनेकी सामर्थ्य इस दर्शनके प्रचलनकी सभाकनाकी विनष्ट कर देगी। भारत एक ऐसे मार्गपर चलनेका प्रयत्न कर रहा है, जिसे स्वयं उसके तथा अन्य देशों द्वारा अनुयुक्त पूर्वशालीन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं द्वारा अवरोधहीन किया गया है।

भारतकी पक्षपातहीन एवं व्यवस्थित जीवन स्थापनाकी दिशामें अर्थात् समाजवादकी ओर प्रगति, शान्तिपूर्ण और सुन्दर हो सकती है। प्रत्येक नया दिन बीतनेके साथ साथ अनेक रूपोंमें यह आधार निर्मित हो रहा है। एक ओर समाजवादी उपकरणोंका विस्तार किया जा रहा है और दूसरी ओर जनताकी बढ़ती हुई सुन्दरता उन्हें अधिक बिल्कु रूपमें कार्यान्वित करनेकी स्वीकृति प्रदान करती है। यदि कुछ थोड़े अल्पसंख्यक इस मार्गमें रुकावटें डालनेका प्रयत्न करते हैं, तो वेबल अस्थायी विचलन उपस्थित कर सकते हैं। यदि यही अल्पसंख्यक इस विचलनको स्थायी बनाना चाहें तो उन्हें स्वयं अपने मूल्य पर यह समझनेके लिये बाधित होना पड़ेगा कि अनेच्छाकी अधिक समय तक दूषित नहीं किया जा सकता।

अनेक प्रधरसे समाजवादकी ओर उन्मुख इस नये सकलणके रहस्योंमें होनेवाले परीक्षणोंका पथ प्रदर्शन भारत करेगा, क्योंकि इसी दिशामें अग्रसर होनेवाले, हिंदी-शिया, बर्मा, मिथ आदि नवोदित राष्ट्रोंकी अनेक बड़ी मयेष्ट आने बस हुआ है।

न च क्षितिज

यह निश्चित है कि राजनीति और अर्थशास्त्रमें अद्वितीय प्रगति होगी । उन्हें समझनेके लिये अधिक गंभीर और रचनात्मक ज्ञान अवेक्षित है क्योंकि सामान्य तरीकोंसे इन्हें समझना अत्यंत कठिन है, जिन्हें इस कथनमें संदेह हो उन्हें अपनी सृष्टि जाग्रत करके देखना चाहिये कि भारत, हिन्देशिया, यार्मा और मित्र आदि देशोंमें स्वतंत्रताके प्रारम्भिक वर्षोंके अंदर इस प्रकारके अनेक प्रत्यक्ष उदाहरण मौजूद हैं ।

अन्य प्रदेशोंके समान भारत भी नवीन अनुभवोंका प्रकाश, नवीन समस्याओंका नाव और नवीन निष्कर्ष खोजनेका गर्व अनुभव करेगा । उसे आरम्भिक औद्योगिक क्रांतिके मर्मभेदों अनुभवोंसे पुनः गुजरनेकी आवश्यकता नहीं है, उसे दूसरोंकी भूलें सुझाने की भी जरूरत नहीं है । यह तो वास्तविक विद्युत् बेगीय प्रगतिकी ओर बढ़ सकता है क्योंकि उसने विश्व-विज्ञान द्वारा प्रस्तुत आणविक युगमें, अपनी यात्राका भीमगणेश किया है ।

इसका अर्थ समझनेके लिये आपको यही देखना पड़ेगा कि अग्नि, चक्र, तथा नवीन धातुकी खोजने मानवजातिकी कद्धानीको नाटकीय ढंगसे किस प्रकार परिवर्तित कर डाला । फिर आणविक शक्ति और उसके प्रयोगोंका आपात कितना अधिक निर्णायक सिद्ध हो सकता है ? प्रथम बार विज्ञानने हमें मरुस्थल, पर्वत और समुद्रको परिवर्तित करनेके लिये असीमित शक्ति प्रदान की है । यह ऐसी शक्ति है जो अनेक शताब्दियों तक पानीकी नन्हीं नन्हीं बूंदोंमें अव्यक्त अवस्थामें पड़ी थी । इस तरह नवीन प्रयत्नोंकी सीमायें अब बड़े-बड़े विस्तृत हो गई हैं । अब और तो और, शून्यमें स्थित ग्रहों तक तथा उसमें भी आगे पहुँचा जा सकता है ।

इन सब बातोंका क्या अर्थ होता है, इसे बतलाना अभी कठिन है । तथापि एक परिणाम निश्चित है । इस तरहके विकासको सम्भावनाओंकी चौकसी तथा रक्षा एक अन्त्यावश्यक कर्तव्य हो गया है । एकमात्र वैज्ञानिक सामाजिक संगठन ही यह कार्य निष्पादित कर सकते हैं । मानवजातीय विशाल साफल्यके बलिदान बिना यह कैसे प्राप्त हो सकता है ? राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नेताओंका यही प्रमुख कर्तव्य हो गया है ।

इतिहास इस बातका साक्षी है कि ज्यों ज्यों हमारे पूर्वज विराट प्रवृत्ति पर नियंत्रण प्राप्त करते गये, उनका आश्चर्यजनक रूपमें अपने पारस्परिक सम्बन्धों पर से नियंत्रण हटता गया। वे विराट प्रचुर और बहुधा अमूर्त शक्तियोंके निगूँथन आखेट करते गये जिन्होंने उन्हें रक्षित शक्तों, बर्ग सघनों, वर्ण एवं सामुदायिक कतहों तथा अन्तराष्ट्रीय युद्धोंमें धसीट लिया।

किन्तु इतिहास इस वर्तमान प्रयत्न तथाकथी भी आलोचित करेगा कि समस्त मानव जातिका महानुद्भूत प्रयत्न मध्य चीनकी शताब्दीमें प्रिवको आणविक विध्वंसमें रखा करना रहा है।

इस जीवित अनुभवमें शिक्षा ग्रहण करनेके पदचान क्या यह संभव है कि भारत विवेक और शांतिपूर्वक समाजकी उन अनेक शक्तियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सके जिन्होंने उसे अत्यंत निर्धनता, भूख और अज्ञानमें संनस्त कर रखा था।

इस प्रश्नका उत्तर हमारे पास है। हम चाहें तो इस दुनियामें आग लगा कर उसे भस्मीभूत कर सकते हैं, अथवा उसने ऊपर एक ऐसे नवीन भवनका निर्माण कर सकते हैं जैसा भूतकालमें कभी सम्भव न हुआ हो।

सूची

अ

- अवादान - ३५, ६१
 अबदुल्ला शेख मोहम्मद - ८६, ६१
 अफगानिस्तान - १२४, १२७
 अमीका - १०, ३२, ३८, ८८, ८६, ६१,
 ११३, ११४, १२१, १२२,
 १२३, १२५, १२६, १२७,
 १२८, १३०, १६६, १८८, १८६,
 १६१, १६३
 अहमदाबादके मिल मालिक - ८६, २०३
 अलबानिया - ५३
 अलजीरिया - ८८, १६८
 अखिलभारतीय शांतिमम्मेलन - २२६
 अखिलभारतीय रेलवे मेन फेडरेशन -
 २१८
 अमेरिकन प्रतिनिधि - ६०
 अरब - १२५, १२६, १३० प्रदेशीय-
 सेल १२५, १२६
 अथर्ववेद - ६३
 अतलांतिक संधि - ६०
 अवादी अधिवेशन - ११७, ११८,
 ११६, २०७
 अफनीमबी समानान्तर - ५८, ८०

आ

- आनेम इड - १६७
 आत्र - १००, ११७, ११६, २२१,
 २२७, २२८
 - के चुनाव - ११७, ११८,
 आइसन हावर - राष्ट्रपति - ६२, १०६,
 १२८
 आसफअली अखण्डा - ७६, २१६
 आणविक तथ्य - ८०, ८१ १८५-७,
 १६४-६, २४१
 आणविक शक्ति सम्मेलन - १२४
 आणविक शस्त्र - १८७, १६३
 आजाद अमुल बलाम - ८२
 आजाद हिन्द फौज
 (इंडियन नेशनल आर्मी, } ५, १६६

इ

- इटली - १३
 इकबाल मोहम्मद - २०
 इकोनोमिक वीकली आफ बाम्बे - १६६

ई

- ईस्टर्न इकोनामिस्ट - ७६
 ईडन, सर एथोनी - १०, १२५
 ईरान - ३५, ६१, ६२, ८८
 ईराक - १२१

उद्जन वम - ४०, ६१, १८७
उत्तरप्रदेश - ७७, ८७
उड़ीसा - २६
उत्पादनमें वृद्धि - १५६

ए

एशिया १०, ३०, ३१, ३२, ३३,
३५, ३८, ४२, ४३, ५८, ५६,
६१, ६३, ६६, ८८, ११३,
११४, १२१, १२२, १२३,
१२५, १२७, १८८, १८६, १६३
एशियायी - अफ्रीकन सम्मेलन - ११३,
१२१,
एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस, १६४७ - २६
एटली प्रीमियर - ८, १०, ५५
एकीकरण योजना - २६, (विलयन
योजना देखिये)

औ

औद्योगिकी - १५६
औद्योगिक ऋणा और विनियोजन
निगम - २१०
औद्योगिक स्वशासन - ४०
औद्योगिक नीति विषयक प्रस्ताव
(१६४८) - ६७, (१६५६) -
१४६

अंबर चरखा - १५५
अश्वत्थान निर्वाहनिधि - ८७
अत्रेज अफसर - २६

क

केबिनेट मिशन - ८०
कंबोडिया - १२५, १६७
कपड़ा - १५४, १५५
कोय कोला - ६८
कोलम्बो सम्मेलन - ११०,
कमिन्समर्थ - ७६
कामन वेल्थ ब्रिटिश - (राष्ट्र मंडल)
२४, ३०, ३४, ४३, ५५, ६८,
१०७, १२६, १८१, २०६
कॉम्रेल पार्टी - (राष्ट्रीय सभा) ४, ५, ६,
८, ६, ११, १५, २०, २१, २२,
२३, २४, २५, ३८, ४४, ४६, ५४,
६६, ६६, ७७, ८३, ८४, ८५, ८६,
८७, ६६, १०२, ११७
दलीय सपर्य - ४६, ५१, ५८, ६६,
७०, ७७, ७६, ८१, ८४, ८३,
११६, १२१, १६८, २१२, २३४,
२३५
कोरप्रेल्ड कनराड - १८
क्रिश्न-सर स्टेफर्ड - ५
कबीर - ३
कगनोविच - १७०

सूची

बाह अर. सी. - १८

अनिदान - १८३

बाहल - १३५

बाहल - १०८

बाहली - ४५

बाहली अधिवेशन - ४८

बाहली - १३, १८, १९, २८, ४५,

६२, ८१, ८६, ९०, १०६, २०१

बाहली अधिवेशन - ४५

बाहली निर्मात्री परिषद् - ८१, ८६, १०८

बाहली अधिवेशन बाहली - १२१

बाहली - ८८, ११४, १६८, १८८

बाहली रफीकामद - ६४, ७७, ८२

११५, ११६

बाहली - ६८

बाहली - ५६ - ५८, ६३, ८०, ८८,

१०३

बाहली - १२१

बाहली - ३३, ६२, ११६ (सोपेयन

सम देखिये)

बाहली - ६४, ७७, २३१

बाहली मजदूर प्रजा पार्टी - २२०

बाहली - १०५

बाहली - ११५

बाहली - ३३

बाहली - ६४

बाहली मजदूर पार्टी - ७६

बाहली राज्य - ८५

(अवाही अधिवेशन और समाजवादी
होना देखिये).

बाहली

बाहली - ६२

बाहली - ४६

बाहली - १०५

बाहली - ११५ - २५, १२७,

१७० - ७१, १७४, १६३

बाहली

बाहली - ६, १६, १७, ४०,

४६ - ४८, ८३, २००. २१५,

२२५, २२६

बाहली - ४८

बाहली - ४८

बाहली - १२६

बाहली - १०६, २१६, २२१

बाहली - ६८

बाहली - ६७

बाहली - ८१, ८६

बाहली - १३, ६५, ६६

बाहली - ६४

बाहली

बाहली - ४७

बाहली

बाहली - १०८

बाहली - ३३, ३८, ४२, ४३,

५५, १६८, १८८
 चीन-४, ३०-३५, ३७, ४२-
 ४३, ५३, ५६, ५७, ५९, ६१,
 ६३, ८०, १११, ११३, ११५,
 ११६, १२५, १६२, २२२-
 २२५, २३८
 -लंगी यात्रा-२२३
 चू एन लाई-१११, ११२, १२६,
 १६८
 चर्विल विन्स्टन-६, १०, २७, २८,
 २२५
 चतुर्दश शीर्षस्थ सम्मेलन-१२४
 चक्रवर्ती-१६३
 चित्तरंजन रेल इनन कारखाना-१३१,
 १५६

ज

जालन-२१०
 जापान-५, ४२, ८८, १२५, २३८,
 -शांति संधि-८०
 जम्मू-१४
 जनसंघ-१५, २४, ८४, २३१
 जारडम-१७४
 जेकोस्तेवानिया-५३
 जिनेवा सम्मेलन-१०६-१११
 जर्मनी-४, २३८; साम्यवादी-२३४
 जिन्ना मो० श्व०-८
 जोर्डन-१२६

जोशी पी० सी०-१०, २२६
 जूनागढ़-१७, २०१
 जनयुद्ध (जन सभान)-७, २१८
 (भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी देखिये)
 जहीर, सज्जाद-६२
 जमींदारी-५१, ८४, ८५, ८७,
 १२०, १२१, २०१

ट

टंडन, पुष्पोत्तमदास-५८, ७८, ८२,
 २१६
 टाटा-६७-६८, १००, १३८, १४०
 १४४, २११ (भाषावाद और
 कांग्रेसदल देखिये)
 टीटो जोसेफ मोज-४१, ११८, १६६,
 १७२
 ट्रावनकोर कोचीन-२६, ८५
 टूमेन हेरी एस-३५, ५७, ६३, ६५,
 ८०

ट्यूडेह पार्टी-२३४

ट्यूनीशिया-८८

ठ

ठापुर, रवीन्द्र नाथ-१३

ड

डालमिया-६७

ड्यू-१०६

डूनेस, जान फास्टर-१६०

डच शासन-५६

डामन-१०६

सूची

त

तेल कंपनी - १०१

तटस्थता - ३७, ५१, ५८

तामिल - १३, ६५, ६६ (भाषावाद-
देखिये)

तिब्बत - ५६, ६०, ६४, १११, ११३

तिलक बा० ग० - ४७, २२४

तोमियादी - १७१

थ

थार्डलेड - २७, १२१

द

दिभाषावाद - १३३, १३५

दादरा - १०६

देसाई मूलाभाई - ७

देशमुख चिंतामणि - १३५

दक्षिण अफ्रीका - ८८

ध

धर आयोग - १३७, १३८

न

नीकरियाँ - १४५, १४६, १४८

नागाभूमि - ६०

नागासाकी - ३३

नागपुर अधिवेशन - १३७

नारायण जयप्रकाश - २१, ७६, २१६,
२२०, २३१

नामिक अधिवेशन - ५८

नसीर गमाल - ८८, १५८

नाटो - ८८, १६८ (अन्तराष्ट्रिय संधि
देखिये)

नवानगर जाम साहब - २५

नाजिमुद्दीन - ६१

नगोव एम० - ८८

नेहरू जवाहरलाल - ५, ८, १६, २६,
३०, ३१, ३६, ३७, ३८, ४३,
४७, ५१, ५५, ६०, ६३, ६४,
६७, ६८, ७४, ७६, ७८, ८०,
८२, ८४, ८७, ८८, १००-
१०२, १०४, १०७, ११३,
११५, ११६, १२२, १२४, १६६,
१६७, १६८, १८१, १८८, १८९,
२१६, २१७, २३४,

नोबिल फ्राइज पानेवाले वैज्ञानिक - १२४

नरेश-राजा - ८४

नीतिनिक विद्रोह - ८, १६६

प

पूर्वी यूरोप - ३२, ४१

प्रशांत महासागर - ४२

पिने धानस - २२४

पाकिस्तान - ११, १४, १५, १८,
१९, २७, ४२, ४५, ४६, ५६,
६४, ८१, ८६, ९०, १०४-
१०८, ११०, १११, १२५,
१२६, १२८

सयुक्त राज्यमे संधि - १०४, १०७,

मैनिंक पडयन - १०४
 पूर्व पश्चिम का तनाव - १०६, १०७
 पूर्वी पाकिस्तान में चुनाव - ११०
 पंचशत - ११२, १२२, १२४, १२२,
 १२३, १६२ - १६७
 पंडित-विजयलक्ष्मी - १५, ५५
 पनीकर के० एम० ३१
 पटेल बल्लभभाई - २५, २७, २८, ३६,
 ४७, ४६, ५०, ५१, ५५, ५८,
 ६०, ६६, ७०, ७५, २०१
 पटवर्धन अच्युत - २१
 पेकिंग - ४२, ५६, ६१ (चीन देखिये)
 पेसू - २६ (भाषावाद देखिये)
 पेराम्बूर सवारी डिब्बा कारखाना - १३१
 प्लासीकी लड़ाई - ३
 पोलैंड - ५३
 पाजीचेरी - १०८
 पुर्नगात-भारतीय वस्तियों - १०६
 पोन्ट्रम सम्मेलन - १२४
 प्रजापार्टी - ७७, २२१
 प्रजा सोशलिस्ट (समाजवादी) - २१७-
 २२१, २३१, २३३
 प्रकाशन टी. - ७७
 प्रवरा-समादरीय लेख - ११६
 पंजाब - १५, १६, १००, १०६
 पूर्वी पंजाब - २६, (भाषावाद देखिये)

पश्चिमी एशिया - ४२ (मध्य पूर्व,
 देखिये)
 पश्चिमी योस - ४१, ६०.
 पश्चिमी जर्मनी - ६०, ६० (जर्मनी
 देखिये)
 पूर्ण स्वराज्य - ४०

फ

फैंज, फैन अइमद - ६२
 फानिस्ट वाद - ४, ३२
 फारुह मुल्तान - ८८
 फारमोसा - ६१
 फ्रेम - १३, ३७, ८८, २३८
 भारतीय वस्तियों - १०८
 फिलिप्पाइन - १२१

व

ब्रिटेन - १२, १६, २७, ३२, ३०७
 ४३, ६६, ८६, २३७
 ब्रिटिशालामी (अमेन) - ४, ६५, ६६,
 २२२-२२५
 ब्रिटिश व्यवसाय - २०२
 ब्रिटेनकी मजदूर पार्टी - ४३
 (कामन केन्थ-राष्ट्र मंडल देखिये)
 बुलगागिन, निमोलाई - ११५, १२४,
 १२५, १२७.
 बलगेरिया - ५३
 बगदाद सचि - १२२, १२६,

सूची

बर्न (ब्रह्मा) — ४, ४२, ५६, १२४
 १६०, २४०,
 बाहुग सम्मेलन — १२१-१२४, १२७,
 बेद्यक — ४३
 बंगाल — १३, १६, १०७
 बरार — २६
 बेरिया, लेबेरेंटी — १६६
 बिहार — १३, २६, ६५, १००
 बिलासपुर — १३,
 बिह्ला — ७६, ६६, ६७, ६८,
 १००, ११५, १४४
 बोगर सम्मेलन — ११३
 बम्बई — २६, ६६,
 बम्बई नगर — ४५, ११०, १३४
 — १३६,
 बोम-मुभापचर — ५, ४७, ४८
 बिक्रीकर — १५७

भ

भाकरा-नागन — १३१
 भावे, विनोद — १६४
 भिलई इस्पात कारखाना — १२८
 भूदान — १६४
 भोपाल नवाब — १८
 भूपत — ८४
 भारतीय कम्युनिस्ट (साम्यवादी) पार्टी
 ७-११, १६, २१-२२, २६-
 २७, २९, ३०, ३५, ३८, ४७,

४६, ५१, ६०, ६८, ७६, ८३,
 ८५, ८६, ११७-११९, १३७,
 १७५, १७६, २१०, २१६,
 २१८, २२१-२३६

भारतीय आर्थिक संबंध — ६६-६६

भारतीय खाद्य स्थिति — ६३-६६.

भारतीय संकट कालीन अन्न —

— महापता नियम — ६५

भारत-चीन मित्रता समिति — २२६,

भारतीय गणतंत्र (गणराज्य) — ३८,

४०, ४३,

भारतीय इस्पात प्रतिनिधि मंडल — १२८

भारत पाकिस्तान समझौता — ४६

भारत सोवियत मित्रता समिति — २२६

भाषावाद — ६४-१००, १३७-१४०

२३६, (कांग्रेस पार्टी दलीप सघर्ष
 भी देखिये)

भूमध्य सागरीय — ८८

भोजन छोड़ो — १६१

भारत छोड़ो नारा — ५

म

मित्र-८७, १२५, १२६, १३०,

१५८, १६८, १६०, २४०

मुद्रास्फीत — १५६

मेकड्यार्थर वी. — ५६, ६३, ८०

मेक नाटन — ४५

मध्य भारत — २६

मद्रास - २६
 महालखोनिम पी सी. - ११६, १३२,
 १४०, १४३, १५२, १५७
 माहे - १०८
 मजदूर - १०३
 मलाया - १६८, १८८
 मलयाली - ६५, १००, (भाषावाद
 देखिये)
 मार्शल योजना - ४१, ६०
 मालनघोव ली - ६१, ११५, १२५
 मचूरिया - ५८
 माउ-त्से-तुंग - ३१, २२७
 मराठा - १३, ६५, ६६, (भाषावाद
 देखिये)
 मार्टिन किंगले - ३०
 मारवासी व्यापारी - ६७, ६८
 मिर्कोयन - १६६, १७०
 मौर्य - ६४
 मध्यपूर्व - ६६, ८८
 मेहता अशोक - ७६, २१६, २२०,
 २३१
 मुसरीक मोहम्मद - ६२, ६१, २३४
 मॅट्रेस फ्रांस पी. - १११
 मिल जे. एस. - २२४
 मोहम्मद अली - ६१, ११० १२१
 मोलोनोव - १७०
 मोकटन वाचर - २७

मोरको - ६१
 माउंटबेटन लार्डे हर्बस - ६, १०
 मुशी क. मा. - ४८
 मुमलमान - १६, १८
 मुस्लिम लीग - ८, ६, १४, ११०,
 २००, २३४
 मैसूर - २६
 मजदूर दल (ब्रिटिश) - ५१
 य
 योरोप - ४२
 योजना प्रथम पंचवर्षीय - ५४, ७३ -
 ७६, ८७, १३१ - १३२, १५७
 योजना आयोग प्रारूपमें कार्यक्रम - ६६,
 ७१, ७३
 योजना द्वितीय पंचवर्षीय - ११६,
 १३२, १४० - १६६
 योजनाका प्रारूप - १४३, १४५,
 १४६, १५०, १५२
 योजना के लिये वित्त - १५२, १५३
 योजना का अनुक्रम - १६५
 योजना विद्वत् टाटा - ७१, ७५
 यालू नदी ५८
 यनाम - १०८
 यूगोस्लेविया - १६६, १७२ (टोटी भी
 देखिये)
 र
 राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम -
 २१०

सूची

राष्ट्रीय योजना समिति - ४८

रियासतें - १३, १४, १७, २५, २६,
२०१

रेडियो सक्रियता - १८५, १८६, १८५
(अणविक तथ्य देखिये)

रेले - १५०, १५१

राजस्थान - १०६ (भाषावाद देखिये)

राजेश्वरराव - ६०

रानराज्य - ५०

रामायणा - ६६

रणदिवे की टी. - १०, २१, ६०

रण एन जी - ७७

रजावार - २६

रजमरा-ईरानके प्रधान मंत्री - ६१

रो-मिगमेन - १८८

रुजवेल्ड एफ. डी - २३७

रुसो - २२४

राय बी सी. १३६

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ - १५, २४, ८४

रुमानिया - ५३

रुस - ३२ (सोवियत संघ देखिये)

राज्य पूंजीवाद - २०६-२०८

(साम्यवादी क्षेत्र देखिये)

राज्य पुनर्गठन आयोग - १००, १३२-
१३६, २१६

राष्ट्रसंघ - २६, ३१, ५६, ५७, ६१,
८८५, १०८

राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद - ८१

ल

लाजपत राय - ४७, २२४

लेनियल-मासीसी प्रधान मंत्री - १११

लेनिन की आई. - ४६, १७३, १७४,
१७६, १८०, १८३

लीवर ब्रदर्स - ६८

ल्हासा - ५६

लिमये, मधु - २२०

लोहिया - रा. म. - २१६, २२०,
२३१

लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस - ४८

लोकतांत्रिक गवेषणदल - २२०

लाम बाटने की योजना - ५३

घ

विलयन योजना - २०१

(एकीकरण योजना देखिये)

विधान निर्मात्री परिषद - २४

विदेशी लागत - ७०

वामपंथी भारतीय - ४१, ४६, ८५,
११६, २१७, २१६

वन महोत्सव - १५८,

विदर्भ - १३३, १३४

वितनाम - ४२, ६१, १०६, १११,
(हिंदीची देखिये)

विश्वामल पर्वत गढ़वाल - ६६

विवेचनानन्द - ६६

वाइसर गणतंत्र - २३४

विमर्श - ६८

विश्व युद्ध द्वितीय - ४१, ६३

विपुलन रेखा - ५६

स

सामान्य चुनाव ६४, ६६, ८२-८७

- परिणाम - ८६

स्वतंत्र - ८४

सार्व भूमिस्वतंत्रता - १४

सुरक्षावादी कानून - २२

सार्वजनिक क्षेत्र - १०१, ११६, १५२,

१६४, २०६ - २०६

संपूर्णानंद - २१६

सोन बाइन - ६४

सन्ध्याप्रद - ३

सरह - २३७

सऊदी अरब - १२५ - १२६, १६७

सौराष्ट्र - २६, ८४

सीधो - १२२

सिंदरो उर्वरक अरबाना - १५८

मिषानिया - ६७

समाजवादी ७, २७, ४१, ४६, ७८,

८६, २१८ (प्रजा पार्टी देखिये)

समाजवादी दंग का समाज - ११७,

१२० (कॉम्रेसके दल, अवादी
अधिवेशन)

सार्वजनिक क्षेत्र और राज्य पूँजीवाद भी
देखिये)

सामाजिक सुरक्षा परियोजना - ८६

समाजवादी संसार - ५८, ७२, ११४,

१६८ - १८१

सोवियत संघ - ३२, ४१, ४२, ५३,

८०, ८१, ६१, ११४, ११५,

१२६ - १२९, १६८, १८१,

१८६, १८७, १८८, २३८

- भारतमें संघ - १२५ - १२६

असुराणिस्थान और काश्मीरसे

संबंध १२६

—द्वितीय पंचवर्षीय योजना— १६१

सोवियत इस्लाम की मशोन - ११५

(भारतीय इस्लाम प्रतिनिधि मंडल
देखिये)

स्वेन - ६

स्वातिन ले - ५७, ८१, ६१, १६८-

१८१

सुरत अधिवेशन - ४७

सीरिया - १२६

स्वतंत्र व्यवसाय मंच - १५१

संयुक्त राष्ट्र अमेरिका - ४, १६, २८,

३३, ३५, ३६, ४०-४३, ४५, ५४,

५५, ५७, ५८, ६१-६३, ६६, ६८,

६६, ८२, ८८, ९०, ६१, १०४,

१०८, १६० - १६१, २३७ - २३८.

- भारतको स्वायत्त कृष्ण - ६४-६५

- राजनीतिक पार्टी - ६२.

सूची

—तेजोमयीके तन्त्र— १६४, १६५

साक्षरता— १६८

संयुक्तसोवियत सोशलिस्ट—

रिपब्लिक (रूस और सोवियत यूनियन
देखिये)— ४, ६०

सशस्त्र सेनायें— २६

सीमान सेनायें— ६

सद्व्यवस्था— पृष्ठ भूमि— १८३—१८५

स्वतंत्र एशिया समिति— २२०

सामुदायिक परियोजना प्रणयन— ८७,
१६१

संविधान— २०, २२—२३, २६

श

श्रीनगर— १६

श्रीरामलू पोद्दी— १००,

श्रीलंका— ११०, १२६

शरणार्थीसंपत्ति— ४४

शासिकादी— ४१

शमदान— १६१

ह

हाथ बरषा— १५५

हिमाचल प्रदेश— २६

हिन्दी साम्राज्यवाद— ६६

हिन्दुसद्दानभा— ७, १५, २४, ८४,
८५, ६७, २००, २१२, २१६,
२१७

हिन्दुस्तान मरतोन कल केन्द्र— १२१

हीरोशिमा— ३३

हिटलर— ३२

हंगरी— ५३

हैदराबाद— १३, ८६—२२, ८५,
२०१— निजाम— २१, २६—२८

हिन्देशिया— ४२, ५६, २४०

१६ राष्ट्रीय सम्मेलन— ३०

हिन्द चीन— ८८, ८६, १०३, १८८
(कितनाम भी देखिये)

ज

जिदलीय समझौते— ५२